संपादकीय

भारत अमेरिका के बिगड़ते संबंध चिंताजनक

भारत और अमेरिका के बीच अब कुछ सामान्य नहीं लग रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के फ्रीज खातों को लेकर अमेरिका ने मुद्दा उठाया था। भारत ने इस पर संज्ञान लेकर अमेरिकी राजनयिक को तलब किया और जोरदार विरोध दर्ज कराया लेकिन इस सबके उलट भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गासेटी स्वयं ही भारत को नसीहत देने लगे हैं। सीएए और गुरपतवंत सिंह पन्नू के मामले में उन्होंने भारत को रेड लाइन पार न करने की गिद्दड़ भभकी दी है। अचानक अमेरिका का ऐसा बदला व्यवहार अचंभित कर रहा है। पिछले लगभग 15 वर्षों से दोनों देश करीब आए थे और हथियारों से लेकर अन्य वैश्विक मुद्दों पर आपस में सहमति और सहयोग बढ़ा था लेकिन अचानक अमेरिका का भारत के प्रति बदलते रवैये के दो कारण हो सकते हैं। एक, भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की डगर पर है जो आने वाले समय में अमेरिका के सामने चुनौती बन सकती है। ऐसे में अमेरिका भारत के बढ़ते प्रभुत्व को कम करना चाहता है। दूसरा कारण दोनों देशों में होने वाले चुनाव भी हो सकते हैं, अमेरिकी सत्तारूढ़ दल भारत विरोधी वोट को अपने पक्ष में करने के लिए भी इस प्रकार के कदम उठा सकता है। जो भी हो भारत और अमेरिका के बिगड़ते रिश्तों से पाकिस्तान और चीन जैसे मुल्क फायदा उठा सकते हैं। भारत और अमेरिका को आपसी संबंधों की बेहतरी में बिगाड़ डालने वाले कारणों को बातचीत के माध्यम से दूर करना चाहिए इसके लिए किसी राजनीतिक स्वार्थ का आड़े नहीं आने देना चाहिए।

प्रेरक प्रसंग

खुशी का अवसर

एक बार रोम का सम्राट किसी बात पर अपने मंत्री से नाराज हो गया, पर मंत्री को इसकी चिंता न थी। वह अत्यंत सुलझा हुआ ईश्वर भक्त था। सम्राट जब भी मंत्री को देखता, उसे लगता कि वह ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसका निरादर कर रहा है। असल में सम्राट खुद को ईश्वर से भी श्रेष्ठ मानता था। सम्राट की ईर्ष्या बढ़ती गई और एक दिन उसने निश्चय किया कि मंत्री के जन्मदिन के मौके पर वह उसे फांसी चढ़ा देगा। मंत्री के जन्मदिन पर उसके परिवार ने विशाल भोज और भजन-संगीत का आयोजन किया जिसमें अनेक लोग आए। तभी राजा का दूत एक लिखित आदेश लेकर आया। मंत्री ने आदेश पढ़ा और मस्ती से नाचने लगा। जब सम्राट को इसका पता चला तो वह मंत्री के घर पहुंच कर बोला, 'तुम्हें पता है न कि आज शाम छह बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी।' मंत्री बोला, 'जी महाराज, तभी तो मैं अपनी मौत का आनंद मना रहा हूं। जन्मदिन व अन्य शुभ अवसर पर तो सभी लोग हमारे साथ होते हैं, लेकिन ऐसे सौभाग्यशाली कम होते हैं जो मृत्यु के समय अपने लोगों को अपने करीब पाते हैं। मैं इस नश्वर संसार को इन सब लोगों के बीच नाचते गाते हुए छोड़ रहा हूं। खुशी का इससे बड़ा अवसर और क्या हो सकता है?' यह सुनकर सम्राट दंग रह गया। उसने उसी क्षण उसकी फांसी की सजा रद्द कर दी और स्वयं भी उसके जन्मदिन के जश्न में शामिल हो गया। साथ ही उसने खुद को ईश्वर से बड़ा मानना भी छोड़ दिया।

आए दिन राजनीतिज्ञों के उलजलूल बयानों से लोकतंत्र में राजनीतिक मर्यादाएं हो रही तार-तार

राजनीति में वैचारिक प्रदूषणः कारण और निवारण

राजनीति की प्रचलित परंपरा में विषय विशेष को लेकर प्रामाणिकता के आधार को भी संदिग्ध करार दिया जाने लगा है। इन हालातों में हो यह रहा है कि हर एक आदमी महज अपने-अपने पूर्वाग्रह के आधार पर ही विषय विशेष को लेकर अपना अभिमत रखने को विवश है।

राजेंद्र बज

राजनीति में तर्क-वितर्क का स्थान कुतर्क ने ले लिया है। वह समय अब नहीं रहा जब राजनीति में उच्चस्तरीय आदर्शों का परिपालन किया जाता रहा था। आए दिन राजनीतिज्ञों के उलजलूल बयानों से लोकतंत्र में राजनीतिक मर्यादाएं तार-तार होती जा रही हैं। अनर्गल प्रलापों का सिलसिला निरंतर जोर पकड़ता जा रहा है।

राजनीति में शुचिता और पवित्रता बीते दौर की बात होती जा रही है। येन-केन-प्रकारेण सत्ताप्राप्ति की चाहत में नैतिक मूल्यों को ताक पर रख दिया गया है। निराधार आरोप तथा आधार सहित आरोप में कोई अंतर नहीं रह गया है। हवा में तैरते आरोप हर एक को संदेह के दायरे में लिए हुए हैं। लगभग यही स्थिति सामाजिक जनजीवन में स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। अलग-अलग परंपराएं व रीति-रिवाजों को अपने अपने पूर्वाग्रह के आधार पर आकलित किया जा रहा है। राजनीति और समाज में विचारधाराएं भी अस्त-व्यस्त होती नजर आती है। व्यावहारिक धरातल पर आम

नागरिकों का राजनीतिक दृष्टिकोण जातीय तथा क्षेत्रीय आधार पर निर्धारित हो रहा है।

राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों का इतना ध्यान केंद्रित नहीं है कि वह बड़ी सोच को लेकर चल सके। ऐसे में छोटे-छोटे कारण ही बड़े परिवर्तन के जनक सिद्ध होते रहे हैं। जो जिसका नेतृत्व करता है, वह उसे अपने तौर तरीके से हांक रहा होता है। उथली सोच के आधार पर नेतृत्व का चयन, राजनीति में उच्चस्तरीय आदर्शों की स्थापना में बाधक सिद्ध हो सकता है। ऐसे में राजनीतिज्ञों द्वारा आए दिन बोले जा रहे अनर्गल बोलों पर लगाम लगाना अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है। अन्यथा आरोप-प्रत्यारोप का यह सिलसिला चलता रहा तो आम नागरिकों से वास्तविकता से टूटता नाता नकारात्मक परिस्थिति का कारक सिद्ध हो सकता है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के चलते अनर्गल प्रलापों का सिलसिला निरंतर विस्तार पाता जा रहा है। स्वस्थ राजनीति एवं समाज की संरचना में मतभिन्नता बाधक होकर अनावश्यक विवाद की जनक सिद्ध हो रही है विकसित भारत की परिकल्पना को साकार सिद्ध करने के लिए राजनीति का शुद्धिकरण समय की मांग है। इन दिनों राजनीति में सच को झूठ और झूठ को सच सिद्ध करने की होड़ सी चल रही है। ऐसे वैसे-चाहे जैसे जनमत का समर्थन पाना राजनेताओं का परम लक्ष्य बन गया है। लक्ष्य को पाने के लिए नैतिक-अनैतिक का भेद नहीं किया जाता। यह स्थिति लोकतंत्र के भविष्य के लिए ठीक नहीं कही जा सकती।

निरंकुश राजनेताओं ने मात्र अनर्गल प्रलाप के माध्यम से राजनीतिक परिस्थितियों को दूषित कर रखा है। इन परिस्थितियों के चलते आम नागरिक राजनीतिक दृष्टि से भ्रमजाल में उलझा हुआ दिखाई देता है। लोकतंत्र के भविष्य की दृष्टि से यह स्थिति चिंताजनक ही है। अपने-अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते इन विचारणीय पहलुओं पर गौर नहीं किया जाना, गहन चिंता का विषय है। दरअसल राजनीति में विरोधाभासी विचारधाराएं कालांतर में समाज में गुठली संघर्षों को भी जन्म दे सकती है। अलग-अलग जाति तथा अलग-अलग वर्ग अलग-अलग राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करते हुए नीति नियमों के विपरीत आचरण करते हुए अराजकता को जन्म दे रहा है।'

कुल मिलाकर विकसित भारत की परिकल्पना को साकार सिद्ध करने के लिए राजनीति के शुद्धिकरण की दिशा में ठोस कदम उठाना आवश्यक है। इस दिशा में सर्वप्रथम आवश्यकता इस बात की है कि अनर्गल आरोप-प्रत्यारोप पर विराम लगाया जाए। निश्चित रूप से जब तक आम नागरिक अपना विषय विशेष पर स्पष्ट अभिमत नहीं रखेंगे, तब तक लोकतंत्र की परिपक्वता में संदेह बना रहेगा। ऐसे में यह जरूरी है कि राजनीति में प्रामाणिक तथा नैतिक मूल्यों की स्थापना की दिशा में कारगर कदम उठाया जाएं। निश्चित रूप से जब तक राजनीति में निराधार को आधार नहीं बनाया जा सकेगा तब ही नागरिकों की राजनीतिक जागृति, सकारात्मक परिणाम दे सकेगी।

अन्यथा भ्रमजाल में निरंतर उलझते नागरिक अस्थिर मन से मतदान करेंगे तो वह भ्रमित अवस्था का ही परिणाम देगा। बेहतर हो यदि राजनीतिक तथा सामाजिक नेतृत्व उन विषयों को चिन्हित करें, जिस पर कि सर्वमान्य स्थिति होना राष्ट्र एवं समाज के लिए परम आवश्यक प्रतीत होता हो। अन्यथा गंभीर से गंभीर विषय पर मतभिन्नता की स्थिति राष्ट्र एवं समाज को भारी पड़ सकती है। यह निश्चित है कि मतभिन्नता की स्थिति में अलग-अलग वर्ग एवं समूह की शारीरिक एवं मानसिक श्रम शक्ति अनावश्यक रूप से जाया होती रहती है। अनावश्यक टकराव की स्थिति समाज में कानून और व्यवस्था के सम्मुख भी चुनौती बना करती है।

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

इलेक्ट्रॉनिक कचरे की देन-पारा प्रदूषण

नरेंद्र देवांगन

विद्युतचालित उपकरणों, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ने दुनिया का स्वरूप बदल दिया है। इनके कारण लोगों की जीवन शैली और कल-कारखानों की कार्यशैली बदलने के साथ ही बढ़ी है दुनिया की जगमगाहट पर इस जगमगाहट के पीछे एक अंधकार भी है जो अत्यंत खतरनाक है। एक अवधि तक उपयोग के पश्चात ये उपकरण खराब या अनुपयोगी हो जाते हैं। उसके बाद इन्हें कचरे के साथ फैंक दिया जाता है।

अनेक देशों में व्यवस्था के कारण या मजबूरी के कारण कुछ हद तक इन्हें अलग किया जाता है या रीसाइकिल करके उससे नए उत्पाद तैयार किए जाते हैं। बचा कचरा अन्य जैविक कूड़े के साथ पड़ा रहता है। इनमें मौजूद भारी धातुएं व जहरीले रसायन रिस-रिस कर बाहर आते हैं और भूमि व जल के साथ वायु को भी प्रदूषित करते हैं।

खतरनाक इलेक्ट्रॉनिक कचराः विभिन्न प्रकार के विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयुक्त होने वाला पारा यानी मरकरी सबसे खतरनाक तत्व है। मिसाल के तौर पर, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीफोन, डीवीडी प्लेयर, फैक्स मशीन, फोटो कॉपियर और एलसीडी युक्त उपकरणों में पारे का उपयोग किया जाता है। वैसे तो इनमें मात्र 2 से 10 मिलीग्राम तक ही पारे का उपयोग होता है पर यदि इसे जोड़ा जाए तो विश्व में पारे की कुल खपत का 30 प्रतिशत इन उपकरणों में प्रयुक्त होता है। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पारा व उसके यौगिक जहां विभिन्न रसायनिक उद्योगों में उत्प्रेरक व अन्य रूपों में प्रयुक्त होते हैं वहीं विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी प्रयोग किए जाते हैं।

फ्लोरोसेंट लैंपः पिछले कुछ समय से फ्लोरोसेंट लैंप का उपयोग बेहताशा बढ़ रहा है क्योंकि इनसे मिलने वाली रोशनी खूबसूरत लगती है, साथ ही बिजली और पैसे की बचत भी होती है पर इस रोशनी के पीछे छिपे अंधेरे को हम नहीं देख पाते हैं यानी किसी कारणवश फ्लोरोसेंट लैंप टूटता है या खराब होने के बाद इसे फैंक दिया जाता है तो उसके अंदर स्थित पारे की कुल मात्रा का 6 से 8 प्रतिशत तत्काल वायु में मिल जाता है।

पारे के यौगिक : पारा वायु के अन्य अवयवों के साथ मिलकर पारे के यौगिक बनाता है जो वातावरण के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। इस तरह भूमि पर फैलने वाला पारा वायु में भी मिल जाता है और भिन्न-भिन्न माध्यमों से होता हुआ जल स्रोतों में भी मिल जाता है। जल में रहने वाले जीव पारे को ग्रहण कर विषैले हो जाते हैं।

हानिकारक है पाराः पारा सामान्य तापमान और दाब पर तरल रूप में रहता है लेकिन 0.3 वायुमंडल दाब व 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही भाप में परिवर्तित हो जाता है। यह वाष्पशील होता है। यह गैस रूप में रंगहीन व गंधहीन होता है, जिससे इसका पता कठिनाई से चल पाता है। यदि पारे की भाप सांस के जरिए शरीर में प्रवेश करती है तो भाप का 80 प्रतिशत शरीर की ऊपरी परत को पार कर जाता है और यह रक्त में मिल जाता है। यह मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। पारे की भाप बच्चों के मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के लिए भी हानिकारक होता है।

बचने के उपाय

- पारे युक्त पदार्थों का उपयोग करते समय कर्मियों को बचाव जैसे मास्क, दस्तानों, गॉगल्स, सुरक्षात्मक कपड़े (एप्रन) आदि का प्रयोग करना चाहिए।
- वायु प्रवाह तंत्र को सुरक्षित तथा प्रभावी बनाना चाहिए। पारेयुक्त वायु को सीधे बाहर छोड़ने के स्थान पर फिल्टर के माध्यम से छोड़ा जाना चाहिए।
- अवैध रूप से चल रहे पारायुक्त उपकरणों की मरम्मत और रिसाइक्लिंग उद्योग को वैधानिक दायरे में लाना चाहिए तथा शिक्षा और नियमों के माध्यम से उन्हें इस बात के लिए बाध्य किया जाना चाहिए कि वे सुरक्षित तरीकों को ही अपनाएं।

खेल हस्तियां

टेस्ट क्रिकेट का पहला रन, पहला शतक

रिकॉर्ड बुक का 'बादशाह' 'ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज चार्ल्स बैनरमैन'

क्रिकेट मौजूदा समय में भारत का सबसे लोकप्रिय खेल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत कब और कैसे हुई? पहला क्रिकेट मैच किन टीमों के बीच खेला गया? उसे किसने और कैसे जीता? तो इसके जवाब दिलचस्प हैं। दरअसल, 15 मार्च 1877 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में पहला टेस्ट मैच शुरु हुआ था। यह टेस्ट वैसे तो ऑल इंग्लैंड विरुद्ध कम्बाइंड न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया इलेवन के खिलाफ खेला गया। बाद में इसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला माना गया। आज भी इसके कई रिकॉर्ड कायम हैं।

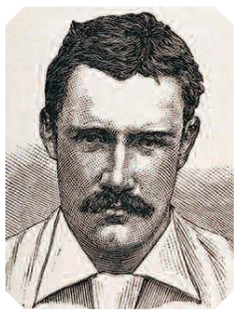

पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड की कप्तानी जेम्स लिलीवाइट ने और ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी डेव ग्रेगरी ने की थी। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और चार्ल्स बैनरमैन की 165 रन की पारी की बदौलत 245 रन बनाए। बैनरमैन टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने थे। बाकी कोई भी बल्लेबाज 20 से ज्यादा रन नहीं बना सका। जवाब में इंग्लैंड की टीम केवल 196 रन पर ही आउट हो गई। इंग्लैंड के लिए ओपनर हैरी जूप ने 63 रन, हैरी चार्लवुड ने 36 रन, एलन हिल ने 35 रन की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी खराब रही और टीम 104 रन पर ही सिमट गई। टॉम हैरोन ही सबसे ज्यादा 20 रन बना सके। इंग्लैंड को जीत के लिए 154 रन का लक्ष्य मिला, लेकिन इंग्लैंड की टीम इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी और 108 रन पर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने यह ऐतिहासिक टेस्ट मैच 45 रन से जीता। इस मैच का नतीजा चौथे दिन आया था। उस समय पांच दिन के टेस्ट में एक दिन रेस्ट होता था। इस तरह तीन दिन यानी रेस्ट डे (18 मार्च) के बाद 19 मार्च को मैच का नतीजा ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में आया था। इंग्लैंड के जेम्स साउदरटन टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रहे। उन्होंने 49 साल 119 दिन की उम्र में पहला टेस्ट मैच खेला था। यह रिकॉर्ड आज तक नहीं टूट सका है। वहीं बैनरमैन टेस्ट मैच की पहली गेंद खेलने वाले खिलाड़ी रहे और पहला टेस्ट शतक लगाने वाले भी।

पहला वनडे मैच 50 ओवर का नहीं बल्कि 40 ओवर का खेला गया था। पहला एक दिवसीय मैच मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) पर 5 जनवरी 1971 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। पहला वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। पहले वनडे मैच में 82 रन की पारी खेलने वाले इंग्लैंड के बैटर जॉन एड्रिच को प्लेयर ऑफ द् मैच के खिताब से नवाजा गए। वनडे इतिहास में एड्रिच मैन ऑफ द् मैच पुरस्कार पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने। वनडे में इंग्लैंड के बल्लेबाज डेनिस एमिस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला शतक जड़ा था उन्होंने साल 1972 में 103 रनों की पारी खेली थी। टॉम ब्रूक्स और लू रोवेन ने क्रिकेट इतिहास के पहले वनडे मैच में अंपायरिंग की भूमिका निभाई थी। वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड के जेफ्री बॉयकॉट ने पहली गेंद का सामना किया इसके साथ ही वह वनडे में आउट होने वाले पहले बल्लेबाज भी थे। ऑस्ट्रेलिया के एलन थॉमसन ने वनडे क्रिकेट के इतिहास में पहला ओवर करने वाले गेंदबाज थे। उस समय 12वां खिलाड़ी भी होता था। ऑस्ट्रेलिया की ओर से 12वें खिलाड़ी के तौर पर जॉन ग्लेसन खेले थे। तो वहीं इंग्लैंड ने 12वां खिलाड़ी नहीं रखा था।

ट्वेंटी-20 की बात करें तो पहला मैच न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 17 फरवरी 2005 में खेला गया, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया था। वहीं टी20 में पहला शतक वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल (117 रन) ने मारा था। उन्होंने 2007 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ये कारनामा किया था।

क्यों खेला गया वनडे मैच?

वनडे मैच खेले जाने की बड़ी ही रोचक कहानी है। साल 1970-71 में इंग्लैंड की टीम एशेज सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया गई। इस दौरान 2 टेस्ट मैच खेले गए, लेकिन तीसरे टेस्ट से पहले ऐसी मूसलाधार बारिश हुई जिससे मैच शुरू करना असंभव था। तीसरे टेस्ट के चार दिन बारिश में धुल गए। ऐसे में एक दिन बचा। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पर दबाव था कि वह मैच नहीं होने से नुकसान की भरपाई कैसे करे? क्योंकि मैच न होने की वजह से दर्शक नहीं आए थे जिससे काफी आर्थिक नुकसान हुआ। ऐसे में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक वनडे मैच आयोजित करने का मन बनाया। बोर्ड ने इंग्लैंड के सामने प्रस्ताव रखा कि इसके अलावा एक अधिक टेस्ट मैच खेला जाएगा जो दौरे का ओवर ऑल सातवां मुकाबला होगा।

पहले वनडे के क्या थे नियम?

पहले वनडे मैच में दोनों टीमों के लिए 40-40 ओवर निर्धारित किए गए। यह तय किया गया कि एक ओवर 8 गेंद का होगा। दोनों टीमें एक-एक पारी खेलेंगी। जो टीम सबसे ज्यादा रन बनाएगी उसे विजेता घोषित किया जाएगा। भले दूसरी टीम ऑल आउट हुई या नहीं। इस दौरान गेंदबाजों के लिए भी नियम बनाए गए और कहा गया कि कोई भी बॉलर मैच में 5 ओवर से ज्यादा नहीं फेंकेगा। कुल मिलाकर नियम ऐसे बनाए गए थे कि मैच का परिणाम हर हाल में निकले। इस पहले वनडे को देखने के लिए एमसीजी पर काफी भीड़ जुटी। आंकड़ों के मुताबिक, 46,006 लोगों ने मैच का लुत्फ उठाया। इस दौरान करीब 34 हजार डॉलर इकट्ठा हुए थे।

इंग्लैंड में जन्में पहले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरः

बैनरमैन का जन्म वूलविच, केंट, इंग्लैंड में हुआ था। लेकिन उनके जन्म के कुछ साल बाद उनके पिता विलियम बैनरमैन पत्नी मार्गरेट के साथ ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स (एनएसडब्ल्यू) में शिफ्ट हो गए। बैनरमैन सिडनी में वारविक क्रिकेट क्लब में शामिल हुए और उन्हें सरे के पूर्व क्रिकेटर - विलियम कैफिन द्वारा प्रशिक्षित किया गया। वहां से वह आगे बढ़ते रहे और पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा बने।

पहली गेंद का सामना किया और टेस्ट में पहला रन बनायाः

पहला टेस्ट मार्च 1877 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) में खेला गया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए बैनरमैन नट थॉमसन के साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए सलामी बल्लेबाज थे। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहला रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर थे जबकि थॉमसन एक रन के स्कोर पर आउट हो गए।

टेस्ट में पहला अर्धशतक, पहला शतक और पहला 150ः

पहले टेस्ट की पहली पारी में, बैनरमैन ने शानदार शतक बनाया और ऑस्ट्रेलियाई टीम की ओर से 20 के स्कोर को पार करने वाले एकमात्र खिलाड़ी थे। उन्होंने 285 गेंदों का सामना करते हुए 165 रन बनाए। उनका शतक जाहिर तौर पर क्रिकेट इतिहास में बेहद खास था क्योंकि यह पहला शतक था। उनके अर्धशतक, शतक और 150 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में पहली बार थे।

रिटायर हर्ट होने वाले पहले बल्लेबाजः बैनरमैन ने टेस्ट के पहले दिन अपना दबदबा बनाए रखा और लंच के तुरंत बाद तक जारी रखा क्योंकि वह बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे और उन्हें रिटायर हर्ट होना पड़ा। यह इंग्लैंड के गेंदबाज जॉर्ज यूलियट का थ्रो था जिससे उनके दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली टूट गई। उलिएट शायद बैनरमैन से निराश थे क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम की ओर से केवल वही आसानी से रन बना सके थे। बैनरमैन 165 के स्कोर पर नाबाद रहे और रिटायर हर्ट हो गए। वह संभवतः पहले क्रिकेटर थे जो किसी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में खेलते समय घायल हो गए थे।

एक रिकॉर्ड जो अभी भी बैनरमैन के नाम पर हैः उनकी 165 रनों की पारी ने ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड के खिलाफ 245 रन बनाने में मदद की। ऑस्ट्रेलियाई कुल रनों में बैनरमैन द्वारा योगदान किए गए रनों के प्रतिशत की गणना करने के बाद, यह ध्यान में आया कि टीम के कुल 245 में से 67.3% रन उनके द्वारा बनाए गए थे। टेस्ट क्रिकेट के लंबे इतिहास में कई वर्ष हो गए हैं लेकिन उच्चतम प्रतिशत रन बनाने का रिकॉर्ड है एक टेस्ट पारी में टीम के कुल योग से रन आउट होना अभी भी उनके नाम पर कायम है। उनके बाद माइकल स्लेटर हैं जिन्होंने 1999 में सिडनी में इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के 184 में से 123 (66.85%) रन बनाए थे।

एक पारी में 15 से अधिक चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाजः 165 रन की अपनी पारी में बैनरमैन ने 18 चौके लगाए। इस प्रकार, वह एक पारी में 15 या अधिक चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज थे। एक पारी में 18 चौकों की उनकी संख्या कई वर्षों तक कायम रही, जब ऑस्ट्रेलिया के बिली मर्डोक ने द् ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ एक पारी में 24 चौके लगाकर इसे तोड़ दिया।

अपने पहले टेस्ट में किसी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक रनः अपने पहले टेस्ट में नाबाद 165 रन का स्कोर आज भी किसी भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी द्वारा नहीं तोड़ा जा सका है। आर्ची जैक्सन 1929 में इस रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब पहुंच गए थे, लेकिन एक ऑस्ट्रेलियाई द्वारा पहली बार बनाए गए 165 रनों की बराबरी करने से दो रन से चूक गए।

एक भारतीय दिग्गज ने तोड़ा बाउंड्री रिकॉर्ड : टेस्ट की अपनी पहली पारी में 18 चौके लगाने के बैनरमैन के रिकॉर्ड को तोड़ने में लगभग 20 साल लग गए। इसे एक भारतीय बल्लेबाज ने तोड़ा था जो एक टेस्ट में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व कर रहा था और वह कोई और नहीं बल्कि रणजीत सिंह थे। उन्होंने 1896 में मैनचेस्टर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड के लिए अपने पहले टेस्ट में 23 चौके लगाए थे।

किसी ऑस्ट्रेलियाई द्वारा पहली टेस्ट पारी में सर्वाधिक चौके लगाने का दूसरा स्थानः किसी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज को पहली टेस्ट पारी में सर्वाधिक चौके लगाने के बैनरमैन के रिकॉर्ड को तोड़ने में लगभग 100 साल लग गए। वेन फिलिप्स ही थे जिन्होंने 1983 में पाकिस्तान के खिलाफ पर्थ में अपनी पहली टेस्ट पारी में 20 चौके लगाकर यह रिकॉर्ड तोड़ा था।

अपनी पहली टेस्ट पारी में किसी सलामी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया पांचवां उच्चतम स्कोरः बैनरमैन का नाबाद 165 रन का स्कोर किसी सलामी बल्लेबाज द्वारा टेस्ट में पहली पारी में बनाए गए सर्वाधिक रनों की सूची में पांचवां है। उनका रिकॉर्ड पाकिस्तानी सलामी बल्लेबाज खालिद इबादुल्ला ने 1964 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 166 रन बनाकर तोड़ा था। बैनरमैन और इबादुल्ला के बाद, तीन और बल्लेबाजों ने अपनी पहली टेस्ट पारी में 165 से ऊपर का स्कोर बनाया और वे 1987 में श्रीलंका के लिए ब्रेंडन कुरुप्पु, 2013 में न्यू के लिए हामिश रदरफोर्ड हैं। 2013 में भारत के लिए न्यूजीलैंड और शिखर धवन।

ऑस्ट्रेलिया के पहले इंग्लैंड दौरे का हिस्साः ऑस्ट्रेलिया ने 1878 में अपनी क्रिकेट टीम के साथ पहली बार इंग्लैंड का दौरा किया, जहां बैनरमैन औसत सूची में शीर्ष पर रहे लेकिन दुर्भाग्य से, किसी भी मैच को टेस्ट का दर्जा नहीं दिया गया।

पहले क्रिकेटर से अंपायर बनेः क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद बैनरमैन ने अंपायरिंग का काम संभाला और संभवतः वह अंपायर बनने वाले पहले क्रिकेटर थे। उन्होंने 1887 से 1902 के बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए 12 मैचों में अंपायरिंग की।

तीन जुलाई, 1851 को जन्मे चार्ल्स बैनरमैन एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर थे जिन्होंने टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया था। वह उन 22 खिलाड़ियों में से एक थे जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में पहले टेस्ट का हिस्सा थे।

सजग मीडिया पब्लिकेशन के लिए प्रकाशक व मुद्रक सम्पूर्ण सिंह द्वारा परोपकार प्रिंटिंग प्रेस 7- माइल स्टोन भादरा रोड़ सिरसा से मुद्रित एवं रविदास नगर श्रीगंगानगर से प्रकाशित, संपादकः बलजीत सिंह। समाचारों के चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत उत्तरदायी। R.N.I. TC No. RAJHIN27980

ACTION INDIA
करनाल, 02 अप्रैल 2024
दैनिक एक्शन इंडिया
www.actionindialive.com

संपादकीय

ऑटिज्म से नौनिहालों को बचाने की चुनौती

चिंतनीय है सालाना करीब 10 हजार बच्चे जन्मजात लाइलाज बीमारी ऑटिज्म के साथ पैदा हो रहे हैं। ये आंकड़ा विगत वर्षों में और बढ़ा है। इस बीमारी की न तो कोई दवा है और न ही प्रॉपर इलाज। सिर्फ जागरूकता और बचाव ही साधन है। बीमारी की गंभीरता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से 2 अप्रैल को विश्व आत्मकेंद्रित जागरूकता यानी विश्व ऑटिज्म दिवस को मनाना आरंभ किया। ताकि जनमानस इस खतरनाक बीमारी के प्रति जागरूक हो सके। आज इस खास दिवस के जरिए ही ऑटिज्म पीड़ित बच्चों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद की आवश्यकता पर प्रकाश डाला जाता है जिससे पीड़ित एक अभिन्न अंग के रूप में पूर्ण और सार्थक जीवन जी सकें। अप्रैल-1988 में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने पहली उद्घोषणा जारी कर 2 अप्रैल को राष्ट्रीय ऑटिज्म जागरूकता माह घोषित किया। ये महत्वपूर्ण प्रगति थी और जागरूकता का एक नया युग शुरू हुआ, जिसने ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के लिए पूर्ण और अधिक उत्पादक जीवन जीने के अवसर खोले। भारत में लगभग 18 मिलियन बच्चे ऑटिज्म से पीड़ित हैं। 2 से 9 वर्ष की आयु के लगभग 1 से 1.5 प्रतिशत बच्चों में ऑटिज्म यानी एएसडी है। सीडीसी रिपोर्ट की मानें तो अमेरिका में लगभग 36 में से एक बच्चा ऑटिज्म से ग्रस्त है। दुनिया की लगभग एक फीसदी आबादी इस समय ऑटिज्म स्पेक्ट्रम से पीड़ित हो चुकी है। सन 2022 में सीडीसी द्वारा किए गए शोध के मुताबिक, कुल संख्या 75,000,000 से अधिक पहुंच गई है। रिपोर्ट की मानें तो प्रत्येक 100 बच्चों में से 1 को ऑटिज्म है। विश्व में ऑटिज्म निदान की उच्चतम दर वाला देश कतर है और सबसे कम दर वाला देश फ्रांस है। लड़कियों की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक लड़कों में ऑटिज्म है। अमेरिका में ऑटिज्म की दर 2000 में 150 में 1 से बढ़ कर 2022 में 100 में 1 हो गई। दुनिया भर में ऑटिज्म पीड़ितों की दर बहुत हो गई है। इसकी समझ, जानकारी और जागरूकता का अभाव रोगी, लोग, परिवार, और समुदाय पर बहुत गहरा पड़ रहा है। यहां तक कि इससे होने वाले भेदभाव का असर भी इसके निदान और उपचार आदि पर पड़ने लगा है। ये बीमारी डरावनी भी होती जा रही है। साल-2008 में कन्वेन्शन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सर्नस विद डिसएबिलिटीज लागू किया गया जिसमें सभी के साथ अक्षम लोगों को मानव अधिकार और की रक्षा और प्रोत्साहन सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया। इसमें ऑटिज्म से पीड़ित सभी वयस्क और बच्चों की सही देखरेख सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया जिससे पीड़ित अपना पूरी तरह और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सके। दिवस को मनाने का मकसद ऑटिज्म पीड़ितों की मदद करके उनके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है जिससे वे समाज का पूरा हिस्सा बन कर जीवन व्यतीत कर सकें।

बहरहाल, ऑटिज्म सामान्य रोग नहीं हैं बल्कि कई बार तो लगता है कि यह रोग नहीं बल्कि ताउम्र रहने वाला विकार है। जीवन भर चलने वाली इस न्यूरोलॉजिकल स्थिति लोगों में यह बचपन में ही आ जाती है जिसका लिंग, नस्ल और सामाजिक आर्थिक दर्जे से कोई लेना-देना नहीं हैं। इससे ग्रस्त बच्चों की समाज में स्वीकार्यता बहुत मुश्किल से मिलती है। कई देशों में तो ऐसे रोगी पागलखाने में भर्ती कर दिए जाते हैं।

बेटियों को भी मिले उचित सम्मान

रमेश सर्राफ धमोरा

> "हम सभी जानते हैं कि एक लड़की समाज के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। वह एक मा, एक बेटी, एक पत्नी इस तरह कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। उसे घर की शांति बनाए रखने वाली स्तंभ माना जाता है और फिर भी उसका अपमान किया जाता है। स्त्रियां ही संतति की परम्परा में मुख्य भूमिका निभाती है फिर भी प्राचीन समाज से लेकर आधुनिक कहे जाने वाले समाज तक स्त्रियां उपेक्षित ही रही है। उन्हें कम से कम सुविधाओं, अधिकारों और उन्नति के अवसरों में रखा जाता रहा है, इसी कारण महिलाओं की परिस्थिति अत्यन्त निचले स्तर पर है"

आज हर क्षेत्र में बालिकाओं के आगे बढने के बावजूद भी वह अनेको कुरीतियों की शिकार हैं। ये कुरीतियों उनके आगे बढने में बाधाएं उत्पन्न करती है। पढ़े-लिखे लोग और जागरूक समाज भी इस समस्या से अछूता नहीं है। देश में आज भी प्रतिवर्ष लाखों लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही कोख में मार दिया जाता है। आज भी समाज के अनेक घरों में बेटा, बेटी में भेद किया जाता है। बेटियों को बेटों की तरह अच्छा खाना और अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती है। समाज में आज भी बेटियो को बोझ समझा जाता है। हमारे देश में यह एक बड़ी विडंबना है कि हम बालिका का पूजन तो करते हैं। लेकिन जब हमारे खुद के घर बालिका जन्म लेती है तो हम दुखी हो जाते हैं। देश में सभी जगह ऐसा देखा जा सकता है। देश के कई प्रदेशों में तो बालिकाओं के जन्म को अभिशाप तक माना जाता है। लेकिन बालिकाओं को अभिशाप मानने वाले लोग यह क्यों भूल जाते हैं कि वह उस देश के नागरिक हैं जहां रानी लक्ष्मीबाई जैसी विरांगनाओं ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। हमारे यहां आज भी बेटी पैदा होते ही उसकी परवरिश से ज्यादा उसकी शादी की चिन्ता होने लगती है। आज महंगी होती शादियों के कारण बेटी का बाप हर समय इस बात को लेकर चिंतित नजर आता है कि उसकी बेटी की शादी की व्यवस्था कैसे होगी। समाज में व्याप्त इसी सोच के चलते कन्या भ्रूण हत्या पर रोक नहीं लग पायी है। कोख में कन्याओ को मार देने के कारण समाज में आज लड़कियों की काफी कमी होने से लिंगानुपात गड़बड़ा गया है। पिछले कुछ वर्षों में देश में जन्म के समय लिंगानुपात में बढ़ोतरी होना शुभ संकेत हैं। संसद में एक सवाल का जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बताया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने बालिकाओं के अधिकारों को स्वीकार करने के लिए जनता की मानसिकता को बदलने की दिशा में सामूहिक चेतना जगाई है। इस योजना ने भारत में सीएसआर (बाल लिंग अनुपात) में गिरावट के मुद्दे पर चिंता जताई है। यह राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) में 15 अंकों के सुधार के रूप में परिलक्षित होता है। जो कि 2014 में 918 था। जबकि 2022-23 में 15 अंक बढ़कर 933 हो गया। अगर समाज में

बेटियों को उचित शिक्षा और सम्मान मिले तो बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नही रहेगी। इसलिए यदि यह कहा जाय की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना नही हम सबकी एक जिम्मेदारी है तो इसमें कुछ गलत नही है। यदि हम सभी एक अच्छे समाज का निर्माण करना चाहते है तो हम सबका यही फर्ज बनता है हम इन बेटियों को भी भयमुक्त वातावरण में पढ़ाये। उन्हें इतना सशक्त बनाये की खुद गर्व से कह सके की देखो वह हमारी बेटी है जो इतना बड़ा काम कर रही है। भारत में हर साल तीन से सात लाख कन्या भ्रूण नष्ट कर दिये जाते हैं। इसलिए यहां महिलाओं से पुरुषो की संख्या 5 करोड़ ज्यादा है। समाज में निरंतर परिवर्तन और कार्य बल में महिलाओं की बढ़ती भूमिका के बावजूद रूढिवादी विचारधारा के लोग मानते हैं कि बेटा बुढ़ापे का सहारा होगा और बेटी हुई तो वह अपने घर चली जायेगी। बेटा अगर मुखाग्नि नहीं देगा तो कर्मकांड पूरा नहीं होगा। आज लड़किया लड़को से किसी भी क्षेत्र में कमतर नहीं हैं। कठिन से कठिन कार्य लड़किया सफलतापूर्वक कर रही हैं। देश में हर क्षेत्र में महिला शक्ति को पूरी हिम्मत से काम करते देखा जा सकता है। लड़कियों ने अपने काम और समर्पण के दम पर कई क्षेत्रों और क्षेत्रों में खुद को साबित किया है। वे अधिक प्रतिभाशाली, आज्ञाकारी, मेहनती और परिवार और अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। लड़कियाँ अपने परिवार और माता-पिता के प्रति अधिक देखभाल करने वाली और प्यार करने वाली होती हैं और वे हर काम में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देती हैं। देश की अर्थव्यवस्था में भी महिलाओं का अहम योगदान है। वे श्रम शक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और व्यवसायों की वृद्धि और विकास में योगदान देती हैं। एक तरफ जहां बेटी को जन्मते ही मरने के लिये लावारिश छोड़ दिया जाता है। वहीं झुंझुनू जिले की मोहना सिंह जैसी बालिकायें भी है जो आज देश में फाईटर प्लेन उड़ा कर पूरे देश में जिले का मान बढ़ा रही हैं। समाज में सभी को मिलकर लडका-लडकी में भेद नहीं करने व समाज के लोगों को लिंग समानता के बारे में जागरूक करने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। बालिकाओं का कोख में तो कत्ल कर उन्हे धरती पर आने से पहले ही मारा जा रहा है। उससे भी घिनोना काम जिन्दा बालिकाओं के साथ किया जा रहा है। देश में बालिकाओं के साथ हर दिन बलात्कार, प्रताडना की घटनायें अखबारो की सुर्खिया बनती हैं। बालिकायें कही भी अपने को सुरक्षित नहीं समझती हैं। चाहे घर हो या स्कूल अथवा कार्य स्थल। हर जगह वहशी भेडिये उन पर नजरे गड़ायें रहते हैं। उन्हे जब भी मौका मिलता है नोंच डालते हैं। ऐसे माहौल में देश की बालिकायें कैसे आगे बढ़ पायेगीं। समाज के पढ़े लिखे लोगों को आगे आकर कन्या भ्रूण हत्या जैसे घिनोने कार्य को रोकने का माहौल बनाना होगा। ऐसा करने वाले लोगों को समझा कर उनकी सोच में बदलाव लाना होगा। लोगों को इस बात का संकल्प लेना होगा कि ना तो गर्भ में कन्या की हत्या करेगें ना ही किसी को करने देगें। तभी देश में कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लग पाना संभव हो पायेगा। सरकार व समाज को मिलकर ऐसे वातावरण का निर्माण करने का प्रयास करना चाहिये जिसमें बालिकायें खुद को महफूज समझ सकें। बालिकाओं पर अत्याचार करने वालों के मन में भय व्याप्त करने के लिये सरकार को कानून में और अधिक सुधार करना चाहिये। बालिकाओं को कई प्रकार के भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। समाज और राष्ट्र के विकास के लिए बालिकाओं के महत्व को स्वीकार करना और बढ़ावा देना आवश्यक है। शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है। एक शिक्षित लड़की ही अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान दे सकती है। कानूनी सुरक्षा बालिकाओं के अधिकारों की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जागरूकता कार्यक्रमों और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से लड़कियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने के लिए भी उतना ही आवश्यक है। हमारे समाज का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज अपनी बच्चियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और उन्हें कितना महत्व देते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कानूनी सुरक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से बालिकाओं को सशक्त बनाना न केवल एक नैतिक दायित्व है बल्कि सामाजिक विकास के लिए एक जरूरी आवश्यकता भी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लड़कियों को आगे बढ़ने, सीखने के समान अवसर मिले। तभी हम एक संतुलित, न्यायसंगत और समृद्ध समाज बना सकेगें।

हम सभी जानते हैं कि एक लड़की समाज के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। वह एक मा, एक बेटी, एक पत्नी इस तरह कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। उसे घर की शांति बनाए रखने वाली स्तंभ माना जाता है और फिर भी उसका अपमान किया जाता है। स्त्रियां ही संतति की परम्परा में मुख्य भूमिका निभाती है फिर भी प्राचीन समाज से लेकर आधुनिक कहे जाने वाले समाज तक स्त्रियां उपेक्षित ही रही है। उन्हें कम से कम सुविधाओं, अधिकारों और उन्नति के अवसरों में रखा जाता रहा है, इसी कारण महिलाओं की परिस्थिति अत्यन्त निचले स्तर पर है ।

(लेखक राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

कविता

लंबी उम्र की ना दुआ किया करो

मोहब्बत में दर्द छुपा लिया करो,
दर्द के छालों को छुपा लिया करो।

आशिकी छुपाना होती नहीं आसां,
जमाने को मेरा नाम बता दिया करो।

हर दर्द की दास्तां होती है जुदा जुदा,
अपने दर्द को दिल में दबा लिया करो।

रूबरू होने की खुशियां चंद लम्हों की,
जुदाई के अहसास को दबा लिया करो।

सन्नाटे का शोर क्यों है इतना रातों में,
शोर को खामोशी में छुपा लिया करो।

इश्क में तेरी दुनिया लुट गई मेरी,
लंबी उम्र की ना दुआ किया करो।

संजीव ठाकुर

मछली जल की रानी है

डॉ. सुरेश कुमार

एक तालाब है। उसमें भी कुछ जीव रहते हैं। जैसी अपनी दुनिया है ठीक उनकी दुनिया है। अपनी दुनिया में लोग एक-दूसरे को पानी पिलाने के चक्कर में रहते हैं। उनकी दुनिया में ऐसी मारा-मारी नहीं है। जो खुद पानी में डूबे हो उन्हें भला पानी पिलाने का क्या मतलब। उसी तालाब में एक बड़ी मछली है। लिग बदलने की सुविधा होती तो मछली की जगह मछला कहना बेहतर होता। बड़ी मछली दिन-ब-दिन और बड़ी होती जा रही है। छोटी मछलियाँ दिन-ब-दिन घटती जा रही हैं। बड़ी मछलियों के पेट में अजीब सी मराड़ मची है, लेकिन पचाने की शक्ति में उसका कोई सानी नहीं है। हिसाब से देखा जाए तो जो पचा सकता है, उसे खाने का पूरा हक है। बड़े छोटों को खा सकते हैं, क्योंकि वे बड़े हैं। छोटे बड़ों को नहीं खा सकते, क्योंकि वे छोटे हैं। वैसे भी कुत्ता दुम हिलाता है न कि दुम कुत्ते को। अगर दुम कुत्तों को हिलाने लगें तो भला कुत्ते अपनी दुम क्यों बक्शने लगे? हरगिज नहीं। भूख लगने सांप अपने संपोलों तक को नहीं छोड़ते फिर भी यह तो कुत्ते की दुम है। दुनिया भर के लोग जिसे महामारी कह रहे हैं, उसे ही ये बड़ी मछलियाँ महाअवसर की तरह भुनाती हैं। एक बार के लिए गिद्ध शवों को खाना छोड़ सकते हैं, किंतु ये बड़ी मछलियाँ कोरोना महामारी से मरने वालों के नाम पर धंधा करना नहीं छोड़ सकतीं। छोटी-छोटी मछलियाँ जैसे-तैसे अपनी जिंदगियाँ बचते-बचाते गुजर-बसर करते हैं और ये बड़ी मछलियाँ एक झटके में उन्हें डकार जाती हैं। ये छोटी-छोटी मछलियाँ बड़ी मेहनत करके अपने दाना-पानी का इंतजाम करती हैं। उसी मेहनत को ये बड़ी मछलियाँ टॉनिक की तरह पी जाती हैं। मेहनत, लगन, आत्मनिर्भरता आदि शब्द सुनने में इतने मधुर लगते हैं कि छोटी मछलियाँ इन्हें सुन-सुन कर ऐसे बड़ी हो जाती हैं जैसे कसाई के यहाँ मिमियाती नन्हीं बकरियाँ। कहते हैं एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। जबकि एक बड़ी मछली पूरे तालाब को खा जाती है। छोटी मछलियाँ जिंदगी भर जिंदगी बचाने के चक्कर में जिंदगी खो बैठती हैं, जबकि बड़ी मछलियाँ उन्हीं जिंदगियों को लीलकर अपनी और अपनी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगियाँ बनाती हैं। जिंदगी लीलने के खेल में छोटी मछलियों को हमेशा जात-पात, धर्म, भाषा तो कभी महंगाई, भ्रष्टाचार, अत्याचार और बेरोजगार में उलझा दिया जाता है। चाहकर वे बाहर नहीं निकल सकतीं। इसी में वे अपना दम तोड़ देती हैं। बड़ी मछलियों पर मारने का आरोप भी नहीं लगता। इन मछलियों को सेलफोन से बांधकर पुस्तकों की दुनिया से कहीं दूर छोड़ दिया जाता है। सोशल मीडिया का दाना जैसे-जैसे इनकी भूख को नचाता है वे वैसे-वैसे नाचती हैं। मछली कहलाने वाली अपने ही जात की मछली के हाथों छलती ही जाती हैं।ययह सब बातें मैं रिलायंस फ्रेश मार्केट के सामने बैठे बेरोजगार गरीब को सुना रहा था। वह मुझसे उल्टे पूछ बैठा भैया यह सब मुझे क्यों सुना रहे हो?

https://t.me/AllNewsPaperPaid

विचार

विस्तारवाद की चाहत के लिए खतरनाक वैश्विक युद्ध की आशंका

संजीव

अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी के अनुसार अमेरिकी अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरस ने सचेत किया है कि रूस और चीन का सीमा विहीन गठबंधन वैश्विक शांति एवं सभ्यता के लिए खतरनाक हो सकता है। यदि पुतिन और शी जिनपिंग के बीच का गठजोड़ रूस यूक्रेन युद्ध में कारगर साबित होता है तो विश्वयुद्ध की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और विश्व युद्ध वर्तमान की मानवीय सभ्यता के लिए एक गतिहीन अवरोध होगा। इस अरबपति अमेरिकी निवेशक जॉर्ज सोरस ने दावोस में अपने वार्षिक प्रतिवेदन में कहा है कि दुनिया को इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए और इसमें पूरे संसाधन झोंक देने चाहिए। वैश्विक सभ्यता को संरक्षित, पल्लवित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ और संभवत एकमात्र तरीका पुतिन को जल्द से जल्द हराना होगा। यह हमला तीसरे विश्वयुद्ध की शुरूआत कर सकता है और हमारी सभ्यता इसे झेल नहीं पाएगी और तहस-नहस हो जाएगी। दावा किया गया है कि पुतिन ने शी जिनपिंग को पहले से ही बता दिया था और दोनों नेताओं की बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मुलाकात भी हुई थी दोनों ने एक लंबा बयान जारी कर घोषणा की थी कि उन दोनों के बीच संबंधों की और सहयोग की कोई सीमा नहीं है। पुतिन ने सी जिनपिंग को यूक्रेन के विरुद्ध विशेष सैन्य अभियान की जानकारी भी दे दी थी। तब शी जिनपिंग ने पुतिन से ओलंपिक खेलों के होते तक सैन्य अभियान रोकने की बात कही थी। इसी बीच रूस के एक राजदूत ने इस्तीफा देकर पुतिन की इस कार्रवाई का खुलकर विरोध किया था और युद्ध में मारे गए सैनिकों के परिवार ने भी रूस में अपना विरोध दर्ज किया है। पुतिन को अपनी गलतियों का अब धीरे-धीरे एहसास हो रहा है जब यूक्रेन में रहने वाले रूसी भाषा के नागरिकों ने यूक्रेन पर हमले की घोर निंदा की है जबकि पुतिन को उनके समर्थन आशा थी जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। पुतिन को अब यह एहसास हो गया है कि उन्होंने यूक्रेन पर आक्रमण करके एक बड़ी गलती की है। अब वह संघर्ष विराम के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने में लगे हैं जो वर्तमान संदर्भों में संभव नहीं है। क्योंकि विश्व समुदाय का रूस पर भरोसा खत्म हो चुका है। अब या तो पुतिन अपनी हार छुपाने के लिए चाइना की मदद विश्व युद्ध लेंगे या फिर अपनी हार स्वीकार कर अपने पद से इस्तीफा देकर पलायन कर जाएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध में आज तक कुल मिलाकर 30 लाख करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं और युद्ध खत्म होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। अमेरिका सहित नैटो देश के सदस्य और अन्य यूरोपीय सदस्य लगातार यूक्रेन की आर्थिक तथा सामरिक मदद करते आ रहे हैं और इस स्थिति में रूस ही कमजोर नजर आ रहा है क्योंकि रूस के तमाम कमांडर और सैनिकों का मनोबल अब लगातार गिरते जा रहा है, इसके पश्चात रूस के नागरिक भी इस युद्ध के अंदरूनी खिलाफ है जबकि यूक्रेन के नागरिक उसी हौसले और उत्साह के साथ अपने नेता जेलेंस्की के साथ खड़े हुए हैं। अब स्थिति यह है कि यूक्रेन के पास ना तो पैसे की कमी है ना ही हथियारों की,वह लगातार रूसी सैनिकों तथा कमांडरों का जमकर विरोध कर रहा है। ये अलग बात है कि मारियोपोल मैं इमारतों के मलबे के निकालने के पश्चात अलग-अलग जगह से चार पांच सौ दबे हुए शव को निकाला गया है। जिससे वहां जनता के बीच हाहाकार मच गया है। इस युद्ध की विभीषिका से यूक्रेन के लगभग एक करोड़ नागरिक यूक्रेन छोड़कर पोलैंड एवं अन्य देशों में शरण लेकर शरणार्थियों की तरह जीवन यापन कर रहे हैं। यूरोपीय देश इन शरणार्थियों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए कृत संकल्प हैं और उन्हें किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

वैश्विक राजनीति में चीन और रूस सर्वथा अलग-थलग पड़ गए हैं। ताजा स्थिति के अनुसार अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान और भारत में टोक्यो सम्मेलन में चीन के बढ़ते औपनिवेशिक वाद के खतरे को भांपते हुए प्रशांत महासागर एवं तीन पेसिफिक क्षेत्र में सैन्य अभ्यास के लिए गठजोड़ कर लिया है। इसी तरह चीन के व्यापारिक फायदों को नुकसान पहुंचाने हेतु अमेरिका ने 13 देशों का एक आर्थिक समूह तैयार कर चीन को वैश्विक राजनीति और आर्थिक योजनाओं से अलग अलग कर दिया है।

एक्शन इंडिया दैनिक

भगवान शंकर जी के ग्यारहवें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार-पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

आरएनआई: HARHIN / 2016 / 68417

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक रवि भारद्वाज, 261 ग्लबोल स्पेसिज, पार्ट-2, सेक्टर-33, करनाल, हरियाणा ने मारुतिनंदन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, ए-15, बड़ा बाग, जीटी करनाल रोड इन्डस्ट्रीयल एरिया, नई दिल्ली-33 से छपवाकर प्रकाशित किया। "एक्शन इंडिया" में प्रकाशित लेखों में व्यक्त किये गये विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। संपादक या प्रकाशक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

स्थानीय संपादक: राजकुमार शर्मा (प्रिन्स)
समूह संपादक : रवि भारद्वाज
9999889104, 9250706656
ई-मेल : actionindiaharyana@gmail.com

वैधानिक सूचना

पाठकों को सलाह है कि एक्शन इंडिया, समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन के आधार पर कोई निर्णय लेने से पहले विज्ञापन में प्रकाशित उक्त उत्पाद या सेवा के बारे में आवश्यक जांच-पड़ताल कर लें। समाचार पत्र प्रबंधक किसी भी विज्ञापन में गुणवत्ता, सेवा आदि के विवरण के बारे में विज्ञापनदाता द्वारा किए गए दावे या उल्लेख की पुष्टि या समर्थन नहीं करता है। अतः समाचार पत्र उक्त विज्ञापनों के बारे में किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

चिंतन

सियासी गंगा में डुबकी लगाइए

प्रभुनाथ शुक्ल

देखिए ! आप कितना भी पाप करिए, लेकिन एक बार गंगा स्नान कर लीजिए सारे पाप धूल जाएंगे। हमारे यहाँ तो यहाँ तक कहा गया है कि गंगा दर्शन मात्र से हमारी मुक्ति हो जाती और सारे पाप धुल जाते हैं। इसीलिए अब लोग पुण्य की चिंता छोड़ दिए हैं और पाप पर पाप किए जा रहें हैं। एक-दो पाप नहीं पूरा घड़ा ही पाप से भर रहें हैं। दरअसल उनके पुण्य में ही पाप की आत्मा बसी है। हमारे वेद और शास्त्रों में गंगा स्नान बेहद पवित्र माना गया है। इसीलिए लोग गलत कार्य करने में कभी नहीं डरते हैं। क्योंकि उनके पास पाप धोने के लिए गंगा है। अब गंगा भी पापियों का पाप धोते-धोते मैली हो चली हैं। आजकल लोग अब गंगा से अधिक पवित्र पाप धोने के लिए सियासी गंगा को मानने लगे हैं।

सच मानिए ! पाप धोने का आजकल सबसे मॉडर्न तरीका भी आ गया है। वह है सियासी गंगा में स्नान। इस गंगा में स्नान करना बेहद पुण्य फलदायी होता है। कहते हैं की सियासी गंगा का स्नान गंगा से भी पवित्र होता है। इस गंगा में स्नान करने से सारे कलुष धुल जाते हैं। इस गंगा में स्नान से कई पीढ़ियां तर जाती हैं। लेकिन इस गंगा में स्नान की शर्त भी है। सियासी गंगा में स्नान का फल तभी मिलता है जब चुनावों का मौसम हो। आप भ्ष्टाचार को शिष्टाचार बना लिए हों। आप के खिलाफ जितनी जांच एजेंसिया हों सब लगी हों। आप विपक्ष में रह कर कितना भी भ्ष्टाचार, बलात्कार, लूट, हत्या जैसा अपराध और पाप किए हो सब धूल जाता है। बस एक बार आप सत्ता की गंगा में डुबकी लगा लिए तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। फिर आपके पास जाँच की आंच कभी नहीं आएगी। सत्ता में आने के बाद फिर आप पाप का घड़ा भरना शुरू कर दीजिए। आजकल चुनावी मौसम में सियासी गंगा में नहाने का दौर चल पड़ा है। ऐसे घाटों पर बड़ी भीड़ दिख रही है। इस भीड़ में वामपंथ, दक्षिण पंथ और सेकुलर का तटबंध टूट गया है। जिस गंगा में लोग अपने पाप की सियासी गठरी लेकर कूद रहें हैं वह भी अपवित्र और मैली हो चला है। लेकिन सियासी घाट पर बैठे पंडे सबसे पवित्र होने का दावा कर रहें हैं और डुबकी लगाने वाले का चंदन लगा और दुपट्टा ओढा स्वागत कर रहे हैं।

दरवाजा

डॉ. सुरेश कुमार

उसके घर बैंक वाले आए थे। लोन देने के लिए नहीं वसूलने के लिए। बहुत देर की जिरह के बाद उन्होंने उसके घर का दरवाजा उखाड़ दिया। उसे अपने साथ ले जाने लगे। मुझे लगा हो न हो इस दरवाजे में कुछ खास है। इतने दिन उसके घर आया गया हूँ उधारी में बहुत सारी चीजें ली भी हैं, लेकिन कभी दरवाजे पर ध्यान नहीं दिया। लंबवत आयताकार वाला दरवाजा सागवान की लकड़ी का बना हुआ था। एक अरसा हुआ उसे रंगे हुए लेकिन अभी भी मजबूत था। बैंक वाले दरवाजा क्या ले गए मानो उसकी जान ले गए। घर वाले छाती पीट-पीटकर रोने-बिलखने लगे। ये पुरानी चीजें भी कब कूड़ा-कचरे की कैटगरी से उठकर मीठी यादें बन जाती हैं, पता ही नहीं चलता। पुरानी चीजों का तिरस्कार बड़ा दुखदायी होता है, क्योंकि हर एक नई चीज कभी न कभी पुरानी पड़ती ही है। नए के चक्कर में पुराने से मुँह मोड़ना संवेदना की कमी का प्रतीक है।मैंने उससे पूछा कि बैंक वाले दरवाजा क्यों ले जा रहे हैं? तो उसने रोते हुए कहा झ्र क्या बताऊँ तुम्हें कि मुझ पर क्या बीत रही है? मैंने बैंक वालों से एक लाख रुपए का कर्जा लिया था। कर्जा देते समय उन्होंने मुझे मुस्कुराते हुए लाख हिदायतें दी थीं कि समय पर कर्जा चुका देना। वरना ब्याज बढ़ने का चक्कर हमेशा बना रहता है। ब्याज और लड़की देखते-देखते बढ़ जाते हैं। मैं फसल के भरोसे था। असमय बरसात के चलते सारी फसल बर्बाद हो गई। सरकार ने इस नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा दिया। उसमें मैं नहीं था। वह क्या था कि उनकी नजर में गरीबों की फसल कभी बर्बाद नहीं होती, होती है तो केवल अमीरों की। मुआवजा अमीरों को मिला और मुझे लानत। कमाल की बात तो यह थी कि मुआवजा उन अमीरों को भी मिला जिनकी ढेर सारी बंजर जमीनें थीं। सच है मुआवजा फसल की बबार्दी देखकर नहीं लोगों की हैसियत देखकर दिया जाता है। वह आगे कहने लगा मैं बैंक वालों का कर्जा चुकाने में असमर्थ था। बाजार से जो कर्जा लिया था उसे चुकाने के लिए गाय-गोरू सब बेच दिए। अब मेरे पास कुछ नहीं था। बैंक वाले कई दिनों से धमका रहे थे। सोचा बैंक वाले हैं आज नहीं तो कल माफ कर ही देंगे।

संपादकीय

मानव विकास सूचकांक में बेहतरी के प्रयास जरूरी

19 मार्च को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि हो रही है, वहीं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मुताबिक भारत में आम आदमी की आमदनी बढ़ने और उनके द्वारा भोजन पर कम और कपड़े, मनोरंजन व अन्य मदों पर अधिक खर्च किए जाने से उनके जीवन स्तर में धीरे-धीरे बेहतरी आ रही है। एचडीआई रिपोर्ट 2022 में भारत अब 193 में से 134वें स्थान पर है। भारत की रैंकिंग में पिछले वर्ष की एचडीआई-2021 के मुकाबले एक पायदान का सुधार हुआ है। 19 मार्च को आरबीआई की रिपोर्ट में कहा, भारत में प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि हो रही है। जयंतीलाल भंडारीः हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) रिपोर्ट 2022 में भारत अब 193 में से 134वें स्थान पर है। भारत की रैंकिंग में पिछले वर्ष की एचडीआई-2021 रिपोर्ट के मुकाबले एक पायदान का सुधार हुआ है। नई रिपोर्ट जारी करने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय लोगों के मानव विकास सूचकांक में भारत की औसत बढ़त को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कहा है और भारत की सराहना की है। जहां 19 मार्च को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि हो रही है, वहीं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मुताबिक भारत में आम आदमी की आमदनी बढ़ने और उनके द्वारा भोजन पर कम और कपड़े, मनोरंजन व अन्य मदों पर अधिक खर्च किए जाने से उनके जीवन स्तर में धीरे-धीरे बेहतरी आ रही है। फिर भी अभी दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत को मानव विकास सूचकांक में आगे बढ़ने के लिए ठोस व कारगर प्रयासों की जरूरत स्पष्ट दिखाई दे रही है। अभी भी दुनिया के अनेक देशों की तुलना में मानव विकास सूचकांक में देश बहुत पीछे है। ऐसे में हमें यह ध्यान रखना होगा कि जहां अर्थव्यवस्था समाज का अहम हिस्सा है वहीं मानव विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सरकार के द्वारा सामाजिक अधोसंरचना पर उसी तरह निवेश किया जाना होगा, जिस तरह भौतिक अधोसंरचना पर खर्च किया जा रहा है। अभी देश में करोड़ों लोगों की गरीबी और स्वास्थ्य की चुनौतियां बड़े पैमाने पर स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। देश में अभी भी 15 करोड़ से अधिक लोग गरीबी की चिंताओं का सामना कर रहे हैं। ज्ञातव्य है कि 2017 में नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में 2025 तक स्वास्थ्य पर खर्च को सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत किया जाना निर्धारित किया गया था। फिर पंद्रहवें वित्त आयोग ने पहली बार स्वास्थ्य के लिए उच्च-स्तरीय कमेटी गठित की थी। इस कमेटी ने भी स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च को 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाने की बात कही है। इस मामले में देश अभी भी पीछे है। हम उम्मीद करें कि सरकार द्वारा यूएनपीडी की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 के मद्देनजर देश में मानव विकास की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, न्यायसंगत और उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, सार्वजनिक सेवाओं में स्वच्छता, बहुआयामी गरीबी, भूख और कुपोषण खत्म करने के लिए नई जनकल्याण योजनाओं, सामुदायिक रसोई व्यवस्था तथा पोषण अभियान-2 को पूरी तरह कारगर व सफल बनाया जाएगा। निश्चित रूप से ऐसा होने पर आगामी वर्ष प्रकाशित होने वाले मानव विकास सूचकांक में भारत की मानव विकास रैंकिंग में सुधार आएगा।

अब बांग्लादेश में 'इंडिया आउट'...?

चीन की खतरनाक कूटनीति हालांकि सफल नहीं हो रही है लेकिन भारत का पलटवार जरूरी, सीमा पर कुछ न कर पाने की बेचैनी में चीन अब भितरघात के रास्ते अपना रहा है। चीन के लिए बांग्लादेश की विपक्षी पार्टियां और ये आतंकी संगठन मददगार साबित हुए हैं। भारतीय उत्पादों के बायकॉट की बात कही जा रही है लेकिन शेख हसीना की सरकार का स्पष्ट तौर पर कहना है कि इस तरह की अपील का असली मकसद बांग्लादेश के बाजार को अस्थिर करना है। बांग्लादेश का बाजार यदि अस्थिर होता है तो निश्चय ही इसका फायदा चीन उठाएगा।

डॉ. विजय दर्डा
चेयरमैन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह

तेजी से तरक्की कर रहे बांग्लादेश में पिछले महीने जब अचानक इंडिया आउट के नारे सुनाई दिए तो सभी का चौंकना स्वाभाविक था। अभी-अभी यही राग तो मालदीव के राष्ट्रपति मो. मुइज्जू अलाप रहे थे। फिर यह राग बांग्लादेश में कैसे और क्यों शुरू हो गया? क्या यह केवल बांग्लादेश के विरोधी दलों का आंदोलन है या फिर इसके पीछे चीन की चाल है? चीन पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि इस पूरे प्रसंग में चीन का हाथ है। सुकून की बात है कि चीन की कूटनीति सफल नहीं हो रही है क्योंकि भारत की संस्कृति रिश्तों को संभालने की रही है। चीन की लुभावनी चाल में फंसने वाले हमारे पड़ोसी भी जानते हैं कि भरोसेमंद साथी तो भारत ही है।

बांग्लादेश के प्रमुख विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) को यह लगता रहा है कि भारत अवामी लीग का समर्थन करता है। वैसे इसमें कोई दो राय है भी नहीं कि अवामी लीग की सर्वोच्च नेता और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ भारत के रिश्ते बहुत मजबूत हैं। उन्होंने बांग्लादेश को तरक्की की राह पर तो तेजी से बढ़ाया ही है, वहां कट्टरपंथ के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति भी अपना रखी है। यहां तक कि इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा के सहयोगी संगठन हिज्ब-उत-तहरीर (एचयूटी), जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश और अंसारुल्ला बांग्ला टीम जैसे समूहों के आतंकवादियों को फांसी के फंदे पर भी लटकाया है।

चीन के लिए बांग्लादेश की विपक्षी पार्टियां और ये आतंकी संगठन मददगार साबित हुए हैं। इन्हीं के माध्यम से बांग्लादेश में 'इंडिया आउट' का अभियान शुरू हुआ है, जिसकी गूंज सोशल मीडिया पर ज्यादा सुनाई दे रही है। भारतीय उत्पादों के बायकॉट की बात कही जा रही है लेकिन शेख हसीना की सरकार का स्पष्ट तौर पर कहना है कि इस तरह की अपील का असली मकसद बांग्लादेश के बाजार को अस्थिर करना है। बांग्लादेश का बाजार यदि अस्थिर होता है तो निश्चय ही इसका फायदा चीन उठाएगा। इसके साथ ही वह बांग्लादेश को उसी तरह अपने चंगुल में फंसा लेगा जिस तरह से उसने पाकिस्तान, श्रीलंका और अब मालदीव को फंसाया है। नेपाल और भारत के संबंधों की मिठास को वह पहले ही कड़वा बना चुका है। म्यांमार और भूटान को भी उसने भारत से दूर करने की कोशिश की है लेकिन भारत के प्रति पड़ोसियों का भरोसा होने के कारण चीन ज्यादा सफल नहीं हो पाया है। अब बांग्लादेश को हमसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। यदि आप भौगोलिक मानचित्र देखें तो चीनी कब्जे वाले तिब्बत और बांग्लादेश के बीच हमारे पूर्वोत्तर के राज्य स्थित हैं। हमारे इन राज्यों में आतंकी समूहों को वह हथियार और ड्रग्स देकर हमें परेशान करने की हरसंभव कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि किसी भी तरह बांग्लादेश से भारत के रिश्ते कड़वे हो जाएं और बांग्लादेश उसकी गोद में जा बैठे। अच्छी बात यह है कि शेख हसीना इस बात को अच्छी तरह समझती हैं। वे चीन की हर चाल के आगे अडिग खड़ी दिख रही हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि जब विपक्षी नेता अपनी पत्नियों के पास मौजूद भारतीय साड़ियों को जलाएंगे, तब ही ये साबित होगा कि विपक्ष वाकई भारतीय उत्पादों के बहिष्कार के लिए प्रतिबद्ध है।

वैसे भी दुनिया यह जानती है कि बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी बीएनपी हमेशा ही भारत विरोधी रही है। बांग्लादेश की आजादी की स्वर्ण जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ढाका दौरे के खिलाफ बांग्लादेश में होने वाले हिंसक विरोध में बीएनपी शामिल थी। बीएनपी की नेता खालिदा जिया दोहरी चाल भी चलती नजर आती हैं। बीएनपी एक ओर भारत की मुखालफत करता है तो दूसरी ओर बीएनपी का एक गुट भारत से अच्छे संबंधों की वकालत भी करता है। मगर हावी कट्टरपंथी ही होते हैं। माना जाता है कि इस चाल के पीछे खालिदा जिया का ही दिमाग है। सवाल यह है कि क्या खालिदा जिया और चीन के बीच कोई समझौता हो चुका है? यह शंका तो पैदा होती है। हालांकि पिछले चुनाव में चीन ने उनका साथ नहीं दिया था क्योंकि जिया के समर्थन में अमेरिका खड़ा था। शायद चीन को यह उम्मीद रही हो कि वह शेख हसीना को अपने पाले में कर लेगा!

यहां इस बात पर भी गौर करना जरूरी है कि चीन को यह बात समझ में आ गई है कि वह भारत को सैन्य शक्ति से नहीं दबा सकता। गलवान में भारत के मुंहतोड़ जवाब से उसे भारत के रवैये का पूरा अंदाजा हो चुका है। वह भारत को हर हाल में कमजोर करना चाहता है क्योंकि उसे इस बात का डर है कि आने वाले वर्षों में भारत उससे बड़ी आर्थिक ताकत न बन जाए। 1978 में अर्थव्यवस्था के दरवाजे बाहरी दुनिया के लिए खोलने के बाद से उसकी अर्थव्यवस्था औसतन 9 प्रतिशत की तेज गति से बढ़ी मगर कोविड ने उसे 2.2 पर ला दिया। वापस वह 8 प्रतिशत पर आया लेकिन 2023 में चीन केवल 5.2 प्रतिशत की रफ्तार ही हासिल कर पाया जबकि इस अवधि में भारत की अर्थव्यवस्था 7.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी। भारत की इस रफ्तार ने चीन को चिंतित कर रखा है। एक पुरानी कहावत है कि यदि खुद की बड़ी लकीर नहीं खींच सकते तो दूसरे की लकीर को मिटाओ। चीन यही कर रहा है। वह भारत को इतना उलझा देना चाहता है कि हमारे विकास की रफ्तार थम जाए। लेकिन उसे यह समझ लेना चाहिए कि भारत उसकी चाल को अच्छी तरह समझता है। भारत की रफ्तार अब कोई नहीं रोक सकता। भारत पलटवार करना जानता है।

छोटे दल निभाएंगे बड़ी चुनावी भूमिका

चुनाव से पहले जिस तरह सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने छोटे-छोटे दलों को इकट्ठा कर व्यापक गठबंधन बनाए, वह तो इन दलों के महत्व का प्रमाण है ही, चुनावी मुकाबले में भी ये दल बड़ी भूमिका निभाते दिख रहे हैं। खासकर सत्तारूढ़ दल भाजपा और उसके नेतृत्व वाले एनडीए की बात करें तो कड़ी चुनौती ये दल ही पेश करेंगे।

राजकुमार सिंह
वरिष्ठ पत्रकार

चुनाव से पहले जिस तरह सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने छोटे-छोटे दलों को इकट्ठा कर व्यापक गठबंधन बनाए, वह तो इन दलों के महत्व का प्रमाण है ही, चुनावी मुकाबले में भी ये दल बड़ी भूमिका निभाते दिख रहे हैं।

देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल भी है, लेकिन जमीनी राजनीतिक हकीकत अलग है। कांग्रेस 2014 के चुनाव में मात्र 44 और फिर 2019 के चुनाव में महज 52 सीटों पर सिमट गई थी। मौजूदा समय में कांग्रेस बमुश्किल दर्जन भर राज्यों में ही अपने दम पर चुनाव लड़ने की हालत में है। केंद्रीय सत्ता के लिए हो रहे लोकसभा चुनाव में छोटे और क्षेत्रीय दल ज्यादा बड़ी भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। चुनाव से पहले जिस तरह सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने छोटे-छोटे दलों को इकट्ठा कर व्यापक गठबंधन बनाए, वह तो इन दलों के महत्व का प्रमाण है ही, चुनावी मुकाबले में भी ये दल बड़ी भूमिका निभाते दिख रहे हैं। खासकर सत्तारूढ़ दल भाजपा और उसके नेतृत्व वाले एनडीए की बात करें तो कड़ी चुनौती ये दल ही पेश करेंगे।

देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल भी है, लेकिन जमीनी राजनीतिक हकीकत अलग है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मात्र 44 और फिर 2019 के चुनाव में 52 सीटों पर सिमट गई कांग्रेस बमुश्किल दर्जन भर राज्यों में ही अपने दम पर चुनाव लड़ने की हालत में है। जीत की संभावना उनमें से भी आधे से कम राज्यों में है। फिलहाल कांग्रेस की सिर्फ तीन राज्योंः हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में सरकार है।

इसके अलावा वह तमिलनाडु और झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में अपने लिए 370 और एनडीए के लिए 400 लोकसभा सीटों का नारा दे रही भाजपा को चुनौती दे पाना कांग्रेस के वश की बात नहीं लगती। कर्नाटक और तेलंगाना में अब कांग्रेस की सरकार होने के चलते समीकरण बदल सकते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत की 'हैट्रिक' रोकने की जिम्मेदारी मुख्यतः छोटे और क्षेत्रीय दलों पर होगी।

दिल्ली की सात लोकसभा सीटों पर आप और कांग्रेस मिल कर भाजपा की जीत की 'हैट्रिक' रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसी मकसद के साथ पंजाब में दोनों अलग-अलग लड़ेंगे. जाहिर है, दिल्ली के अलावा गुजरात और गोवा में भी भाजपा का ग्राफ नीचे लाने की कवायद में आप की भूमिका महत्वपूर्ण होनेवाली है। राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाने के बावजूद आप है तो छोटा दल ही, जिसके एकमात्र लोकसभा सांसद ने भी कमल थाम लिया।

आप से आगे चलें तो लोकसभा चुनाव में भाजपा का मुकाबला क्षेत्रीय दलों पर ही निर्भर करेगा। 80 लोकसभा सीटोंवाला उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। भाजपा पिछली बार वहां से अकेले 62 और सहयोगियों के साथ 64 सीटें जीतने में सफल रही थी। तब सपा-बसपा-आरएलडी गठबंधन था और उसने 15 सीटें जीती थीं। इस बार सपा-कांग्रेस गठबंधन है।

सपा 63 और कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ रही है। बड़ा सवाल यही है कि क्या यह गठबंधन भाजपा को पिछली जितनी सीटों पर भी रोक पाएगा? इसका जवाब भी मुख्य रूप से सपा पर निर्भर करेगा। अतीत का अनुभव बताता है कि कांग्रेस के मुकाबले क्षेत्रीय और छोटे दल भाजपा को ज्यादा जोरदार टक्कर देते रहे हैं। छोटे दलों की बड़ी चुनौती से भाजपा कैसे पार पाएगी- 'हैट्रिक' उस पर ज्यादा निर्भर करेगी।

इंडिया की लोकतंत्र बचाओ महारैली के बेसुरे स्वर

निश्चित ही एकजुटता के ये स्वर बेसूरे, असहज एवं बनावटी है, इंडिया गठबंधन के राजनैतिक क्षितिज पर जो वरिष्ठ राजनेता हैं उनकी आवाज व किरदार भारतीय जीवन को प्रभावित नहीं कर रहा है। इंडिया गठबंधन से जुडे़ दलों की केन्द्र एवं प्रांतों की सरकारों के शासन-काल में तो अपराध, भ्रष्टाचार और साम्प्रदायिकता के जबड़े फैलाए, आतंकवाद, प्रांतवाद, जातिवाद की जीभ निकाले, मगरमच्छ सब कुछ निगलता रहा है। सब अपनी जातियों और ग्रुपों को मजबूत करते रहे हैं-देश को नहीं। प्रथम पंक्ति का नेता ही नहीं है जिसे मोदी के मुकाबले में खड़ा किया जा सके। भारत के लोग केवल बुराइयों से लड़ते नहीं रह सकते, वे व्यक्तिगत एवं सामूहिक, निश्चित सकारात्मक लक्ष्य के साथ जीना चाहते हैं। अन्यथा जीवन की सार्थकता नष्ट हो जाएगी। दो तरह के नेता होते हैं- एक वे जो कुछ करना चाहते हैं, दूसरे वे जो कुछ होना चाहते हैं। असली नेता को सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी होकर, प्रासंगिक और अप्रासंगिक के बीच भेदरेखा बनानी होती है।

ललित गर्ग
वरिष्ठ पत्रकार

दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन इंडिया की लोकतंत्र बचाओं महारैली में जुटे 28 दलों के नेता आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कोई प्रभावी संदेश देने में नाकाम रहे हैं। भले ही चुनाव के ठीक पहले विपक्षी दलों ने इसके जरिए अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने में कामयाबी हासिल की हो। लेकिन यह एकजुटता भ्रष्ट नेताओं को बचाने की एक मुहिम ही बनकर सामने आयी है। इसमें स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार की भ्रष्टाचार पर गई कार्रवाई की बौखलाहट झलक रही थी। इस रैली में सभी दलों के नेताओं ने देश विकास के मुद्दों, सिद्धान्तों एवं नैतिक तकाजे की बजाय मोटे तौर पर सत्ता पक्ष की भ्रष्टाचार के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए इसी के इर्दगिर्द ही अपनी बातें रखीं। लोकतंत्र बचाओ रैली से उपजे विचारों ने किन्हीं पवित्र उद्देश्यों के बजाय सत्ता हासिल करने की लालसा को ही उजागर किया, यह निराश करने वाली रैली किसी बड़े बदलाव की वाहक बनती हुई नजर नहीं आयी।

इस रैली में भारतीय जनता पार्टी एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शानदार जीत की संभावना से बौखलाए नेताओं की खींच ही ज्यादा सामने आयी है। यही कारण है कि रैली में जो मुद्दा जोरशोर से उठा, वह यह रहा कि यदि भाजपा फिर से सत्ता में आ गई तो लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा और संविधान भी। यह समझना कठिन है कि कोई दल लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करता है तो उससे लोकतंत्र और संविधान कैसे खत्म हो जाएगा। आम जनता के मतों से जीत हासिल करने वाला दल किस तरह से लोकतंत्र को ध्वस्त करने वाला हो सकता है। विपक्षी एकता का यह महाकुंभ मोदी को कोसने की बजाय किन्हीं ठोस मुद्दों के सहारे कोई प्रभावशाली विमर्श खड़ा करने की कोशिश करता तो वह आम जनता को आकर्षित करता और यही स्वस्थ राजनीतिक परिपक्वता का परिचायक होता। लेकिन ऐसा न होना समूचे देश के विपक्षी दलों की नाकामी, उद्देश्यहीनता एवं राजनीतिक अपरिपक्वता का द्योतक हैं।

इस रैली में अनेक मुद्दे उठे, जिनमें प्रमुख रहा केंद्रीय एजेंसियों का कथित दुरुपयोग और राजनीतिक भ्रष्टाचार। प्रियंका गांधी ने इस रैली में सरकार के सामने पांच मांगें रखीं। इनमें प्रमुख दो हैं जिनमें चुनाव आयोग से माँग की गई है कि विपक्षी नेताओं पर छापों की कार्रवाई रोकी जाए। दूसरी और महत्वपूर्ण मांग ये है कि गिरफ्तार हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को तुरंत रिहा किया जाए। इस रिहाई की मांग के पीछे कांग्रेस का उद्देश्य बचे-खुचे संगठनों या पार्टियों को इंडिया गठबंधन से जोड़े रखना है। नीतीश कुमार और ममता बेनर्जी जैसे मजबूत खम्भे पहले ही उखड़ चुके हैं इसलिए जो कुछ बचा है उसे कांग्रेस समेटे रखना चाहती है, यही उसकी विवशता है। वैसे, इंडिया गठबंधन के घटक दलों के आपसी अंतर्विरोध की छाया भी इस रैली दिखी। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि विरोध किसी खास व्यक्ति से जुड़ा नहीं बल्कि मौजूदा

सरकार की तानाशाही के खिलाफ केंद्रित है। जबकि इस रैली का मकसद आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करना बताया गया। यहां आम आदमी पार्टी एवं कांग्रेस के बीच के अन्तर्विरोध को सहज ही समझा जा सकता है।

यह रैली भले ही अठाइस दलों का जमावड़ा बनी, इसे विपक्षी दलों की एकजुटता का प्रदर्शन भी कहा गया है। लेकिन जबसे इंडिया गठबंधन बना है, तब से उसमें टूट एवं बिखराव के स्वर सुनाई दे रहे हैं। विचारभेद के साथ मनभेद भी सामने आये हैं। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक तमाम राज्यों में टिकट बंटवारे के सवाल पर इंडिया गठबंधन से जुड़े दलों की आपसी खटपट की खबरें भी आ रही थीं। भले ही ये विवाद गिनी-चुनी सीटों को लेकर थे, लेकिन संदेश स्पष्ट था कि चुनाव सिर पर आने के बाद भी इंडिया गठबंधन से जुड़े दल एकजुट नहीं हो पा रहे। रामलीला मैदान की रैली के जरिए इन दलों ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि मोदी विरोध एवं भाजपा को सत्ता से दूर करने के मुद्दों पर वे एक स्वर में बोल सकते हैं और लगातार बोलते भी रहे हैं, फिर उसके लिये इस महारैली की क्या जरूरत? निश्चित ही एकजुटता के ये स्वर बेसूरे, असहज एवं बनावटी है, इंडिया गठबंधन के राजनैतिक क्षितिज पर जो वरिष्ठ राजनेता हैं उनकी आवाज व किरदार भारतीय जीवन को प्रभावित नहीं कर रहा है। इंडिया गठबंधन से जुडे.दलों की केन्द्र एवं प्रांतों की सरकारों के शासन-काल में तो अपराध, भ्रष्टाचार और साम्प्रदायिकता के जबड़े फैलाए, आतंकवाद, प्रांतवाद, जातिवाद की जीभ निकाले, मगरमच्छ सब कुछ निगलता रहा है। सब अपनी जातियों और ग्रुपों को मजबूत करते रहे हैं-देश को नहीं। प्रथम पंक्ति का नेता ही नहीं है जिसे मोदी के मुकाबले में खड़ा किया जा सके। भारत के लोग केवल बुराइयों से लड़ते नहीं रह सकते, वे व्यक्तिगत एवं सामूहिक, निश्चित सकारात्मक लक्ष्य के साथ जीना चाहते हैं। अन्यथा जीवन की सार्थकता नष्ट हो जाएगी।

दो तरह के नेता होते हैं- एक वे जो कुछ करना चाहते हैं, दूसरे वे जो कुछ होना चाहते हैं। असली नेता को सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी होकर, प्रासंगिक और अप्रासंगिक के बीच भेदरेखा बनानी होती है। संयुक्त रूप से कार्य करें तो आज भी वे भारत को विकास की नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने सहचिन्तन को शायद कमजोरी मान रखा है। नेतृत्व के नीचे शून्य तो सदैव खतरनाक होता ही है पर यहां तो ऊपर-नीचे शून्य ही शून्य है। इंडिया गठबंधन की चोटी से लेकर प्रांत स्तर पर, समाज स्तर पर तेजस्वी और खरे नेतृत्व का नितान्त अभाव है। यह सोच का दिवालियापन ही है कि दिखते हुए भ्रष्टाचार के बावजूद उसका विरोध नहीं करके, ऐसे भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिये लोकतंत्र बचाओ रैली का आयोजन हो रहे हैं। राजनीतिक भ्रष्टाचार एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन वह भी उतना सच है कि इस मामले में कोई भी दल दूध का धुला नहीं है। राजनीति के हमाम में सब नंगे हैं। विपक्षी दल कुछ भी दावा करें, सच्चाई यह है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान उनके पास भी नहीं है। राजनीति में काले धन का इस्तेमाल होता रहा है और कोई भी यह दावे के साथ कहने की स्थिति में नहीं कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। जो विपक्षी नेता भ्रष्टाचार के आरोप में केंद्रीय एजेंसियों की जांच का सामना कर रहे हैं अथवा उन्हें जेल जाना पड़ा है, उनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कहीं कुछ गलत नहीं किया। प्रधानमंत्री ने मेरठ में चुनावी महासंग्राम की शुरूआत करते हुए कहा कि अगर विपक्षी नेता पाक-साफ हैं तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें छोड़ क्यों नहीं रहा है? कुछ तो गड़बड़ होगी ही। कुल मिलाकर बयानों का तीखापन यहाँ- वहाँ आने लगा है। लोकसभा चुनाव के प्रचार में धार आ गई है। यह धार दिन ब दिन और पैनी होती जाएगी।

भारत के केनवास पर शांति, प्रेम, ईमानदारी, विकास और सह-अस्तित्व के रंगों की जरूरत है, पर आज इंडिया गठबंधन इन रंगों को भरने की पात्रता खोकर नायकविहीन है। रंगमंच पर नायक अभिनय करता है, राजनीतिक मंच पर नायक के चरित्र को जीना पड़ता है, कथनी-करनी में समानता, दृढ़ मनोबल, इच्छा शक्ति और संयमशीलता के साथ। लेकिन भारतीय लोकतंत्र की यह एक बड़ी विडम्बना है कि यहां विपक्षी दलों में नायक कम, खलनायक अधिक है। तभी एक मोदी अठाइस दलों के नेताओं पर भारी पड़ रहा है। देखना यह है कि विपक्षी दलों ने राजनीतिक भ्रष्टाचार का मामला उठाकर मोदी सरकार को घेरने की जो कोशिश की, उससे देश की जनता कितनी प्रभावित होगी और इसकी आवश्यकता महसूस करेगी या नहीं कि इस गठबंधन को सत्ता में लाना आवश्यक है। विपक्षी दलों ने जो मुद्दे उठाये, वे प्रभाव पैदा नहीं कर पाये। चुनावी बांड का ही मुद्दा ले, इसमें संदेह नहीं कि चुनावी बांड से दिए जाने वाले चंदे का जो विवरण सामने आया है, उससे अनेक गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जिन कंपनियों का नाम लेकर यह कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने उन पर अनुचित दबाव डालकर चंदा हासिल किया, उनमें से अनेक ने विपक्षी दलों को भी अच्छा-खासा चंदा दिया है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

आज समाज
RNI NO:HARHIN/2017/72026*
प्रकाशक, मुद्रक एवं कार्यकारी निदेशक **राकेश शर्मा** द्वारा मै गुडमॉर्निंग इंडिया मीडिया प्रा लिमिटेड के लिए गांव सद्दोपुर स्प्रिंग फील्ड पब्लिक स्कूल के सामने, अम्बाला-चंडीगढ़ हाइवे, अम्बाला-134004, हरियाणा से मुद्रित कराकर, गांव सद्दोपुर स्प्रिंग फील्ड पब्लिक स्कूल के सामने अम्बाला-चंडीगढ़ हाइवे, अम्बाला-134004 हरियाणा से प्रकाशित। **संपादक : अमित गुप्ता**
* पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी

संपादकीय

नई दिल्ली, मंगलवार 2 अप्रैल 2024
संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

कांग्रेस को आंशिक राहत, पर केजरीवाल न्यायिक हिरासत में

रविवार को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में 28 दलीय विपक्षी गठबन्धन इंडिया द्वारा जबर्दस्त शक्ति प्रदर्शन के बाद सोमवार को इंडिया के दो घटकों को लेकर जो अदालती फैसले आये हैं, उनमें से एक आंशिक तौर पर राहत भरा है परन्तु दूसरा उसे मायूस करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना तथा जस्टिस एजी मसीही की खंडपीठ ने जहां कांग्रेस से आयकर द्वारा 3500 करोड़ रुपये से अधिक की टैक्स वसूली पर 24 जुलाई तक रोक लगा दी, वहीं दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री तथा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। उन्हें कथित दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था।

कांग्रेस को आयकर विभाग ने उसे प्राप्त चंदे पर टैक्स वसूलने सम्बन्धी नोटिस जारी किया था। दो नोटिसों में क्रमशः 1745 करोड़ तथा 1823 करोड़ रुपए चुकाने के लिये उसे कहा गया था। इसके पहले एक अन्य कार्रवाई में कांग्रेस के बैंक खातों को सील कर दिया गया है जिसके कारण उसे चुनाव अभियान चलाने में दिक्कत आ रही है। कुछ दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कांफ्रेंस कर सख्त नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी उसे चुनाव में कमजोर करने के लिये अपनी एजेंसी (आईटी) के जरिये यह कार्रवाई कर रही है। पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन भी बता चुके हैं कि कांग्रेस का 2019 का कुल चुनावी खर्च 800 करोड़ रुपये ही था। ऐसे में उसकी हैसियत इतनी बड़ी राशि चुकाने की नहीं है। यह केन्द्रीय चुनाव आयोग राजीव कुमार के उस आश्वासन व दावे के बिलकुल खिलाफ है जिसमें उन्होंने कहा था कि आयोग सभी दलों को चुनाव लड़ने के समान अवसर (लेवल प्लेईंग फील्ड) देने के लिये कटिबद्ध है।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड्स सम्बन्धी सभी जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा केन्द्रीय निर्वाचन आयोग को जो दी गई है; और जिसे इसी आदेश की ही अनुपालना में उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है- उससे साफ हो गया है कि किस प्रकार से इस योजना का सर्वाधिक लाभ भाजपा को ही मिला है। इतना ही नहीं, चंदा बटोरने के लिये भाजपा ने किस प्रकार से सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया, उसका भी पर्याप्त खुलासा हुआ है। आयकर, ईडी व सीबीआई द्वारा छापे डलवाकर या जेल का डर दिखाकर कारोबारियों से बॉन्ड्स खरीदवाए गए जिन्हें भाजपा ने भुनाया। हर रोज जिस प्रकार से बॉन्ड्स को लेकर नयी-नयी कहानियां सामने आ रही हैं उससे स्पष्ट हो गया है कि यह योजना भाजपा सरकार द्वारा काले धन को सफेद करने का जरिया बनी और उसकी सबसे बड़ी लाभार्थी वह खुद रही।

वैसे 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना को असंवैधानिक करार देने वाले फैसले के बाद पहली बार मोदी ने इस पर एक टिप्पणी करते हुए कहा कि- 'जो लोग आज इसे लेकर नाच रहे हैं वे बाद में पछताएंगे। पहले तो चुनावी चंदे के स्रोत को कोई जान ही नहीं पाता था लेकिन अब लोग जान सकते हैं।' सामान्यतया प्रेस वार्तालाप से दूर रहने वाले मोदी ने एक तमिल चैनल से बातचीत में कहा कि 'पहले भी पीएमएलए कानून था परन्तु पूर्ववर्ती सरकारें इसका उपयोग ही नहीं करती थीं। पहले की सरकार ने 10 वर्षों में केवल कुछ लाख रुपये ही वसूले।' मोदी ने इस आरोप से भी इंकार किया कि उनकी सरकार जांच एजेंसियों को निर्देशित करती है और उनके कामों में दखलंदाजी करती है। वैसे प्रधानमंत्री की बातों में शायद ही कोई यकीन करे।

एक ओर भाजपा के पास इस प्रकार से कमाया गया अकूत धन और दूसरी तरफ वह अपने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को पूर्णतः संसाधनविहीन करने पर तुली है। पिछले कुछ समय से जिस तरह से कांग्रेस उसके सामने दमदारी से खड़ी है और उसके ईर्द-गिर्द करीब ढाई दर्जन दल जिस मजबूती से खड़े हैं, उससे भाजपा को लोकसभा चुनाव में अपनी जमीन खिसकती नज़र आ रही है। इसलिये भाजपा यह चुनाव बेहद गैर लोकतांत्रिक एवं निहायत अनैतिक तरीके से लड़ रही है। चुनावों की घोषणा हो जाने तथा आचार संहिता लागू रहते में जिस प्रकार से जांच एजेंसियों के मार्फत भाजपा सरकार विरोधी दल के नेताओं व पार्टियों को तंग कर रही है या उन्हें जेलों में डाल रही है, उससे भी लोगों में रोष है जिसका परिणाम चुनावी नतीजों में दिखलाई पड़ सकता है।

उधर एक अन्य घटनाक्रम में अंततः अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज ही दिया गया। 22 मार्च को ईडी द्वारा उनके शासकीय आवास से गिरफ्तार केजरीवाल को पहली बार 6 दिनों तथा दूसरी बार 4 दिनों की ईडी हिरासत दी गई थी। सोमवार को उन्हें फिर से पेश किया गया था। वैसे तो ईडी ने उनकी और हिरासत की मांग नहीं की परन्तु आरोप लगाया कि 'केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं', तो वहीं अब भी दिल्ली के सीएम पद पर काबिज केजरीवाल ने तिहाड़ जेल रवाना होने के पहले चेतावनी दे दी कि 'प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं वह देश के लिये अच्छा नहीं है'। उन्हें तिहाड़ की जेल नंबर-2 में रखा गया है जहां पहले से उनके सहयोगी एवं आप सरकार के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया, आबकारी मंत्री रहे सत्येन्द्र जैन तथा सांसद संजय सिंह इसी आरोप में न्यायिक हिरासत में हैं। इस घटनाक्रम का भी असर आसन्न चुनावों पर लाजिमी है।

डंका तो बज रहा है पर बदनामी का

बहुत शोर है कि मोदी के राज में दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी कई मौकों पर अपने मुंह से कह चुके हैं कि पहले तो लोग भारत में पैदा होने पर शर्म महसूस करते थे, पर अब गर्व करते हैं। वह भारत को विश्व गुरु बनाने के इशारे करते रहे हैं। उसे विशेष रूप से आर्थिक, सैन्य और सांस्कृतिक महाशक्ति बनाने के दावे करते रहे हैं। विदेश मंत्री, एस जयशंकर ने अभी पिछले ही दिनों दावा किया था कि अब 'कोई भी बड़ा वैश्विक मुद्दा, भारत की सलाह के बिना तय ही नहीं होता है।'

लेकिन, अगर यही सच है तो विदेश मंत्री के उक्त दावे के करीब ही अर्थ द्वारा प्रकाशित, एक लाख सैंतीस लाख से ज्यादा लोगों के सर्वे में, 67 फीसद लोगों की यह राय क्यों थी कि बड़ी ताकतों में भारत की आवाज का ही विश्व के भू-राजनीतिक मामलों में सबसे कम असर है। दूसरी ओर अमेरिका के संबंध में ऐसा ही मानने वाले सिर्फ 11 फीसदी थे, जबकि चीन के मामले में ऐसा मानने वाले 13 फीसदी और रूस के मामले में ऐसा मानने वाले 15 फीसदी। किसी देश के प्रभाव का एक और पैमाना, उसके पासपोर्ट को अन्य देशों में मिलने वाला वजन माना जाता है। लेकिन, हैंकले पासपोर्ट इंडैक्स पर भारत, अब 85वें स्थान पर है। पिछले साल के मुकाबले भी भारत एक स्थान नीचे ही खिसका है।

वास्तव में इसमें हैरानी की कोई बात भी नहीं है क्योंकि विश्व में भारत का डंका बजने का, प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरों के समय, प्रवासी भारतीयों को जुटाकर किए जाने वाले प्रायोजित ईवेंटों के अलावा, कोई कारण भी नहीं है। बेशक, अपने आकार के चलते भारत, दुनिया की चौथी बड़ी सैन्य शक्ति है। इसी प्रकार, आकार से ही जुड़ा भारत का सकल घरेलू उत्पाद, उसे दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में पांचवें स्थान पर पहुंचा देता है। और वर्तमान विकास दर से, अगले पांच साल में भारत के तीसरे स्थान पर पहुंच जाने में भी, जिसकी 'मोदी की गारंटी' का बहुत शोर है, हैरानी की कोई बात नहीं होगी। लेकिन, इन गिनतियों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह तथ्य है कि प्रतिव्यक्ति आय के पैमाने से वही भारत, 197 देशों में 142वें स्थान पर है। जाहिर है कि किसी देश की सामर्थ्य का कहीं वास्तविक परिचायक, यही स्थान है।

हैरानी की बात नहीं है कि जनता की वास्तविक दशा को दर्शाने वाले सभी महत्वपूर्ण सूचकांक, भारत का डंका बज रहे होने की नहीं, उसकी दुर्दशा की ही कहानी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की पांच एजेंसियों द्वारा खाद्य सुरक्षा तथा पोषण पर 2023 में तैयार की गई रिपोर्ट बताती है कि 74.1 फीसद यानी करीब 1.043 अरब भारतीय, सर्वे के वर्ष 2021 में, एक स्वस्थ खुराक हासिल करने में असमर्थ थे। इसी रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार, 2020-22 के दौरान भारत की 16.6 फीसद आबादी कुपोषित थी। यह भी गौरतलब है कि ग्लोबल हंगर इंडैक्स पर भारत, 2022 में 107वें स्थान पर था और ग्लोबल फूड सिक्यूरिटी इंडैक्स पर, 68वें स्थान पर।

इन्हीं हालात का नतीजा हाल में तीन ऐसी अतियों के रूप में भी देखने को मिला है, जो बाकी दुनिया में भारत की बदहाली का डंका बज रहे होने की ही संकेतक हैं। इनमें एक का संबंध, यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना की ओर से झोंके गए कुछ भारतीयों के हताहत होने की धीरे-धीरे आ रही खबरों से है। जाहिर है कि भारी मुश्किलों तथा मजबूरियों के चलते ये भारतीय नागरिक, रूसी सेना के सहायकों के रूप में काम करने पहुंचे थे और किसी प्रकार उन्हें युद्ध के खतरों के बीच झोंक दिया गया। इसी का दूसरा रूप, इज़रायल-फिलिस्तीन युद्ध के बीच, इज़रायल की मांग पर, वहां गिरमिटिया बनाकर भारतीय मजदूरों के भेजे जाने का है, जिसमें भाजपा की केंद्र तथा हरियाणा व उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों की, सक्रिय हिस्सेदारी है। इन मजदूरों के युद्धग्रस्त देश में जाने पीछे की मजबूरी का अंदाजा एक मजदूर के इस चर्चित कथन से लगाया जा सकता है कि, 'यहां भूख से मरने से तो, इज़रायल में लड़ाई में मरना ही बेहतर है।' तीसरा रूप, पिछले ही दिनों डंकी मारकर अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए एक गुजराती भारतीय परिवार के मारे जाने के बाद आई, इस आशय की खबरों का है कि अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने वालों में अब, भारतीयों की संख्या ही सबसे बड़ी है। क्या यही विश्व गुरु बनने के लक्षण हैं?

लेकिन, बात सिर्फ भारत के अपेक्षाकृत गरीब तथा पिछड़ा होने की ही होती, तब भी गनीमत थी। मोदी राज ने अपने दस साल में देश को उल्टे ही रास्ते पर धकेल दिया है, जहां उसकी गांठ की पूंजी भी लुटती जा रही है। लंबे और शानदार स्वतंत्रता आंदोलन से निकले भारत ने अपने लिए जिस समावेशी, धर्मनिरपेक्ष, जनतंत्र को अपनाया था, जनता के लिए जिस तरह की स्वतंत्रताएं व कानूनी समानताएं सुनिश्चित की थीं, उस सब को व्यवस्थित तरीके से खोखला कर के खत्म किया जा रहा है। इसका नतीजा यह है कि आज दुनिया में भारत का अगर कोई डंका बज रहा है, तो यह बदनामी का डंका है। ऐसे ही डंके के हिस्से के तौर पर, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की कथित शराब घोटाले के सिलसिले में, चुनाव से ठीक पहले ईडी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ जर्मनी तथा अमेरिका ने चिंता जताई है। बेशक, मोदी सरकार ने उनके चिंता जताने पर आपत्ति भी दर्ज कराई है, लेकिन ये सब तो बदनामी का डंका और जोर-जोर से बजने की ही निशानियां हैं।

यह संयोग ही नहीं है कि मोदी राज में लगातार गिरकर, विश्व प्रेस फ्रीडम इंडैक्स पर भारत, 161वें स्थान पर पहुंच चुका है। यहां भी वह 2022 के 150वें स्थान से 11 अंक नीचे फिसल कर पहुंचा है। समावेशीपन सूचकांक पर भारत 117वें स्थान पर है और वैश्विक जेंडर गैप सूचकांक पर भी, 127 वें स्थान पर है। उधर चुनावी जनतंत्र सूचकांक पर भी भारत, 108वें स्थान पर है और कुल मिलाकर जनतंत्र सूचकांक पर 10 स्थान नीचे खिसक कर, 51वें स्थान पर चला गया है। वास्तव में वी-डेम इंस्टीट्यूट ने जो भारत को 2018 से चुनावी तानाशाही घोषित कर रखा है, उसके दायरे में उसने इस साल भारत का सबसे तेजी से तानाशाही की ओर बढ़ना दर्ज किया है।

राजेंद्र शर्मा

> जिस जी-20 की सफलता का और उससे दुनिया भर में भारत की शान बढ़ने का इतना ढोल पीटा गया, प्रधानमंत्री मोदी का एक महंगा प्रचार ईवेंट भर साबित हुआ है। इससे भारत के ग्लोबल साउथ यानी विकासशील दुनिया का नेता बनकर उभरने के दावों का झूठ भी उसके फौरन बाद, तभी उजागर हो गया जब अमेरिका की वफादारी के चक्कर में भारत ने, क्यूबा में हवाना में हो रही जी-77 शिखर बैठक में, विदेश मंत्री को भेजने की हामी भरने के बाद, अपने पांव पीछे खींच लिए।

स्वतंत्रताओं के छीने जाने का आलम यह है कि किसान आंदोलन के ताजा चक्र की पूर्व-संध्या में ही, किसानों का दिल्ली पहुंचना असंभव बनाने के लिए युद्ध जैसे दमनमारी इंतजामात ही नहीं कर लिए गए, हरियाणा में पूरे आठ जिलों में इंटरनैट पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने के साथ ही (ऐसी पाबंदी लगाने में भारत पहले ही विश्व गुरु बन चुका है) किसान आंदोलन से जुड़े लोगों तथा इस आंदोलन की खबर दे सकने वाले पत्रकारों तक के सोशल मीडिया खाते, सरकारी आदेश से बंद करा दिए गए। इससे खीझे एक्स (पहले ट्विटर) ने सारी दुनिया में यह जानकारी प्रसारित कर दी कि भारत सरकार ने मजबूर कर के उससे उक्त खाते बंद कराए हैं, वह खुद लोगों की स्वतंत्रता के इस दमन के खिलाफ है और उक्त खाते केवल भारत में बंद किए जाएंगे और भारत से बाहर देखे जा सकेंगे। जाहिर है कि ये सब तो बदनामी के ही डंके हैं।

ऐसे ही डंके तब बजते हैं कि जब योरोप, अमेरिका तथा शेष दुनिया के धार्मिक स्वतंत्रताओं तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के क्षय तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर बढ़ते हमलों पर बार-बार उंगली ही नहीं रखते हैं, अपनी सरकारों से इसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी करते हैं और अमेरिका जैसी सरकारें, भारत के साथ संवाद में इन चिंताओं को उठाने के वादे भी करती हैं। विश्व में धार्मिक स्वतंत्रताओं की स्थिति की निगरानी करने वाली अमेरिकी संस्था, यूएससीआईआरएफ ने 2023 की अपनी रिपोर्ट में लगातार चौथे साल अमेरिकी सरकार से आग्रह किया था कि 'भारत में धर्म या आस्था की स्वतंत्रता के व्यवस्थित, लगातार जारी तथा भीषण उल्लंघनों' के लिए, उसे 'विशेष चिंता का देश' घोषित किया जाए! ऐसा ही एक और डंका हाल ही में तब बजा था जब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि कैसे भारत में 128 बुलडोजर कार्रवाइयों में मुसलमानों को निशाना बनाया गया था और ऐसी सबसे ज्यादा कार्रवाइयां मध्य प्रदेश में ही हुई थीं, जिनकी संख्या 56 थी।

बेशक, मोदी सरकार सच्चाई को छुपाने की कोशिश में, नियमतः ऐसे सभी संकेतकों को नकारती है। और तो और उसने कोविड से मौतों की वास्तविक संख्या को भी छुपाने की कोशिश की थी और भारत में तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के दसवें हिस्से के बराबर ही मौतें होने का दावा किया था। लेकिन, इस तरह के खंडनों तथा सच्चाई को छुपाने की कोशिशों से तो, दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा और गिरती ही है। दूसरी ओर, एक बड़ी ताकत बन जाने की झूठी शान की कीमत भारत को अपने सभी पड़ौसी देशों—पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, यहां तक कि मालदीव भी—के साथ रिश्तों के खराब से असहज तक बने रहने के रूप में चुकानी पड़ रही है। उधर अमेरिका के नेतृत्व में सामराजी ताकतों ने भारत को, समाजवादी चीन की घेराबंदी का औजार बनाने के लिए, उसके साथ जो रणनीतिक रिश्ते बनाए हैं तथा उसे लेकर क्वॉड व आई-2 यू-2 जैसे जो गुट बनाएं हैं, भारत के जूनियर पार्टनर बनने की सच्चाई को छुपा नहीं सकते हैं। जिस जी-20 की सफलता का और उससे दुनिया भर में भारत की शान बढ़ने का इतना ढोल पीटा गया, प्रधानमंत्री मोदी का एक महंगा प्रचार ईवेंट भर साबित हुआ है। इससे भारत के ग्लोबल साउथ यानी विकासशील दुनिया का नेता बनकर उभरने के दावों का झूठ भी उसके फौरन बाद, तभी उजागर हो गया जब अमेरिका की वफादारी के चक्कर में भारत ने, क्यूबा में हवाना में हो रही जी-77 शिखर बैठक में, विदेश मंत्री को भेजने की हामी भरने के बाद, अपने पांव पीछे खींच लिए। यानी डंका जरूर बज रहा है, पर बदनामी का डंका।

(लेखक साप्ताहिक पत्रिका लोक लहर के संपादक हैं।)

दिल्ली के मुख्यमंत्री के बाद ईडी की नजर अब केरल पर

■ **पी. श्रीकुमारन**

प्रवर्तन निदेशालय, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और आप के अन्य नेताओं के खिलाफ अपनी कार्रवाई के बाद, जिसे वह एक 'सफल' अभियान मानता है, ने अब केरल पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं।

लेकिन केंद्रीय जांच एजंसी को पता होना चाहिए कि केरल एक अलग चाय का प्याला है। उत्तर भारतीय राज्य में उसने जो रणनीति सफलतापूर्वक अपनाई है वह केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में नहीं चलेगी।

एजंसी ने केरल के खिलाफ अपने अभियान में जो नवीनतम कदम उठाया है, वह मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी टी. वीणा की कंपनी से जुड़े कथित मासिक भुगतान विवाद के संबंध में जांच रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज करना है। ईसीआईआरएजंसी की कोच्चि इकाई द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत दायर किया गया है।

यह कार्रवाई अगस्त 2003 में आयकर अंतरिम निपटान बोर्ड (आईटीएसआईबी) की एक रिपोर्ट के आधार पर की गई है जिसमें कहा गया था कि उनकी कंपनी, एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को कोच्चि स्थित कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड से मासिक भुगतान के रूप में 1.72 करोड़ रुपये मिले थे। सीएमआरएल, हालांकि बदले में दी गई किसी भी सेवा का कोई सुबूत नहीं था। मासिक भुगतान मामले में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसआईएफओ) द्वारा जांच चल रही है।

वीणा के अलावा, सीएमआरएल और केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम (केएसआईडीसी) की भूमिका की भी जांच की जा रही है, जिसके पास सीएमआरएल में 13.4 प्रतिशत शेयर हैं। यह उल्लेख किया जा सकता है कि फरवरी में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कंपनी के मामलों में एसएफआईओ द्वारा जांच का आदेश देने में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) की कार्रवाई को चुनौती देने वाली एक्सालॉजिक द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था।

> थॉमस इसाक को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वह केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोर्ड(केआईआईएफबी)फंड द्वारा मसाला बांड के मुद्दे की जांच के संबंध में उन्हें 'ठीक' करने के ईडी के प्रयासों का सफलतापूर्वक विरोध कर रहे हैं। ईडी इसहाक को एक के बाद एक समन जारी करने में व्यस्त है और वह बार-बार इससे पल्ला झाड़ रहे हैं। केरल के पूर्व वित्त मंत्री ने समन को अवैध और मनमाना बताते हुए ईडी के कदम का विरोध किया था।

ईडी का नवीनतम कदम एलडीएफ सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्र सरकार के आदेश पर उसके पिछले प्रयासों की निराशाजनक विफलता की पृष्ठभूमि में आया है। न केवल इस तरह के दुस्साहस विफल हो गये, बल्कि लोगों ने सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाले एलडीएफ को 2021 के राज्य विधानसभा चुनावों में बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापस लाकर एलडीएफ सरकार के खिलाफ भाजपा और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिकफ्रंट (यूडीएफ) के अभियान का करारा जवाब दिया। निन्दा का अभियान स्पष्ट रूप से मतदान के रुझान पर कोई प्रभाव डालने में विफल रहा।

मुख्यमंत्री की बेटी और सीपीआई (एम) केंद्रीय समिति के सदस्य थॉमस इसाक के खिलाफ ईडी के नवीनतम कदम का समय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहा है। यह और कुछ नहीं बल्कि घबराई हुई मोदी सरकार का एक हताश कदम है, जो चुनावी बांड मामले में हुए खुलासों के प्रतिकूल प्रभाव से जूझ रही है। लोगों का ध्यान मुद्दे से भटकाने के लिए ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है। भगवा खेमा स्पष्ट रूप से सोचता है कि इस तरह के कदमों से उसे भरपूर चुनावी लाभ मिलेगा। लेकिन अगर वह ऐसा सोचता है तो यह आत्मसंतुष्टि की झूठी भावना में खोना होगा। कुछ भी हो, इस दुस्साहस का संघ परिवार और मोदी सरकार पर बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। संकेत पहले से ही मौजूद हैं।

भाजपा-आरएसएस कबीला इतना डरा हुआ क्यों है? कारण स्पष्ट हैं। नागरिक संशोधन कानून (सीएए) और चुनावी बांड मुद्दे के खिलाफ वामपंथी दलों द्वारा चलाया जा रहा अभियान लोगों के मन में बड़ा प्रभाव पैदा कर रहा है। वाम दल निस्संदेह लाभप्रद स्थिति में हैं क्योंकि वे एकमात्र ऐसे दल हैं जिन्होंने चुनावी बांड नहीं लिया है। यह सीपीआई (एम) थी जिसने चुनावी बांड के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया और एक अनुकूल फैसला जीता, जिसने मोदी सरकार की विश्वसनीयता को एक विनाशकारी झटका दिया है।

यह विशेष रूप से वाम दलों के खिलाफ आक्रामक अभियान की व्याख्या करता है, और वीणा को निशाना बनाया गया है क्योंकि वह पिनाराई विजयन की बेटी हैं जो केंद्र सरकार और भाजपा-आरएसएस जोड़ी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री अपनी चुनावी रैलियों में सीएए मुद्दे और चुनावी बांड मामले का प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहे हैं, जो भगवा खेमे में निराशा उत्पन्न करते हुए भारी भीड़ को आकर्षित कर रहा है।

थॉमस इसाक को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वह केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोर्ड (केआईआईएफबी) फंड द्वारा मसाला बांड के मुद्दे की जांच के संबंध में उन्हें 'ठीक' करने के ईडी के प्रयासों का सफलतापूर्वक विरोध कर रहे हैं। ईडी इसहाक को एक के बाद एक समन जारी करने में व्यस्त है और वह बार-बार इससे पल्ला झाड़ रहे हैं। केरल के पूर्व वित्त मंत्री ने समन को अवैध और मनमाना बताते हुए ईडी के कदम का विरोध किया था।

अपनी ओर से, केरल के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर विपक्षी दलों को डराने-धमकाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कड़ी आलोचना की है। उन्होंने अपने दिल्ली समकक्ष अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का भी जिक्र करते हुए कहा कि इसे पहली या आखिरी गिरफ्तारी नहीं माना जा सकता। लोकतंत्र खतरे में है और समय की मांग है कि हम अपनी पूरी ताकत से इसकी रक्षा करें। सीपीआई (एम) नेता एकजुट हो गये हैं और केरल के मुख्यमंत्री को पूर्ण समर्थन मिल रहा है।

अपनी कड़ी प्रतिक्रिया में, सीपीआई (एम) के राज्य सचिव एमवी गोविंदन ने कहा कि ईडी का कदम केरल में विपक्ष के नेता वीडी सतीसन की मदद करने के लिए है, जो पिनाराई के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गोविंदन ने कहा, ईडी भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए विपक्षी नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी केंद्र सरकार ने ईडी और अन्य जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया था। गोविंदन ने गैर-भाजपा नेताओं के खिलाफ ईडी की छापेमारी पर कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पार्टी तभी प्रतिक्रिया देती है जब ईडी कांग्रेस नेताओं के पीछे जाती है।

एक बात की भविष्यवाणी निश्चितता के साथ की जा सकती है। एलडीएफ सरकार के खिलाफ ईडी की ओर से किसी भी दुस्साहस का भगवा खेमे और केंद्र सरकार पर बुरा असर पड़ना तय है। केरल में एलडीएफ के लिए बढ़ते समर्थन ने स्पष्ट रूप से भाजपा-आरएसएस कबीले को परेशान कर दिया है। इसलिए यह पिनाराई सरकार को किसी भी तरह से अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन केरल के प्रबुद्ध लोग पूरी तरह से एलडीएफ सरकार और मुख्यमंत्री के पीछे हैं क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि वह लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में आगे आकर नेतृत्व कर रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी भारत का विचार बरकरार रहे।

पावन प्रसंग

धैर्यवान बनिए

कोई भी काम करने में धैर्य की नितांत आवश्यकता होती है जो धैर्यवान है, वह कर्म करने से पहले उसके शुभाशुभ परिणाम पर विचार कर सकता है। उसको सफल बनाने के लिए मार्ग निर्धारित कर सकता है। अपने कर्म के सत-असत एवं उपयोगिता-अनुपयोगिता पर सोच सकता है। इसके विपरीत जो अधैर्यवान है, आवेश अथवा उद्वेगपूर्ण है; वह न तो कर्म की इन आवश्यक भूमिकाओं पर विचार कर सकता है और न दक्षता प्राप्त कर सकता है, वह तो अस्त-व्यस्त क्रियाकलाप की तरह एक निरर्थक श्रम ही होता है।

अधैर्यवान मनुष्य का बहुत बड़ा दुर्गुण है। अधीर व्यक्ति में अपेक्षित गंभीरता का अभाव ही रहता है, जिससे वह चपलता के अधीर व्यक्ति के मन-बुद्धि स्थिर नहीं रहते वह न किसी विषय में ठीक से सोच सकता है और न कर्तृत्व का निर्णय कर सकता है। अधैर्यवान व्यक्ति अदक्षता, अस्त-व्यस्तता,, अनिर्णयत्मकता एवं अक्षमता के कारण जीवन के हर क्षेत्र में असफल होकर दुख भोगता है। इसके विपरीत जो धैर्यवान है, वह जिस कार्य को पकड़ता है, उसे पूर्ण मनोयोग, बुद्धि और समग्र शक्ति लगाकर पूरा किए बिना नहीं रहता। धैर्यवान व्यक्ति कर्म करके उसके फल की प्रतीक्षा में व्यग्र नहीं होता, बल्कि फलासक्ति से रहित होकर कार्य किया करता है।

धैर्य न हो तो मानसिक दौर्बल्य के कारण मन सदा भयभीत रहेगा। जब मनुष्य के मन में शंका बढ़ जाती है, तब दुख के मिट जाने पर भी उसका आभास रहा करता है। जो व्यक्ति धैर्यवान होते हैं, वे संकट के समय अपने विवेक को नष्ट नहीं होने देते। उनके आत्मबल के कारण ही उस समय भी शांति मिलती है और दूसरे लोग भी उनका अनुकरण करने को बाध्य होते हैं। तब वह संकट उतना व्यथित नहीं करता, जितना कि धीरज के अभाव में। धैर्यवान मनुष्य के अंतःकरण में अत्यन्त शांति, भविष्य की सुखद आशा और उदारता की प्रबलता रहती है। वह बुरे दिन के फेर में पड़कर घबराता नहीं, बल्कि उन दिनों को हँसते हुए टालने की चेष्टा करता रहता है।

इसके विपरीत जिसके मन में धैर्य नहीं होता, उसके मन में जो आशा-निराशा की तरंगें उठती हैं, वे वैसी ही हैं,जैसे कोई बालू की दीवार खड़ी होकर भी ढह पड़े। संकट के समय उसकी मानसिक वेदना बढ़ जाती है और वह अपने भावों पर नियंत्रण रखने में समर्थ नहीं होता। ऐसे लोगों की दशा बहुत खराब होती देखी गई है और उनमें भी कुछ अत्यन्त दुर्बल प्रवृत्ति के मनुष्यों का मानसिक संतुलन तो यहां तक बिगड़ जाता है कि वे आत्महत्या तक कर बैठते हैं। सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य पालनार्थ भी कर्मों को सुव्यवस्थित करने के लिए धैर्य की आवश्यकता है। मान लीजिए कि आप किसी मुकदमे में फंसे हैं, परंतु उसके निर्णय में विलंब है; इस बीच कोई अधिकारी व्यक्ति उस मुकदमे की जांच के समय आपको किसी बात पर डांटता है तो उससे आपका विचलित हो उठना ही आपके हार का कारण बन सकता है। यदि आप उसमें धैर्य से काम लें तो विजय प्राप्त कर सकते हैं।

धैर्य के लिए दोषरहित मनोवृत्ति और अपने कर्म के उचित होने का विश्वास होना चाहिए। यदि आपका कार्य न्याययुक्त नहीं है तो आप कितने भी साहस से काम लें, मन में शंका भरी रहेगी और धैर्य आपका साथ नहीं देगा। इसके विपरीत यदि आप यह समझते हैं कि आप जो कार्य कर रहे हैं, वह न्याययुक्त होते हुए भी बिगड़ रहा है, तो भी आपका मन निर्भीक रहेगा और अपने धैर्यबल से ही सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसे मत भूलिए कि संसार में धन और प्रतिष्ठा ही सब कुछ नहीं है। धनवान तो मूर्ख भी हो जाते हैं और कभी-कभी निम्न स्तर के लोग भी ऊंची प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं, परन्तु उनमें से जिसमें भी अहंकार उत्पन्न हुआ, वहीं पतित हो गया। वह 'अहं' ही उन्हें नष्ट करने का कारण बनता है, फिर न आत्मबल साथ रहता है और न धैर्य ही।

धैर्यवान पुरुष वही कहलाता है, जिसे अपने पर पूर्ण भरोसा हो। जो व्यक्ति अपनी योग्यता पर विश्वास करता हुआ धैर्य का संबल ग्रहण करता है, वह कष्ट पाता हुआ भी प्रसन्नचित्त रहता है; क्योंकि वह कठिनाइयों से घबराता नहीं।

युग निर्माण योजना

आपके पत्र

किशोरियों की शिक्षा में डिजिटल दुनिया का सहयोग

काजल (बदला हुआ नाम) एक 15 वर्षीय लड़की है जो अपने परिवार के साथ दिल्ली स्थित उत्तम नगर इलाके में रहती है। उसके परिवार में कुल छः सदस्य हैं। काजल अपनी चार बहनों, मां और मौसी के साथ किराए के घर में रहती है। कोरोना महामारी के दौरान उसके पिता की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण काजल और उसके परिवार को अनेक आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसी बीच, ऑनलाइन शिक्षा के कारण काजल की पढ़ाई में भी बाधा आने लगी। घर में एंड्रॉयड फोन नहीं होने के कारण वह ऑनलाइन क्लास से वंचित रहने लगी। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात स्थानीय स्वयंसेवी संस्था प्रोत्साहन इंडिया फाउंडेशन की शिक्षिका रेहाना से हुई। जिन्होंने काजल की पारिवारिक स्थिति को देखते हुए संस्था की ओर से उसे एक डिजिटल उपकरण के रूप में टैब उपहार में दिया। इस उपकरण ने काजल के जीवन में क्रांति ला दी। उसने फिर से अपनी पढ़ाई को शुरू किया। आज वह दसवीं कक्षा में पढ़ रही है, इस डिजिटल उपकरण के कारण न केवल काजल बल्कि उसकी मौसी ने भी ओपन स्कूलिंग के माध्यम से अपनी बारहवीं कक्षा पास की है।

डिजिटल दुनिया के सहयोग से आज काजल और सकीना वह सब कर सकती हैं जो वह करना चाहती हैं। लेकिन हमारे आस-पास ऐसी कई लड़कियों के उदाहरण हैं, जो आज भी विभिन्न कारणों से शिक्षा से वंचित हैं। अक्सर समाज की रूढ़िवादी सोच किशोरियों के समुचित विकास में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। प्रोत्साहन इंडिया की शिक्षिका रेहाना बताती हैं कि 'केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि दिल्ली जैसे महानगरों में बसे झुग्गी झोपड़ी इलाकों में भी किशोरियों को इन्हीं बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यदि घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो सबसे पहले घर की लड़की का स्कूल छुड़वा दिया जाता है ताकि लड़कों को पढ़ने का अवसर मिले। फिर चाहे वह लड़की, लड़के की तुलना में पढ़ने में होशियार ही क्यूं न हो, उसकी पढ़ाई छुड़वाकर उसे घर के कामों में लगा दिया जाता है। कोरोना महामारी के दौरान सबसे अधिक बालिकाओं की शिक्षा प्रभावित हुई है। सभी आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान लड़कियों का स्कूल ड्रॉप आउट तेज़ी से बढ़ा है। ऐसे में संस्था के माध्यम से उनके लिए डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराना किसी वरदान से कम नहीं है।

भारत जैसे विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश में महिला साक्षरता की दर अभी भी चिंताजनक स्थिति में है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू (डब्लू पी आर) की वेबसाइट के अनुसार विश्व की औसत साक्षरता दर 83.41 प्रतिशत की तुलना में भारत में साक्षरता की दर 74 प्रतिशत है। वहीं महिला साक्षरता की बात करें तो विश्व में 71.88 प्रतिशत की तुलना में भारत में महिला साक्षरता की दर मात्र 65.8 प्रतिशत है। जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुरुषों की साक्षरता दर 79.16 प्रतिशत की तुलना में भारत में साक्षरता की दर 82.4 प्रतिशत है। यह अंतर बताता है कि भारत में महिलाओं की शिक्षा पर आज तक गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया है। रेहाना इसका मुख्य कारण बताती हैं कि इसके पीछे वित्तीय बोझ, रूढ़िवादी सोच, परिवार का सपोर्ट न मिलना और लड़कियों की शिक्षा की तरफ झुकाव नहीं होना अहम है।

भारत में 15 से 18 साल के आयु वर्ग की लगभग 40 प्रतिशत लड़कियां ऐसी हैं जो दुबारा स्कूल नहीं जा सकी। हालांकि महामारी के बाद बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और सभी राज्य सरकारों ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। स्कूलों में छात्राओं के बीच मुफ़्त लैपटॉप और कहीं टैबलेट भी वितरित किये गए हैं। लेकिन नतीजे संतोषजनक नहीं कहे जा सकते हैं। रेहाना कहती हैं कि पुरुष और महिला शिक्षा के बीच आंकड़ों के इस अंतर को किसी योजना या कानून बनाने से खत्म नहीं किया जा सकता है। इसके लिए समाज में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। जब तक समाज बालिका शिक्षा को महत्व नहीं देगा उस समय तक इन आंकड़ों में किसी प्रकार के परिवर्तन की उम्मीद बेमानी होगी।

ज्योति, दिल्ली

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770
ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

https://t.me/AllNewsPaperPaid

इंडिया की लोकतंत्र बचाओ महारैली के बेसूरे स्वर

-ललित गर्ग

दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन इंडिया की लोकतंत्र बचाओं महारैली में जुटे 28 दलों के नेता आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कोई प्रभावी संदेश देने में नाकाम रहे हैं। भले ही चुनाव के ठीक पहले विपक्षी दलों ने इसके जरिए अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने में कामयाबी हासिल की हो। लेकिन यह एकजुटता भ्रष्ट नेताओं को बचाने की एक मुहिम ही बनकर सामने आयी है। इसमें स्पष्ट रूप से केन्द्र सरकार की भ्रष्टाचार पर गई कार्रवाई की बौखलाहट झलक रही थी। इस रैली में सभी दलों के नेताओं ने देश विकास के मुद्दों, सिद्धान्तों एवं नैतिक तकाजे की बजाय मोटे तौर पर सत्ता पक्ष की भ्रष्टाचार के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए इसी के इर्दगिर्द ही अपनी बातें रखीं। लोकतंत्र बचाओ रैली से उपजे विचारों ने किन्हीं पवित्र उद्देश्यों के बजाय सत्ता हासिल करने की लालसा को ही उजागर किया, यह निराश करने वाली रैली किसी बड़े बदलाव की वाहक बनती हुई नजर नहीं आयी।

इस रैली में भारतीय जनता पार्टी एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शानदार जीत की संभावना से बौखलाए नेताओं की खींच ही ज्यादा सामने आयी है। यही कारण है कि रैली में जो मुद्दा जोरशोर से उठा, वह यह रहा कि यदि भाजपा फिर से सत्ता में आ गई तो लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा और संविधान भी। यह समझना कठिन है कि कोई दल लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करता है तो उससे लोकतंत्र और संविधान कैसे खत्म हो जाएगा। आम जनता के मतों से जीत हासिल करने वाला दल किस तरह से लोकतंत्र को ध्वस्त करने वाला हो सकता है। विपक्षी एकता का यह महाकुंभ मोदी को कोसने की बजाय किन्हीं ठोस मुद्दों के सहारे कोई प्रभावशाली विमर्श खड़ा करने की कोशिश करता तो वह आम जनता को आकर्षित करता और यही स्वस्थ राजनीतिक परिपक्वता का परिचायक होता। लेकिन ऐसा न होना समूचे देश के विपक्षी दलों की नाकामी, उद्देश्यहीनता एवं राजनीतिक अपरिपक्वता का द्योतक हैं।

इस रैली में अनेक मुद्दे उठे, जिनमें प्रमुख रहा केंद्रीय एजेंसियों का कथित दुरुपयोग और राजनीतिक भ्रष्टाचार। प्रियंका गांधी ने इस रैली में सरकार के सामने पाँच माँगें रखीं। इनमें प्रमुख दो हैं जिनमें चुनाव आयोग से माँग की गई है कि विपक्षी नेताओं पर छापों की कार्रवाई रोकी जाए। दूसरी और महत्वपूर्ण माँग ये है कि गिरफ्तार हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को तुरंत रिहा किया जाए। इस रिहाई की माँग के पीछे कांग्रेस का उद्देश्य बचे-खुचे संगठनों या पार्टियों को इंडिया गठबंधन से जोड़े रखना है। नीतीश कुमार और ममता बेनर्जी जैसे मजबूत खम्भे पहले ही उखड़ चुके हैं इसलिए जो कुछ बचा है उसे कांग्रेस समेटे रखना चाहती है, यही उसकी विवशता है। वैसे, इंडिया गठबंधन के घटक दलों के आपसी अंतर्विरोध की छाया भी इस रैली दिखी। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि विरोध किसी खास व्यक्ति से जुड़ा नहीं बल्कि मौजूदा सरकार की तानाशाही के खिलाफ केंद्रित है। जबकि इस रैली का मकसद आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करना बताया गया। यहां आम आदमी पार्टी एवं कांग्रेस के बीच के अन्तर्विरोध को सहज ही समझा जा सकता है।

यह रैली भले ही अठाइस दलों का जमावड़ा बनी, इसे विपक्षी दलों की एकजुटता का प्रदर्शन भी कहा गया है। लेकिन जबसे इंडिया गठबंधन बना है, तब से उसमें टूट एवं बिखराव के स्वर सुनाई दे रहे हैं। विचारभेद के साथ मनभेद भी सामने आये हैं। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक तमाम राज्यों में टिकट बंटवारे के सवाल पर इंडिया गठबंधन से जुड़े दलों की आपसी खटपट की खबरें भी आ रही थीं। भले ही ये विवाद गिनी-चुनी सीटों को लेकर थे, लेकिन संदेश स्पष्ट था कि चुनाव सिर पर आने के बाद भी इंडिया गठबंधन से जुड़े दल एकजुट नहीं हो पा रहे। रामलीला मैदान की रैली के जरिए इन दलों ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि मोदी विरोध एवं भाजपा को सत्ता से दूर करने के मुद्दों पर वे एक स्वर में बोल सकते हैं और लगातार बोलते भी रहे हैं, फिर उसके लिये इस महारैली की क्या जरूरत? निश्चित ही एकजुटता के ये स्वर बेसूरे, असहज एवं बनावटी है, इंडिया गठबंधन के राजनैतिक क्षितिज पर जो वरिष्ठ राजनेता हैं उनकी आवाज व किरदार भारतीय जीवन को प्रभावित नहीं कर रहा है। इंडिया गठबंधन से जुडे.दलों की केन्द्र एवं प्रांतों की सरकारों के शासन-काल में तो अपराध, भ्रष्टाचार और साम्प्रदायिकता के जबड़े फैलाए, आतंकवाद, प्रांतवाद, जातिवाद की जीभ निकाले, मगरमच्छ सब कुछ निगलता रहा है। सब अपनी जातियों और ग्रुपों को मजबूत करते रहे हैं-- देश को नहीं। प्रथम पंक्ति का नेता ही नहीं है जिसे मोदी के मुकाबले में खड़ा किया जा सके। भारत के लोग केवल बुराइयों से लड़ते नहीं रह सकते, वे व्यक्तिगत एवं सामूहिक, निश्चित सकारात्मक लक्ष्य के साथ जीना चाहते हैं। अन्यथा जीवन की सार्थकता नष्ट हो जाएगी।

दो तरह के नेता होते हैं- एक वे जो कुछ करना चाहते हैं, दूसरे वे जो कुछ होना चाहते हैं। असली नेता को सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी होकर, प्रासंगिक और अप्रासंगिक के बीच भेदरेखा बनानी होती है। संयुक्त रूप से कार्य करें तो आज भी वे भारत को विकास की नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने सहचिन्तन को शायद कमजोरी मान रखा है। नेतृत्व के नीचे शून्य तो सदैव खतरनाक होता ही है पर यहां तो ऊपर-नीचे शून्य ही शून्य है। इंडिया गठबंधन की चोटी से लेकर प्रांत स्तर पर, समाज स्तर पर तेजस्वी और खरे नेतृत्व का नितान्त अभाव है। यह सोच का दिवालियापन ही है कि दिखते हुए भ्रष्टाचार के बावजूद उसका विरोध नहीं करके, ऐसे भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिये लोकतंत्र बचाओ रैली का आयोजन हो रहे हैं। राजनीतिक भ्रष्टाचार एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन वह भी उतना सच है कि इस मामले में कोई भी दल दूध का धुला नहीं है। राजनीति के हमाम में सब नंगे हैं। विपक्षी दल कुछ भी दावा करें, सच्चाई यह है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान उनके पास भी नहीं है। राजनीति में काले धन का इस्तेमाल होता रहा है और कोई भी यह दावे के साथ कहने की स्थिति में नहीं कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। जो विपक्षी नेता भ्रष्टाचार के आरोप में केंद्रीय एजेंसियों की जांच का सामना कर रहे हैं अथवा उन्हें जेल जाना पड़ा है, उनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कहीं कुछ गलत नहीं किया। प्रधानमंत्री ने मेरठ में चुनावी महासंग्राम की शुरूआत करते हुए कहा कि अगर विपक्षी नेता पाक-साफ हैं तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें छोड़ क्यों नहीं रहा है? कुछ तो गड़बड़ होगी ही। कुल मिलाकर बयानों का तीखापन यहाँ- वहाँ आने लगा है। लोकसभा चुनाव के प्रचार में धार आ गई है। यह धार दिन ब दिन और पैनी होती जाएगी। भारत के केनवास पर शांति, प्रेम, ईमानदारी, विकास और सह-अस्तित्व के रंगों की जरूरत है, पर आज इंडिया गठबंधन इन रंगों को भरने की पात्रता खोकर नायकविहीन है। रंगमंच पर नायक अभिनय करता है, राजनीतिक मंच पर नायक के चरित्र को जीना पड़ता है, कथनी-करनी में समानता, दृढ़ मनोबल, इच्छा शक्ति और संयमशीलता के साथ। लेकिन भारतीय लोकतंत्र की यह एक बड़ी विडम्बना है कि यहां विपक्षी दलों में नायक कम, खलनायक अधिक है। तभी एक मोदी अठाइस दलों के नेताओं पर भारी पड़ रहा है। देखना यह है कि विपक्षी दलों ने राजनीतिक भ्रष्टाचार का मामला उठाकर मोदी सरकार को घेरने की जो कोशिश की, उससे देश की जनता कितनी प्रभावित होगी और इसकी आवश्यकता महसूस करेगी या नहीं कि इस गठबंधन को सत्ता में लाना आवश्यक है। विपक्षी दलों ने जो मुद्दे उठाये, वे प्रभाव पैदा नहीं कर पाये। चुनावी बांड का ही मुद्दा ले, इसमें संदेह नहीं कि चुनावी बांड से दिए जाने वाले चंदे का जो विवरण सामने आया है, उससे अनेक गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जिन कंपनियों का नाम लेकर यह कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने उन पर अनुचित दबाव डालकर चंदा हासिल किया, उनमें से अनेक ने विपक्षी दलों को भी अच्छा-खासा चंदा दिया है।

क्या इस बार कच्चातिवु द्वीप बनेगा दक्षिण का चुनावी मुद्दा?

अशोक भाटिया

आरटीआई से मिले जवाब के बाद तमिलनाडु में कच्चातिवु द्वीप श्रीलंका को सौंपे जाने का मुद्दा गरमा गया है। फ्ळककेके मुताबिक, 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के। अन्नामलाई ने द्वीप को लेकर एक फ्ळककआवेदन दिया गया था, जिसका जवाब सामने आने के बाद सियासी घमासन मच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उत्तर प्रदेश के मेरठ से अपने लोकसभा चुनाव अभियान की शुरूआत के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर विपक्ष को घेरा। उन्होंने कच्चाथीवू द्वीप का जिक्र कर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल के दौरान इस द्वीप को लेकर श्रीलंका के साथ समझौता किया गया था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, आंखें खोलने वाली और चौंका देने वाली बात। नए तथ्यों से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से कच्चातिवु द्वीप को छोड़ दिया। इससे हर भारतीय नाराज है और लोगों के मन में यह बात बैठ गई है कि हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना 75 सालों से कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा है।

वैसे भी भारतीय प्रधानमंत्री पहले भी कच्चातिवुद्वीप को लेकर कांग्रेस पर आक्रामक रहे हैं और उन्होंने पिछले साल अगस्त महीने में भी कच्चातिवुद्वीप का जिक्र कर कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश की थी।अब तो रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने अपनी मेरठ कि सभा में हुनकर भरी कि कैसे कांग्रेस और इंडी अलायंस देश की अखंडता और देश की एकता को तोड़ते रहे हैं। आज ही कांग्रेस का एक और देश विरोधी कारनामा देश के सामने आया है। तमिलनाडु में भारत के समुद्री तट से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समुंदर में एक टापू है, एक द्वीप है कच्चाथीवू अलग-अलग नाम भी लोग बोलते हैं। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है लेकिन कांग्रेस ने चार-पांच दशक पहले इसे यह कह कर दे दिया कि ये द्वीप गैर-जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। इन्होंने मां भारती का एक अंग काट दिया और भारत से अलग कर दिया। देश कांग्रेस के रवैये की कीमत आज तक चुका रहा है। गौरतलब है कि अगस्त 2023 मेंप्रधानमंत्री मोदी ने इस ट्वीप का जिक्र करते हुए कहा था, कि ₹कांग्रेस का इतिहास मां भारती को छिन्न-भिन्न करने का रहा है ।इस बात का खुलासा भाजपा तमिलनाडु प्रमुख के अन्नामलाई की तरफ से दस्तावेजों के खुलासे के बाद आया है, जिससे यह संकेत मिलता है, कि कांग्रेस ने कभी भी छोटे, निर्जन द्वीप को ज्यादा महत्व नहीं दिया। रिपोर्ट के अनुसार, जवाहरलाल नेहरू ने एक बार यहां तक कहा था, कि वह ₹द्वीप पर अपना दावा छोड़ने₹ में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे।

यह कहानी नई नहीं है और जिन परिस्थितियों में इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत ने 1974 में कच्चातिवुपर अपना दावा छोड़ दिया था, उसे अच्छी तरह से समझना जरूरी है। हालांकि, भाजपा के तमिलनाडु अभियान ने इसे राज्य के सबसे गर्म राजनीतिक विषयों में से एक बना दिया है। आइये जानते हैं, कि कच्चातिवुद्वीप को लेकर विवाद क्या है, खासकर तमिलनाडु राज्य की राजनीति में इस विषय पर एक बार फिर से राजनीति क्यों गर्म है?

कच्चातिवु द्वीप हिंद महासागर में भारत के दक्षिण छोर पर है। 285 एकड़ में फैला यह द्वीप भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में बना हुआ है। 17वीं शताब्दी में यह द्वीप मदुरई के राजा रामानंद के अधीन था। अंग्रेजों के शासनकाल में कच्चातिवु द्वीप मद्रास प्रेसीडेंसी के पास आया। उस दौर में यह द्वीप मछलीपालन के लिए अहम स्थान रखता था। यही वजह थी कि भारत और श्रीलंका दोनों मछली पकड़ने के लिए इस द्वीप पर अपना-अपना दावा करते थे। आजादी के बाद समुंद्र की सीमा को लेकर 1974-76 के बीच 4 समझौते किए गए थे। समझौते के तहत भारतीय मछुआरों को द्वीप पर आराम करने और जाल सुखाने में इजाजत की गई और यह द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया गया।

यह द्वीप भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में बना हुआ है। साल 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका की राष्ट्रपति श्रीमावो भंडारनायके के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के तहत इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को कच्चातिवु द्वीप सौंप दिया था। इस समझौते को लेकर 26 जून को कोलंबो और 28 जून को दिल्ली में दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी। बैठक के बाद ही कुछ शर्तों के साथ इस द्वीप को श्रीलंका को सौंपा गया। शर्त यह रखी गई थी कि भारतीय मछुआरे इसका इस्तेमाल जाल सुखाने और आराम करने के लिए करते रहेंगे। यह भी कहा गया था कि इस द्वीप पर बने चर्च में भारतीयों को बिना वीजा जाने की इजाजत नहीं होगी। और न ही भारतीय मछुआरे यहां पर मछलियां पकड़ सकेंगे।

जब इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को यह द्वीप सौंपा को सबसे ज्यादा विरोध तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि इसका पुरजोर विरोध किया था। इसको लेकर साल 1991 में तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव में उस द्वीप को वापस लेने की मांग की गई। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। साल 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कच्चातिवु द्वीप को लेकर हुए समझौते को अमान्य घोषित करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि तोहफे में इस द्वीप को श्रीलंका को देना असंवैधानिक है ।कच्चातिवु द्वीप को लेकर समय-समय पर सियासी घमासान हुआ। 2011 में जब जयललिता दोबारा तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनीं तो उन्होंने विधानसभा में इसको लेकर प्रस्ताव पास कराया।

जब श्रीलंका में गृहयुद्ध चल रहा था उस दौरान श्रीलंकाई नौसैनिक बल, जाफना से बाहर स्थित लिट्टे की सप्लाई चेन को काटने के काम में व्यस्त थे, इसलिए भारतीय मछुआरों के लिए श्रीलंकाई जलक्षेत्र में जाना आम बात बन गई थी। जिसकी वजह से श्रीलंकाई मछुआरों में काफी नाराजगी रहती थी, क्योंकि बड़े भारतीय ट्रॉलर जहाज ना सिर्फ काफी ज्यादा मछलियां पकड़ते थे, बल्कि श्रीलंकाई मछली पकड़ने के जाल और उनकी नावों को भी नुकसान पहुंचाते थे। साल 2009 श्रीलंकाई गृहयुद्ध खत्म हो गये और उसके बाद नाटकीय अंदाज में स्थितियां बदलने लगीं। कोलंबो ने अपनी समुद्री सुरक्षा बढ़ानी शुरू कर दी और भारतीय मछुआरों पर अब उन्होंने कार्रवाई करनी शुरू कर दी। भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारियां शुरू हो गईं और कच्चातिवुद्वीप के आसपास श्रीलंका ने भारतीय मछुआरों के मछली पकड़ने पर सख्ती से रोक लगानी शुरू कर दी।

आज तक, श्रीलंकाई नौसेना नियमित रूप से भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार करती है और हिरासत में टॉर्चर करती है, जिसकी वजह से कई मछुआरों की मौत हो चुकी है। जब जब मछुआरों की मौत होती है, कच्चातिवुद्वीप को फिर से भारत में मिलाने की मांग उठने लगती है। लिहाजा, कच्चातिवुद्वीप को लेकर तामिलनाडु की राजनीति गर्म हो जाती है। भारत के दिग्गज विदेश नीति एक्सपर्ट ब्रह्मा चेलानी ने कच्चातिवुद्वीप को श्रीलंका को देना भारत की बड़ी रणनीतिक भूल बताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, कि ₹कच्चातिवुएक छोटा सा द्वीप हो सकता है, लेकिन सीमाओं को लेकर भारत के प्रधानमंत्रियों के उदारता का एक लंबा रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने कहा है, कि ₹मणिपुर की कबाव घाटी और सिंधु जल का बड़ा हिस्सा उपहार में देने से लेकर 1954 में तिब्बत में अपने अलौकिक अधिकारों को छोड़ने और फिर 2003 में औपचारिक रूप से अपना महत्वपूर्ण तिब्बत कार्ड छोड़ने से लेकर तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को चीन के हिस्से के रूप में मान्यता देना, भारत के प्रधानत्रियों के उदारता का ये एक लंबा रिकॉर्ड है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है, कि भारतीय कूटनीति के भोलेपन का उदाहरण 1972 का शिमला समझौता है, जिसके तहत भारत ने बगैर कुछ हासिल किए बातचीत की टेबल पर युद्ध में जो लाभ मिला था, उसे गंवा दिया। ब्रह्मा चेलानी ने अपने ट्वीट में लिखा है, कि ₹भारत अपने इतिहास को फिर से याद कर रहा है, क्योंकि मोदी सहित लगभग हर भारतीय प्रधान मंत्री ने शासन-कला की अनिवार्यताओं को सीखने या पिछली भूलों से सबक लेने के बजाय, विदेश-नीति के पहिये को फिर से बनाने की कोशिश की है। उनका इशारा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में, गलवान घाटी हिंसा होने तक चीन को लेकर अपनाए गये रणनीति को लेकर था, जब मोदी सरकार ने चीन से शांति के लिए लगातार बैठकें की थी। खुद प्रधानमंत्री मोदी चीन गये थे और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भारत दौरे के दौरान भव्य स्वागत किया गया था। लेकिन, सरकार को उस वक्त चीनी मकसद का अहसास हुआ, जब गलवान घाटी में चीनी घुस आए और हिंसक झड़प में कई भारतीय सैनिक मारे गये।

अब जबकि चीन लगातार हिंद महासागर में घुसपैठ कर रहा है, लिहाजा कच्चातिवु द्वीप अब रणनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण हो गया है और सरकार से अपील की जा रही है, कि फिर से कच्चातिवु द्वीप पर भारत अपना दावा करे। फिलहाल, इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी से इतर कुछ और होने की संभावना नहीं है, लेकिन आगे भी कच्चातिवु पर दावा करना भारत के लिए आसान नहीं है, क्योंकि चीन ऐसे ही किसी मौके की तलाश में है, जब वो श्रीलंका को भारत के लिए भड़काकर हिंद महासागर में कोई और ड्रामा कर सके। अब लोकसभा चुनाव के बीच एक बार फिर यह द्वीप बहस का विषय बन गया है। जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री ने हाल ही में ट्वीट किया है।

बेटियों को भी मिले उचित सम्मान

-रमेश सर्राफ धमोरा

आज हर क्षेत्र में बालिकाओं के आगे बढने के बावजूद भी वह अनेको कुरीतियों की शिकार हैं। ये कुरीतियों उनके आगे बढने में बाधाएं उत्पन्न करती है। पढ़े-लिखे लोग और जागरूक समाज भी इस समस्या से अछूता नहीं है। देश में आज भी प्रतिवर्ष लाखों लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही कोख में मार दिया जाता है। आज भी समाज के अनेक घरों में बेटा, बेटी में भेद किया जाता है। बेटियों को बेटों की तरह अच्छा खाना और अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती है। समाज में आज भी बेटियो को बोझ समझा जाता है।

हमारे देश में यह एक बड़ी विडंबना है कि हम बालिका का पूजन तो करते हैं। लेकिन जब हमारे खुद के घर बालिका जन्म लेती है तो हम दुखी हो जाते हैं। देश में सभी जगह ऐसा देखा जा सकता है। देश के कई प्रदेशों में तो बालिकाओं के जन्म को अभिशाप तक माना जाता है। लेकिन बालिकाओं को अभिशाप मानने वाले लोग यह क्यों भूल जाते हैं कि वह उस देश के नागरिक हैं जहां रानी लक्ष्मीबाई जैसी विरांगनाओं ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे।

हमारे यहां आज भी बेटी पैदा होते ही उसकी परवरिश से ज्यादा उसकी शादी की चिन्ता होने लगती है। आज महंगी होती शादियों के कारण बेटी का बाप हर समय इस बात को लेकर चिंतित नजर आता है कि उसकी बेटी की शादी की व्यवस्था कैसे होगी। समाज में व्याप्त इसी सोच के चलते कन्या भ्रूण हत्या पर रोक नहीं लग पायी है। कोख में कन्याओ को मार देने के कारण समाज में आज लड़कियों की काफी कमी होने से लिंगानुपात गड़बड़ा गया है।

पिछले कुछ वर्षों में देश में जन्म के समय लिंगानुपात में बढ़ोतरी होना शुभ संकेत हैं। संसद में एक सवाल का जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बताया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने बालिकाओं के अधिकारों को स्वीकार करने के लिए जनता की मानसिकता को बदलने की दिशा में सामूहिक चेतना जगाई है। इस योजना ने भारत में सीएसआर (बाल लिंग अनुपात) में गिरावट के मुद्दे पर चिंता जताई है। यह राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) में 15 अंकों के सुधार के रूप में परिलक्षित होता है। जो कि 2014 में 918 था। जबकि 2022-23 में 15 अंक बढ़कर 933 हो गया।

अगर समाज में बेटियों को उचित शिक्षा और सम्मान मिले तो बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नही रहेगी। इसलिए यदि यह कहा जाय की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना नही हम सबकी एक जिम्मेदारी है तो इसमें कुछ गलत नही है। यदि हम सभी एक अच्छे समाज का निर्माण करना चाहते है तो हम सबका यही फर्ज बनता है हम इन बेटियों को भी भयमुक्त वातावरण में पढ़ाये। उन्हें इतना सशक्त बनाये की खुद गर्व से कह सके की देखो वह हमारी बेटी है जो इतना बड़ा काम कर रही है।

भारत में हर साल तीन से सात लाख कन्या भ्रूण नष्ट कर दिये जाते हैं। इसलिए यहां महिलाओं से पुरुषो की संख्या 5 करोड़ ज्यादा है। समाज में निरंतर परिवर्तन और कार्य बल में महिलाओं की बढ़ती भूमिका के बावजूद रूढिवादी विचारधारा के लोग मानते हैं कि बेटा बुढ़ापे का सहारा होगा और बेटी हुई तो वह अपने घर चली जायेगी। बेटा अगर मुखाग्नि नहीं देगा तो कर्मकांड पूरा नहीं होगा।

आज लड़किया लड़को से किसी भी क्षेत्र में कमतर नहीं हैं। कठिन से कठिन कार्य लड़किया सफलतापूर्वक कर रही हैं। देश में हर क्षेत्र में महिला शक्ति को पूरी हिम्मत से काम करते देखा जा सकता है। लड़कियों ने अपने काम और समर्पण के दम पर कई क्षेत्रों और क्षेत्रों में खुद को साबित किया है। वे अधिक प्रतिभाशाली, आज्ञाकारी, मेहनती और परिवार और अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। लड़कियाँ अपने परिवार और माता-पिता के प्रति अधिक देखभाल करने वाली और प्यार करने वाली होती हैं और वे हर काम में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देती हैं। देश की अर्थव्यवस्था में भी महिलाओं का अहम योगदान है। वे श्रम शक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और व्यवसायों की वृद्धि और विकास में योगदान देती हैं।

एक तरफ जहां बेटी को जन्मते ही मरने के लिये लावारिश छोड़ दिया जाता है। वहीं झुंझुनू जिले की मोहना सिंह जैसी बालिकायें भी है जो आज देश में फाईटर प्लेन उड़ा कर पूरे देश में जिले का मान बढ़ा रही हैं। समाज में सभी को मिलकर लडका-लडकी में भेद नहीं करने व समाज के लोगों को लिंग समानता के बारे में जागरूक करने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। बालिकाओं का कोख में तो कत्ल कर उन्हे धरती पर आने से पहले ही मारा जा रहा है। उससे भी घिनोना काम जिन्दा बालिकाओं के साथ किया जा रहा है। देश में बालिकाओं के साथ हर दिन बलात्कार, प्रताडना की घटनायें अखबारो की सुर्खिया बनती हैं। बालिकायें कही भी अपने को सुरक्षित नहीं समझती हैं। चाहे घर हो या स्कूल अथवा कार्य स्थल। हर जगह वहशी भेडिये उन पर नजरे गड़ायें रहते हैं। उन्हे जब भी मौका मिलता है नोंच डालते हैं। ऐसे माहौल में देश की बालिकायें कैसे आगे बढ़ पायेगीं।

समाज के पढ़े लिखे लोगों को आगे आकर कन्या भ्रूण हत्या जैसे घिनोने कार्य को रोकने का माहौल बनाना होगा। ऐसा करने वाले लोगों को समझा कर उनकी सोच में बदलाव लाना होगा। लोगों को इस बात का संकल्प लेना होगा कि ना तो गर्भ में कन्या की हत्या करेगें ना ही किसी को करने देगें। तभी देश में कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लग पाना संभव हो पायेगा।

सरकार व समाज को मिलकर ऐसे वातावरण का निर्माण करने का प्रयास करना चाहिये जिसमें बालिकायें खुद को महफूज समझ सकें। बालिकाओं पर अत्याचार करने वालों के मन में भय व्याप्त करने के लिये सरकार को कानून में और अधिक सुधार करना चाहिये। बालिकाओं को कई प्रकार के भेदभाव का शिकार होना पड़ता है।

समाज और राष्ट्र के विकास के लिए बालिकाओं के महत्व को स्वीकार करना और बढ़ावा देना आवश्यक है। शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है। एक शिक्षित लड़की ही अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान दे सकती है। कानूनी सुरक्षा बालिकाओं के अधिकारों की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जागरूकता कार्यक्रमों और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से लड़कियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने के लिए भी उतना ही आवश्यक है।

हमारे समाज का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज अपनी बच्चियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और उन्हें कितना महत्व देते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कानूनी सुरक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से बालिकाओं को सशक्त बनाना न केवल एक नैतिक दायित्व है बल्कि सामाजिक विकास के लिए एक जरूरी आवश्यकता भी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लड़कियों को आगे बढ़ने, सीखने के समान अवसर मिले। तभी हम एक संतुलित, न्यायसंगत और समृद्ध समाज बना सकेगें। हम सभी जानते हैं कि एक लड़की समाज के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। वह एक मा, एक बेटी, एक पत्नी इस तरह कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। उसे घर की शांति बनाए रखने वाली स्तंभ माना जाता है और फिर भी उसका अपमान किया जाता है। स्त्रियां ही संतति की परम्परा में मुख्य भूमिका निभाती है फिर भी प्राचीन समाज से लेकर आधुनिक कहे जाने वाले समाज तक स्त्रियां उपेक्षित ही रही है। उन्हें कम से कम सुविधाओं, अधिकारों और उन्नति के अवसरों में रखा जाता रहा है, इसी कारण महिलाओं की परिस्थिति अत्यन्त निचले स्तर पर है।

विस्तारवाद की चाहत के लिए खतरनाक वैश्विक युद्ध की आशंका

संजीव ठाकुर

अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी के अनुसार अमेरिकी अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरस ने सचेत किया है कि रूस और चीन का सीमा विहीन गठबंधन वैश्विक शांति एवं सभ्यता के लिए खतरनाक हो सकता है। यदि पुतिन और शी जिनपिंग के बीच का गठजोड़ रूस यूक्रेन युद्ध में कारगर साबित होता है तो विश्वयुद्ध की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और विश्व युद्ध वर्तमान की मानवीय सभ्यता के लिए एक गतिहीन अवरोध होगा। इस अरबपति अमेरिकी निवेशक जॉर्ज सोरस ने दावोस में अपने वार्षिक प्रतिवेदन में कहा है कि दुनिया को इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए और इसमें पूरे संसाधन झोंक देने चाहिए। वैश्विक सभ्यता को संरक्षित, पल्लवित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ और संभवत एकमात्र तरीका पुतिन को जल्द से जल्द हराना होगा। यह हमला तीसरे विश्वयुद्ध की शुरूआत कर सकता है और हमारी सभ्यता इसे झेल नहीं पाएगी और तहस-नहस हो जाएगी। दावा किया गया है कि पुतिन ने शी जिनपिंग को पहले से ही बता दिया था और दोनों नेताओं की बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मुलाकात भी हुई थी दोनों ने एक लंबा बयान जारी कर घोषणा की थी कि उन दोनों के बीच संबंधों की और सहयोग की कोई सीमा नहीं है। पुतिन ने सी जिनपिंग को यूक्रेन के विरुद्ध विशेष सैन्य अभियान की जानकारी भी दे दी थी। तब शी जिनपिंग ने पुतिन से ओलंपिक खेलों के होते तक सैन्य अभियान रोकने की बात कही थी। इसी बीच रूस के एक राजदूत ने इस्तीफा देकर पुतिन की इस कार्रवाई का खुलकर विरोध किया था और युद्ध में मारे गए सैनिकों के परिवार ने भी रूस में अपना विरोध दर्ज किया है। पुतिन को अपनी गलतियों का अब धीरे-धीरे एहसास हो रहा है जब यूक्रेन में रहने वाले रूसी भाषा के नागरिकों ने यूक्रेन पर हमले की घोर निंदा की है जबकि पुतिन को उनके समर्थन आशा थी जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। पुतिन को अब यह एहसास हो गया है कि उन्होंने यूक्रेन पर आक्रमण करके एक बड़ी गलती की है। अब वह संघर्ष विराम के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने में लगे हैं जो वर्तमान संदर्भों में संभव नहीं है। क्योंकि विश्व समुदाय का रूस पर भरोसा खत्म हो चुका है। अब या तो पुतिन अपनी हार छुपाने के लिए चाइना की मदद विश्व युद्ध लेंगे या फिर अपनी हार स्वीकार कर अपने पद से इस्तीफा देकर पलायन कर जाएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध मैं आज तक कुल मिलाकर 30 लाख करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं और युद्ध खत्म होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। अमेरिका सहित नैटो देश के सदस्य और अन्य यूरोपीय सदस्य लगातार यूक्रेन की आर्थिक तथा सामरिक मदद करते आ रहे हैं और इस स्थिति में रूस ही कमजोर नजर आ रहा है क्योंकि रूस के तमाम कमांडर और सैनिकों का मनोबल अब लगातार गिरते जा रहा है, इसके पश्चात रूस के नागरिक भी इस युद्ध के अंदरूनी खिलाफ है जबकि यूक्रेन के नागरिक उसी हौसले और उत्साह के साथ अपने नेता जेलेंस्की के साथ खड़े हुए हैं। अब स्थिति यह है कि यूक्रेन के पास ना तो पैसे की कमी है ना ही हथियारों की,वह लगातार रूसी सैनिकों तथा कमांडरों का जमकर विरोध कर रहा है। ये अलग बात है कि मारियोपोल मैं इमारतों के मलबे के निकालने के पश्चात अलग-अलग जगह से चार पांच सौ दबे हुए शव को निकाला गया है। जिससे वहां जनता के बीच हाहाकार मच गया है। इस युद्ध की विभीषिका से यूक्रेन के लगभग एक करोड़ नागरिक यूक्रेन छोड़कर पोलैंड एवं अन्य देशों में शरण लेकर शरणार्थियों की तरह जीवन यापन कर रहे हैं। यूरोपीय देश इन शरणार्थियों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए कृत संकल्प हैं और उन्हें किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। वैश्विक राजनीति में चीन और रूस सर्वथा अलग-थलग पड़ गए हैं। ताजा स्थिति के अनुसार अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान और भारत में टोक्यो सम्मेलन में चीन के बढ़ते औपनिवेशिक वाद के खतरे को भांपते हुए प्रशांत महासागर एवं तीन पेसिफिक क्षेत्र में सैन्य अभ्यास के लिए गठजोड़ कर लिया है। इसी तरह चीन के व्यापारिक फायदों को नुकसान पहुंचाने हेतु अमेरिका ने 13 देशों का एक आर्थिक समूह तैयार कर चीन को वैश्विक राजनीति और आर्थिक योजनाओं से अलग अलग कर दिया है। चीन अब क्वाड सम्मेलन को अपना विरोधी बताकर लद्दाख में अपनी सैन्य तैयारियां भारत के विरुद्ध बढ़ाने में लग गया है। 13 देशों के आर्थिक समुदाय ने भी चीन को एक खुला संदेश देकर चुनौती दे दी है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका तथा चीन के विरुद्ध आर्थिक क्षेत्र तथा सामरिक क्षेत्र में खुली प्रतिस्पर्धा मैदान में आ गई है। अमेरिका वैसे भी पूर्व से ही रूस का विरोधी रहा है अब अमेरिका चीन तथा रूसी गठबंधन को आने वाले समय के लिए एक बड़ा खतरा मानते पूरे विश्व को इन दोनों के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। वैश्विक शांति और सभ्यता को नष्ट होने से बचाने के लिए इन दोनों देशों पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक भी है।

(लघु कहानी) “जुनून”

एक छोटे से गाँव में एक निर्धन किसान रहता था ।वह बहुत मेहनती और ईमानदार था ।वह पढ़-लिखकर एक बड़ा आदमी बनना चाहता था,लेकिन वह पैसे की कमी की वजह से केवल आठवीं तक ही पढ़ पाया था ।उसकी कम उम्र में ही शादी हो जाने और पैसे की कमी के कारण वह आगे की पढाई नहीं कर सका,जिसका उसे सदा बहुत अफसोस रहता था ।उसके घर में कई वर्ष बीत जाने के बाद जब लड़का पैदा हुआ,तब वह अपने मन में ठान लिया कि वह अपने लड़के को पढ़ा-लिखाकर एक बड़ा आदमी बनायेगा ।वह बचपन से ही अपने लड़के के मन में अपनी अधूरी ईच्छा के बारे में हमेशा बताया करता था,ताकि उसके अंदर पढ़ने का ₹जूनून₹ पैदा हो सके ।वह अपनी क्षमता से आगे बढ़कर लड़के का एडमिशन सरकारी स्कूल में न करवाकर एक अच्छे प्राईवेट स्कूल में करवा दिया ।उसके पढ़ाई का खर्च खेती से पूरा न होने स्थिति में वह खाली समय में मजदूरी करने लगा ।इस तरह वह अपने लड़के को बारहवीं तक पढ़ा लिया ।उसके आगे की पढ़ाई के लिए किसी बड़े शहर में भेजने के लिए उसके पास पैसे नहीं हो पा रहे थे ।ऐसी स्थिति में एक सज्जन व्यक्ति के सलाह से वह तकनीकी शिक्षा हासिल करवा दिया और लड़का अच्छी तैयारी कर सरकारी नौकरी प्राप्त कर लिया और अपने पिता जी के सारे सपने को साकार कर दिया ।अब उसके पास वो सब कुछ है,जो पहले उसके पास नहीं था।

शिक्षा- इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए मन में ठान ले और जुनून पैदा कर ले,तो उसे सफलता जरूर मिलती है।

-रजनीश राज

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

विपक्ष की रैली का संदेश

दिल्ली के रामलीला मैदान से विपक्षी गठबंधन कठ.ऊकअ ने हुंकार भरी। विपक्ष की लोकतंत्र बचाओ महारैली में तमाम विपक्षी नेता शामिल हुए। इस महारैली में अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग तो उठी ही, साथ ही सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को विपक्षी गठबंधन कठ.ऊकअ. की रैली में जुटी भीड़ को लेकर जो भी दावे और प्रतिदावे हों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनाव के ठीक पहले विपक्षी दलों ने इसके जरिए अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने की काफी हद तक कामयाब कोशिश की है। लगभग सभी प्रमुख दलों के बड़े नेता इसमें शामिल हुए और सबने मोटे तौर पर सत्ता पक्ष की कथित ज्यादतियों और लोकतंत्र पर हो रहे हमलों के इर्दगिर्द ही बातें रखीं।

रुपेश कुमार सिंह
संपादक
चौथी वाणी

अंतर्विरोध की छाया : वैसे, I.N.D.I.A. के घटक दलों के आपसी अंतर्विरोध की छाया भी रैली पर इस रूप में दिखी कि इसके मुख्य मकसद को लेकर दो तरह की बातें सामने आईं। आम आदमी पार्टी की तरफ से जहां इसका मकसद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करना बताया गया, वहीं कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि विरोध किसी खास व्यक्ति से जुड़ा नहीं बल्कि मौजूदा सरकार की तानाशाही के खिलाफ केंद्रित है।

रैली की टाइमिंग : यह रैली ऐसे समय हुई, जब महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक तमाम राज्यों में टिकट बंटवारे के सवाल पर कठ.ऊकअ. से जुड़े दलों की आपसी खटपट की खबरें आ रही थीं। भले ही ये विवाद गिनी-चुनी सीटों को लेकर थे, नैरेटिव ऐसा बन रहा था कि चुनाव सिर पर आने के बाद भी I.N.D.I.A. से जुड़े दल एकजुट नहीं हो पा रहे। रामलीला मैदान की रैली के जरिए इन दलों ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि बड़े मुद्दों पर वे एक स्वर में बोल सकते हैं।

राजनीतिक पहलू : जहां तक एऊ और अन्य एजेंसियों की कार्रवाई का सवाल है तो इसमें दो राय नहीं कि इन पर सरकार का और इन एजेंसियों का अपना पक्ष है, लेकिन इसके बावजूद चुनाव के ठीक पहले राज्यों के निर्वाचित मुख्यमंत्रियों के खिलाफ इस तरह के सख्त कदम अभूतपूर्व हैं और इनके राजनीतिक पहलू भी हैं।

रिव्यू पिटिशन : यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि 2005 से अब तक एऊ के दर्ज किए 5,906 केसों में से मात्र 25 निपटाए जा सके हैं। पिछले 17 वर्षों में 0.42% मामलों का निपटना इस शिकायत को दमदार बनाता है कि इन मामलों में प्रक्रिया ही सजा का रूप लेती जा रही है। यही नहीं, जिस ढटछअ के तहत राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसके सख्त प्रावधानों पर न केवल तीखी बहस है बल्कि उस कानून के खिलाफ रिव्यू पिटिशन भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

निष्पक्षता का तकाजा : सवाल उठता है कि क्या एजेंसियों को चुनाव होने तक विपक्षी दलों और नेताओं के खिलाफ अतिवादी कदमों से परहेज करना चाहिए और क्या चुनाव आयोग को इस तरह का कोई निर्देश जारी करना चाहिए? इस पर गंभीरता से विचार करना इसलिए भी जरूरी है कि क्योंकि किसी लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने ही नहीं चाहिए, होते हुए दिखने भी चाहिए।

आओ दिव्यांगजनों को सम्मानजनक भाव वाले नजर से आत्मियता रख चुनौतियों में उनकी मदद करें

चुनाव आयोग द्वारा दिव्यांगजनों के लिए सम्मानजनक भाव रखने,राजनीतिक दलों के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन जरूरी

दिव्यांगजनों की चुनौतियों का समाधान करने कार्यवाही उन्मुख, समयबद्ध,दृढ़ प्रतिबद्ध समाधान करना समय की मांग : एडवोकेट किशन भावनानी

लेखक
किशन सनमुखदास भावनानी
गोंदिया (महाराष्ट्र)

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर दिव्यांगजनों को विकलांगता शब्द के रूप में जाना जाता है।अधिकांश विकसित देशों में विकलांगता को मानव जीवन का हिस्सा माना जाता है। ऐसे समाज में ऐसी व्यवस्थाएँ की जाती हैं कि एक विकलांग व्यक्ति भी रोजमर्रा की हर गतिविधि में हिस्सा ले सके। इन जगहों पर अमूमन लोग यह मानते हैं कि स्थाई या अस्थाई रूप से हर व्यक्ति अपने जीवन में विकलांगता को कभी-न-कभी महसूस करता है। यही कारण है कि यहाँ विकलांगता को एक सामान्य प्राकृतिक घटना की तरह देखा जाता है। गैर-विकसित और कम पढ़े-लिखे समाज में विकलांगता को विकलांग व्यक्ति की निजी समस्या के रूप में देखा जाता है। विकलांगता को अक्सर पूर्व जन्म के बुरे कर्मों से भी जोड़ दिया जाता है। ऐसे समाज में आधारभूत संरचनाओं को विकलांग लोगों के लिए सुगम्य बनाने पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसी जगहों पर विकलांगजन के पास कोई विशेषाधिकार भी नहीं होते।इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकलांगता एक सापेक्ष शब्द है जिसका अर्थ अलग-अलग व्यक्तियों के लिए अलग हो सकता है।परंतु भारत में इनका नाम दिव्यांग रूपी सम्मानजनक भाव वाले नजर से रखा गया है।सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत जागरूकता के लिए 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को शामिल किया गया है। अधिनियम में पूर्व में प्रचलित 7 प्रकार की दिव्यांगताओं के स्थान पर अब 21 प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल की गई है। अधिनियम के अंतर्गत दिव्यांगता के 21 प्रकार एवं उनके लक्षण जैसे चलन दिव्यांगता, बौनापन, मांसपेशी दुर्विकास, तेजाब हमला पीड़ित, दृष्टि बाधित, अल्पदृष्टि, श्रवण बाधित, कम, ऊंचा सुनना, बोलने एवं भाषा की दिव्यांगता, कुष्ठ रोग से मुक्त, प्रमस्तिष्क घात, बहु दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने की दिव्यांगता, स्वलीनता, मानसिकरूग्णता,बहु-स्केलेरोसिस पार्किंसंस, हेमोफिलिया, थेलेसीमिया, सिक्कल कोशिका रोग शामिल है। वैसे तो भारत में दिव्यांगजनों के सम्मान हेतु अनेक योजनाएं बनाई गई है जो केंद्र राज्य से लेकर जिला स्तर पर कार्यालय है भारतीय निर्वाचन आयोग ने भी अनेक स्तरों पर सुविधा दिव्यांगजनों को प्रदान की है। परंतु चूंकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के नेतृत्व में दिव्यांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के छठे बैठक में अनेक योजनाओं कार्यों पर मंथन किया गया है और चुनाव आयोग द्वारा भी दिव्यांगों के लिए राजनीतिक दलों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, इसलिए आज हम मीडिया पीआईबी में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे दिव्यांगजनों की चुनौतियों का समाधान करने कार्यवाही उन्मुख समयबद्ध समाधान करना समय की मांग है। साथियों बात अगर हम दिनांक 21 दिसंबर 2023 को चुनाव आयोग द्वारा जारी राजनीतिक दलों के लिए दिशा निर्देशों की करें तो, दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं ये हैं (1) राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों को किसी भी सार्वजनिक बयान/भाषण के दौरान, अपने लेखन/लेख/आउटरीच सामग्री या राजनीतिक अभियान में निःशक्तता/दिव्यांगजनों पर गलत/अपमानजनक/निरादरयुक्त संदर्भों का उपयोग नहीं करना चाहिए।(2) राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों को किसी भी सार्वजनिक भाषण के दौरान, अपने लेखन/लेखों/राजनीतिक अभियान में मानवीय अक्षमता के संदर्भ में निःशक्तता/दिव्यांगजनों का या निःशक्तता/दिव्यांगजनों को निरूपित करने वाले शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए।(3)राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों को निःशक्तता/दिव्यांगता से संबंधित ऐसी टिप्पणियों से सख्ती से बचना चाहिए जो आक्रामक हो सकती हैं या रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों को कायम रख सकती हैं।(4)ऐसी भाषा, शब्दावली, संदर्भ, उपहास, अपमानजनक संदर्भ के उपयोग या दिव्यांगजनों का अपमान जैसा कि बिंदु (), () और () में उल्लिखित है, पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 92 के प्रावधान लागू हो सकते हैं।(5)भाषणों, सोशल मीडिया पोस्ट, विज्ञापनों और प्रेस विज्ञप्तियों सहित सभी प्रचार अभियान सामग्रियों की राजनीतिक दल के भीतर आंतरिक समीक्षा अवश्य की जानी चाहिए ताकि लोगों/ दिव्यांगजनों के प्रति सक्षमवादी भाषा, चाहे वह आक्रामक या भेदभावपूर्ण, सक्षमवादी भाषा के दृष्टांतों की पहचान और दोष सुधार की जा सके।(6) सभी राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए और अपनी वेबसाइट पर घोषित करें कि वे निःशक्तता एवं जेंडर की दृष्टि से संवेदनशील भाषा और शिष्ट भाषा का उपयोग करेंगे और साथ ही अंतर्निहित मानवीय समानता, समता, गरिमा और स्वायत्तता का सम्मान करेंगे।(7) सभी राजनीतिक दल सीआरपीडी (दिव्यांगजनों के अधिकारों पर कन्वेंशन) में उल्लिखित अधिकार-आधारित शब्दावली का उपयोग करेंगे और किसी भी प्रकार की अन्य शब्दावली के उपयोग से बचेंगे।(8) सभी राजनीतिक दल अपनेसार्वजनिक भाषणों/अभियानों/कार्यकलापों/कार्यक्रमों को सभी नागरिकों के लिए सुलभ बनाएंगे। (9) सभी राजनीतिक दल अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया विषय-वस्तु को डिजिटल रूप से अभिगम्य बनाएंगे, ताकि दिव्यांगजन सुगमतापूर्वक इंटरएक्शन कर सकें।(10) सभी राजनीतिक दल राजनीतिक प्रक्रिया के सभी स्तरों पर पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए दिव्यांगता पर एक प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान कर सकते हैं और

सक्षम भाषा के उपयोग से संबंधित दिव्यांगजनों की शिकायतों को सुनने के लिए नोडल प्राधिकारी नियुक्त करेंगे। (11) राजनीतिक दल पार्टी और जनता के व्यवहार संबंधी अवरोध को दूर करने और समान अवसर प्रदान करने के लिए सदस्यों और पार्टी कार्यकर्ताओं जैसे स्तरों पर अधिक दिव्यांगजनों को शामिल करने का प्रयास कर सकते हैं। साथियों बात अगर हम छठवीं केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठक की करें तो, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के सक्रिय नेतृत्व में दिव्यांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की छठी बैठक डीएआईसी, नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में ओडिशा, यूपी, गोवा, तमिलनाडु के प्रतिष्ठित मंत्रियों के साथ-साथ राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और विभिन्न संगठनों के प्रमुख प्रतिनिधियों ने भाग लिया, बैठक में दिव्यांगता क्षेत्र के केन्द्रीय मुद्दों को संबोधित किया गया, जिससे परिवर्तनकारी प्रगति के एक नए युग की शुरुआत हुई,विचार विमर्श में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन की स्थिति, सुगम्य भारत अभियान, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र परियोजना और दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के सशक्तिकरण के लिए डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा अभिनव पहल शामिल हैं। चर्चा में राज्य प्रतिज्ञाओं में उपयुक्त पदों की पहचान, उच्च समर्थन आवश्यकताओं वाले दिव्यांगजनों के लिए योजनाएं और प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में पर्पल फेस्ट जैसे त्योहारों का आयोजन भी शामिल था। मंत्री जी सशक्त मार्गदर्शन में, बोर्ड ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम को तेजी से लागू करने, राज्य नियमों को अधिसूचित करने और राज्य सलाहकार बोर्ड और जिला स्तरीय समितियों की स्थापना करने का आह्वान किया। जिला-स्तरीय न्यायालयों को नामित करने और दिव्यांगजनों के लिए स्वतंत्र आयुक्तों की नियुक्ति की अनिवार्यता का प्रभावशाली समर्थन किया गया।डीईपीडब्ल्यूडी सचिव ने इस बात पर बल दिया कि दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण एक सामूहिक जिम्मेदारी है, उन्होंने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सभी मंत्रालयों/विभागों के बीच सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने कई गुणा प्रभाव के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की वकालत की और दिव्यांगजनों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए कार्रवाई-उन्मुख, समयबद्ध समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। बोर्ड के सदस्यों ने दिव्यांगों का एक व्यापक डेटाबेस बनाने से लेकर दिव्यांगों के लिए एक समर्पित टीवी चैनल की स्थापना के प्रस्ताव तक बहुमूल्य सुझाव दिए। दिव्यांगजनों को केवल लाभ प्राप्तकर्ता के बजाय करदाता बनने में सक्षम बनाने की दृष्टि को प्रमुखता मिली।

सुरेश पचौरी के भाजपा में जाने के मायने

क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस में षड़यंत्रपूर्वक काम कर रहा एक गुट

चौथी वाणी: मध्य प्रदेश कांग्रेस के साथ ही देश भर में कांग्रेस के कद्दावर नेता के रुप में अपनी अलग पहचान रखने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी का अचानक से कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने से अनेक राजनीतिक प्रश्न उठ खड़े हुए हैं। इस घटना क्रम के राजनीतिक लोग अनेक मायने निकालने में लगे हुए हैं। सुरेश पचौरी मध्य प्रदेश की राजनीति में चार दशक से सक्रिय चेहरा है। उनका भी प्रदेश कांग्रेस में एक मजबूत गुट है, उनके कांग्रेस से जाने के बाद यह गुट अब भाजपा में जाकर कांग्रेस को धीरे-धीरे खोखला कर सकता है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है मध्य प्रदेश कांग्रेस में कि एक-एक कर कई बड़े नेता उसका हाथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम रहे हैं। इसके पीछे क्या षड़यंत्र पूर्वक एक गुट मध्य प्रदेश कांग्रेस में काम कर रहा है ? यह वह सवाल है जो प्रदेश कांग्रेस की हालत देखकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कांग्रेस के कुछ नेताओं की उपेक्षा करना, नाराज नेताओं को न मनाना, उन्हें पार्टी की ओर से कोई काम न देना ये किसी षड़यंत्र के तहत ही किया जा रहा है। सुरेश पचौरी 1980 से लेकर 2018 तक प्रदेश कांग्रेस के मजबूत नेताओं में शुमार रहे। राजीव गांधी के दौर में उनका कद लगातार बढ़ता गया। इसी दौरान वे राज्यसभा में भेजे गए। भाषण शैली और अपनी बात को रखने में सुरेश पचौरी का कोई सानी नहीं हैं। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों पर जबरदस्त पकड़ रखने वाले पचौरी ने धीरे-धीरे राष्ट्रीय राजनीति में अपना दखल बढ़ाया। इसके चलते वे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री बनाए गए। उन्हें रक्षा उत्पादन का राज्यमंत्री बनाया गया था। इसके बाद वे मनमोहन सिंह की कैबिनेट में भी शामिल रहे। इस बार उन्हें कार्मिक और संसदीय कार्य राज्यमंत्री बनाया गया था। दोनों ही सरकार में उन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंपे गए थे। अपने 50 वर्ष के राजनीतिक सफर में वे भारतीय युवा कांग्रेस के महासचिव रहे। कांग्रेस सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। इन सब के साथ वे चार बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने उमा भारती के खिलाफ भोपाल लोकसभा से चुनाव भी लड़ा। अपने पचास साल के कांग्रेस में सफर के दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश में कई नेताओं को तैयार किया। इसमें प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एनपी प्रजापति, पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो सहित विधायक आरिफ मसूद, पूर्व विधायक शंशाक भार्गव, संजय शुक्ला, विशाल पटेल, सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी,महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा जैसे तमाम नेता उन्होंने प्रदेश भर में तैयार किए। इसके बाद भी ऐसे नेता की उपेक्षा करना, उन्हें उनकी काबिलियत के अनुसार काम न देना, उन्हें नजरअंदाज करना यह कई संकेत देता रहा।

पचौरी का मन बदलना आसान काम नहीं

सुरेश पचौरी कभी केंद्र में कांग्रेस के रणनीतिकारों में शामिल हुआ करते थे, लेकिन धीरे-धीरे पार्टी ने उन्हें हाशिये पर रखना शुरू किया। उनका अपना प्रभाव प्रदेश के ब्राह्मणों में हैं, पार्टी ने उनके इस प्रभाव को भी समझने का प्रयास नहीं किया। उनके समर्थकों को तवज्जो मिलना कम होती गई। उनकी सलाह के बगैर ही मध्य प्रदेश कांग्रेस में निर्णय होने लगे। पिछले 5 साल ये यही स्तिथि बनी हुई थी। इसलिए न वे, बल्कि उनसे जुडे़ कई नेता भी कांग्रेस के पूर्व और वर्तमान नेतृत्व से खफा होने लगे।

राज्यसभा में दिग्विजय सिंह ने दिया झटका

मध्य प्रदेश से राज्यसभा की चार सीटों को भरा जाना था, जिसमें से कांग्रेस के खाते में एक सीट आना थी। इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपने समर्थक अशोक सिंह को भेजने में सफलता पाई। जबकि अशोक सिंह का राजनीतिक कद प्रदेश की राजनीति में ऐसा नहीं हैं कि उसका फायदा कांग्रेस को मिल सके, इसके बाद भी सुरेश पचौरी, अरुण यादव जैसे दिग्गज नेताओं को दरकिनार कर दिग्विजय सिंह समर्थक को राज्यसभा में भेजा गया। पचौरी लंबे समय से पार्टी में उपेक्षित चल रहे थे। पचौरी के भाजपा में जाने के बाद दिग्विजय सिंह से खफा कई नेता भी अब भाजपा की तरफ जाने से परहेज नहीं करेंगे। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बीच में कांग्रेस में और बड़ी टूट देखने को मिल सकती है। खास बात यह है कि कांग्रेस में उपेक्षित चल रहे नेताओं को मनाने का काम पार्टी का कोई भी नेता नहीं कर रहा है। इससे साफ है कि कांग्रेस के ताकतवर नेता भी चाहते हैं कि पार्टी में उनका ही बोलबाला रहे और उनके विरोधी भाजपा का दामन थामते रहें।

छात्रों के लिए विज्ञान समाचार पत्रों के लाभ

विजय गर्ग

छात्रों के लिए विज्ञान समाचार पत्रों के कई लाभ हैं। इसमे शामिल है:

1. वैज्ञानिक साक्षरता बढ़ाना: विज्ञान समाचार पत्र छात्रों को वैज्ञानिक अनुसंधान और खोजों पर नवीनतम जानकारी प्रदान करते हैं। इससे उन्हें जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं और सिद्धांतों की बेहतर समझ विकसित करने में मदद मिलती है, और उन्हें विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में नवीनतम विकास के साथ अद्यतन रखा जाता है।

2. आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना: विज्ञान समाचार पत्र अक्सर ऐसे लेख प्रस्तुत करते हैं जिनमें छात्रों को वैज्ञानिक जानकारी का विश्लेषण और मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। यह महत्वपूर्ण सोच कौशल को बढ़ावा देता है क्योंकि छात्रों को स्रोतों की विश्वसनीयता का आकलन करने, अनुसंधान पद्धतियों की जांच करने और प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अपनी राय बनाने की आवश्यकता होती है।

3. कक्षा की शिक्षा को वास्तविक दुनिया से जोड़ना: विज्ञान समाचार पत्र कक्षाओं में प्राप्त सैद्धांतिक ज्ञान और वास्तविक दुनिया में इसके व्यावहारिक अनुप्रयोगों के बीच अंतर को पाटते हैं। वास्तविक जीवन के उदाहरणों और केस अध्ययनों के बारे में पढ़कर, छात्र देख सकते हैं कि चिकित्सा, इंजीनियरिंग और पर्यावरण विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक अवधारणाओं को कैसे व्यवहार में लाया जाता है।

4. विज्ञान के प्रति प्रेरक जिज्ञासा और जुनून: विज्ञान समाचार पत्र अक्सर प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के काम और उनकी अभूतपूर्व खोजों को उजागर करते हैं। छात्रों को इन उपलब्धियों से अवगत कराने से विज्ञान के बारे में उनकी जिज्ञासा प्रेरित और उत्तेजित हो सकती है, जिससे उन्हें वैज्ञानिक अनुसंधान या संबंधित क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

5. वैज्ञानिक संचार कौशल में सुधार: विज्ञान समाचार पत्र वैज्ञानिक जानकारी को सुपाच्य प्रारूप में प्रस्तुत करते हैं जो व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ है। इन लेखों को पढ़कर और उनका विश्लेषण करके, छात्र सीख सकते हैं कि स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा का उपयोग करके वैज्ञानिक अवधारणाओं को प्रभावी ढंग से कैसे संप्रेषित किया जाए।

6. अंतःविषय ज्ञान को बढ़ावा देना: विज्ञान समाचार पत्र जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान से लेकर भौतिकी और खगोल विज्ञान तक वैज्ञानिक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं। विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के लेख पढ़कर, छात्र अपने ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं और विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्र कैसे परस्पर क्रिया करते हैं और जुड़ते हैं, इसकी अधिक समग्र समझ विकसित कर सकते हैं।

7. सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना: विज्ञान समाचार पत्र अक्सर उन वैज्ञानिक मुद्दों को संबोधित करते हैं जिनका महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव होता है, जैसे जलवायु परिवर्तन, आनुवंशिक इंजीनियरिंग, या नए चिकित्सा उपचारों का विकास। इन विषयों पर ध्यान देकर, छात्र नवीनतम वैज्ञानिक बहसों के बारे में सूचित रह सकते हैं और महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर चर्चा में योगदान दे सकते हैं।

क्या इस बार कच्चातिवु द्वीप बनेगा दक्षिण का चुनावी मुद्दा?

आरटीआई से मिले जवाब के बाद तमिलनाडु में कच्चातिवु द्वीप श्रीलंका को सौंपे जाने का मुद्दा गरमा गया है। फळक के मुताबिक, 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के। अन्नामलाई ने द्वीप को लेकर एक फळकआवेदन दिया गया था, जिसका जवाब सामने आने के बाद सियासी घमासन मच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उत्तर प्रदेश के मेरठ से अपने लोकसभा चुनाव अभियान की शुरूआत के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर विपक्ष को घेरा। उन्होंने कच्चाथीवू द्वीप का जिक्र कर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल के दौरान इस द्वीप को लेकर श्रीलंका के साथ समझौता किया गया था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, आंखें खोलने वाली और चौंका देने वाली बात। नए तथ्यों से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से कच्चातिवु द्वीप को छोड़ दिया। इससे हर भारतीय नाराज है और लोगों के मन में यह बात बैठ गई है कि हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना 75 सालों से कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा है। वैसे भी भारतीय प्रधानमंत्री पहले भी कच्चातिवुद्वीप को लेकर कांग्रेस पर आक्रामक रहे हैं और उन्होंने पिछले साल अगस्त महीने में भी कच्चातिवुद्वीप का जिक्र कर कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश की थी।अब तो रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने अपनी मेरठ कि सभा में हुनकर भरी कि कैसे कांग्रेस और इंडी अलायंस देश की अखंडता और देश की एकता को तोड़ते रहे हैं। आज ही कांग्रेस का एक और देश विरोधी कारनामा देश के सामने आया है। तमिलनाडु में भारत के समुद्री तट से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समुंदर में एक टापू है, एक द्वीप है कच्चाथीवू अलग-अलग नाम भी लोग बोलते हैं। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है लेकिन कांग्रेस ने चार-पांच दशक पहले इसे यह कह कर दे दिया कि ये द्वीप गैर-जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। इन्होंने मां भारती का एक अंग काट दिया और भारत से अलग कर दिया। देश कांग्रेस के रवैये की कीमत आज तक चुका रहा है। गौरतलब है कि अगस्त 2023 मेंप्रधानमंत्री मोदी ने इस ट्वीप का जिक्र करते हुए कहा था, कि "कांग्रेस का इतिहास मां भारती को छिन्न-भिन्न करने का रहा है।इस बात का खुलासा भाजपा तमिलनाडु प्रमुख के अन्नामलाई की तरफ से दस्तावेजों के खुलासे के बाद आया है, जिससे यह संकेत मिलता है, कि कांग्रेस ने कभी भी छोटे, निर्जन द्वीप को ज्यादा महत्व नहीं दिया। रिपोर्ट के अनुसार, जवाहरलाल नेहरू ने एक बार यहां तक कहा था, कि वह "द्वीप पर अपना दावा छोड़ने" में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे। यह कहानी नई नहीं है और जिन परिस्थितियों में इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत ने 1974 में कच्चातिवुपर अपना दावा छोड़ दिया था, उसे अच्छी तरह से समझना जरूरी है। हालांकि, भाजपा के तमिलनाडु अभियान ने इसे राज्य के सबसे गर्म राजनीतिक विषयों में से एक बना दिया है।आइये जानते हैं, कि कच्चातिवुद्वीप को लेकर विवाद क्या है, खासकर तमिलनाडु राज्य की राजनीति में इस विषय पर एक बार फिर से राजनीति क्यों गर्म है? कच्चातिवु द्वीप हिंद महासागर में भारत के दक्षिण छोर पर है। 285 एकड़ में फैला यह द्वीप भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में बना हुआ है। 17वीं शताब्दी में यह द्वीप मदुरई के राजा रामानंद के अधीन था। अंग्रेजों के शासनकाल में कच्चातिवु द्वीप मद्रास प्रेसीडेंसी के पास आया। उस दौर में यह द्वीप मछलीपालन के लिए अहम स्थान रखता था। यही वजह थी कि भारत और श्रीलंका दोनों मछली पकड़ने के लिए इस द्वीप पर अपना-अपना दावा करते थे। आजादी के बाद समुंद्र की सीमा को लेकर 1974-76 के बीच 4 समझौते किए गए थे। समझौते के तहत भारतीय मछुआरों को द्वीप पर आराम करने और जाल सुखाने में इजाजत की गई और यह द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया गया। यह द्वीप भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में बना हुआ है। साल 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका की राष्ट्रपति श्रीमावो भंडारनायके के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के तहत इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को कच्चातिवु द्वीप सौंप दिया था। इस समझौते को लेकर 26 जून को कोलंबो और 28 जून को दिल्ली में दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी। बैठक के बाद ही कुछ शर्तों के साथ इस द्वीप को श्रीलंका को सौंपा गया। शर्त यह रखी गई थी कि भारतीय मछुआरे इसका इस्तेमाल जाल सुखाने और आराम करने के लिए करते रहेंगे। यह भी कहा गया था कि इस द्वीप पर बने चर्च में भारतीयों को बिना वीजा जाने की इजाजत नहीं होगी। और न ही भारतीय मछुआरे यहां पर मछलियां पकड़ सकेंगे। जब इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को यह द्वीप सौंपा को सबसे ज्यादा विरोध तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि इसका पुरजोर विरोध किया था। इसको लेकर साल 1991 में तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव में उस द्वीप को वापस लेने की मांग की गई। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। साल 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कच्चातिवु द्वीप को लेकर हुए समझौते को अमान्य घोषित करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि तोहफे में इस द्वीप को श्रीलंका को देना असंवैधानिक है।कच्चातिवु द्वीप को लेकर समय-समय पर सियासी घमासान हुआ। 2011 में जब जयललिता दोबारा तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनीं तो उन्होंने विधानसभा में इसको लेकर प्रस्ताव पास कराया। जब श्रीलंका में गृहयुद्ध चल रहा था उस दौरान श्रीलंकाई नौसैनिक बल, जाफना से बाहर स्थित लिट्टे की सप्लाई चेन को काटने के काम में व्यस्त थे, इसलिए भारतीय मछुआरों के लिए श्रीलंकाई जलक्षेत्र में जाना आम बात बन गई थी। जिसकी वजह से श्रीलंकाई मछुआरों में काफी नाराजगी रहती थी, क्योंकि बड़े भारतीय ट्रॉलर जहाज ना सिर्फ काफी ज्यादा मछलियां पकड़ते थे, बल्कि श्रीलंकाई मछली पकड़ने के जाल और उनकी नावों को भी नुकसान पहुंचाते थे। साल 2009 श्रीलंकाई गृहयुद्ध खत्म हो गये और उसके बाद नाटकीय अंदाज में स्थितियां बदलने लगीं। कोलंबो ने अपनी समुद्री सुरक्षा बढ़ानी शुरू कर दी और भारतीय मछुआरों पर अब उन्होंने कार्रवाई करनी शुरू कर दी। भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारियां शुरू हो गईं और कच्चातिवुद्वीप के आसपास श्रीलंका ने भारतीय मछुआरों के मछली पकड़ने पर सख्ती से रोक लगानी शुरू कर दी। आज तक, श्रीलंकाई नौसेना नियमित रूप से भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार करती है और हिरासत में टॉर्चर करती है, जिसकी वजह से कई मछुआरों की मौत हो चुकी है। जब जब मछुआरों की मौत होती है, कच्चातिवुद्वीप को फिर से भारत में मिलाने की मांग उठने लगती है। लिहाजा, कच्चातिवुद्वीप को लेकर तामिलनाडु की राजनीति गर्म हो जाती है। भारत के दिग्गज विदेश नीति एक्सपर्ट ब्रह्मा चेलानी ने कच्चातिवुद्वीप को श्रीलंका को देना भारत की बड़ी रणनीतिक भूल बताया है।उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, कि "कच्चातिवुएक छोटा सा द्वीप हो सकता है, लेकिन सीमाओं को लेकर भारत के प्रधानमंत्रियों के उदारता का एक लंबा रिकॉर्ड रहा है।" उन्होंने कहा है, कि "मणिपुर की कबाव घाटी और सिंधु जल का बड़ा हिस्सा उपहार में देने से लेकर 1954 में तिब्बत में अपने अलौकिक अधिकारों को छोड़ने और फिर 2003 में औपचारिक रूप से अपना महत्वपूर्ण तिब्बत कार्ड छोड़ने से लेकर तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को चीन के हिस्से के रूप में मान्यता देना, भारत के प्रधानत्रियों के उदारता का ये एक लंबा रिकॉर्ड है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है, कि "भारतीय कूटनीति के भोलेपन का उदाहरण 1972 का शिमला समझौता है, जिसके तहत भारत ने बगैर कुछ हासिल किए बातचीत की टेबल पर युद्ध में जो लाभ मिला था, उसे गंवा दिया।" ब्रह्मा चेलानी ने अपने ट्वीट में लिखा है, कि "भारत अपने इतिहास को फिर से याद कर रहा है, क्योंकि मोदी सहित लगभग हर भारतीय प्रधान मंत्री ने शासन-कला की अनिवार्यताओं को सीखने या पिछली भूलों से सबक लेने के बजाय, विदेश-नीति के पहिये को फिर से बनाने की कोशिश की है।"

लेखक
अशोक भाटिया
वसई पूर्व, मुंबई

प्रकाशक, संपादक, मुद्रक रूपेश कुमार सिंह, रैप एक्सप्रर्टस प्राइवेट लिमिटेड पटना द्वारा, कॉमी तंजीम पब्लिसर्स प्रा. लिमिटेड, अमीन मंजिल, सब्जीबाग, पटना-800004 से मुद्रित। ज्योति प्रकाश भवन, जकरियापुर एसएफसी कॉलोनी, जीरो माइल गंगा पेट्रोल पंप के नजदीक, पटना से प्रकाशित। संपर्क सूत्र ! 9835055017@7004145686] RNI NO&BIHHIN/2021/85413, RNI TITLE CODE : BIHHIN/11898

विपक्ष की एकजुटता कितनी असरदार

दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को विपक्षी गठबंधन की रैली में जुटी भीड़ को लेकर जो भी दावे और प्रतिदावे हों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनाव के ठीक पहले विपक्षी दलों ने इसके जरिए अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने की काफी हद तक कामयाब कोशिश की है। लगभग सभी प्रमुख दलों के बड़े नेता इसमें शामिल हुए और सबने मोटे तौर पर सत्ता पक्ष की कथित ज्यादतियों और लोकतंत्र पर हो रहे हमलों के इर्द गिर्द ही बातें रखीं। वैसे इंडिया के घटक दलों के आपसी अंतर्विरोध की छाया भी रैली पर इस रूप में दिखी कि इसके मुख्य मकसद को लेकर दो तरह की बातें सामने आईं। आम आदमी पार्टी की तरफ से जहां इसका मकसद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करना बताया गया, वहीं कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि विरोध किसी खास व्यक्ति से जुड़ा नहीं बल्कि मौजूदा सरकार की तानाशाही के खिलाफ केंद्रित है। यह रैली ऐसे समय हुई, जब महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक तमाम राज्यों में टिकट बंटवारे के सवाल पर इंडिया से जुड़े दलों की आपसी खटपट की खबरें आ रही थीं। भले ही ये विवाद गिनी-चुनी सीटों को लेकर थे, नैरेटिव ऐसा बन रहा था कि चुनाव सिर पर आने के बाद भी मीडिया से जुड़े दल एकजुट नहीं हो पा रहे। रैली के जरिए इन दलों ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि बड़े मुद्दों पर वे एक स्वर में बोल सकते हैं। जहां तक ईडी और अन्य एजेंसियों की कार्रवाई का सवाल है तो इसमें दो राय नहीं कि इन पर सरकार का और इन एजेंसियों का अपना पक्ष है। यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि 2005 से अब तक ईडी के दर्ज किए 5,906 केसों में से मात्र 25 निपटाए जा सके हैं। पिछले 17 वर्षों में 0.42% मामलों का निपटना इस शिकायत को दमदार बनाता है कि इन मामलों में प्रक्रिया ही सजा का रूप लेती जा रही है। सवाल उठता है कि क्या एजेंसियों को चुनाव होने तक विपक्षी दलों और नेताओं के खिलाफ अतिवादी कदमों से परहेज करना चाहिए और क्या चुनाव आयोग को इस तरह का कोई निर्देश जारी करना चाहिए? इस पर गंभीरता से विचार करना इसलिए भी जरूरी है कि क्योंकि किसी लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने ही नहीं चाहिए, होते हुए दिखने भी चाहिए।

बांग्लादेश में भारत के दुश्मन कौन ?

आर.के. सिन्हा

(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं)

कोई चाहे तो बांग्लादेश के विपक्ष से एहसान फरामोशी सीख सकता है। जिस भारत ने बांग्लादेश को , या यूँ कहें कि 1970 तक के पूर्वी पाकिस्तान, की प्रताड़ित और पीड़ित आम जनता के हितों की रक्षा के लिए पाकिस्तान से युद्ध मोल लिया, उस बांग्लादेश की प्रमुख विपक्षी दल

हिन्दुओं और प्राचीन हिन्दू मंदिरों पर हमले लगातार होते रहते हैं। कुछ साल पहले बांग्लादेश में अमेरिकी ब्लॉगर अभिजीत रॉय की निर्मम हत्या और उनकी पत्नी के ऊपर हुए जानलेवा हमले से वहां पर कठमुल्लों की बढ़ती ताकत का पता चलता है। वहां पर धर्मनिरपेक्ष ताकतों के लिए स्पेस जीवन के सभी क्षेत्रों में घट रहा है।अविजित रॉय बांग्लादेशी मूल के अमेरिकी थे। वे हिन्दू थे। वे और उनकी पत्नी बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे अपने ब्लॉग के जरिए। अभिजीत की हत्या से बांग्लादेश में हिन्दुओं की भयावह होती स्थिति पर पूरी दुनिया का ध्यान गया था। बांग्लादेश में कठमुल्ले हिन्दुओं की जान के पीछे पड़े रहते हैं।

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलती रहती है। उसके जहरीले अभियान से पड़ोसी मुल्क के कठमुल्लों को भी भारत और अपने ही बांग्लादेश के हिन्दुओं के खिलाफ हिंसा करने का मौका मिल जाता है। बांग्लादेश में बीएनपी ने हाल ही में भारत के उत्पादों के बायकाट का आह्वान भी किया है। इसके चलते वहां प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद की सरकार और विपक्ष आमने-सामने है।

मुस्लिम बहुल बांग्लादेश में भारत विरोधी भावना कोई नई बात नहीं है। पिछले साल क्रिकेट विश्व कप में भारत की हार के बाद ढाका और वहां के कई शहरों में जश्न मना था।मैं तो स्वयं 1970 के भारत - पाक युद्ध में युद्ध संवाददाता के हैसियत से बांग्लादेश में भारतीय सेना के साथ रहा था । युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने लाखों बांग्ला भाषी मुसलमान भाइयों को कत्लेआम से बचाया , हजारों बंगाली बेटियों और बहनों को पाकिस्तानी सेना द्वारा किए जा रहे बलात्कार से रक्षा की । इन सभी अत्याचारों का मैं प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूँ । लेकिन ,बांग्लादेश की आजादी के बाद जब बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने सभी युद्ध संवाददाताओं के साथ - साथ वरिष्ठ संपादकों को एक विशेष ट्रेन भेजकर बुलाया , तभी जगह - जगह इंडियाज जिनीस - पत्तर भालो नेईह्व के वाल पेंटिंग देखने को मिले । जब मैंने शेख मुजीब के पीआरओ से पूछा कि भारत ने तो युद्ध के बाद लाखों बांग्लादेशियों को भुखमरी से बचाया , हजारों मकान बनवाये , फिर यह क्या चल रहा है ? तब पीआरओ ने कहा , आप चिंता मत कीजिए । कुछ हिंदू विरोधी कट्टरपंथी हैं, उन्हें ठीक करने में सरकार लगी हुई है ।ह्व लेकिन वे तो आज भी बने हुए हैं, बल्कि कई गुना बढ़ गये हैं।

बांग्लादेश में भारत के कथित हस्तक्षेप को लेकर विरोध और असहमति 1990 के दशक से देखी जा रही है । लेकिन , हाल के वर्षों में विरोध के ये सुर कहीं ज्यादा मुखर हुए हैं। आपको याद ही होगा कि बीएनपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने देश में बीती जनवरी में हुए आम चुनाव का बहिष्कार किया था। इस चुनाव में जीत के बाद शेख हसीना चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी थीं। आप कह सकते हैं कि आम चुनाव के बाद से बीएनपी के अधिकांश नेता ये माहौल बनाने में जुटे हुए हैं कि बांग्लादेश के एकतरफा चुनाव को सिर्फ. भारत की वजह से वैधता मिली है और इसलिए लोगों को भारत और उसके उत्पादों का बहिष्कार करना चाहिए। बांग्लादेश से आ रही खबरों से संकेत मिल रहे हैं कि बीएनपी की विदेश मामलों की कमेटी (एफआरसी) चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध प्रगाढ़ करना चाह रही है। संकेत बहुत साफ है कि बीएनपी भारत से नफरत करती है। हालांकि उसकी नफरत की वजह समझ से परे है। भारत का 1947 में बंटवारा हुआ। पंजाब और बंगाल सूबों के कुछ हिस्से पाकिस्तान में चले गए। आगे चलकर पाकिस्तान का वह भाग, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, 1971 में एक स्वतंत्र देश के रूप में विश्व मानचित्र पर उभरा । नए देश का नाम बांग्लादेश के रूप में जाना गया। उसकी स्थापना में भारत का योगदान रहा। पर वहां पर शुरू से ही घनघोर कठमुल्ले छाए रहे। उनकी जहालत की एक तस्वीर लगातार देखने को मिलती रहती है। वहां पर

हिन्दुओं और प्राचीन हिन्दू मंदिरों पर हमले लगातार होते रहते हैं। कुछ साल पहले बांग्लादेश में अमेरिकी ब्लॉगर अभिजीत रॉय की निर्मम हत्या और उनकी पत्नी के ऊपर हुए जानलेवा हमले से वहां पर कठमुल्लों की बढ़ती ताकत का पता चलता है। वहां पर धर्मनिरपेक्ष ताकतों के लिए स्पेस जीवन के सभी क्षेत्रों में घट रहा है।अविजित रॉय बांग्लादेशी मूल के अमेरिकी थे। वे हिन्दू थे। वे और उनकी पत्नी बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे अपने ब्लॉग के जरिए। अभिजीत की हत्या से बांग्लादेश में हिन्दुओं की भयावह होती स्थिति पर पूरी दुनिया का ध्यान गया था।

बांग्लादेश में कठमुल्ले हिन्दुओं की जान के पीछे पड़े रहते हैं। उन्हें तो बस मौके की तलाश होती है। यह अफसोसजनक बात है कि बांग्लादेश में हिन्दू कतई सुरक्षित नहीं हैं। जबकि बांग्लादेश में सदियों से बसे हिन्दुओं ने बंग बंधु शेख मुजीबुर उर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था । जिस बांग्लादेश में 'हिफाजत-ए-इस्लाम' जैसा जहरीला संगठन सक्रिय होगा उसका भगवान ही मालिक है। यह अपने देश के सड़क छाप लोगों को यह समझाने में सफल रहा कि इस्लाम खतरे में है। कैसे खतरे में है? कोई यह भी तो बता दे। बांग्लादेश में 90 फीसद से अधिक मुसलमान हैं।

तस्लीमा नसरीन ने भी अपने उपन्यास लज्जा में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की दर्दनाक स्थिति पर विस्तार से लिखाहै। इसलिए ही उनकी जान के दुश्मन हो गए यह कठमुल्ले। उसी विरोध के कारण तसलीमा को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। तसलीमा लसरीन का उपन्यास ह्यलज्जाह्व1993 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। वह लज्जा में साम्प्रदायिक उन्माद के नृशंस रूप को सामने लाती है। लज्जा के आने के बाद कट्टरपंथियों ने उनके खिलाफ फतवा जारी किया था। जिस कारण से वह अमेरिका चली गईं थीं। अपनी जान बचाने की गरज से तसलीमा स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका में भी रहीं । वह 2004 में कोलकाता आ गईं थीं। उन पर 2007 में हैदराबाद में भारत के कठमुल्लों ने हमला किया। उनसे मेरी भी मुलाकात हुई है। वह मेरे सांसद आवास में पधारी भी थीं। तब मुझे पता चला था कि बांग्लादेश में किन कठोर स्थितियों में हिन्दू रहने को अभिशप्त हैं।

भारत का विरोध करने वालों से कोई पूछे कि क्या जब भारत ने पाकिस्तान की जालिम फौजों से पूर्वी पाकिस्तान को बचाया था तब उसका कोई निजी हित-स्वार्थ था। भारत ने तब मानवता के आधार पर पूर्वी पाकिस्तान की जनता की मदद की थी। लाखों बांग्लादेशियों को अपने यहां शरण भी थी। पर अगर कोई इंसान या समाज एहसान फरामोशी पर उतर आए तो आप क्या कर सकते हैं। बीएनपी की नेता खालिदा जिया तो घनघोर भारत विरोधी रही हैं। वह जब अपने देश की प्रधानमंत्री थीं तब वहां टाटा ग्रुप की इनवेस्टमेंट करने की योजना का कसकर विरोध हुआ था। उसे हवा बीएनपी ही दे रही थी। टाटा ग्रुप की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से की जा रही थी। टाटा ग्रुप को ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा बताने वाले भूल गए थे कि टाटा ग्रुप भारत से बाहर दर्जनों देशों में कारोबार करता है। वहां पर तो उस पर कभी कोई आरोप नहीं लगाता।

खैर,बीएनपी के भारतीय माल के बहिष्कार के आह्वान का प्रधानमंत्री शेख हसीना ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा जब बीएनपी सत्ता में थी, तब मंत्रियों की पत्नियां भारत जाया करती थीं। वे वहाँ साड़ियां खरीदती थीं और इधर-उधर घूमा करती थीं...वो एक सूटकेस के साथ जाती थीं और छह-सात बक्सों के साथ लौटती थीं। शेख हसीना भी भारतीय साड़ियां पहनना पसंद करती हैं। बांग्लादेश की स्थापना के बाद लग रहा था कि वहां पर हिन्दुओं की स्थिति सुधर जाएगी। उन्हें इंसान समझा जाएगा, पर यह हो न सका। भारत की चाहत रही है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना सत्तासीन रहें। यानी वहां पर अवामी लीग के नेतृत्व वाली सरकार रहे। निश्चित रूप से बांग्लादेश में शेख हसीना का सत्ता पर काबिज होना भारत और वहां के हिन्दुओं के हित में है।

अभी सीखना होगा कंगना रनौत को राजनीति का ककहरा

केएस तोमर

कंगना ने अपने परिवार से विद्रोह किया, जो उनके बॉलीवुड में जाने के खिलाफ थे, क्योंकि फिल्म उद्योग अनिश्चितताओं एवं दुविधाओं से भरा है, भले ही अवसर काफी हों। कंगना के माता-पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर बने, लेकिन उन्होंने मेडिकल प्रवेश परीक्षा ही नहीं दी। कम आय होने पर रोटी एवं अचार पर गुजारा करने के बावजूद उन्होंने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई। हालांकि मुंबई में अपना घर नहीं होने और बढ़ते कर्ज के कारण उनके जीने का संघर्ष बढ़ गया था। कंगना स्पष्टवादी इंसान हैं, जो खुद को 'जिद्दी और विद्रोही' बता सकती हैं। कंगना रनौत को आगे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सक्रिय राजनीति फिल्मी परी कथाओं जैसी नहीं होती है। अनिवार्य रूप से मतदाता उनसे एक पूर्णकालिक राजनेता होने की उम्मीद करेंगे। इसके लिए उन्हें मंडी को अपना स्थायी निवास स्थान बनाना होगा, ताकि लोग उनसे अपनी शिकायतों के निवारण के लिए संपर्क कर सकें। विश्लेषकों का मानना है कि राजनीति का अनुभव नहीं होने के कारण उन्हें असाधारण मेहनत करनी होगी, हालांकि मोदी के करिश्मे और भारी लोकप्रियता से यह संभव हो सकता है। साथ ही, उन्हें भाजपा के अनुशासित कार्यकर्ताओं, विशाल संसाधनों और आरएसएस की चुनावी मशीनरी का समर्थन भी मिलेगा। 2021 में हुए मंडी लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस की प्रतिभा सिंह ने भाजपा से यह सीट छीन ली थी, जो मुख्यत: दिवंगत वीरभद्र सिंह के प्रति सहानुभूति के कारण थी, लेकिन राजनीतिक माहौल अब बदल गया है, क्योंकि कांग्रेस अव्यवस्थित है, जिससे कंगना को फायदा हो सकता है। यह एक संयोग ही था कि कंगना को उनके 37वें जन्मदिन पर 23 मार्च को मंडी लोकसभा सीट से टिकट दिए जाने की खुशखबरी मिली। खुद को दक्षिणपंथी विचारधारा से जोड़ने वाली और कट्टर मोदी समर्थक बताने वाली कंगना का आरएसएस से घनिष्ठ संबंध रहा है।

उन्नीसवीं सदी के विक्टोरियन यथार्थवादी दार्शनिक थॉमस हार्डी के 'अवसर और नियति' के दर्शन के अनुरूप एक अनजान दुनिया में खुद को स्थापित करना उनका अकल्पनीय सपना था। इसलिए वह फिल्म उद्योग में अपनी किस्मत आजमाने मुंबई की खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ीं, जहां वह विजयी होकर उभरीं।

कंगना के लिए मुंबई की ग्लैमरस जिंदगी से अनिश्चित राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखना पूर्वनिर्धारित लगता है, जो उन्हें अपने पहाड़ी राज्य के लोगों की सेवा का अवसर दे सकता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के भांबाला गांव की लड़की कंगना रनौत की इतनी बड़ी सफलता का श्रेय उनके दृढ़ संकल्प, प्रतिबद्धता और इच्छाशक्ति को दिया जा सकता है।

बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक और हिंदुत्व विचारधारा तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कट्टर समर्थक कंगना रनौत मंडी लोकसभा सीट से राजनीति के नए क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं, जिससे मुकाबला फिल्मी अंदाज में पलट सकता है। लगता है कि कंगना ने अपने करियर की दूसरी पारी के लिए अपने पत्ते अच्छे से खेले और भाजपा के उन वरिष्ठ नेताओं को पछाड़ दिया, जो दशकों से पार्टी के प्रति समर्पित थे।

कंगना ने अपने परिवार से विद्रोह किया, जो उनके बॉलीवुड में जाने के खिलाफ थे, क्योंकि फिल्म उद्योग अनिश्चितताओं एवं दुविधाओं से भरा है, भले ही अवसर काफी हों। कंगना के माता-पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर बने, लेकिन उन्होंने मेडिकल प्रवेश परीक्षा ही नहीं दी। कम आय होने पर रोटी एवं अचार पर गुजारा करने के बावजूद उन्होंने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई। हालांकि मुंबई में अपना घर नहीं होने और बढ़ते कर्ज के कारण उनके जीने का संघर्ष बढ़ गया था। कंगना स्पष्टवादी इंसान हैं, जो खुद को 'जिद्दी और विद्रोही' बता सकती हैं।

कंगना रनौत को आगे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सक्रिय राजनीति फिल्मी परी कथाओं जैसी नहीं होती है। अनिवार्य रूप से मतदाता उनसे एक पूर्णकालिक राजनेता होने की उम्मीद करेंगे। इसके लिए उन्हें मंडी को अपना स्थायी निवास स्थान बनाना होगा, ताकि लोग उनसे अपनी शिकायतों के निवारण के लिए संपर्क कर सकें। विश्लेषकों का मानना है कि राजनीति का अनुभव नहीं होने के कारण उन्हें असाधारण मेहनत करनी होगी, हालांकि मोदी के करिश्मे और भारी लोकप्रियता से यह संभव हो सकता है। साथ ही, उन्हें भाजपा के अनुशासित कार्यकताओं, विशाल संसाधनों और आरएसएस की चुनावी मशीनरी का समर्थन भी मिलेगा। 2021 में हुए मंडी लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस की प्रतिभा सिंह ने भाजपा से यह सीट छीन ली थी, जो मुख्यतः दिवंगत वीरभद्र सिंह के प्रति सहानुभूति के कारण थी, लेकिन राजनीतिक माहौल अब बदल गया है, क्योंकि कांग्रेस अव्यवस्थित है, जिससे कंगना को फायदा हो सकता है।

यह एक संयोग ही था कि कंगना को उनके 37वें जन्मदिन पर 23 मार्च को मंडी लोकसभा सीट से टिकट दिए जाने की खुशखबरी मिली। खुद को दक्षिणपंथी विचारधारा से जोड़ने वाली और कट्टर मोदी समर्थक बताने वाली कंगना का आरएसएस से घनिष्ठ संबंध रहा है। यही वजह है कि राजनीति का अनुभव नहीं होने के बावजूद पार्टी ने उन्हें टिकट दिया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हिमाचल प्रदेश से हैं और कंगना को टिकट दिलाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा उन्हें केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का भी समर्थन हासिल है, जो राज्य के हमीरपुर जिले के हैं। सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने की अपनी महत्वाकांक्षा पूरी होने के बाद बेहद उत्साहित कंगना ने कहा, 'मैं अपने जन्मस्थान हिमाचल प्रदेश से चुनाव लड़ने का मौका देने के लिए भाजपा नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूं।'

कंगना और विवाद एक-दूसरे के पर्यायवाची हो गए हैं। अक्सर वह अपने विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में रहती हैं। बार-बार उल्लंघन के कारण ट्विटर ने भी उनके खाते को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया था, लेकिन बाद में प्रतिबंध हटा लिया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि राजनीति में नवागंतुक होने के कारण कंगना को अपनी फिल्मी शैली से दूर रहना होगा और जमीनी स्तर के पार्टी कार्यकताओं और मतदाताओं के साथ घुलना-मिलना होगा, ताकि उन्हें लगे कि वह एक आम आदमी की तरह हैं, न कि बॉलीवुड की फिल्म स्टार। उन्हें अपने व्यक्तित्व में इस तरह के बदलाव से गुजरना होगा, जो एक सफल राजनीतिज्ञ बनने के लिए अनिवार्य है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

ब्रह्म ही तो है अन्न

भारतीय जीवन दर्शन में अन्न को प्रसाद मानकर सम्मान देने की परंपरा में उसे ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। आज भी जिम्मेदार पीढ़ी के लोग खाने से पहले भोजन को प्रणाम करते तथा पहला कौर जीव-जंतुओं के लिये निकालते हैं। मकसद अन्न के महत्व को गरिमा देना और उसका उचित इस्तेमाल ही होता है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी की वह रिपोर्ट एक काले सच को उजागर करती है कि पूरी दुनिया में 19 फीसदी भोजन बर्बाद कर दिया जाता है। एक भयावह सच्चाई यह भी है कि दुनिया में करीब 78.3 करोड़ लोग लंबे समय से भूख से जूझ रहे हैं। युद्धरत गाजा में इस भूख के संकट की भयावह स्थिति जब-तब उजागर होती रहती है। संयुक्त राष्ट्र की यह हालिया रिपोर्ट एक कठोर हकीकत से रूबरू भी कराती है कि पर्याप्त संसाधनों के बावजूद खाद्यान्न का न्यायसंगत वितरण नहीं हो पा रहा है। दूसरे शब्दों में यह एक नैतिक संकट भी है। दरअसल, भोजन की बबार्दी एक तरह से हमारे पर्यावरण को भी अस्थिर करती है। निश्चित रूप से यह संकट भारत में भी विद्यमान है। खाद्य सुरक्षा के नजरिये से भोजन की बबार्दी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अनुसार भारत में कुल भोजन का एक-तिहाई हिस्सा उपभोग से पहले खराब हो जाता है। एक अनुमान के अनुसार भोजन की यह बबार्दी एक साल में प्रतिव्यक्ति पचास किलो होने की आशंका है। दरअसल, संयुक्त राष्ट्र की एक अन्य रिपोर्ट भारत में कुपोषण से जुड़े संकट को भी उजागर करती है। जिसमें बताया गया है कि देश की 74 फीसदी आबादी स्वस्थ आहार का खर्च वहन नहीं कर सकती। ऐसे में भोजन का एक-तिहाई हिस्सा बर्बाद होना नैतिक अपराध ही है। वहीं दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत में भी खाद्य उत्पादन और अपशिष्ट से जुड़े ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर्यावरण पर प्रतिकूल असर डाल रहा है। दरअसल, कचरे के ढेरों में खराब खाद्यान्नों के अंश विघटित होने से ग्लोबल वार्मिंग के वाहक मीथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं। वैश्विक संगठनों का आग्रह है कि दुनिया में खाद्य प्रणालियों में पूर्ण बदलाव लाएं। साथ ही समान वितरण को प्राथमिकता देने को प्रेरित किया जाना चाहिए। ऐसे में जब देश में लाखों लोग रोटी के लिये संघर्ष कर रहे हों, भोजन की बबार्दी नैतिक दृष्टि से अपराध ही है। इस संकट से उबरने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रणनीति की जरूरत है। जिसके लिये जागरूकता अभियान चलाने, नीतिगत उपायों में बदलाव लाने तथा समुदाय संचालित पहलों को एकीकृत प्रयासों से मूर्त रूप देने का प्रयास होना चाहिए। वहीं सरकारी हस्तक्षेप से अपशिष्ट को कम करने के लिये नियम बनाने की भी जरूरत है। समाज के स्तर पर भोजन को बर्बाद होने से रोकने के लिये दीर्घकालीन प्रयासों को प्रोत्साहित करना होगा। ऐसी व्यवस्था बनाएं, जिसमें सरकारी एजेंसियों, स्वयंसेवी संगठनों व निजी उद्यमों के मध्य बेहतर तालमेल से बचे भोजन के पुनर्वितरण की कुशल व्यवस्था बन पाये।

संयुक्त राष्ट्र की यह हालिया रिपोर्ट एक कठोर हकीकत से रूबरू भी कराती है कि पर्याप्त संसाधनों के बावजूद खाद्यान्न का न्यायसंगत वितरण नहीं हो पा रहा है। दूसरे शब्दों में यह एक नैतिक संकट भी है। दरअसल, भोजन की बबार्दी एक तरह से हमारे पर्यावरण को भी अस्थिर करती है। निश्चित रूप से यह संकट भारत में भी विद्यमान है। खाद्य सुरक्षा के नजरिये से भोजन की बबार्दी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अनुसार भारत में कुल भोजन का एक-तिहाई हिस्सा उपभोग से पहले खराब हो जाता है।

इंडिया की लोकतंत्र बचाओ महारैली के बेसूरे स्वर

आरती कुमारी

दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन इंडिया की लोकतंत्र बचाओं महारैली में जुटे 28 दलों के नेता आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कोई प्रभावी संदेश देने में नाकाम रहे हैं। भले ही चुनाव के ठीक पहले विपक्षी दलों ने इसके जरिए अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने में कामयाबी हासिल की हो। लेकिन यह एकजुटता भ्रष्ट नेताओं को बचाने की एक मुहिम ही बनकर सामने आयी है। इसमें स्पष्ट रूप से केन्द्र सरकार की भ्रष्टाचार पर गई कार्रवाई की बौखलाहट झलक रही थी। इस रैली में सभी दलों के नेताओं ने देश विकास के मुद्दों, सिद्धान्तों एवं नैतिक तकाजे की बजाय मोटे तौर पर सत्ता पक्ष की भ्रष्टाचार के रैली में अनेक मुद्दे उठे, जिनमें प्रमुख रहा केंद्रीय एजेंसियों का कथित दुरुपयोग और राजनीतिक भ्रष्टाचार। प्रियंका गांधी ने इस रैली में सरकार के सामने पाँच माँगें रखीं। इनमें प्रमुख दो हैं जिनमें चुनाव आयोग से माँग की गई है कि विपक्षी नेताओं पर छापों की कार्रवाई रोकी जाए। दूसरी और महत्वपूर्ण माँग ये है कि गिरफ्तार हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को तुरंत रिहा किया जाए। इस रिहाई की माँग के पीछे कांग्रेस का उद्देश्य बचे-खुचे संगठनों या पार्टियों को इंडिया गठबंधन से जोड़े रखना है। नीतीश कुमार और ममता बेनर्जी जैसे मजबूत खम्भे पहले ही उखड़ चुके हैं इसलिए जो कुछ बचा है उसे कांग्रेस समेटे रखना रहे हैं, फिर उसके लिये इस महारैली की क्या जरूरत? निश्चित ही एकजुटता के ये स्वर बेसूरे, असहज एवं बनावटी है, इंडिया गठबंधन के राजनैतिक क्षितिज पर जो वरिष्ठ राजनेता हैं उनकी आवाज व किरदार भारतीय जीवन को प्रभावित नहीं कर रहा है। इंडिया गठबंधन से जुडे. दलों की केन्द्र एवं प्रांतों की सरकारों के शासन-काल में तो अपराध, भ्रष्टाचार और साम्प्रदायिकता के जबड़े फैलाए, आतंकवाद, प्रांतवाद, जातिवाद की जीभ निकाले, मगरमच्छ सब कुछ निगलता रहा है। सब अपनी जातियों और ग्रुपों को मजबूत करते रहे हैं-- देश को नहीं। प्रथम पंक्ति का नेता ही नहीं है जिसे मोदी के मुकाबले में खड़ा किया होता रहा है और कोई भी यह दावे के साथ कहने की स्थिति में नहीं कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। जो विपक्षी नेता भ्रष्टाचार के आरोप में केंद्रीय एजेंसियों की जांच का सामना कर रहे हैं अथवा उन्हें जेल जाना पड़ा है, उनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कहीं कुछ गलत नहीं किया। प्रधानमंत्री ने मेरठ में चुनावी महासंग्राम की शुरूआत करते हुए कहा कि अगर विपक्षी नेता पाक-साफ हैं तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें छोड़ क्यों नहीं रहा है? कुछ तो गड़बड़ होगी ही। कुल मिलाकर बयानों का तीखापन यहाँ- वहाँ आने लगा है। लोकसभा चुनाव के प्रचार में धार आ गई है। यह धार दिन ब दिन और पैनी होती जाएगी। भारत के

खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए इसी के इर्दगिर्द ही अपनी बातें रखीं। लोकतंत्र बचाओ रैली से उपजे विचारों ने किन्हीं पवित्र उद्देश्यों के बजाय सत्ता हासिल करने की लालसा को ही उजागर किया, यह निराश करने वाली रैली किसी बड़े बदलाव की वाहक बनती हुई नजर नहीं आयी। इस रैली में भारतीय जनता पार्टी एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शानदार जीत की संभावना से बौखलाए नेताओं की खींच ही ज्यादा सामने आयी है। यही कारण है कि रैली में जो मुद्दा जोरशोर से उठा, वह यह रहा कि यदि भाजपा फिर से सत्ता में आ गई तो लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा और संविधान भी। यह समझना कठिन है कि कोई दल लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करता है तो उससे लोकतंत्र और संविधान कैसे खत्म हो जाएगा। आम जनता के मतों से जीत हासिल करने वाला दल किस तरह से लोकतंत्र को ध्वस्त करने वाला हो सकता है। विपक्षी एकता का यह महाकुंभ मोदी को कोसने की बजाय किन्हीं ठोस मुद्दों के सहारे कोई प्रभावशाली विमर्श खड़ा करने की कोशिश करता तो वह आम जनता को आकर्षित करता और यही स्वस्थ राजनीतिक परिपक्वता का परिचायक होता। लेकिन ऐसा न होना समूचे देश के विपक्षी दलों की नाकामी, उद्देश्यहीनता एवं राजनीतिक अपरिपक्वता का द्योतक हैं। इस चाहती है, यही उसकी विवशता है। वैसे, इंडिया गठबंधन के घटक दलों के आपसी अंतर्विरोध की छाया भी इस रैली दिखी। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि विरोध किसी खास व्यक्ति से जुड़ा नहीं बल्कि मौजूदा सरकार की तानाशाही के खिलाफ केंद्रित है। जबकि इस रैली का मकसद आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करना बताया गया। यहां आम आदमी पार्टी एवं कांग्रेस के बीच के अन्तर्विरोध को सहज ही समझा जा सकता है। यह रैली भले ही अठाइस दलों का जमावड़ा बनी, इसे विपक्षी दलों की एकजुटता का प्रदर्शन भी कहा गया है। लेकिन जबसे इंडिया गठबंधन बना है, तब से उसमें टूट एवं बिखराव के स्वर सुनाई दे रहे हैं। विचारभेद के साथ मनभेद भी सामने आये हैं। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक तमाम राज्यों में टिकट बंटवारे के सवाल पर इंडिया गठबंधन से जुड़े दलों की आपसी खटपट की खबरें भी आ रही थीं। भले ही ये विवाद गिनी-चुनी सीटों को लेकर थे, लेकिन संदेश स्पष्ट था कि चुनाव सिर पर आने के बाद भी इंडिया गठबंधन से जुड़े दल एकजुट नहीं हो पा रहे। रामलीला मैदान की रैली के जरिए इन दलों ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि मोदी विरोध एवं भाजपा को सत्ता से दूर करने के मुद्दों पर वे एक स्वर में बोल सकते हैं और लगातार बोलते भी जा सके। भारत के लोग केवल बुराइयों से लड़ते नहीं रह सकते, वे व्यक्तिगत एवं सामूहिक, निश्चित सकारात्मक लक्ष्य के साथ जीना चाहते हैं। अन्यथा जीवन की सार्थकता नष्ट हो जाएगी। दो तरह के नेता होते हैं- एक वे जो कुछ करना चाहते हैं, दूसरे वे जो कुछ होना चाहते हैं। असली नेता को सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी होकर, प्रासंगिक और अप्रासंगिक के बीच भेदरेखा बनानी होती है। संयुक्त रूप से कार्य करें तो आज भी वे भारत को विकास की नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने सहचिन्तन को शायद कमजोरी मान रखा है। नेतृत्व के नीचे शून्य तो सदैव खतरनाक होता ही है पर यहां तो ऊपर-नीचे शून्य ही शून्य है। इंडिया गठबंधन की चोटी से लेकर प्रांत स्तर पर, समाज स्तर पर तेजस्वी और खरे नेतृत्व का नितान्त अभाव है। यह सोच का दिवालियापन ही है कि दिखते हुए भ्रष्टाचार के बावजूद उसका विरोध नहीं करके, ऐसे भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिये लोकतंत्र बचाओ रैली का आयोजन हो रहे हैं। राजनीतिक भ्रष्टाचार एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन वह भी उतना सच है कि इस मामले में कोई भी दल दूध का धुला नहीं है। राजनीति के हमाम में सब नंगे हैं। विपक्षी दल कुछ भी दावा करें, सच्चाई यह है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान उनके पास भी नहीं है। राजनीति में काले धन का इस्तेमाल केनवास पर शांति, प्रेम, ईमानदारी, विकास और सह-अस्तित्व के रंगों की जरूरत है, पर आज इंडिया गठबंधन इन रंगों को भरने की पात्रता खोकर नायकविहीन है। रंगमंच पर नायक अभिनय करता है, राजनीतिक मंच पर नायक के चरित्र को जीना पड़ता है, कथनी-करनी में समानता, दृढ़ मनोबल, इच्छा शक्ति और संयमशीलता के साथ। लेकिन भारतीय लोकतंत्र की यह एक बड़ी विडम्बना है कि यहां विपक्षी दलों में नायक कम, खलनायक अधिक है। तभी एक मोदी अठाइस दलों के नेताओं पर भारी पड़ रहा है। देखना यह है कि विपक्षी दलों ने राजनीतिक भ्रष्टाचार का मामला उठाकर मोदी सरकार को घेरने की जो कोशिश की, उससे देश की जनता कितनी प्रभावित होगी और इसकी आवश्यकता महसूस करेगी या नहीं कि इस गठबंधन को सत्ता में लाना आवश्यक है। विपक्षी दलों ने जो मुद्दे उठाये, वे प्रभाव पैदा नहीं कर पाये। चुनावी बांड का ही मुद्दा ले, इसमें संदेह नहीं कि चुनावी बांड से दिए जाने वाले चंदे का जो विवरण सामने आया है, उससे अनेक गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जिन कंपनियों का नाम लेकर यह कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने उन पर अनुचित दबाव डालकर चंदा हासिल किया, उनमें से अनेक ने विपक्षी दलों को भी अच्छा-खासा चंदा दिया है।

प्रियंका गांधी ने इस रैली में सरकार के सामने पाँच माँगें रखीं। इनमें प्रमुख दो हैं जिनमें चुनाव आयोग से माँग की गई है कि विपक्षी नेताओं पर छापों की कार्रवाई रोकी जाए। दूसरी और महत्वपूर्ण माँग ये है कि गिरफ्तार हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को तुरंत रिहा किया जाए। इस रिहाई की माँग के पीछे कांग्रेस का उद्देश्य बचे-खुचे संगठनों या पार्टियों को इंडिया गठबंधन से जोड़े रखना है। नीतीश कुमार और ममता बेनर्जी जैसे मजबूत खम्भे पहले ही उखड़ चुके हैं इसलिए जो कुछ बचा है उसे कांग्रेस समेटे रखना चाहती है, यही उसकी विवशता है। वैसे, इंडिया गठबंधन के घटक दलों के आपसी अंतर्विरोध की छाया भी इस रैली दिखी। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि विरोध किसी खास व्यक्ति से जुड़ा नहीं बल्कि मौजूदा सरकार की तानाशाही के खिलाफ केंद्रित है। जबकि इस रैली का मकसद आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करना बताया गया। यहां आम आदमी पार्टी एवं कांग्रेस के बीच के अन्तर्विरोध को सहज ही समझा जा सकता है। यह रैली भले ही अठाइस दलों का जमावड़ा बनी, इसे विपक्षी दलों की एकजुटता का प्रदर्शन भी कहा गया है। लेकिन जबसे इंडिया गठबंधन बना है, तब से उसमें टूट एवं बिखराव के स्वर सुनाई दे रहे हैं। विचारभेद के साथ मनभेद भी सामने आये हैं। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक तमाम राज्यों में टिकट बंटवारे के सवाल पर इंडिया गठबंधन से जुड़े दलों की आपसी खटपट की खबरें भी आ रही थीं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

क्या इस बार कच्चातिवु द्वीप बनेगा दक्षिण का चुनावी मुद्दा ?

अशोक भाटिया

आरटीआई से मिले जवाब के बाद तमिलनाडु में कच्चातिवु द्वीप श्रीलंका को सौंपे जाने का मुद्दा गरमा गया है। फ्ळकके मुताबिक, 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के। अन्नामलाई ने द्वीप को लेकर एक फ्ळकआवेदन दिया गया था, जिसका जवाब सामने आने के बाद सियासी घमासन मच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उत्तर प्रदेश के मेरठ से अपने लोकसभा चुनाव अभियान की शुरूआत के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर विपक्ष को घेरा। उन्होंने कच्चाथीवू द्वीप का जिक्र कर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल के दौरान इस द्वीप को लेकर श्रीलंका के साथ समझौता किया गया था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, आंखें खोलने वाली और चौंका देने वाली बात। नए तथ्यों से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से कच्चातिवु द्वीप को छोड़ दिया। इससे हर भारतीय नाराज है और लोगों के मन में यह बात बैठ गई है कि हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना 75 सालों से कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा है। वैसे भी भारतीय प्रधानमंत्री पहले भी कच्चातिवुद्वीप को लेकर कांग्रेस पर आक्रामक रहे हैं और उन्होंने पिछले साल अगस्त महीने में भी कच्चातिवुद्वीप का जिक्र कर कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश की थी।अब तो रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने अपनी मेरठ कि सभा में हुनकर भरी कि कैसे कांग्रेस और इंडी अलायंस देश की अखंडता और देश की एकता को तोड़ते रहे हैं। आज ही कांग्रेस का एक और देश विरोधी कारनामा देश के सामने आया है। तमिलनाडु में भारत के समुद्री तट से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समुंदर में एक टापू है, एक द्वीप है कच्चाथीवू अलग-अलग नाम भी लोग बोलते हैं। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है लेकिन कांग्रेस ने चार-पांच दशक पहले इसे यह कह कर दे दिया कि ये द्वीप गैर-जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। इन्होंने मां भारती का एक अंग काट दिया और भारत से अलग कर दिया। देश कांग्रेस के रवैये की कीमत आज तक चुका रहा है। गौरतलब है कि अगस्त 2023 मेंप्रधानमंत्री मोदी ने इस ट्वीप का जिक्र करते हुए कहा था, कि कांग्रेस का इतिहास मां भारती को छिन्न-भिन्न करने का रहा है।इस बात का खुलासा भाजपा तमिलनाडु प्रमुख के अन्नामलाई की तरफ से दस्तावेजों के खुलासे के बाद आया है, जिससे यह संकेत मिलता है, कि कांग्रेस ने कभी भी छोटे, निर्जन द्वीप को ज्यादा महत्व नहीं दिया। रिपोर्ट के अनुसार, जवाहरलाल नेहरू ने एक बार यहां तक कहा था, कि वह द्वीप पर अपना दावा छोड़ने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे। यह कहानी नई नहीं है और जिन परिस्थितियों में इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत ने 1974 में कच्चातिवुपर अपना दावा छोड़ दिया था, उसे अच्छी तरह से समझना जरूरी है। हालांकि, भाजपा के तमिलनाडु अभियान ने इसे राज्य के सबसे गर्म राजनीतिक विषयों में से एक बना दिया है।आइये जानते हैं, कि कच्चातिवुद्वीप को लेकर विवाद क्या है, खासकर तमिलनाडु राज्य की राजनीति में इस विषय पर एक बार फिर से राजनीति क्यों गर्म है? कच्चातिवु द्वीप हिंद महासागर में भारत के दक्षिण छोर पर है। 285 एकड़ में फैला यह द्वीप भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में बना हुआ है। 17वीं शताब्दी में यह द्वीप मदुरई के राजा रामानंद के अधीन था। अंग्रेजों के शासनकाल में कच्चातिवु द्वीप मद्रास प्रेसीडेंसी के पास आया। उस दौर में यह द्वीप मछलीपालन के लिए अहम स्थान रखता था। यही वजह थी कि भारत और श्रीलंका दोनों मछली पकड़ने के लिए इस द्वीप पर अपना-अपना दावा करते थे। आजादी के बाद समुंद्र की सीमा को लेकर 1974-76 के बीच 4 समझौते किए गए थे। समझौते के तहत भारतीय मछुआरों को द्वीप पर आराम करने और जाल सुखाने में इजाजत की गई और यह द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया गया। यह द्वीप भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में बना हुआ है। साल 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका की राष्ट्रपति श्रीमावो भंडारनायके के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के तहत इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को कच्चातिवु द्वीप सौंप दिया था। इस समझौते को लेकर 26 जून को कोलंबो और 28 जून को दिल्ली में दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी। बैठक के बाद ही कुछ शर्तों के साथ इस द्वीप को श्रीलंका को सौंपा गया। शर्त यह रखी गई थी कि भारतीय मछुआरे इसका इस्तेमाल जाल सुखाने और आराम करने के लिए करते रहेंगे। यह भी कहा गया था कि इस द्वीप पर बने चर्च में भारतीयों को बिना वीजा जाने की इजाजत नहीं होगी। और न ही भारतीय मछुआरे यहां पर मछलियां पकड़ सकेंगे। जब इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को यह द्वीप सौंपा को सबसे ज्यादा विरोध तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि इसका पुरजोर विरोध किया था। इसको लेकर साल 1991 में तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव में उस द्वीप को वापस लेने की मांग की गई। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। साल 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कच्चातिवु द्वीप को लेकर हुए समझौते को अमान्य घोषित करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि तोहफे में इस द्वीप को श्रीलंका को देना असंवैधानिक है।कच्चातिवु द्वीप को लेकर समय-समय पर सियासी घमासान हुआ। 2011 में जब जयललिता दोबारा तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनीं तो उन्होंने विधानसभा में इसको लेकर प्रस्ताव पास कराया। जब श्रीलंका में गृहयुद्ध चल रहा था उस दौरान श्रीलंकाई नौसैनिक बल, जाफना से बाहर स्थित लिट्टे की सप्लाई चेन को काटने के काम में व्यस्त थे, इसलिए भारतीय मछुआरों के लिए श्रीलंकाई जलक्षेत्र में जाना आम बात बन गई थी। जिसकी वजह से श्रीलंकाई मछुआरों में काफी नाराजगी रहती थी, क्योंकि बड़े भारतीय ट्रॉलर जहाज ना सिर्फ काफी ज्यादा मछलियां पकड़ते थे, बल्कि श्रीलंकाई मछली पकड़ने के जाल और उनकी नावों को भी नुकसान पहुंचाते थे। साल 2009 श्रीलंकाई गृहयुद्ध खत्म हो गये और उसके बाद नाटकीय अंदाज में स्थितियां बदलने लगीं। कोलंबो ने अपनी समुद्री सुरक्षा बढ़ानी शुरू कर दी और भारतीय मछुआरों पर अब उन्होंने कार्रवाई करनी शुरू कर दी। भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारियां शुरू हो गईं और कच्चातिवुद्वीप के आसपास श्रीलंका ने भारतीय मछुआरों के मछली पकड़ने पर सख्ती से रोक लगानी शुरू कर दी। आज तक, श्रीलंकाई नौसेना नियमित रूप से भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार करती है और हिरासत में टॉर्चर करती है, जिसकी वजह से कई मछुआरों की मौत हो चुकी है। जब जब मछुआरों की मौत होती है, कच्चातिवुद्वीप को फिर से भारत में मिलाने की मांग उठने लगती है। लिहाजा, कच्चातिवुद्वीप को लेकर तामिलनाडु की राजनीति गर्म हो जाती है। भारत के दिग्गज विदेश नीति एक्सपर्ट ब्रह्मा चेलानी ने कच्चातिवुद्वीप को श्रीलंका को देना भारत की बड़ी रणनीतिक भूल बताया है।उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, कि कच्चातिवुएक छोटा सा द्वीप हो सकता है, लेकिन सीमाओं को लेकर भारत के प्रधानमंत्रियों के उदारता का एक लंबा रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने कहा है, कि मणिपुर की कबाव घाटी और सिंधु जल का बड़ा हिस्सा उपहार में देने से लेकर 1954 में तिब्बत में अपने अलौकिक अधिकारों को छोड़ने और फिर 2003 में औपचारिक रूप से अपना महत्वपूर्ण तिब्बत कार्ड छोड़ने से लेकर तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को चीन के हिस्से के रूप में मान्यता देना, भारत के प्रधानत्रियों के उदारता का ये एक लंबा रिकॉर्ड है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है, कि भारतीय कूटनीति के भोलेपन का उदाहरण 1972 का शिमला समझौता है, जिसके तहत भारत ने बगैर कुछ हासिल किए बातचीत की टेबल पर युद्ध में जो लाभ मिला था, उसे गंवा दिया। ब्रह्मा चेलानी ने अपने ट्वीट में लिखा है, कि भारत अपने इतिहास को फिर से याद कर रहा है, क्योंकि मोदी सहित लगभग हर भारतीय प्रधान मंत्री ने शासन-कला की अनिवार्यताओं को सीखने या पिछली भूलों से सबक लेने के बजाय, विदेश-नीति के पहिये को फिर से बनाने की कोशिश की है। उनका इशारा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में, गलवान घाटी हिंसा होने तक चीन को लेकर अपनाए गये रणनीति को लेकर था, जब मोदी सरकार ने चीन से शांति के लिए लगातार बैठकें की थी। खुद प्रधानमंत्री मोदी चीन गये थे और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भारत दौरे के दौरान भव्य स्वागत किया गया था। लेकिन, सरकार को उस वक्त चीनी मकसद का अहसास हुआ, जब गलवान घाटी में चीनी घुस आए और हिंसक झड़प में कई भारतीय सैनिक मारे गये। अब जबकि चीन लगातार हिंद महासागर में घुसपैठ कर रहा है, लिहाजा कच्चातिवुद्वीप अब रणनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण हो गया है और सरकार से अपील की जा रही है, कि फिर से कच्चातिवुद्वीप पर भारत अपना दावा करे। फिलहाल, इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी से इतर कुछ और होने की संभवना नहीं है, लेकिन आगे भी कच्चातिवुपर दावा करना भारत के लिए आसान नहीं है, क्योंकि चीन ऐसे ही किसी मौके की तलाश में है, जब वो श्रीलंका को भारत के लिए भड़काकर हिंद महासागर में कोई और ड्रामा कर सके। अब लोकसभा चुनाव के बीच एक बार फिर यह द्वीप बहस का विषय बन गया है। जिसको लेकरप्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री ने हाल ही में ट्वीट किया है।

संपादकीय

"जब दिल बोलता है, तो दिमाग को आपत्ति करना अशोभनीय लगता है।"
-मिलान कुंदेरा

लोकसभा चुनाव से ऐन पहले कच्चातिवु द्वीप के संवेदनशील मुद्दे के उठने पर विपक्ष की चिंता समझी जा सकती है, लेकिन इससे जुड़े जो तथ्य सामने आए हैं, वे केंद्र की तत्कालीन सरकार के फैसले पर सवाल तो उठाते ही हैं, जिसके कारण तमिल मछुआरों के आर्थिक व सामाजिक ताने-बाने को ठेस पहुंची थी।

अतीत का भूत

विवादास्पद कच्चातिवु द्वीप मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ही अंदाज में कांग्रेस पर निशाना तो साधा ही है, इस रोशनी में इससे जुड़े जो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, उन्होंने तमिलनाडु और देश की राजनीति में एक पुरानी बहस को फिर जिंदा कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दरअसल इस मामले में भाजपा की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के. अन्नामलाई के सूचना के अधिकार आवेदन पर मिली जानकारियों का हवाला देते हुए कच्चातिवु द्वीप को श्रीलंका को सौंपे जाने के लिए कांग्रेस को कसूरवार ठहराया है। उल्लेखनीय है कि कच्चातिवु, रामेश्वरम (भारत) और नेदुनतिवु (श्रीलंका) के मध्य 285 एकड़ में फैला एक छोटा निर्जन द्वीप है, जहां स्थित बीसवीं सदी के एक चर्च की वजह से आगंतुकों की कमी-कभार आमद भले हो, पेयजल के अभाव के चलते स्थायी निवास तकरीबन नामुमकिन है। मध्यकाल की शुरुआत में यह द्वीप श्रीलंका के जाफना साम्राज्य के नियंत्रण में था, लेकिन 17वीं सदी तक यह मदुरई के राजा रामानंद के अधीन आ गया था। ब्रिटिश शासन में यह मद्रास प्रेसीडेंसी के अधीन था, हालांकि पारंपरिक तौर पर दोनों देशों के मछुआरे इसका उपयोग करते रहे। आजादी के बाद भी यह द्वीप भारत का हिस्सा रहा, जिस पर श्रीलंका दावा जताता रहा। 1974 में इस मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व श्रीलंका की तत्कालीन राष्ट्रपति सिरिमावो भंडारनायके के मध्य हुए समझौते के तहत यह द्वीप भारत द्वारा स्वेच्छा से श्रीलंका को सौंप दिया गया। तमिलनाडु की तत्कालीन द्रमुक सरकार समझौते से पहले राज्य सरकार से विमर्श न किए जाने को लेकर शुरुआत से ही इसके खिलाफ थी। 1991 में भी राज्य विधानसभा में इसके विरोध में एक प्रस्ताव पारित हुआ और 2008 में भी राज्य की तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इस फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था। दरअसल, इस मामले से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण पहलू तमिल मछुआरों की आजीविका और उनके सामाजिक ताने-बाने का है।

आलम यह है कि आज कच्चातिवु में मछलियां पकड़ने के लिए भारतीय मछुआरों को अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पार करनी पड़ती है, जिसमें कई बार उन्हें श्रीलंकाई नौसेना का भी सामना करना पड़ता है। खुद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन इसके समाधान के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख चुके हैं। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले इस संवेदनशील मुद्दे के उठने पर विपक्ष की चिंता समझी जा सकती है, पर अरुणाचल और चीन जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने वालों के खिलाफ भाजपा को एक बड़ा मुद्दा जरूर मिल गया है।

जीवन धारा

रामचंद्र शुक्ल

साहसी आदमी पहले तो जल्दी डरता नहीं और डरता भी है, तो संभल कर अपने बचाव के उद्योग में लग जाता है। भय जब स्वाभाविक हो जाता है, तब कायरता भी भीरुता कहलाती है और भारी दोष माना जाता है।

सुखी और निर्भय होने का सबको अधिकार है

***किसी** आती हुई आपदा की भावना या दुख के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण मनोविकार होता है, उसी को भय कहते हैं। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए। क्रोध दुख के कारण के स्वरूपबोध के बिना नहीं होता। यदि दुख का कारण चेतन होगा और यह समझा जाएगा कि उसने जान-बूझकर दुख पहुंचाया है, तभी क्रोध होगा। पर भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं; इतना भर मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुंचेगी। यदि कोई ज्योतिषी किसी से कहे कि 'कल तुम्हारे हाथ-पांव टूट जाएंगे' तो उसे क्रोध न आएगा; भय होगा। पर उसी से यदि कोई दूसरा आकर कहे कि 'कल अमुक-अमुक तुम्हारे हाथ-पैर तोड़ देंगे', तो वह तुरंत त्योरी बदलकर कहेगा कि 'कौन है हाथ-पैर तोड़नेवाले? देख लूंगा।'*

भय का विषय दो रूपों में सामने आता है-असाध्य रूप में और साध्य रूप में। असाध्य विषय वह है, जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव हो या असंभव समझ पड़े। साध्य विषय वह है, जो प्रयत्न द्वारा दूर किया या रखा जा सकता हो। मान लीजिए, दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे या आनंद से बातचीत करते चले जा रहे हैं। इतने में सामने शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने आदि का प्रयत्न करें, तो बच सकते हैं। विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार तो होती ही है, पर बहुत कुछ मनुष्य की प्रकृति पर भी अवलंबित रहती है। क्लेश के कारण का ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता का निश्चय अपनी विवशता या अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। यदि यह अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने के अनभ्यास या साहस के अभाव के कारण होती है, तो मनुष्य स्तंभित हो जाता है और उसके हाथ-पांव नहीं हिल सकते। पर कड़े दिल का या साहसी आदमी पहले तो जल्दी डरता नहीं और डरता भी है, तो संभल कर अपने बचाव के उद्योग में लग जाता है। भय जब स्वभावगत हो जाता है, तब कायरता भी भीरुता कहलाती है और भारी दोष माना जाता है। जीवन के और अनेक व्यापारों में भी भीरुता दिखाई देती है। एक ही प्रकार की भीरुता ऐसी है, जिसकी प्रशंसा होती है। वह धर्म-भीरुता है।

जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार निर्भय होने का भी। निर्भयता के लिए दो बातें अपेक्षित होती हैं -पहली तो यह कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट न हो; दूसरी यह कि दूसरे हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस न कर सकें। इनमें से एक का संबंध उत्कृष्ट शील से है और दूसरी का शक्ति और पुरुषार्थ से। इस संसार में किसी को न डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती। साधु से साधु प्रकृति वाले को क्रूर लोभियों और दुर्जनों से क्लेश पहुंचता है।

कूटनीति से ही हारेगा इस्लामिक स्टेट

तालिबान अकेले 'आईएसआईएस-के' के खतरे को रोकने में असमर्थ है। यह देखते हुए कि अफगानिस्तान में अमेरिकी पदचिह्न अब नहीं हैं, कूटनीति का तकाजा है कि इस्लामिक स्टेट के खिलाफ तालिबान से खुफिया जानकारी लेने के लिए सहयोग बढ़ाया जाए, जिससे आतंकवाद विरोधी हितों को फायदा होगा।

क्रिस्टोफर पी. कोस्टा
द न्यूयॉर्क टाइम्स

इस्लामिक स्टेट के खिलाफ आतंक-विरोधी जंग में अमेरिका ने कई जीतें दर्ज की हैं, इसके बावजूद वह अभी तक यह समझ नहीं पाया है कि उसे कैसे हराया जाए। रूस की राजधानी मास्को में 22 मार्च को एक कन्सर्ट हॉल पर हुए आतंकवादी हमले में 130 से ज्यादा लोग मारे गए और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह ताजा घटना याद दिलाती है कि इस्लामिक स्टेट एक भयावह खतरा बना हुआ है, खासकर इस्लामिक स्टेट-खोरासन (आईएसआईएस-के), जो अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान में सक्रिय है।

नए साल की शुरुआत से ही 'आईएसआईएस-के' ने ईरान और तुर्किये में जानलेवा हमले शुरू कर दिए। मास्को हमले के चार दिन बाद आईएसआईएस से संबद्ध अल-बतर मीडिया ने इटली, स्पेन और ब्रिटेन के लिए धमकी भरा संदेश प्रकाशित किया- 'अगला कौन'? फ्रांस और इटली, दोनों ने तबसे आतंकी खतरे से निपटने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। इस्लामिक स्टेट को उसकी स्वघोषित 'खिलाफत' से अलग करना उसे हराने के समान नहीं है। अपने चरम दिनों में इसमें 80 से अधिक देशों के 40,000 से ज्यादा विदेशी लड़ाके थे। आईएसआईएस ने खुद को अन्य देशों में पुनर्गठित किया है, अब वह ज्यादा खतरनाक रूप में, लेकिन पहचान में न आने योग्य ढंग से भूमिगत हो रहा है।

इस खतरे को अमेरिका और उसके सहयोगियों तक पहुंचने से रोकने के लिए अमेरिका को दो दशकों की आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञता को बचाना होगा। इसके अलावा, कुछ और गंभीर खतरे हैं, जिन पर वाशिंगटन को ध्यान देना चाहिए, जिनमें चीनी दुस्साहस और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की चुनौती शामिल है।

लेकिन अमेरिकियों को सुरक्षित रखने के लिए आतंकवाद का मुकाबला रणनीतिक प्राथमिकता में बने रहना चाहिए-और इसमें दुनिया के उन हिस्सों में इस्लामिक स्टेट पर नजर रखने का तरीका खोजना शामिल है, जहां अब अमेरिका का कोई पदचिह्न नहीं है।

11 सितंबर, 2001 को अल कायदा के आतंकी हमले के बाद अमेरिकियों को खुद को तैयार रखने के लिए कहा गया था, क्योंकि आतंक से जंग पीढ़ियों तक चलने वाली थी। दशकों तक चली जंग में अमेरिका ने कुछ भयंकर गलतियां कीं और अपना ध्यान राष्ट्रीय सुरक्षा से हटाकर विभिन्न भू-राजनीतिक खतरों पर केंद्रित कर लिया।

सक्रिय संघर्ष क्षेत्रों से अपने सैनिकों और खुफिया तंत्रों को वापस बुलाकर अमेरिका ने 'आईएसआईएस-के' जैसे समूहों को फिर से उभरने का मौका दिया है। यह हार मानने का समय नहीं है, अन्यथा हम खुद को एक उभरते हुए प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए पाएंगे।

पश्चिम के आक्रामक सैन्य अभियानों ने खिलाफत को खत्म करने में मदद की और हाल के वर्षों में फिलीपीन और सीरिया सहित अन्य देशों में आईएसआईएस लड़ाकों की गतिविधियों को कम कर दिया। लेकिन गायब होने के बजाय वे फिर से संगठित हो रहे हैं, उसी बैनर के तले नए लड़ाकों की भर्ती कर रहे हैं और नई साजिशें रच रहे हैं। उनमें से कुछ गुट अन्य देशों में फिर से प्रकट हो गए हैं, वे बेहतर ढंग से प्रशिक्षित हैं और उन्हें तलाशना व उनसे बचना मुश्किल है। जैसा कि हम अभी देख रहे हैं, वे कुछ लक्षित देशों में घुसपैठ करके आतंकी हमलों को अंजाम देने पर आमादा हैं।

अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी से पहले 'आईएसआईएस-के' का प्रभाव सीमित था, खासकर दूसरे देशों में हमला करने की उसकी क्षमता। तालिबान और 'आईएसआईएस-के' एक-दूसरे के दुश्मन हैं और 2015 से ही दोनों एक-दूसरे से लड़ रहे हैं। सत्ता में आने के बाद तालिबान 'आईएसआईएस-के' से मुकाबला करने और उसके लड़ाकों को नियंत्रण में रखने का इरादा रखता था, लेकिन उसे मिली-जुली सफलता ही मिली। बेशक तालिबानी लड़ाके बेहद प्रभावशाली हैं, लेकिन नई आतंकवाद विरोधी भूमिका में वे उतने प्रभावी नहीं हैं। उन्होंने 'आईएसआईएस-के' के कमांडरों को खत्म करने और कुछ क्षेत्र वापस पाने में थोड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी अब भी अफगानिस्तान की सीमाओं पर सक्रिय हैं-और अब भी हमला करने की क्षमता रखते हैं। चूंकि तालिबान को अफगानिस्तान में 'आईएसआईएस-के' के कैदियों को सीमित करने में कुछ सफलता मिली है, इसलिए समूह ने जानबूझकर अपनी ऊर्जा 'अंतरराष्ट्रीयकरण' के एजेंडे पर केंद्रित की है। 'आईएसआईएस-के' के पास अब चरमपंथियों का एक विशाल नेटवर्क है, जिसका वह फायदा उठा सकता है, जो काकेशस और मध्य एशिया जैसे अस्थिर क्षेत्रों में फैला हुआ है। हजारों मध्य एशियाई लोग इस्लामिक स्टेट में शामिल हो गए हैं, जिनमें कई उच्चके और ताजिक 'आईएसआईएस-के' में नेतृत्व की स्थिति में हैं।

तालिबान अकेले 'आईएसआईएस-के' के खतरे को रोकने में असमर्थ है। अल कायदा और तालिबान का विरोध करने वाले समूहों का विवेकपूर्ण समर्थन करके तालिबान को सत्ता से हटाने की कोशिश करने का समय शायद बीत चुका है। ऐसे में, अब कूटनीति का तकाजा है कि वाशिंगटन एवं उसके सहयोगी तालिबान को 'आईएसआईएस-के' पर दबाव बनाने के लिए प्रोत्साहन देकर उनसे खुफिया जानकारी साझा करे। हो सकता है कि तालिबान ने 11 सितंबर के हमलों के बाद ओसामा बिन लादेन को अमेरिका को सौंपने से मुल्ला उमर के दुर्भाग्यपूर्ण इन्कार से सीख ली हो। या शायद नहीं भी।

हालांकि 'आईएसआईएस-के' को हराने के प्रयास में तालिबान से एक विश्वसनीय आतंकवाद विरोधी भागीदार बनने की उम्मीद करना अवास्तविक है। लेकिन सहयोग का कुछ स्तर आवश्यक है, चाहे वह कितना भी अरुचिकर क्यों न हो। आतंकवाद-विरोध में इतनी महत्वपूर्ण मानवीय बुद्धिमत्ता केवल जमीनी स्तर पर ही एकत्रित की जा सकती है। चूंकि अफगानिस्तान में अमेरिकी पदचिह्न अब नहीं है, इसलिए इस्लामिक स्टेट के खिलाफ तालिबान से मिली खुफिया जानकारी से आतंकवाद विरोधी हितों को फायदा होगा। पर यह सहयोग सूचना साझा करने तक ही सीमित रहना चाहिए, प्रशिक्षण या उपकरण देने तक नहीं।

भीरुता का संयोजक...

सूत्र

भीरुता के संयोजक अवयवों में क्लेश सहने की आवश्यकता और अपनी शक्ति का अविश्वास प्रधान है। शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागनेवाला शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता, तभी अपनी शक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी रक्षा का विश्वास नहीं रखता। भीरुता की तह में सहन करने की अक्षमता और अपनी शक्ति का अविश्वास छिपा रहता है।

दूसरा पहलू

ऑस्ट्रेलिया के क्वीन्सलैंड में ही सांपों की सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। यहां 120 किस्म के सांप पाए जाते हैं।

इतने सांप क्यों निकल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में?

ऑस्ट्रेलिया के क्वीन्सलैंड प्रांत स्थित सनशाइन कोस्ट की एक जेल से फोन आया। एक सेल में सांप था। कुछ घंटों के बाद एक स्कूल, एक गैरेज और एक रिटायरमेंट रूम के स्विमिंग पूल से भी सांप निकलने की खबरें आईं। सांप पकड़ने की सर्विस चलाने वाले स्टूअर्ट मैकेंजी के लिए इतना अच्छा समय कभी नहीं था। इन दिनों रोज उनके पास सांप पकड़ने की 35 से ज्यादा कॉल आती है। क्वीन्सलैंड में सांपों की सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इन्हें 120 किस्म के सांप पाए जाते हैं। इनमें से दो तिहाई सांप जहरीले होते हैं, जिनमें से कुछ तो अत्यंत खतरनाक होते हैं। इसके बावजूद सांप काटने से होने वाली मौत का आंकड़ा बहुत कम, सालाना दो ही है।

नताशा फ्रॉस्ट

अप्रैल से सितंबर तक, जो ऑस्ट्रेलिया में ठंड का समय है, सुषुप्तावस्था के दौरान सांपों में अमूमन सुस्ती आ जाती है। इस अवधि में कई बार वे सप्ताह भर तक न खाते-पीते हैं, न ही हिलते-डुलते हैं। लेकिन जब से पृथ्वी गर्म हो रही है, और दक्षिणी क्वीन्सलैंड का मौसम उपोष्णकटिबंधीय से उष्णकटिबंधीय हुआ है, तब से सांपों की सुषुप्तावस्था की अवधि भी घटी है। यानी मानवीय आवासों में उनकी गतिविधियां पहले की तुलना में बढ़ गई हैं। 'सिर्फ यही नहीं कि यहां सांप अब पूरे साल तुलनात्मक रूप से ज्यादा सक्रिय रहते हैं, बल्कि वे रातों को भी लंबे समय तक सक्रिय रहते हैं', क्वीन्सलैंड यूनिवर्सिटी में जीवविज्ञान के प्रोफेसर ब्रायन फ्राई कहते हैं। मैकेंजी कहते हैं कि सांपों की सक्रियता बढ़ने के कारण अब उनकी जाड़े की छुट्टी छोटी होती जा रही है। सांप पकड़ने वाले अपने साथ सिर्फ धातु का एक हुक रखते हैं, जिसमें सांपों को फंसाकर बैग में बंद कर देते हैं, फिर उन्हें ऐसी जगह छोड़ आते हैं, जहां से उनके मानवीय आवासों में लौटने की आशंका कम रहती है। वे इसका ध्यान रखते हैं कि सांपों को कम से कम नुकसान पहुंचे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का कानून कंगारू और दूसरे वन्यजीवों के साथ सांपों को भी संरक्षण देता है। सांप पकड़ने की फीस करीब 100 डॉलर है। चूंकि अगले 25 साल में सनशाइन कोस्ट की आबादी 50 फीसदी बढ़कर पांच लाख हो जाने का अनुमान है, ऐसे में वहां बहुत तेजी से जंगल काटकर भवन निर्माण का काम चल रहा है। इससे भी आसपास के जंगल और झाड़ियों में रहने वाले सांप भोजन और ठिकाने की खोज में मानवीय आबादी में घुस रहे हैं।

सांप पकड़ने के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सांपों को कम से कम नुकसान पहुंचे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कंगारू के साथ सांपों को भी संरक्षण देता है।

आंकड़े

गन्ना उत्पादक देश

गन्ने के उत्पादन में ब्राजील के बाद हमारा देश दूसरे स्थान पर है। ब्राजील में कुल वैश्विक उत्पादन का सबसे ज्यादा 38 फीसदी उत्पादन होता है।

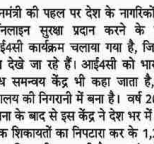

आंकड़े वर्ष 2021 के | स्रोत: FAO

जो व्यक्ति सत्य-शील का त्याग कर देता है, उससे इंसानियत स्वतः दूर हो जाती है। भोग-विलास में फंसकर व्यक्ति अपना और दूसरों का जीवन कष्टमय बना देता है।

सत्य और सुख

अंतर्यात्रा
शिव कुमार गोयल

खलील जिब्रान से एक बार किसी ने पूछा, आज दानवता, हिंसा और अनैतिकता का बोलबाला क्यों है? जिब्रान ने उसे बताया, ईश्वर ने जब आदमी को दुनिया में भेजा, तो उसके दोनों हाथों में एक-एक घड़ा थमा दिया और कहा कि एक घड़े में सत्य भरा है, जिसका पालन कल्याणकारी होगा। दूसरे में सुख है, जो विषय-वासना की चाह पैदा करता है। तुम जगत में जा रहे हो, जहां शैतान (अज्ञान) और माया (अविद्या) का राज है। प्राण देकर भी सत्य की रक्षा करना, और सुख की कामना सीमित रखना। यह मत भूलना कि तुम्हारे दाहिने हाथ में सत्य का घड़ा है और बाएं हाथ में सुख का।

इंसान दोनों घड़े लेकर चला। रास्ते में वह पेड़ की छाया में बैठा, तो नींद आ गई। ईश्वर की बात सुनकर शैतान पीछा कर ही रहा था। उसने घड़े का स्थान बदल दिया। इंसान भ्रम में पड़कर सत्य को लुटाने लगा। सत्य-शील का घड़ा खाली हो गया। उसके पास केवल सुख-सुविधाएं ही रह गईं। इसी कारण आज संसार में दानवता, हिंसा और क्रूरता का बोलबाला दिखाई देता है। जो व्यक्ति सत्य-शील का त्याग कर देता है, उससे इंसानियत स्वतः दूर हो जाती है। भोग-विलास और दुर्व्यसनों में फंसकर व्यक्ति अपना और दूसरों का जीवन कष्टमय बना देता है।

आज का इतिहास

भारत ने दूसरी बार 2011 में क्रिकेट विश्व कप पर किया कब्जा

दो अप्रैल, यह दिन भारत के लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2011 में आज ही के दिन भारत ने दूसरी बार क्रिकेट विश्व कप पर कब्जा करके 1983 की विश्व कप जीत की स्मृतियों को ताजा कर दिया। 1679 : मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी सल्तनत के हिंदुओं पर फिर से जजिया कर लगाया। इस कर को अकबर ने समाप्त किया था। 1902 : हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के फनकार बड़े गुलाम अली खां का जन्म। 1933: भारतीय क्रिकेट के जनक माने जाने वाले रणजीत सिंह का निधन। 1912 : टाइटैनिक का सामुद्रिक परीक्षण शुरू। 1970 : असम पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत के उत्तर-पूर्व में मेघालय को स्वायत्तशासी राज्य का दर्जा हासिल हुआ।1986 : अमेरिकी विमानन कंपनी के बोइंग विमान में बीच हवा में बम फटने से सुराख हुआ। चार यात्री हवा के दबाव से विमान से गिरे। पायलट ने विमान को सुरक्षित उतारा।

साइबर सुरक्षा के लिए मजबूत पहल

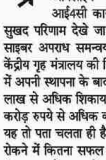

'आई4सी' के कारण प्रवर्तन एजेंसियों और हितधारकों के बीच समन्वय में न सिर्फ सुधार हुआ है, बल्कि यह साइबर अपराध से निपटने में भी सक्षम है।

रूपाली मेहरा | रणनीति

प्रधानमंत्री की पहल पर देश के नागरिकों को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करने के लिए आई4सी कार्यक्रम चलाया गया है, जिसके सुखद परिणाम देखे जा रहे हैं। आई4सी को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र भी कहा जाता है, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की निगरानी में बना है। वर्ष 2020 में अपनी स्थापना के बाद से इस केंद्र ने देश भर में 4.7 लाख से अधिक शिकायतों का निपटारा कर के 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की बचत की है। इन आंकड़ों से यह तो पता चलता ही है कि भारत साइबर अपराधों को रोकने में कितना सफल हुआ है, यह भी स्पष्ट होता है कि 2020 के बाद से दर्ज मामलों की संख्या में 500 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और बचाई गई धनराशि में 800 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यानी राष्ट्रव्यापी साइबर अपराध रोकथाम तंत्र अब गति पकड़ चुका है।

ऐसे समय में, जब भारत दुनिया की शीर्ष तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की ओर अग्रसर है, मजबूत साइबर सुरक्षा प्रणाली का काफी महत्व है। जब तक देश खुद को साइबर-अनुकूल राष्ट्र के रूप में स्थापित नहीं कर लेता, तब तक विकसित भारत की परिकल्पना अधूरी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक भाषण में कहा भी था-'साइबर सुरक्षा अब केवल डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है। यह राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा का विषय है।' भारत के सामने साइबर सुरक्षा की बड़ी चुनौती है। जब भारत ने जी-20 की वेबसाइट लॉन्च किया था, तो हैकरों द्वारा प्रति मिनट 16 लाख हमले हुए थे और भारत इनसे बचाव करने में सफल रहा था। जी-20 शिखर सम्मेलन में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा भी था- 'हालांकि, प्रौद्योगिकी मनुष्यों, समुदायों और देशों को करीब लाने की दिशा में एक सकारात्मक विकास है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व और वैश्विक ताकतें प्रौद्योगिकी का उपयोग नागरिकों और सरकारों को आर्थिक व सामाजिक नुकसान पहुंचाने के लिए कर रही हैं। इसलिए यह सम्मेलन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह डिजिटल दुनिया को सभी के लिए सुरक्षित बनाने की समन्वित कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण वैश्विक पहल हो सकता है।' गृहमंत्री अक्सर कहते रहे हैं कि, आतंकवाद, आतंक के वित्तपोषण, कट्टरपंथ, सहित नई और उभरती, पारंपरिक और गैर-पारंपरिक चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्रों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों की क्षमताओं को बढ़ाना आवश्यक है। केंद्र सरकार ने एक समान साइबर रणनीति की रूपरेखा तैयार करने, साइबर अपराधों की वास्तविक समय पर रिपोर्टिंग करने, एलईए क्षमता का निर्माण करने, विश्लेषणात्मक उपकरण बनाने, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं का राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित करने, साइबर स्वच्छता सुनिश्चित करने और हर नागरिक तक साइबर जागरूकता फैलाने की दिशा में काम किया है। देश में शुरू की गई सेफ सिटी परियोजना ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों अपराधों से निपटने के लिए अत्याधुनिक कमांड सेंटर प्रदान करती है।

देश में जो तीन नए आपराधिक कानून बने हैं, उनमें भी साइबर अपराधियों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले कानूनों की खामियों को लगभग समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। अपराधी तत्वों द्वारा इस्तेमाल किए गए डिजिटल उपकरणों को अब सबूत के रूप में मान्यता दे दी गई है। जांच एजेंसियों को सशक्त बनाते हुए देश के सभी पुलिस स्टेशनों में क्राइम ऐंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क ऐंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) लागू किया गया है। भारतीय साइबर-अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) के जरिये साइबर अपराध के खिलाफ एक समन्वित और व्यापक कार्रवाई सुनिश्चित हो सकती है। आई4सी साइबर अपराध से संबंधित सभी मुद्दों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके कारण प्रवर्तन एजेंसियों और हितधारकों के बीच समन्वय में न सिर्फ सुधार हुआ है, बल्कि साइबर अपराध से निपटने के लिए जरूरी क्षमता भी हासिल हो गई है।

Special arrangements by Amar Ujala

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक समीर माहेश्वरी द्वारा नवभारत प्रेस, नवभारत भवन, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जी.ई.रोड, रायपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित. प्रधान संपादक : समीर माहेश्वरी, संपादक : राजेश आर. जोशी* (पी.आर.बी. कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिये जिम्मेदार)
■ रायपुर फोन : 0771-4343434, 2535555-66-77, ■ पुष्पनेश्वर : 0674-2380511/2380518 ■ बिलासपुर : 07752-230591, 407748, 224563 ■ वर्ष 65 ■ अंक 46 (रजि.नं. 13045/59 आरएनआई), पो. रजिस्टर्ड नं. छ.ग./रायपुर संभाग/61/2022-24 ■ भिलाई फोन : (0788) 2294181, 4030655

संपादकीय

भारत 'एशिया की फैक्ट्री' बन सकता है, बशर्ते !

कई स्थापित संस्थाओं के प्रमुखों और भारत पर शोध कर रहे विद्वानों ने माना है कि देश चीन को पछाड़कर 'एशिया की फैक्ट्री' बन सकता है, लेकिन उनका शक अफसरशाही की क्षमता और लगन को लेकर है। मैन्युफेक्चरिंग क्षेत्र में सिंगापुर की एक कंपनी भारत में उपक्रम लगाने आई तो उसे कागजी कार्रवाई में छह माह लगे। वर्ल्ड बैंक के भारतीय मूल के अध्यक्ष ने कहा कि भारत में इस मकाम पर पहुंचने की क्षमता तो है पर उसके पास समय केवल तीन-चार साल का ही है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक भारतीय लेखक ने आगामी 4 अप्रैल को रिलीज होने वाली पुस्तक में लिखा कि भारत को पहले शिक्षा और अफसरशाही में सुधार करना होगा। उनके शोध के अनुसार कक्षा से जितने प्रतिशत छात्र नदारद रहते हैं, उतने ही शिक्षक भी नहीं आते। औसतन हर 15 माह में अधिकारियों का ट्रांसफर होता है, लिहाजा उद्देश्य-विशेष पर न तो उसकी समझ विकसित होती है ना ही उसे अंजाम देने का समय मिलता है। अगर आंकड़े देखें तो फिलहाल भारत और चीन में जमीन-आसमान का अंतर है। चीन में भारत के मुकाबले 12 गुना ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, जिनमें दूने से ज्यादा कामगार लगे हैं। उनका जीडीपी में प्रतिशत-शेयर भी डेढ़ गुना है और उनसे निर्यात भी आठ गुना अधिक है। ध्यान रहे कि चीन की जीडीपी का आयतन भी साढ़े छह गुना ज्यादा है। आबादी में जरूर भारत ने विगत वर्ष चीन को पछाड़ दिया। उपरोक्त शोधकर्ता ने पाया कि ग्रामीण भारत में जहां पांच साल की स्कूलिंग के बाद हर पांच में तीन बच्चे कक्षा 2 के शब्द लिख-बोल नहीं सकते और जहां पिछले पांच वर्षों में यह प्रतिशत लगातार बढ़ा है, सरकारों का ध्यान मिशन मोड में आकर शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार पर होना चाहिए। अगले पांच वर्षों में देश की जीडीपी वृद्धि औसतन 6.5% रहने की उम्मीद है जबकि चीन, जापान और दक्षिण कोरिया अपने विकास-काल में औसत 10 फीसदी की रफ्तार से दौड़े थे। भारत के नीति-निर्माताओं को आमूलचूल बदलाव करना होगा।

प्रेरणा

कष्ट कभी भी उतना परेशान नहीं करता, जितनी उसकी चिंता पीड़ा पहुंचाती है। - **स्वेट मॉर्डेन**

बामुलाहिजा • यह सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि उसे खतरा महसूस हो रहा है या नहीं...

न्यायपालिका को आज किससे खतरा है?

शेखर गुप्ता
एडिटर-इन-चीफ, 'द प्रिन्ट'
𝕏@ShekharGupta

उच्चतर न्यायपालिका को लेकर पिछले दिनों काफी गहमागहमी रही। सबसे पहले तो बार काउंसिल के 600 वकीलों (हरीश साल्वे सहित) के दस्तखत से सीजेआई के नाम एक पत्र भेजा गया, जिसमें न्यायपालिका को ऐसे समय में पूरा समर्थन देने की पेशकश की गई, जबकि कुछ पार्टियां न्यायपालिका को कमजोर करने के मकसद से उस पर हमला कर रही हों। इस कदम को आमतौर पर चलने वाली राजनीति का हिस्सा माना जा सकता है, क्योंकि कुछ राज्यों (खासकर पश्चिम बंगाल) में बार काउंसिल के चुनाव पार्टियों के चुनाव चिह्न पर लड़े जाते रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी कई बार हिमायत भी कर चुके हैं। उन्होंने न्यायपालिका को समर्थन जाहिर करने वाले उपरोक्त पत्र को साझा भी किया, जिसमें वकीलों ने चिंता जताई कि न्यायपालिका खतरे में है और जिसमें उन्होंने दिलचस्प टिप्पणी की है- 50 साल पहले कांग्रेस ने 'प्रतिबद्ध न्यायपालिका' की मांग की थी।

यह हमें 1973 और 1977 के दौर में ले जाता है, जब इंदिरा सरकार ने सीजेआई के पद पर वरिष्ठतम जज को नियुक्त करने की मान्य परंपरा का दो बार उल्लंघन किया। दोनों नियुक्तियां राजनीति से प्रेरित थीं। दरअसल, दोनों नियुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उस गहमागहमी भरे दशक में जारी किए गए अहम फैसले से जुड़ी थीं। पहला मामला अप्रैल 1973 का है, जब तीन वरिष्ठतम जजों- जयशंकर मणिलाल शेलत, ए.एन. ग्रोवर, के.एस. हेगड़े को किनारे करके अजितनाथ राय को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उक्त तीनों जजों ने इस्तीफा दे दिया। यह मामला केशवानंद भारती मामले में सुनाए गए फैसले से जुड़ा था। 13 जजों की पीठ ने 7-6 के बहुमत से फैसला सुनाया था कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है। राय उन छह जजों में थे जिन्होंने इससे इनकार किया था। जिन तीन जजों को किनारे किया गया था, उन्होंने बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को मान्य किया था, जिसके लिए हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए।

दूसरा मामला जनवरी 1977 का है, जिसके चंद दिनों बाद आपातकाल को वापस ले लिया गया था, लेकिन इंदिरा गांधी सबसे ज्यादा परेशानी पैदा करने वाले जज को सजा दिए बिना छोड़ने वाली नहीं थीं। इस बार जस्टिस एच.आर. खन्ना को किनारे करके एम.एच. बेग को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। खन्ना ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 1973 में ही दिए जा चुके संकेत को समझ लिया होगा। वे केशवानंद भारती मामले में फैसला सुनाने वाले बहुमत वाले सात जजों में शामिल थे। इससे भी अहम बात यह है कि इमरजेंसी वाले दौर में बंदी प्रत्यक्षीकरण से जुड़े जिस मशहूर 'एडीएम जबलपुर मामले' में पांच जजों की पीठ ने चार के बहुमत से नागरिक स्वाधीनताओं में कटौती करने के सरकार के फैसले का समर्थन किया था, उससे असहमति केवल जस्टिस खन्ना ने दर्ज कराई थी।

इंदिरा गांधी का सत्ता-तंत्र जजों को अपनी समाजवादी धारा के प्रतिकूल मानता था। उनकी अंदरूनी मंडली सोवियत-शैली वाला वामपंथी झुकाव रखती थी। इसलिए उनका मानना था कि भारत को ऐसे जजों की जरूरत थी, जिनमें जनता की इच्छा को लागू करने के उनके प्रयासों की समझ हो। इस दृष्टि से जजों को एक निर्वाचित सरकार

यह परिदृश्य 50 साल पहले के परिदृश्य से उल्टा है?

यह परिदृश्य 50 साल पहले से उल्टा है? सोच यह है कि न्यायपालिका खतरे में है और वकीलों व कार्यपालिका की जमात उसकी 'रक्षा' को एकजुट है। खतरा क्या इतना गंभीर है कि यह उस परिदृश्य से उल्टा है जब न्यायपालिका इंदिरा गांधी की कार्यपालिका से संघर्ष कर रही थी?

द्वारा शासन की 'लोकप्रिय' शैली के प्रति 'प्रतिबद्ध' होना चाहिए था। माना जाता है कि 'प्रतिबद्ध न्यायपालिका' का विचार सबसे पहले पेश करने का श्रेय दिवंगत मोहन कुमारमंगलम को है, जिन्हें इंदिरा मंत्रिमंडल में शामिल एकमात्र कम्युनिस्ट नेता माना जाता था। सर्वसत्तावादी नेताओं की एक खब्त यह होती है कि तमाम संस्थाएं उनके हिसाब से 'परफेक्ट' हों क्योंकि वे मानते हैं कि केवल वे ही संस्थाओ को जन्म दे सकते हैं और उनकी रक्षा कर सकते हैं। श्रीमती गांधी ने जजों को 'सुपरसीड' करके न्यायपालिका को ऐसी ही एक संस्था में तब्दील करना चाहा। प्रधानमंत्री मोदी 1973 में शुरू हुए इसी चलन का जिक्र कर रहे हैं।

इसके बाद तो यही सवाल उभरता है कि न्यायपालिका को दबाने की कोशिश कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री का एक्स पर पोस्ट कांग्रेस की ओर ही इशारा कर रहा है। अगर ऐसा है, तो यही कहा जाएगा कि मात्र 52 सांसदों वाली कांग्रेस अपनी हैसियत से कई गुना ज्यादा ताकत जता रही है! न्यायपालिका को 'परफेक्ट' नहीं कहा जा सकता है, लेकिन क्या इन दिनों वह जरूरत से ज्यादा 'इम्परफेक्ट' हो रही है? अगर आप मोदी-विरोधी हैं तब आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट 2010 से 2014 के बीच के घोटाले वाले यूपीए-2 दौर में रास्ते से भटक गया। उस दौर में हमारे 'मी लॉर्ड' तमाम प्रभावशाली आरोपी हस्तियों को दोषी ठहराने के आदेश जारी कर रहे थे, जिनमें कुछ बिलकुल मौखिक थे और वे टू-जी स्पेक्ट्रम जैसे 'घोटाले' की जांच की सीधी निगरानी कर रहे थे। लेकिन क्या यह पत्र और उसका समर्थन गुमनाम चुनावी बॉन्ड पर दिए फैसले के कारण आया है? हो सकता है, हालांकि जो खुलासे हुए हैं वे एकपक्षीय नहीं हैं। चुनावी बॉन्ड का लाभ हर दल को मिला और गोपनीयता बनाए रखने में सबकी मिलीभगत रही, लेकिन इससे कुछ अहम मुद्दे उभरे हैं, जैसे यह कि 'एजेंसियों' या रेगुलेटरों ने कंपनियों पर जो छापे मारे और जो कार्रवाई की गई, उनके बीच क्या संबंध है और भुगतान का समय क्या था? वकीलों के पत्र को इसलिए सावधानी से पढ़ें कि इसे लिखने के पीछे के कारण को समझ सकें। इसे बचाव की कार्रवाई के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि इसे तब भेजा गया है, जब चुनाव अभियान शुरू हुआ है। **(ये लेखक के अपने विचार हैं)**

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

कोई प्रिय भजन गुनगुनाने से भी शांति मिलती है

मनोवैज्ञानिक लोग इस बात की सलाह देते हैं कि यदि आप उदास हैं तो अपने भीतर के 'इनर चाइल्ड' पर काम करें। हर मनुष्य के भीतर एक बच्चा है और वह जिंदा है। जैसे ही हम अपने भीतर के बच्चे के प्रति जागरूक होते हैं, अपने बचपन की कुछ यादों को ताजा करते हैं तो सकारात्मक होने लगते हैं। भीतर शांति उतरने लगती है। आध्यात्मिक जगत में भी इसका प्रयोग होता है। उसका नाम है भजन। जैसे बच्चे किसी भी दृश्य को देखकर बहुत सरलता से ताली बजाते हैं। कोई पंक्ति दोहराने लगते हैं। भजन में ऐसा ही होता है। रामराज्य पर एक जगह तुलसीदास जी ने लिखा है- 'भजहु प्रनत प्रतिपालक रामहि। सोभा सील रूप गुन धामहि।' अयोध्या के लोग एक-दूसरे को ये सीख देते थे कि रामजी के गुण गाएं। 'श्री राम को भजो, शोभा, शील, रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथजी को भजो'। दो-दो बार भजो शब्द इसलिए लिखा है कि भजन करने से भी हम अपने भीतर के इनर चाइल्ड तक पहुंच जाते हैं। दिनभर में दो-तीन बार किसी भजन की प्रिय लगने वाली केवल एक पंक्ति को यदि ताली बजाकर, आंख बंद करके अकेले में गुनगुनाएं, तो आप पाएंगे कि धीरे-धीरे शांति उतरने लगी है। • Facebook: Pt. Vijayshankar Mehta

मुद्दा • लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होने वाले चुनावों का महत्व ही इसमें है कि वे सबको समान अवसर मुहैया कराते हैं

चुनाव न केवल निष्पक्ष हों बल्कि निष्पक्ष दिखाई भी दें

आरती जेरथ
राजनीतिक टिप्पणीकार
aratijerath@gmail.com

हाल के दिनों में, अमेरिका और जर्मनी की सरकारों के साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासचिव के कार्यालय ने भी भारत में चुनावों की प्रक्रिया के दौरान हुई दो घटनाओं पर चिंता जताई है। इनमें से एक थी आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और दूसरी थी कांग्रेस को आयकर के नोटिस और पार्टी के खातों को फ्रीज कर देना। उन्होंने इन दोनों ही मुद्दों के समाधान के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और सामयिक कानूनी प्रक्रिया के पालन का आह्वान किया है।

यकीनन, यह टिप्पणी भारत के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप है और मोदी सरकार ने अमेरिका और जर्मनी के दूतों को बुलाकर अपना विरोध सही तरीके से दर्ज कराया। फिर भी, हमें एक बार ठहरकर इस पर विचार करना चाहिए कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में आज हमारी संस्थाओं पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? अहम सवाल यह है कि आज हम उस बिंदु पर क्यों पहुंच गए हैं, जहां पश्चिम के देशों और संयुक्त राष्ट्र को भी लगता है कि वे हमारी आलोचना करने के लिए वैसे ही स्वतंत्र हैं, जैसे वे नियमित रूप से चीन और रूस जैसे निरंकुश देशों या पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे हमारे उन पड़ोसियों की आलोचना करते आ रहे थे, जो बहुत पहले ही लोकतंत्र कहलाने का अधिकार गंवा चुके थे? यह इसलिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये टिप्पणियां ऐसे समय आ रही हैं, जब भारत पिछले साल एक सफल जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर चुका है, उसने यूक्रेन और रूस के बीच तनाव कम करने के लिए सक्रिय रूप से मध्यस्थता भी की थी। वह एक वर्ल्ड लीडर बनने की महत्वाकांक्षा रखता है। ऐसे में हमें ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। भारत आम चुनाव की दहलीज पर है और इस घटना पर पूरी दुनिया का ध्यान लगा हुआ है। नरेंद्र मोदी का लगातार तीसरा कार्यकाल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए मायने रखता है।

वर्तमान के भू-राजनीतिक हालात कुछ ऐसे हैं कि उसमें पश्चिम के लिए भारत की लोकतांत्रिक साख का गहरा होना और भी अधिक महत्वपूर्ण है। चीन के उदय और बीजिंग और मॉस्को के बीच आपसी हितों की धुरी के निर्माण ने स्थापित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया है। भारत- अपने विशाल आकार, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ- रूस-चीन धुरी के समक्ष स्थिरता लाने वाली शक्ति के रूप में उभरने की क्षमता रखता है। हालांकि इसके पीछे पश्चिम का अपना एजेंडा हो सकता है, लेकिन हमारे लिए भी यह समझना महत्वपूर्ण है कि चीन के समक्ष भारत का उदय हमारे लिए फायदेमंद है। यह जरूरी है कि हम एक ऐसी शक्ति के रूप में विकसित हों, जिसे दुनिया भर में सम्मान की दृष्टि से देखा जाए, खासकर हमारे निकटतम-पड़ोस में। और इसमें चीन भी शामिल है, जिसके साथ आज हम विभिन्न बिंदुओं पर सीमा-विवाद में फंसे हुए हैं।

लेकिन चीन का काउंटरपार्ट बनने के लिए हमें एक भिन्न नैरेटिव को सामने रखना होगा और इस नैरेटिव को लोकतंत्र के इर्द-गिर्द रचना होगा। अगर हमें भी एक लोकतांत्रिक तानाशाही के रूप में देखा जाने लगे तो हम चीन से बहुत अलग साबित नहीं होंगे। हमें स्वतंत्र पहचान बनानी होगी, जो चीन और रूस से अलग हो। यह सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि हमें पश्चिम से अपने लिए कोई मान्यता चाहिए। बल्कि यह ग्लोबल साउथ का लीडर बनने की हमारी आकांक्षा के भी अनुरूप है।

आज दो निर्वाचित मुख्यमंत्री- दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और झारखंड के हेमंत सोरेन- भ्रष्टाचार के ऐसे आरोपों में जेल की सलाखों के पीछे हैं, जिनका अभी तक प्रमाणित होना शेष है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस करोड़ों रुपए के बकाया कर-नोटिस की शृंखला के कारण कमजोर पड़ रही है। यहां तक कि राहुल गांधी को भी कहना पड़ रहा है कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं। चुनाव प्रक्रिया प्रभावी होने के बावजूद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) विपक्षी उम्मीदवारों के खिलाफ मामले दर्ज कर रहा है। लेकिन जिन लोगों ने भाजपा से हाथ मिला लिया है- जैसे कि राकांपा के अजित पवार गुट के प्रफुल्ल पटेल- उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को सीबीआई द्वारा हटाकर उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है।

चुनाव न केवल निष्पक्ष होने चाहिए बल्कि निष्पक्ष दिखने भी चाहिए। लोकतांत्रिक चुनावों का महत्व ही समान अवसर प्रदान करने में निहित है। हमें सावधान रहना चाहिए कि कहीं हम बांग्लादेश और पाकिस्तान की डगर पर ना चल पड़ें, जहां प्रमुख विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है और चुनावी लड़ाई को एकतरफा बना दिया जाता है।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

वेब भास्कर

पक्षियों के व्यवहार की अनोखी कहानी कहती यह पुरस्कृत तस्वीर

पक्षियों का व्यवहार बताती यह तस्वीर इस साल के वर्ल्ड नेचर फोटोग्राफी अवॉर्ड्स में विजेता चुनी गई है। इंग्लैंड के शेटलैंड द्वीप पर फोटोग्राफर ट्रेसी को गैनेट्स पक्षियों का झुंड मंडराता नजर आया। अचानक, इन पक्षियों ने पानी के अंदर गोता लगाकर शिकार करना शुरू कर दिया। ट्रेसी ने भी मौके को भुनाते हुए फोटोग्राफी शुरू कर दी। लेकिन पानी के अंदर एक मछली के लिए आपस में लड़ते दो गैनेट्स की तस्वीर ने उन्हें भी चकित कर दिया, जबकि पानी में और भी मछलियां थीं। हजारों तस्वीरों में यह विजेता रही। **तस्वीर साभार :** worldnaturephotographyawards

नजरिया • व्यक्ति केंद्रित राजनीति इसका कारण है

जनसमर्थन का एक बड़ा मौका गंवा रही है आम आदमी पार्टी

मुकेश माथुर
दैनिक भास्कर
𝕏@mukesh1275

आम आदमी पार्टी की स्थापना के अगले कुछ वर्षों में पांच-छह काबिल नेताओं को बाहर कर चुके अरविंद केजरीवाल की टीम से करीब-करीब इतने ही बड़े नेता जेल गए और अब खुद केजरीवाल भी वहीं पर हैं। पार्टी में खौफनाक सन्नाटा है। इतिहास में पहली बार किसी सीएम के जेल चले जाने के बावजूद पार्टी जनसहानुभूति को बड़े पैमाने पर नहीं भुना पा रही है। वह भी तब जब सामने चुनाव हैं। एक-दो अपवाद छोड़ दें तो केजरीवाल ने सेकंड लाइन बनने ही नहीं दी। वन मैन शो! किसी कंपनी के उस सीईओ की तरह जो अपने ही प्रतिभाशाली सहकर्मियों से असुरक्षा महसूस करता है और उन्हें बाहर करता जाता है। बिना समझे कि वे अच्छा करेंगे तो नाम उसी का होगा।

व्यक्ति केंद्रित राजनीति सिर्फ 'आप' की समस्या नहीं है। भाजपा में भी यही हो रहा है। कांग्रेस की तो त्रासदी है कि व्यक्ति नहीं परिवार-केंद्रित नेतृत्व है। इसकी अपनी जटिलताएं हैं। क्या व्यक्ति-आधारित व्यवस्था लीडर के अवसान के बाद आने वाले खालीपन के कारण बुरी ही मानी जाएगी? नहीं। भारत नायक-प्रधान देश है। विलक्षण प्रतिभा, नेतृत्व क्षमता और आम आदमी से कनेक्ट कर लेने वाला चेहरा चमत्कार करता आया है।

प्रधानमंत्री मोदी से पहले लंबी फेहरिस्त है। इंदिरा गांधी, जयललिता, लालू यादव, ममता, मायावती, बाल ठाकरे और फिर अरविंद केजरीवाल। दुर्भाग्य यह कि राजनीति के इन सभी लीजेंड्स में से ज्यादातर की पार्टियां आज अगला नेतृत्व तैयार न करने के परिणाम भोग रही हैं। नेतृत्व तैयार किया भी तो उसमें खून के रिश्ते का पूर्वाग्रह आड़े आ गया। वारिस योग्य था तो पार्टी फिर खड़ी हो गई। नहीं था तो गाड़ी दचके खा खाकर चल रही है।

दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एक व्यक्ति की 'गारंटी' पर चुनाव लड़ रही है। कंगना रनौट ने कहा- काम से नहीं मोदीजी के नाम से जीतेंगे। यह अति-निर्भरता मोदी के करिश्माई नेतृत्व के कारण आज चुनाव जिता रही है, लेकिन भविष्य में उसी सामर्थ्य वाला चेहरा नहीं मिला तो? क्या यह ठीक न रहता कि मोदी के चेहरे के साथ एक सशक्त टीम को भी प्रोजेक्ट किया जाता? भारत की क्रिकेट टीम हमेशा एक-दो सितारों या कभी चार खिलाड़ियों (सचिन, लक्ष्मण, द्रविड़, गांगुली) के इर्द-गिर्द घूमती रही है। ऑस्ट्रेलिया 11 काबिल खिलाड़ियों की टीम के तौर पर मैदान में उतरती और खूब जीतती आई है। भाजपा-आरएसएस के सामने मोदी के बाद का ब्लूप्रिंट तैयार करने की चुनौती है। कांग्रेस में परिवार ने पार्टी का पुनरुद्धार रोक रखा है। नए नेतृत्व, विचारधारा में आमूलचूल परिवर्तन और चौतरफा नई एप्रोच की जरूरत है। यह बदलाव रस्मी तौर पर परिवार से बाहर के व्यक्ति को अध्यक्ष बना देने भर से नहीं आने वाला। लोकतंत्र की दुहाई देने वाली कांग्रेस में भीतर का लोकतंत्र तिरोहित है। पूर्व एआईएडीएमके सुप्रीमो दिवंगत जयललिता को 2014 में निर्विरोध चुना गया। तर्क- 'किसी ने नामांकन ही नहीं किया।' विडम्बना देखिए जयललिता के निधन के बाद कैसा राजनीतिक शून्य पैदा हुआ। बसपा। 'सुप्रीमो' मायावती ने भतीजे आकाश को उत्तराधिकारी घोषित किया। क्या परिवार से बाहर का अनुभवी नेता पार्टी के खत्म होते जनाधार को वापस न जुटाता? वह यह काम कुशलता से करता अगर बहनजी अपने स्वर्णिम काल में ही उसे साथ की कुर्सी पर बैठातीं। 'आप'। विधानसभा चुनाव में राजस्थान जैसे राज्यों में सशक्त चेहरा नहीं था। केजरीवाल समय नहीं दे पाए।

एक करिश्माई चेहरे पर अति-निर्भरता में कुछ अच्छा है तो बहुत कुछ खराब। एक-दो अपवादों को छोड़ दें तो केजरीवाल ने सेकंड लाइन बनने ही नहीं दी। आम आदमी पार्टी ही नहीं, भाजपा के सामने भी भविष्य की यही चुनौती है।

पार्टियों में चुनाव के वक्त लिस्ट बनती है स्टार प्रचारकों की। एक समय भाजपा की सूची में अटल, आडवाणी, जोशी सहित कई सितारे हुआ करते थे। हर एक की सभा में जबर्दस्त भीड़ जुटती। आज मोदी, राहुल, केजरीवाल के अलावा कथित स्टार खाली कुर्सियां देखकर लौटते हैं। अक्सर तूफान से घिरी पार्टी में नए नायक की एंट्री भी होती है लेकिन 'आप' में फिलहाल गुंजाइश कम है। क्या 'आप' के प्रहसन में बाकी पार्टियों के लिए भी सीख छिपी है?

क्लाइमेट • हाल ही में वन दिवस मनाया गया, लेकिन जागरूकता का साफ अभाव दिखा है

अब छाया के लिए भी पेड़ नहीं फ्लाईओवर सहारा हैं

डॉ. अनिल जोशी
पद्मभूषण से सम्मानित
पर्यावरणविद्
draniljoshi@gmail.com

गर्मियां शुरू हो चुकी हैं। विडंबना है कि छांव के लिए पेड़ नजर नहीं आते, रेहड़ी वाला भी फ्लाईओवर के नीचे छांव ढूंढता है। ऐसे हालात में भी अगर हम जल-जंगल की बात नहीं करें तो विनाश से कोई नहीं बचा सकता। हाल ही में (21 मार्च) अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। लेकिन इस पर व्यापक चर्चा नहीं हुई।

देश में करीब 24.62% वनक्षेत्र का दावा किया जाता है, यह आंकड़ा छद्म ज्यादा लगता है। क्योंकि सच्चाई यह है कि यह किसी भी हालत में 14-15% से ज्यादा नहीं है। सरकारी आंकड़े में सभी तरह के पेड़ों को जोड़कर वन का दर्जा दे दिया जाता है। फॉरेस्ट पॉलिसी कहती है कि देश में करीब 33% भूमि पर वन होने चाहिए। राज्यों की भी इसमें हिस्सेदारी समान रूप से होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका सबसे बड़ा मखौल हरियाणा ने उड़ाया है, जहां मात्र 3.5% वन ही बचे हैं। हरियाणा में भूमिगत जल की स्थिति भी बदतर है। लेकिन यहां सरकार की चिंताओं में वनों के लिए स्थान नहीं है क्योंकि शायद उनकी समझ से परे है कि वन भी भूमिगत जल को संचित कर सकते हैं। अकेले अमेजॉन में दुनिया भर के 31% वन हैं। इसके अलावा कई देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने वनों को सुरक्षित रखा है। इसमें रूस का नंबर सबसे आगे आता है, जिसके पास 815 मिलियन हेक्टेयर वन है। उसके बाद ब्राजील, कनाडा, चीन और ऑस्ट्रेलिया हैं, जहां करीब 100 मिलियन हेक्टेयर वन हैं।

एक सवाल यह भी उभरता है कि क्या हमारे 'सरकारी वन' वाकई प्राकृतिक बचे हुए हैं? सही मायनों में प्राकृतिक वन वहीं है, जहां के वृक्ष प्रकृति-भूगोल के हिसाब से हों। देखने में आया है कि हम किसी भी तरह के पेड़ों वाले इलाके को वन का दर्जा दे देते हैं। यही सबसे बड़ी चिंता है। प्रकृति ने स्थान विशेष में खास प्रजातियों को पनपने का मौका दिया है। उदाहरण के लिए केरल में अगर कटहल के पेड़ प्रचुर मात्रा में हैं तो गंगा बेसिन में साल के वृक्ष होते हैं। ओक के वृक्ष हिमालय में ही पाए जाते हैं जबकि अन्य प्रजातियां बेल-कीकर मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते है। क्योंकि इन वनों की संरचना में प्रकृति ने बहुत बड़ा योगदान किया है और यह प्रकृति की मेहनत ही है कि उसने एक स्थान विशेष को खास वनों से आच्छादित किया। लेकिन हमने लगातार कुछ समय से इस रिश्ते को भी ध्वस्त कर दिया। आज हम किसी भी तरह के वृक्षों को लगाकर वनों का दर्जा दे देते हैं। इन छद्म वनों का मिट्टी से भी कोई खासा रिश्ता नहीं होता। इसलिए आज एक बहुत बड़ी जरूरत यह भी है कि हम क्लाइमेट फॉरेस्ट्री, जलवायु वानिकी को जन्म दें और उस पर बहस करें। जिसका सीधा मतलब है कि स्थान विशेष की जलवायु से जो मिलता है, वही वहां का वृक्ष और वन कहलाएगा। यह आज अपने देश और दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी मानी जा सकती है।

एक आंकड़े के अनुसार 50 साल में एक पेड़ 11 लाख रुपए के करीब ऑक्सीजन पैदा करता और करीब 63 लाख रुपए के वायु प्रदूषण को नियंत्रित करता है। एक व्यक्ति प्रतिवर्ष 7.01 टन कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है और उसी की तुलना में एक वृक्ष करीब सात ही टन ऑक्सीजन भी देता है। यह तभी संभव है जब वह वृक्ष स्थानीय हो, क्योंकि अगर आप ऐसे वृक्ष को किसी और जलवायु क्षेत्र में लगाएंगे तो उसकी क्षमताएं अलग होंगी। इसलिए वृक्ष और स्थान विशेष का एक रिश्ता है जो वहां की मिट्टी, पानी व अन्य जलवायु से मिलते हैं। हर एक व्यक्ति दिन भर में करीब 21,600 बार सांस लेता-छोड़ता है और प्रति मिनट में उसे 8 लीटर हवा चाहिए, जिसमें 20% ऑक्सीजन होती है। यह आंकड़ा यह जताने की कोशिश कर रहा है कि वृक्ष और जीवन में क्या रिश्ता है। देश की आबादी के अनुसार आने वाले समय में क्या हमारे पास पर्याप्त वृक्ष होंगे ताकि बेहतर सांस ले सकें? सोचिए। **(ये लेखक के अपने विचार हैं)**

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • मंगलवार • 2अप्रैल • 2024
www.rashtriyasahara.com

रैली की सफलता

नेताओं के जुटान के नजरिए से देखा जाए तो विपक्षी इंडिया गठबंधन की दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली एक सफल रैली थी। इसने अपने अंतर्विरोधों के साथ और उसके बावजूद भी एकजुटता जाहिर की है, जिससे यह संदेश गया है कि इंडिया में एनडीए को चुनौती देने का दम-खम है। भ्रष्टाचार के कथित मामले में जांच एजेंसियों की 'एकपक्षीय' सक्रियता से भी उनके नेताओं के चुनावी जोश में कोई फर्क नहीं पड़ा है। इंडिया के 27-28 दलों की मंच पर कतारबद्ध मौजूदगी इसे प्रामाणिक बनाती है। तभी तो रैली में रखे कांग्रेस के पांच न्यायों में से एक 'चुनाव के दौरान विपक्षी राजनीतिक दलों का आर्थिक रूप से गला घोंटने की जबरन कार्रवाई को तुरंत बंद करने की आयोग से मांग' पर कदम उठाया गया है। आयकर विभाग ने जुलाई तक उसके खाते पर किसी

कार्रवाई से इनकार कर दिया है। यह त्वरित सफलता है। इसके अलावा, चुनाव आयोग से आम चुनावों में समान अवसर मुहैया कराने, चुनाव में हेराफेरी करने के उद्देश्य से विपक्षी दलों के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाइयों पर रोक लगवाने, चुनावी चंदे का उपयोग कर भाजपा द्वारा बदले की भावना, जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी का गठन करने तथा सरकार से हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की तुरंत रिहाई की मांग उन पांच न्यायों में शामिल है। ये बिंदु विपक्ष के चुनाव प्रचार एवं मुद्दे की एक व्यापक आम समझ जाहिर करते हैं। इन्हीं मुद्दों पर विपक्ष चुनाव में सरकार को घेरेगा। इनके बावजूद, दलगत सिद्धांतों एवं इसी आधार पर सीट शेयरिंग के साथ चुनिंदा नेताओं के व्यक्तित्व को लेकर एक समझ में आ सकने वाली दुविधा से यह रैली अछूती नहीं थी। इसकी आयोजक-संयोजक कही जाने वाली आप इसको अपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर फोकस करना चाहती थी, जो कांग्रेस के कड़े विरोध के चलते संभव नहीं हुआ। पर आप को इससे कोई फायदा नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं है। इस रैली से सुनीता केजरीवाल की सियासत में एक ग्रैंड इंट्री हुई है, जिन्होंने गारंटी के छह मुद्दे रखने के साथ अपने पति को इस्तीफा नहीं दिलाने पर जनस्वीकृति भी ली है। अगर 'संवैधानिक व्यवस्था ध्वस्त होने' या नैतिकता पालन के नाम पर अरविंद केजरीवाल हटे या हटाए गए तो उनकी पत्नी उनकी जगह ले लेंगी। हालांकि इंडिया की इस रैली की उसकी एकजुटता से शासन के वैकल्पिक एजेंडे की उम्मीद थी, जो पूरी नहीं हुई।

सहमति-असहमति के बीच

राज्यपालों की ओर से विधेयकों को रोके जाने की आलोचना करते हुए सर्वोच्च अदालत की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा उनका काम उन पर फैसला लेना है। यह शर्म की बात है कि अदालत को राज्यपालों को उनकी ड्यूटी याद दिलानी पड़े। हैदराबाद में हुए कार्यक्रम में उन्होंने महाराष्ट्र व पंजाब के फैसलो का भी जिक्र किया। कहा कि सवाल यह था कि क्या राज्यपाल के पास फ्लोर टेस्ट कराने का कोई ठोस सबूत थे कि मौजूदा सरकार विधायकों का विश्वास खो चुकी है। राज्यपालों को अदालतों में खींचने को भी उन्होंने संविधान के तहत स्वस्थ प्रवृत्ति नहीं कहा। नोटबंदी के फैसले का भी उन्होंने विरोध किया और काला धन जमा करने वालों को हुए फायदे व आम लोगों को हुई परेशानी पर भी बोलीं। हालांकि जस्टिस उन पांच जजों वाली पीठ के हिस्सा थीं, जिसने सरकार के इस फैसले में असहमति जताई थी कि यह

जल्दबाजी में लागू किया गया। उनका यह कहना कि इससे सिर्फ कानून तोड़ने वालों को ही फायदा हुआ, जिन्होंने अपना काला धन सफेद बना लिया। सरकार पर इस तरह के आरोप विपक्ष द्वारा भी लगाए जाते रहे हैं। यह सच है कि नोटबंदी के दौर को याद कर आम लोगों के अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राज्यपाल संवैधानिक पद है, जिसकी गरिमा का ख्याल रखा जाना चाहिए। लंबे समय से देखने में आ रहा है कि राज्य सरकारों और राज्यपाल के दरम्यान सामंजस्य नहीं बन पाता। खासकर जहां-जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं, वहां राज्यपाल केंद्र की शह पर अड़चनें खड़ी करते हैं, जिससे सरकारों को अदालत का रुख करने को मजबूर होना पड़ता है। इस विवाद का निपटारा सत्ताधारी दल को संवैधानिक तौर पर करने की पहल करनी चाहिए। गौरतलब है जस्टिस नागरत्ना अपने कड़े फैसलों के लिए जानी जाती हैं और 2027 में उनके पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की संभावना है। ऐसे में उनके किसी भी नजरिये या तल्ख टिप्पणी की उपेक्षा की जानी उचित नहीं कही जा सकती। ये विचार उनके नितांत निजी हो सकते हैं मगर इनसे असहमति नहीं रखी जा सकती। किसी भी सरकार के सौ फीसद फैसले सही नहीं ठहराये जा सकते, थोड़ी-बहुत ऊंच-नीच से मुकरा नहीं जा सकता। तब भी जबकि नोटबंदी के फैसले पर अब तक कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता।

टू दि प्वाइंट/ आलोक पुराणिक

भूलना जरूरी है

स्मार्ट युनिवर्सिटी ने कारोबार विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया, इसमें प्रथम पुरस्कार विजेता नियम इस प्रकार है-
गर्मी, आईपीएल और चुनाव सबकी शुरुआत हो चुकी है।

गर्मी का कारोबार शुरू हो चुका है, पंखे, एयरकंडीशनर वगैरह की बिक्री के इश्तिहार आना शुरू हो गए हैं। आईपीएल तो विशुद्ध कारोबार है, जो लगातार चलता है। और चुनाव तो इस देश में परमानेंट कारोबार है। कुल मिलाकर कारोबार ही सब कुछ। दुनिया कारोबार है, कारोबार की ही दुनिया है। चुनाव से पहले ही ओपिनियन पोल का धंधा शुरू हो गया था। सरकार किसकी बनेगी, इस प्रश्न के जवाब की तलाश बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। ऐसे ऐसे एक्सपर्ट सरकार बनने बनाने पर राय दे रहे हैं, जिनकी कभी भी कोई भी राय सही साबित ना हुई। हमेशा गलत बोलने वाले एक्सपर्ट लोग बार-बार बोलते जाते हैं क्योंकि उन्हे पब्लिक की कमजोर याददाश्त पर पक्का भरोसा होता है। नेता और ओपिनियन पोल एक्सपर्ट दोनों का सहारा है पब्लिक की कमजोर याददाश्त। याददाश्त अगर मजबूत हो तो ना नेता और ना ओपिनियन पोल एक्सपर्ट अपना काम चला सकते। याददाश्त अगर नेता की मजबूत हो, तो याद रहेगा कि जिस पार्टी के साथ इस चुनाव में गठबंधन हो रहा है, उस पार्टी के नेता तो हमें जाने कितनी गाली दे चुके हैं। नेता गाली याद ना रखता, सिर्फ कुरसी मिलने की संभावना देखता है। भविष्य की ओर देखनेवाला नेता पुरानी गालियों को भूल जाता है। पुरानी गालियों को याद रखे नेता तो पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। नेता को भूलना पड़ता है। ओपिनियन पोल वाला भी पब्लिक की कमजोर याददाश्त के भरोसे रहता है। पब्लिक की याददाश्त तेज हो जाए, तो कईयों के धंधे चौपट हो जाएं। पब्लिक को याद क्यों ना रहता। जी पब्लिक क्या-क्या याद रखे। रोज बीस सीरियल देखती है पब्लिक। रजत का अफेयर पिंकी के साथ चल रहा है या रीना के साथ, यह याद रखना ही बहुत मुश्किल है। सीरियल के कैरेक्टर याद रखो, नेताओं के बयान याद रखो, किस पोल एक्सपर्ट ने किसकी सरकार बनाई-इसे याद रखो। कितना याद रखें जी। तो पब्लिक भूल जाती है और यही उसकी हित में है। भूलना जरूरी है। याद रह जाए तो प्रेम और चुनाव दोनों ही कष्ट देते हैं।

जरूरी है अब विश्व संसद

सामयिक

रघु ठाकुर

डॉक्टर लोहिया का सारा जीवन संघर्षों का और मौलिक विचारों को देने का इतिहास है। जर्मनी से पढ़कर आने के बाद वे महात्मा गांधी की अगुवाई में आजादी के आंदोलन में शामिल हुए और 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी और कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण ने ही भूमिगत रहकर आंदोलन की कमान संभाली थी और लगातार लगभग ढाई वर्ष अपनी गिरफ्तारी होने तक देश की जनता और नौजवानों को आंदोलन के लिए प्रेरित करते रहे।

डॉक्टर लोहिया एक मौलिक विचारक थे, जिन्होंने अपने जीवन के कालखंड के बहुत आगे का विचार किया था। उनकी मृत्यु के बाद उनके आजादी के आंदोलन और समाजवादी आंदोलन के सहकर्मी लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि लोहिया बहुत आगे तक का सोचते थे इसलिए कई बार देश के लोग उन्हें समझ नहीं सके। लोहिया स्वतः भी जानते थे कि वे जो विचार दे रहे हैं वह 50 से 100 वर्ष बाद के लिए हैं और उन्हें विश्वास था कि भले ही उस समय का समाज उनके विचारों को समझ ना पा रहा हो परंतु किसी-न-किसी दिन समझेगा जरूर और इसलिए उन्होंने खुद यह कहा था कि लोग मेरी बात सुनेंगे शायद मेरे मरने के बाद पर सुनेंगे जरूर। 12 अक्टूबर 1967 को 57 वर्ष की अल्पायु में उनके निधन के आज लगभग 67 वर्षों के बाद लोहिया के विचारों की गूंज फिर सुनाई पड़ने लगी है। बौद्धिक जगत विश्वविद्यालय में और दुनिया भर के विभिन्न देशों में लोहिया की चर्चा हो रही है। लोहिया शताब्दी वर्ष में भारत में व दुनिया के अनेक देशों के विश्वविद्यालय में लोहिया साहित्य और विचारों पर चर्चा हुई है।

डॉक्टर लोहिया ने अपने जीवन काल में सात क्रांतियां को दुनिया में परिवर्तन के लिए जरूरी बताया था। उन्हें 'सप्त क्रांति' कहा जाता है। इन सप्त क्रांतियों में दुनिया में प्रचलित सभी प्रकार की विषमताओं को समाप्त करने का लक्ष्य था। आर्थिक सामाजिक, राजनीतिक असमानता, रंगभेद की समाप्ति, निशस्त्रीकरण, लैंगिक असमानता युद्ध की समाप्ति आदि इसमें शामिल थे। लोहिया अपने आप को विश्व नागरिक मानते थे और चाहते थे कि समूची दुनिया के 18 वर्ष की उम्र से अधिक के लोगों द्वारा निर्वाचित विश्व संसद बने। आज दुनिया इन समस्याओं से जूझ रही है। इन सब का हल विश्व संसद ही हो सकता है। आज की दुनिया में सीमांत आतंकवाद, धार्मिक आतंकवाद, नक्सली आतंकवाद जैसे अनेकों आतंकवादों से दुनिया प्रभावित है। रूस-यूक्रेन युद्ध को लगभग दो वर्ष होने को हैं। इस्राइल ने हमास को नष्ट करने के उद्देश्य से लगभग पूरी गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया है। अमेरिका ईरान के बीच छद्म युद्ध चल रहा है, किसी भी दिन

खुलकर युद्ध में तब्दील हो सकता है इसकी आशंका बनी हुई है। भारत अफगानिस्तान के बीच पाक अधिकृत कश्मीर समस्या है। 1959 से तिब्बत पर चीन का कब्जा है। दलाई लामा व उनके हजारों अन्य निर्वासित होकर जीवन बिता रहे। भारत की हजारों किलोमीटर भूमि पर चीन का कब्जा है। ऐसे ही दुनिया में सीमा विवाद युद्ध के लिए तनाव के कारण बने हुए हैं। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद अफगानिस्तान की तबाही छिपी हुई नहीं है।

समूची दुनिया में घुसपैठ की समस्या बढ़ रही है, जो कि भयावह तनाव व हिंसा का कारण बन रही है। पोलैंड की सीमा से हजारों लोग अमेरिका की सीमा में प्रवेश के लिए बर्फ में पड़े मर रहे हैं। वे अमेरिका में बसना चाहते हैं, परन्तु अमेरिका बसाने की स्थिति में नहीं है। म्यांमार से रोहिंग्या को पलायन के लिए विवश किया जा रहा है। बड़ी संख्या में बांग्लादेशी भारत की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। यह बड़ी समस्या है। इन सब का हल डॉ. लोहिया की विश्व सांसद के बनने से ही निकाल सकता है। हम संयुक्त राष्ट्र से अपील करेंगे लोहिया के जन्मदिन 23 मार्च को 'विश्व सांसद दिवस' घोषित करे। हम प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध करेंगे कि लोहिया की विश्व संसद की कल्पना भारत के प्राचीन सिद्धांत व संस्कृति को नया आयाम दे सकती है। अगर एक दुनिया बनेगी तो नेक दुनिया बनेगी। डॉक्टर लोहिया ने जुलाई 1950 में एक लेख लिखा था- तीसरा खेमा विश्व परिप्रेक्ष्य में। दरअसल, लोहिया ने 1947 से ही विश्व संसद की चर्चा शुरू कर दी थी और दुनिया में जहां-जहां भी उनके संपर्क के लोग थे उनके साथ विश्व संसद की कल्पना पर काम करने के लिए वह पहल करने लगे थे। उनका यह लेख भी उसी का एक हिस्सा है, उसे लेकर कुछ अंश मैं यहां दे रहा हूं।

भारत की 6000 साल और उससे भी अधिक पुरानी संस्कृति में कुछ बात तो है जो और संस्कृतियों और धर्म की रही, लेकिन जिसे यहां अधिक पूर्णता मिली। विवेक के प्रकाश में सहानुभूति का कोमल ज्ञान तब तक अधूरा है, जब तक सारे विश्व और उसकी प्रत्येक वस्तु के साथ तादात्म्य का अनुभव न हो। मैं नहीं जानता कि सहानुभूति की इस भावना को समाजवाद और वर्ग संघर्ष से कैसे जोड़ा जाए। विश्व सरकार का आंदोलन प्रगति पर है निश्चय ही इसमें कई धुंधलके और दरारें हैं, लेकिन इसका मुख्य विचार की सारे विश्व के लिए एक सर्वोच्च संस्था हो; लोगों के दिलों में जगह बना रहा है। कुछ लोगों को विश्व सरकार का विचार आज यथार्थ और अव्यावहारिक लगता है। इसके बजाए वे क्षेत्रीय एकता के लिए काम करना बेहतर मानते हैं, जैसे पश्चिमी यूरोप की सरकार, एशिया की सरकार आदि। इसके साथ ही कई लोगों का विचार है कि एक आर्थिक विश्व के बिना एक राजनीतिक विश्व असंभव है, जबकि कुछ लोग विश्व सरकार को शुद्ध राजनीतिक स्तर तक ही रखना चाहते हैं। विश्व संघीय सरकार के लिए विश्व आंदोलन एक संगठन है, जिसका उद्देश्य है विश्व सरकार के लिए काम करने वाले सभी ग्रुपों और शक्तियों को इकट्ठा करना। इसका काम आसान नहीं है। कमजोरी और फूट इसके दो दोष हैं।

लोहिया के लेख के यह अंश बताते हैं कि 1950 से ही समाजवादी आंदोलन ने लोहिया के मार्गदर्शन में विश्व संसद व सरकार बनाने के लिए कार्य करना शुरू कर दिया था, यहां तक की भारत में ही लोहिया की पहल पर विश्व नागरिकता का रजिस्टर तैयार करने का काम शुरू हुआ था। वह लोहिया की मृत्यु के बाद शिथिल हो गया। संयुक्त राष्ट्रसंघ अगर 23 मार्च को विश्व संसद दिवस घोषित करेगा तो समूची दुनिया में फिर से लोहिया का यह विचार तेजी से जन संवाद व जन विमर्श का केंद्र बनेगा और दुनिया विश्व संसद के बारे में सोचने व आगे बढ़ाने को प्रेरित होगी।

लोहिया के लेख के यह अंश बताते हैं कि 1950 से ही समाजवादी आंदोलन ने लोहिया के मार्गदर्शन में विश्व संसद व सरकार बनाने के लिए कार्य करना शुरू कर दिया था, यहां तक की भारत में ही लोहिया की पहल पर विश्व नागरिकता का रजिस्टर तैयार करने का काम शुरू हुआ था। संयुक्त राष्ट्रसंघ अगर 23 मार्च को विश्व संसद दिवस घोषित करेगा तो दुनिया में फिर से लोहिया का विचार तेजी से जन संवाद व जन विमर्श का केंद्र बनेगा

समुद्री भोजन के लिए भारत में मजबूत नियामकीय ढांचा

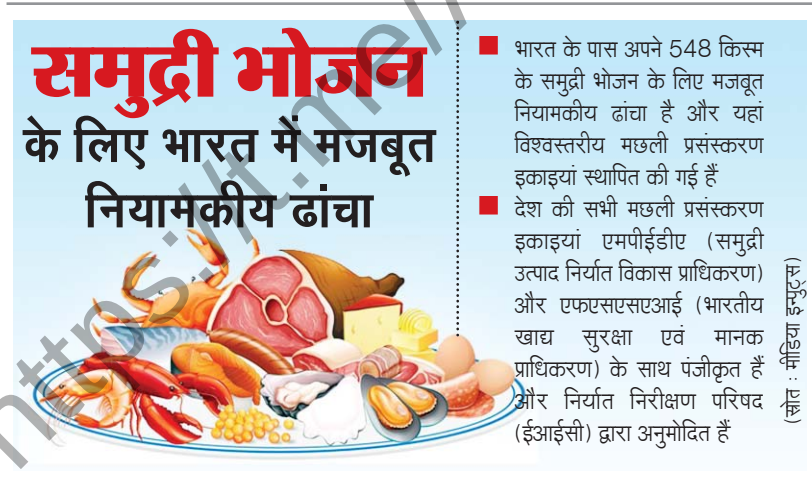

- भारत के पास अपने 548 किस्म के समुद्री भोजन के लिए मजबूत नियामकीय ढांचा है और यहां विश्वस्तरीय मछली प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की गई हैं
- देश की सभी मछली प्रसंस्करण इकाइयां एमपीईडीए (समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) और एफएसएसएआई (भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) के साथ पंजीकृत हैं और निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) द्वारा अनुमोदित हैं

(स्रोत : मीडिया इनपुट्स)

भारत के सब नेता अपने को शेर समझते हैं-
एक बार एक बंदर ने देखा एक चूहा इधर उधर भाग रहा था बन्दर ने पूछा तुम क्यों भाग रहे हो? चूहा बोला मैं भाग रहा हूं क्योंकि मैंने सुना एक शिकारी शेर मारने आ रहा है। बंदर बोला मगर तुम तो चूहा हो। चूहा बोला मेरी मां कहती है कि मेरा बेटा शेर है।

पूर्व जस्टिस मार्कण्डेय काटजू
@mkatju

रफ्तार के नए सौदागर मयंक यादव

क्रिकेट **मनोज चतुर्वेदी**

क्रिकेट में पेस गेंदबाजी की बात है तो पिछले एक दशक में भारत ने इस क्षेत्र में खासी तरक्की की है। ईशांत शर्मा के बाद से शुरू हुए सिलसिले ने जसप्रीत बुमराह की सफलताओं के बाद इस क्षेत्र में खासी तरक्की देखी गई है। दो-तीन साल पहले उमरान मलिक के आईपीएल में सबसे तेज गेंद 153 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार निकालने के बाद अब इस साल लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए पदार्पण करने वाले मयंक यादव ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 155.8 किमी. की रफ्तार निकालकर इस सत्र में अब तक के सबसे तेज गेंदबाज होने का गौरव हासिल कर लिया है। मयंक ने इस मैच में लगातार 150 किमी. से ऊपर की रफ्तार निकालकर लखनऊ को मैच जिताने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 27 रन देकी तीन विकेट लिए। उनकी गति के बारे में हारने वाली टीम के कप्तान शिखर धवन ने कहा कि मयंक की गति ने हमें सरप्राइज कर दिया।

हम सभी जानते हैं कि कुछ सालों पहले तक पेस गेंदबाजी की चर्चा होती थी, तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों की ही चर्चा हुआ करती थी, लेकिन बुमराह के आने के बाद से भारत भी इस क्षेत्र में लगातार उपलब्धियां हासिल करता रहा है। इससे प्रेरणा पाकर तमाम युवा इस क्षेत्र में सामने आ रहे हैं। पर हमें इन युवाओं के ग्रेजुएशन की व्यवस्था और बेहतर करने की जरूरत है। आईपीएल के माध्यम से ही दो-तीन साल पहले उमरान मलिक निकले थे।

जम्मू-कश्मीर का यह पेस गेंदबाज अब तक भारतीय टीम का नियमित सदस्य नहीं बन सका है। अब मयंक यादव की गति की चर्चा तो हो रही है। पर जरूरत इन गेंदबाजों को भारतीय टीम तक पहुंचाने की है। अगर यह गेंदबाज खेलेंगे तो 150 किमी. से ज्यादा की गति निकालने वाले गेंदबाजों की लाइन लग सकती है। मयंक यादव इस बार के घरेलू सीजन की शुरुआत से ही बीसीसीआई चयनकर्ताओं के राडार पर आ गए हैं। असल में देवधर ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन ने उन्हें सुर्खियां दिलाई हैं। उन्होंने देवधर ट्रॉफी में 12 विकेट निकाले और संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछली टेस्ट सीरीज के दौरान उन्हें विराट कोहली, रोहित शर्मा

और केएल राहुल को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया था। यह सभी बल्लेबाज उनकी गेंदबाजी से प्रभावित भी हुए, लेकिन इसी दौरान पसली में फ्रेक्चर होने से वह रणजी सीजन में नहीं खेल सके। एलएसजी के सहायक कोच विजय दहिया की निगाह मयंक पर पड़ी और उन्होंने तत्काल गौतम गंभीर से बात करके उन्हें 2022 की नीलामी में 20 लाख रुपए में खरीद लिया। पर वह चोटिल होने की वजह से 2023 के आईपीएल सीजन में नहीं खेल सके, लेकिन अब वह एक ही प्रदर्शन से सभी की आंखों का तारा बन गए हैं। मयंक के पिता प्रभु यादव बताते हैं कि वह बचपन से ही उसे वेस्टइंडीज के पेस गेंदबाज कर्टली एम्ब्रोस की कहानियां सुनाते थे कि उसकी गेंदबाजी की गति से विरोधी बल्लेबाजों के मन में डर बना रहता था। वह कहते हैं कि मैं उससे इसी तरह का गेंदबाज बनने के लिए कहता था। मयंक को गेंदबाजी में तेजी इसलिए भी भाती थी कि वह बचपन से ही एयरो प्लेन, सुपर बाइक जैसी तेज चीजों को पसंद करते थे। मयंक के 14 साल का होने पर वह उसे तारक सिन्हा संचालित सोनेट क्लब ले गए। वहां कोच देवेंद्र शर्मा ने उनके कॅरियर को शेप देने में अहम भूमिका निभाई। यह कहा जा रहा है कि पिता बचपन से ही चाहते थे कि उनका बेटा भी सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेटर बने, जिससे उनका नाम भी दुनिया में फैल सके।

मयंक को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था। वह स्कूल से लौटते ही गली में साथी बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने लगते। इसके बाद वह स्कूल की टीम से खेलने लगे। वह जब 14 साल की उम्र में सोनेट क्लब में शामिल हुए तो उनके कॅरियर को सही दिशा मिली। कोच शर्मा बताते हैं कि वह जब क्लब में ट्रायल में भाग लेने आया था, तब उसके पास सही स्पाइक्स भी नहीं थे। पर उसमें ट्रायल में भाग लेने वाले अन्य गेंदबाजों से तेजी ज्यादा थी। वह कहते हैं कि वह बहुत ही सामान्य लड़का है। 2021-22 के सत्र में जब पहली बार उसे विजय हजारे ट्रॉफी के लिए दिल्ली टीम में चुना गया, तो उसने क्लब में सभी सदस्यों को मिठाई खिलाई। वह याद करते हुए बताते हैं कि विजय हजारे ट्रॉफी के मैच में उसे आखिरी ओवर में तीन रन बचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई और उसने दिल्ली को जिता दिया था। मयंक ने आईपीएल का पहला मैच खेलने के बाद कहा था कि मेरा पहला विकेट ही मेरे लिए सबसे महत्त्वपूर्ण है। मयंक के प्रदर्शन पर पूर्व टेस्ट क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने कहा कि जिस तरह शोएब अख्तर का नाम उनके शहर की मशहूर ट्रेन 'रावलपिंडी एक्सप्रेस' रखा गया, उसी तरह मयंक दिल्ली से आता है तो उसका नाम 'राजधानी एक्सप्रेस' रखना चाहिए।

विराम का राज **ओशो**

ऐसा हुआ कि अमेरिका में पहली दफा ट्रेनें चलाई गईं; ट्रेन की पटरियां डाली गईं; तो एक आदिवासी कबीले में भी पहली दफे ट्रेन गुजरने वाली थी। अमेरिकी प्रेसीडेंट उसका उद्घाटन करने गया। स्टेशन पर झाड़ के नीचे एक आदिवासी लेटा हुआ सारा दृश्य बड़े मजे से देख रहा है; बीच-बीच में अपने हुक्के से दम लगा लेता है, फिर अपने लेटकर वही देख रहा है ऐसे जैसे दुनिया में कुछ करने को नहीं है। प्रेसीडेंट उसके पास गया और उसने कहा कि तुम्हें शायद पता नहीं कि यह बड़ी ऐतिहासिक घटना है, इस ट्रेन का गुजरना। उस आदिवासी ने पूछा, इससे क्या होगा? तो प्रेसीडेंट ने उसे समझाने के लिए कहा कि तुम लकड़ियां काटकर शहर जाते हो बेचने कितने दिन लगते हैं? उसने कहा कि दो दिन जाने में लगते हैं, एक दिन बेचने में लग जाता है, दो दिन लौटने में लगते हैं सप्ताह में पांच दिन लग जाते हैं और फिर दो दिन घर आराम करना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है। अभी ये आराम के दिन हैं : दो दिन। प्रेसीडेंट ने कहा, 'अब तुम समझ सकोगे। ट्रेन से तुम घंटे भर में पहुंच जाओगे, और दिन भर में बिक्री करके रात घंटे भर में घर वापस आ जाओगे।' सोचा था प्रेसीडेंट ने कि आदिवासी बहुत प्रसन्न होगा, वह थोड़ा उदास हो गया। उसने कहा, 'फिर छह दिन, बाकी दिन क्या करेंगे? यह तो बहुत झंझट हो गई।' समय कम हो तो बचाओ, बचाने का अर्थ है गति को तेज कर लो, सब चीजों में गति कर लो। सब चीजों में गति हो जाती है, एक हड़बड़ाहट पैदा हो जाती है, भीतर एक तनाव पैदा हो जाता है। तुम सदा भागे भागे हो; जहां हो वहां नहीं हो। तुम्हें कहीं और आगे होना था, वहां तुम अभी पहुंचे नहीं हो। जब तुम वहां पहुंचोगे, तब तुम वहां नहीं हो। तुम सदा अपने से आगे भागे जा रहे हो। चित्त बहुत अशांत और बेचैनी से भर जाता है। ऐसी हड़बड़ी में कैसे तुम स्वयं को पा सकोगे? क्योंकि स्वयं को पाने के लिए एक स्थिति चाहिए जैसे कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, सिर्फ आंख बंद करके बैठे रहना है, अपने में डूबना है। इसलिए पूरब में तो कभी-कभी आत्मज्ञान की घटना घट जाती है। पश्चिम में बहुत मुश्किल हो गई है। और पूरब में घट जाती है, क्योंकि पूरब को खयाल है कि जल्दी कुछ भी नहीं है यह जन्म ही नहीं, अनंत जन्म हैं। यात्रा लंबी है। समय बहुत है। विश्राम किया जा सकता है। जिसने विश्राम की कला सीख ली, जिसने विराम का राज समझ लिया, वह परमात्मा को उपलब्ध हो जाएगा।

रीडर्स मेल

कर प्रणाली में हो सुधार

देश की जीडीपी में कृषि का बड़ा योगदान है, लेकिन कुछ सरकार की बेरुखी तो कुछ मौसम की बेरुखी के कारण किसानों का मोह खेती से भंग हो रहा है। तभी तो देश के कुछ राज्यों में किसान अपनी जमीन बेच रहे हैं। कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए और गंभीरता से इस वर्ष काम करना होगा। कुछ समय पहले डॉ. मनमोहन सिंह ने आर्थिक मंदी से देश को उबारने के लिए पांच उपाय सुझाए थे। पहले उपाय में उन्होंने जीएसटी को तर्कसंगत बनाने की सलाह, दूसरे में गांवों में खपत बढ़ाने एवं कृषि में और सुधार लाने, तीसरे में कर्ज की कमी को पूंजी निर्माण के लिए जरूरी, जबकि चौथे में नौकरी बढ़ाने वाले क्षेत्रों की तरफ गंभीरता दिखाने और पांचवें उपाय में उन्होंने अमेरिका-चीन में चल रहे ट्रेडवॉर में नए निर्यात बाजारों को तलाशने की सलाह दी थी, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कर प्रणाली में भी और सुधार की जरूरत है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

विधर्मियों से मुकाबला जरूरी

अमरकंटक के एक दिवसीय प्रवास पर आए आरएसएस के सर संघचालक मोहन जी भागवत ने अनुशासित समाज निर्माण के लिए संतों को आश्रम से बाहर आने का आह्वान किया है। वास्तव में मोहन जी द्वारा कही यह बात की आवश्यकता हिंदू समाज लंबे समय से अनुभव कर रहा है। आज हम देखते हैं साधु-संतों को मिलने वाले मान सम्मान का दोहन करने के लिए विभिन्न प्रकार के झूठे आचार्य, शंकराचार्य, साधु बन कर कुछ लोग समाज में विचरण कर रहे हैं, जिनके द्वारा किए जा रहे कर्मों से न सिर्फ समाज भ्रमित हो रहा है बल्कि इससे सनातन हिंदू धर्म की श्रेष्ठ संत परंपरा पर आघात भी हो रहा है। हिंदू सनातन धर्म में साधु संत ही श्रेष्ठ हिंदू संस्कृति के संवाहक के रूप में अग्रणी और मार्गदर्शक रहे हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण सामने आए हैं, जब ईसाई और मुस्लिम मजहबी लोग साधु-संतों के चोले में मतांतरण और संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। विधर्मियों द्वारा इस परंपरा को दूषित कलंकित करने का कुचक्र हिंदू और संत समाज दोनों को समझना होगा और मिलकर इनसे मुकाबला करना होगा।

युवराज पल्लव, बिजनौर, उप्र

डरना जरूरी है

सोशल मीडिया पर भिन्न-भिन्न करतब दिखा कर रील डालने का एक प्रचलन सा चल गया है, जिसका कोई अंत नजर नहीं आता दिख रहा है क्योंकि यह करने वाले युवा न केवल इन खतरनाक स्टंट के जरिये आसान पैसा बनाना चाहते हैं, परंतु वह प्रसिद्ध भी होने की आस रखते हैं। कानून को अपने हाथ में लेना और नियम तोडना न केवल इनकी खुद की जान के लिए खतरनाक है बल्कि इससे दूसरे लोगों को भी उतना ही खतरा रहता है। यह एक अच्छी बात है कि पुलिस इन लोगों को पकड़ कर लंबे चालान काट रही है और इसी से आम जनता और युवाओं में एक कड़ा संदेश जा रहा है कि ऐसा करना उनको कितना भारी पड़ सकता है, लेकिन जुर्माना न भर पाने वालो को भी कड़ाई से निपटा जाए ताकि कोई युवा यह न सोचे कि मैं ऐसे खतरनाक करतब की रील बनाकर बिना जुर्माना भरे सड़कों पर घूमता रहूंगा।

बाल गोविंद, नोएडा

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
• राष्ट्रीयता • कर्त्तव्य • समर्पण
वर्ष-33, अंक 230

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित। । समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

https://t.me/AllNewsPaperPaid

एकजुटता प्रयास
लोकतंत्र बचाओ रैली

विपक्ष ने एकजुटता प्रयास के अंतर्गत 'लोकतंत्र बचाओ रैली' आयोजित की। सत्तारूढ़ अवस्थापना द्वारा कथित रूप से संघीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर जन-भावनायें उभारने के लिए विपक्षी दलों के समूह 'इंडिया' ने राजधानी के रामलीला मेंदान में रैली आयोजित की। अपने कई कैबिनेट सहयोगियों की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी करोड़ों रुपये के शराब नीति घोटाले में सीखचों के पीछे हैं। यह रैली संभवत: इस गिरफ्तारी की निन्दा करने के लिए थी, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि यह किसी व्यक्ति पर केन्द्रित नहीं है और इसका उद्देश्य लोकतंत्र व संविधान बचाना है। विपक्ष ने इस रैली के माध्यम से एक राजनीतिक संदेश देने व अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता दिखाने का प्रयास किया किया है। विपक्ष यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि वह हमारे महान देश के आधारभूत लोकतांत्रिक व संवैधानिक मूल्यों की रक्षा कर रहा है। रैली में उपस्थित विपक्षी नेताओं में रांकापा के शरद पवार, शिवसेना-यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी, भाकपा महासचिव डी.राजा, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती तथा झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शामिल थे। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे व राहुल गांधी तथा 'आप' नेता व पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रैली में शामिल थे।

सुनीता केजरीवाल ने जेल में बंद अपने पति अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ कर सुनाया जिसके अनुसार, 'भारत बहुत कष्ट की स्थिति में है और यह अत्याचार कारगर नहीं सिद्ध होगा।' रैली में उपस्थित नेताओं

ने केन्द्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग तथा सरकार द्वारा विपक्ष को कथित रूप से पंगु बनाने के प्रयासों को बार-बार रेखांकित किया। वर्तमान समय में कई विपक्षी नेता भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में हैं और कांग्रेस के बैंक खाते आयकर नियमों के उल्लंघन में फ्रीज किए गए हैं। भाजपा ने इस विपक्षी रैली पर व्यंग्य करते हुए इसे 'अलीबाबा और चालीस चोर' बैठक कहा है। भाजपा ने विपक्ष पर निशाना लगाते हुए कहा है कि यह 'लोकतंत्र बचाओ' के बजाय 'परिवार बचाओ' और 'भ्रष्टाचार छिपाओ' रैली है। हालांकि, इस रैली ने विपक्षी एकता प्रदर्शित करने का प्रयास जरूर किया है, पर यह मंच पर फोटो खिंचवाने तक सीमित है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में तथा 'आप' ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। रैली में विपक्षी नेताओं के खिलाफ केन्द्रीय एजेंसियों की कार्रवाई रोकने तथा जेल में बंद हेमंत सोरेन व अरविंद केजरीवाल को रिहा करने की मांग की गई। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी नेता स्वयं को देश के कानून से ऊपर समझते हैं। जेल में बंद सभी विपक्षी नेताओं के खिलाफ विभिन्न आरोपों में कानून-सम्मत कार्रवाई की गई है और उनको अदालतों द्वारा सजा मिली है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मेरठ में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है इनमें से कई को तो सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिली है और उनका 'भ्रष्टाचार विरोधी अभियान' लगातार चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ईडी द्वारा जब्त 17,000 करोड़ रुपयों से अधिक धनराशि उत्पीड़ित लोगों को वापस कर चुकी है। उन्होंने जनता से वादा किया है कि उनकी अगली सरकार भ्रष्टाचारियों से जब्त पैसा जनता को वापस लौटाने की व्यापक योजना पर काम कर रही है। जनता व खासकर देश की युवा पीढ़ी का भाजपा पर विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोकतंत्र के नाम पर 'भ्रष्टाचारी बचाओ' नेताओं के प्रति जनता की हमदर्दी पैदा होने की कोई संभावना नहीं है।

नैनो-उर्वरकों से टिकाऊ खेती

भारत वर्तमान समय में नैनो-उर्वरकों का उत्पादन बढ़ा रहा है। लेकिन इसकी तकनीकी संभावनाओं तथा इस व्यवस्था में तार्किक परिवर्तन के बारे में कुछ आशंकायें हैं।

उत्तम गुप्ता
(लेखक, नीति विश्लेषक हैं)

हाल ही में केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है, 'इस वित्त वर्ष में वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में द्रव नैनो किस्म के प्रयोग के कारण यूरिया के उपभोग में 8 प्रतिशत कमी की संभावना है। इसके तथा घरेलू उत्पादन में वृद्धि के कारण यूरिया के आयात में वित्त वर्ष 2023 में एक बटा पांच से अधिक कमी आई है। इस उर्वरक का उर्वरक सब्सिडी बिल में 70 प्रतिशत का योगदान है। नैनो यूरिया उपभोग का विस्तार होने तथा ओडिशा के तालचेर में नए बड़े यूरिया प्लांट की सितंबर, 2023 में स्थापना से दो-तीन साल में आयातों से मुक्ति मिल सकती है।' मंत्री का बयान नैनो उर्वरकों की अभूतपूर्व संभावनाओं की ओर संकेत करता है। नैनो यूरिया के साथ ही उद्योग ने नैनो-डीएपी तथा नैनो रूप में अन्य उर्वरकों का उत्पादन शुरू किया है जिनमें नैनो-पोटाश, नैनो-जिंक, नैनो-बोरान, आदि शामिल हैं। इससे न केवल उर्वरक सब्सिडी में काफी कमी आई है, बल्कि उर्वरक प्रयोग में असंतुलन कम हुआ है जिससे मृदा स्वास्थ्य बेहतर हुआ है तथा पर्यावरण-हितैषी लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिली है। इसके अतिरिक्त अनेक अन्य लाभ भी प्राप्त हुए हैं जिनमें विदेशी मुद्रा की बचत, चालू खाते के घाटे में कमी तथा लाजिस्टिक श्रृंखला पर बोझ घटना शामिल है जिसमें खासकर परिवहन व भंडारण ढांचा शामिल है। नैनो-यूरिया नैनोकणों के रूप में होती है जिसमें नाइट्रोजन कण का आकार 20-50 नैनोमीटर-एनएम होता है। इसी प्रकार नैनो-डीएपी में पोलीमर से ढके डीएपी कण 100 एनएम से छोटे होते हैं। नैनो यूरिया पौधों को नाइट्रोजन द्रव रूप में देती है, जबकि परंपरागत यूरिया सफेद ठोस कणों के रूप में होती है। इसी प्रकार नैनो-डीएपी द्रव रूप में नाइट्रोजन व फास्फोरस तत्व देती है।

नैनो-उर्वरकों में कणों के बहुत छोटे होने के कारण इनका सतह क्षेत्र 1एमएम यूरिया कणों से 10,000 गुना अधिक होता है। इससे पौधों की पत्तियां इनका आसानी से शोषण कर लेती हैं। ये कण पौधों के छोटे छिद्रों या स्टोमेटा के माध्यम से प्रवेश कर सीधे कोशिका भित्तियों को पार कर कोशिकाओं में मिल जाते हैं। कोशिका के भीतर पहुंचने पर ये धीरे-धीरे पोषक तत्व छोड़ते हैं और पूर्ण असशोषण सुनिश्चित करते हैं, जबकि परंपरागत विधियों में इनका काफी हिस्सा बेकार चला जाता है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव-इफ्को की खोजी संस्थान नैनो बायोटेक्नोलोजी रिसर्च सेंटर ने दावा किया है कि नैनो यूरिया की प्रभावशीलता परपंरपगत यूरिया के 40 प्रतिशत की तुलना में 80 प्रतिशत है। नैनो-यूरिया फसल के उत्पादन में 3-16 प्रतिशत वृद्धि करती है। इसी प्रकार नैनो-डीएपी भी प्रयोग में बचत तथा फसल उत्पादकता बढ़ाने में उपयोगी है। परंपरागत यूरिया के प्रयोग से पर्यावरणीय चिन्तायें पैदा होती हैं जिनमें नाइट्रेट लीचिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर क्षरण तथा भूमिगत जल प्रदूषण शामिल हैं। इसकी तुलना में नैनो-यूरिया के प्रयोग से मृदा, जल व वायु प्रदूषण कम होता है। एक अध्ययन के अनुसार नैनो-यूरिया के दो बार छिड़काव से नाइट्रोजन लोड केवल 25 प्रतिशत बढ़ता है जबकि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन भी परंपरागत विधियों की तुलना में कम होता है। इफ्को-एनबीआरसी ने दावा किया है कि नैनो-यूरिया की 500 मिली की बोतल परंपरागत यूरिया के 45 किलो बोरे के बराबर है। इसमें 46 प्रतिशत या 20 किलो नाइट्रोजन होता है जबकि नैनो-यूरिया में यह 20 ग्राम होता है। इसके बावजूद दोनों को समान माना गया है। इसका अर्थ है कि नैनो-रूप में यूरिया परंपराग यूरिया से 1000 गुना अधिक प्रभावी है।

क्षमता में इसी अंतर के कारण इफ्को ने किसानों को बिना किसी सब्सिडी के 500 मिली बोतल 240 रुपये में देने का निर्णय किया है। इसके उलट परंपरागत यूरिया के 45 किलो बोरे की सप्लाई लागत ग्यारह गुना अधिक है। देश में उत्पादित यूरिया की तुलना में आयातित यूरिया के मामले में यह खर्च और बढ़ जाता है। सरकार को 240 रुपये की समान कीमत में उपलब्ध कराने के लिए 2410 रुपये सब्सिडी देनी पड़ती है। डीएपी के मामले में इफ्को-एनबीआरसी का दावा है कि 500 मिली नैनो-डीएपी बोतल परंपरागत डीएपी के 50 किलो बोरे के बराबर है। इसे किसानों को बिना किसी सब्सिडी के 600 रुपये में दिया जा सकता है, जबकि परंपराग डीएपी इससे सात गुना महंगी 4,000 रुपये की है। सरकार द्वारा दी जाने वाली 2,650 रुपये की सब्सिडी के कारण डीएपी किसानों को 1,350 रुपये में मिलती है जो समान क्षमता वाली 500 मिली बोतल की तुलना में दूनी है। मनसुख मंडाविया के अनुसार भारत वितत वर्ष 2023-24 में नैनो-यूरिया की लगभग 55 मिलियन बोतलें तैयार करेगा जो 2.5 मिलियन टन परंपरागत यूरिया का स्थान लेंगी। एक स्तर पर इससे यूरिया के अत्यधिक उपभोग से बचने में सहायता मिलेगी और उर्वरक प्रयोग में असंतुलन में कमी आएगी जिससे मृदा स्वास्थ्य में सुधार होगा। दूसरी ओर इससे सब्सिडी में भारी कमी आएगी। इसके साथ ही परंपरागत यूरिया के आयात पर होने वाला खर्च भी घटेगा। चूंकि नैनो-यूरिया पर किसी सब्सिडी की जरूरत नहीं होगी, इसलिए 13,400 करोड़ रुपये की पूरी धनराशि बच जाएगी।

इसी प्रकार परंपरागत डीएपी के स्थान पर नैनो-डीएपी के प्रयोग से भी सब्सिडी में बचत होगी। सरकार का इरादा 2024-25 तक नैनो-यूरिया का उत्पादन बढ़ा कर 440 मिलियन बोतल करना है। यह बीस मिलियन टन परंपरागत यूरिया या कुल वर्तमान उपभोग का लगभग 60 प्रतिशत है। आश्चर्य है कि क्या इस सीमा तक हस्तांतरण तकनीकी रूप से संभव होगा। सामान्यत: यूरिया का प्रयोग दो बार होता है। बेसल ड्रेसिंग के तौर पर ठोस उर्वरक को बुआई या रोपाई के पहले पूरे खेत में किया जाता है। इसके बाद टाप ड्रेसिंग में उर्वरक को सीधे पत्तियों पर छिड़का जाता है। नैनो-यूरिया केवल टाप ड्रेसिंग में ही परंपरागत यूरिया का स्थान लेगी क्योंकि बेसल प्रयोग केवल ठोस रूप में होता है।

वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि 16.5 मिलियन टन यूरिया प्रयोग का केवल 50 प्रतिशत नैनो-यूरिया के अंतर्गत आता है। इस स्तर पर भी यूरिया आयात की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जो वर्तमान समय में 2023-24 में लगभग 6.4 मिलियन टन है। केवल इतना ही नहीं, बाकी 10 मिलियन टन के लिए नैनो-यूरिया के उपयोग से प्राकृतिक गैस-एनजी के आयात में 'भारी' कमी आएगी जो यूरिया उत्पादन का प्रमुख कच्चा माल है। प्रति टन यूरिया के उत्पादन में 600 क्यूबिक मीटर एनजी का प्रयोग होता है। ऐसे में यदि 10 मिलियन टन परंपरागत सामग्री का उपयोग हो तो एनजी की आवश्यकता 6000 मिलियन क्यूबिक मीटर होगी। यदि इसके बजाय यह क्षमता प्रयोग में 1000 गुना अंतर के कारण नैनो-यूरिया के क्षेत्र में आ जाता है तो केवल 6 मिलियन क्यूबिक मीटर एनजी की जरूरत होगी। इसके कारण गैस आयात पर खर्च घटने से भारी बचत होगी। वर्तमान समय में भारत अपनी कुल एनजी आवश्यकता का पचास प्रतिशत आयात करता है। यूरिया के घरेलू उत्पादन में भी इसका उपयोग होता है, जबकि कुल आवश्यकता के एक तिहाई की पूर्ति आयातित एलएनजी से होती है। परंपरागत उर्वरकों के स्थान पर नैनो-उर्वरकों के प्रयोग से ढांचागत संरचना पर पड़ने वाला बोझ भी घटेगा।

45 किलो के परंपरागत यूरिया की हैंडलिंग, मूविंग, भंडारण और वितरण पर आने वाला खर्च 500 मिली की नैनो-यूरिया बोतल की तुलना में बहुत अधिक है। इसी प्रकार 50 किलो के परंपरागत डीएपी बोरे की तुलना में 500 मिली नैनो-डीएपी के परिवहन व अन्य वितरण खर्च में बहुत अधिक अंतर होगा। हालांकि, स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बार-बार नैनो-उर्वरकों का प्रयोग बढ़ाने के पक्ष में बयान दिए हैं, पर इसके बावजूद किसानों में परंपरागत उर्वरकों के स्थान पर नैनो-उर्वरकों का प्रयोग बढ़ाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान की जरूरत है। प्रधानमंत्री द्वारा ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन प्रयोग में दक्ष बनाने और उनका प्रयोग कृषि संबंधी कार्यों में करने की योजनाओं को देखते हुए नैनो द्रव उर्वरकों के प्रयोग में व्यापक वृद्धि होने की आशा है।

शिक्षकों का उत्थान आवश्यक

> "आज के डिजिटल युग में, शिक्षकों को छात्रों के सीखने और जुड़ाव को बढ़ाने के लिए अपने निर्देश में प्रौद्योगिकी को प्रभावी ढंग से एकीकृत करने के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।"

साक्षी सेठी
(लेखिका, शिक्षक हैं)

युवा दिमागों को सशक्त बनाने से लेकर चरित्र को ऊंचा उठाने तक, एक शिक्षक के कर्तव्य असंख्य और महत्वपूर्ण हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शिक्षक के कर्त्तव्य न तो कम होते हैं और न ही छोटे, बल्कि वे मन को ऊँचा उठाते हैं और चरित्र को ऊर्जा प्रदान करते हैं। शिक्षा प्रणालियों और समाज की बेहतरी के लिए शिक्षकों को ऊपर उठाने की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। जिस तरह छात्र सीखते समय संज्ञानात्मक विकास से गुजरते हैं, उसी तरह शिक्षक भी पेशेवर सीखने में संलग्न होने पर संज्ञानात्मक विकास का अनुभव करते हैं जो अंतत: उनके अभ्यास पर प्रतिबिंबित होता है और उनके दृष्टिकोण को परिष्कृत करता है। निरंतर व्यावसायिक विकास के अवसर और शिक्षकों को उनकी निरंतर कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए मान्यता देने से मनोबल और प्रेरणा बढ़ सकती है। यह शिक्षकों को अपने कौशल को निखारने, नवीनतम शैक्षणिक तकनीकों के साथ अद्यतन रहने और उनकी विषय वस्तु विशेषज्ञता को और गहरा करने में मदद कर सकता है, जिससे वे अपने शिक्षण प्रथाओं की निगरानी और विनियमन कर सकते हैं, छात्रों की जरूरतों के आधार पर अपने दृष्टिकोण को अनुकूलित कर सकते हैं और शिक्षकों के रूप में उनकी प्रभावशीलता में सुधार कर सकते हैं।

आज के डिजिटल युग में, शिक्षकों को छात्रों के सीखने और जुड़ाव को बढ़ाने के लिए अपने निर्देश में प्रौद्योगिकी को प्रभावी ढंग से एकीकृत करने के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। कुछ प्रथाओं में शिक्षण और मूल्यांकन के लिए शैक्षिक सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया संसाधनों और ऑनलाइन प्लेटफार्मों का उपयोग करना शामिल है। शिक्षकों को विभिन्न निर्देशात्मक रणनीतियों और शिक्षण विधियों में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है जो विभिन्न विषयों, ग्रेड स्तरों और छात्र आबादी के लिए प्रभावी हों और इसमें निर्देश को अलग करने, कक्षा में प्रौद्योगिकी को शामिल करने और आकर्षक सीखने के अनुभव बनाने की समझ शामिल हो। एक शिक्षक का संज्ञानात्मक विकास एक आजीवन यात्रा है जो निरंतर सीखने, प्रतिबिंब और विकास की विशेषता है। संज्ञानात्मक विकास में मजबूत आधार वाले शिक्षक समझते हैं कि छात्र कैसे सीखते हैं और शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने निर्देश को अनुकूलित कर सकते हैं। इस प्रकार के शिक्षक प्रभावी शिक्षण रणनीतियों का उपयोग करने, निर्देश को अलग करने और आकर्षक सीखने के अनुभव बनाने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होते हैं जिसके परिणामस्वरूप शैक्षणिक उपलब्धि में सुधार होता है और छात्र जुड़ाव और प्रेरणा का उच्च स्तर प्राप्त होता है। जब शिक्षक संज्ञानात्मक विकास से गुजरते हैं, तो वे छात्रों की समझ, आलोचनात्मक सोच और समस्या-समाधान कौशल को बेहतर ढंग से विकसित करने में सक्षम होते हैं। आज के परिदृश्य में, एक शिक्षक को अपग्रेड करना या उसका कौशल बढ़ाना समय की मांग बन गया है। सरकार सहित कई स्कूल, कॉलेज और संस्थान छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने, आधुनिक शिक्षा की चुनौतियों से निपटने और सकारात्मक शिक्षण परिणामों में योगदान करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और स्वभाव के साथ शिक्षकों के समग्र विकास में सुधार की दिशा में काम कर रहे हैं। और समग्र विकास.

कुल मिलाकर, शिक्षकों को ऊपर उठाने में शिक्षण गुणवत्ता, शिक्षक कल्याण और शिक्षा प्रणालियों की समग्र प्रभावशीलता में सुधार के लिए एक समग्र दृष्टिकोण शामिल है। शिक्षकों में निवेश करके और उन्हें आवश्यक सहायता और संसाधन प्रदान करके, हम छात्रों के सीखने के परिणामों को बढ़ा सकते हैं और मजबूत और अधिक जीवंत समुदायों का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही, शैक्षिक प्रक्रिया में माता-पिता/अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को शामिल करने जैसी रणनीतियों को लागू करने से शिक्षकों के लिए समर्थन मजबूत हो सकता है और छात्रों के लिए सीखने का अधिक अनुकूल माहौल बन सकता है।

शिक्षण पेशे में प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धी वेतन और लाभ की पेशकश भी आवश्यक है क्योंकि पर्याप्त मुआवजा समाज द्वारा शिक्षा और शिक्षकों को दिए जाने वाले मूल्य को दर्शाता है। केवल जब प्रशासक अपने शिक्षकों की स्थिति को ऊंचा करना सीखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक समर्थन, संसाधन और मान्यता प्राप्त है, तो सुधार के मामले में समाज और यहां तक कि पूरे देश की मदद की जा सकती है। छात्र परिणाम, आजीवन सीखने को बढ़ावा देना, समानता और समावेशिता को बढ़ावा देना और समाज में शिक्षा के व्यापक लक्ष्यों को आगे बढ़ाना।

आप की बात

परिवार में टकराव

शरद पवार द्वारा स्थापित राकांपा पहले चाचा शरद पवार और भतीजे अजित पवार के बीच दो भागों में बंटी। अजित पवार कुछ लोगों के साथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए। मजेदार बात है कि शिंदे सरकार भी शिवसेना के दो गुटों में विभाजित होने का परिणाम है, जिसे भाजपा व एनसीपी-अजित पवार गुट का समर्थन है। महाराष्ट्र की सरकार पहले भी तीन पहियों-शिवसेना, कांग्रेस, रांकापा की गाड़ी पर चल रही थी और अभी भी वो तीन पहियों के वाहन पर सवार है। राकांपा का गठन भी इंदिरा कांग्रेस को तोड़ कर हुआ था जिसके मुखिया शरद पवार बने थे। बारामती में पारिवारिक टकराव में नया मोड़ आने वाला है। यहाँ शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और अजित पवार की धर्मपत्नी सुनेत्रा पवार यानी ननद-भौजाई आमने-सामने आ रहीं हैं। सुप्रिया सुले कह चुकीं हैं कि हमारी लड़ाई विचारों की है न कि निजी। देखना होगा कि वैचारिक टकरावों या चुनावी टकरावों के बावजूद परिवारों की एकजुटता कहां तक बनी रहती है। देश में परिवारवाद व वंशवाद की आलोचना करते समय राजनेता अपने समर्थकों और विरोधियों के परिवार में अंतर करते हैं, लेकिन मजबूरी में जनता को इनमें से किसी न किसी को वोट देना पड़ता है। मतदाताओं को ही रास्ता निकालना है।

– **शकुंतला महेश नेनावा,** इंदौर

विपक्ष की रैली

रामलीला मैदान दिल्ली अपने नाम को सार्थक कर रहा है। यहां साल भर में 10 –15 बार विभिन्न तरह की रेलियां, धरने व आंदोलन होते ही हैं। इस बार विपक्ष ने यहां रैली की। रामलीला मैदान को जैसे यह वरदान प्राप्त है कि यहां जो भी आंदोलन, आयोजन होंगे उनका राष्ट्रीय स्तर के सभी चैनल ब्रॉडकास्ट करेंगे। कैमरे की फ्लैश लाइट अपनी और आते ही लोग तरह-तरह की हरकतें करने लगते हैं ताकि देश-दुनिया में वे अपना चेहरा दिखा सके। इस रैली में भी भरपूर भीड़ इकट्ठी हुई और विपक्षियों को लगने लगा कि अभी भी लोगों के मन में उनके लिए कुछ सहानुभूति है। इस रैली ने विपक्ष में जोश भर दिया है। लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि इसका नेतृत्व कौन महान नेता कर रहा है। आप वालों ने इसे केजरीवालकी गिरफ्तारी से जोड़ा तो कांग्रेस ने इसे केन्द्र सरकार की नीतियों के खिलाफआंदोलन बताया। विपक्ष की यह रैली नेताओं के एकसाथ फोटो खिंचवाने का मौका जरूर बना, पर अनेक राज्यों में उनकी आपस में लड़ाई जारी है। इस रैली में जेल में बंद अनेक नेताओं की पत्नियां एकत्र हुईं और उन्होंने अपनी पीड़ा साझा की। लेकिन देखना होगा कि भ्रष्टाचार के आरोपों में बंद नेताओं के प्रति हमदर्दी पैदा होगी या नहीं।

– **सुभाष बुडावन वाला,** रतलाम

सोशल मीडिया

सोशल मीडिया आज लोगों के जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। यह न केवल मनोरंजन, बल्कि अभिव्यक्ति का अच्छा माध्यम है। दुनिया भर में अनेक सोशल साइटस का व्यापक इस्तेमाल हो रहा है। इनके द्वारा देश-दुनिया की खबरें पलक झपकते ही हमारे मोबाईल स्क्रीन पर होती हैं। यह अपनी आवाज सरकार और अधिकारियों तक पहुंचाने का अचूक हथियार बन गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इनका दुरूपयोग भी बढ़ रहा है। इनके माध्यम से बिना रोक टोक अश्लीलता परोसी जा रही है। धीरे-धीरे ये प्लेटफार्म फेक न्यूज का अड्डा बनते जा रहे हैं। जहां से बड़ी संख्या में फर्जी न्यूज प्रसारित कर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। धार्मिक एवं जातिगत उन्माद फैलाने वाले पोस्ट शेयर कर हिंसा एवं दंगो को हवा दी जा सकती है। किसी की फोटो के साथ छेड़ छाड़ कर और गलत रूप में पेश कर उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा सकता है। प्रख्यात राजनीतिक हस्तियों पर अभद्र टीका टिप्पणी तो आम बात हो गई है। सोशल मीडिया अपनी बात रखने का बेहतरीन मंच है, लेकिन इसका प्रयोग जिम्मेदारी और शालीनता से होना चाहिए। ऐसा न होने पर आम जनता से अभिव्यक्ति का यह साधन छिन भी सकता है।

– **शिवेन्द्र यादव.** कुशीनगर

डाटा की चोरी

हमारा निजी डाटा, कंपनियों एवं सरकारी डाटा बैंक से हैकिंग का जरिए चुरा लिए जाते हैं। एक बार लेने के बाद लाखों की संख्या में डाटा को सुरक्षित रखना लगभग असंभव होता जा रहा है। अमेरिका में वहां की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी एटीएंडटी के लगभग 73 मिलियन लोगों की निजी जानकारी डार्क वेब में लीक हो गई है। एक हैकर ने दावा किया कि उसके पास 73 मिलियन इस कंपनी के ग्राहकों के डेटा तक पहुंच है। इसमें उनके नाम, पते, फोन नंबर, एसएसएन और जन्मतिथि शामिल हैं। पता चला कि हैकर ने चोरी की गई जानकारी को हजारों डॉलर में बेच दिया है। कंपनी ने कहा है कि कम से कम 7.6 मिलियन मौजूदा खाताधारक और 65.4 मिलियन पूर्व उपयोगकर्ता इस डाटा चोरी से प्रभावित हुए हैं। इस प्रकार यह डाटा कुल अमेरिकी आबादी के 20 फीसदी लोगों का है। ऑनलाइन साइबर हैकर्स ने जासूसी का काम को और आसान बना दिया है। आज कोई नहीं कह सकता कि उसका निजी डाटा सुरक्षित हाथों में है। एआई के युग में डाटा चोरी व्यक्तियों, पूरे समाजों व देशों के लिए खतरनाक हो सकती है।

– **जंग बहादुर सिंह,** जमशेदपुर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

विचार
नवभारत टाइम्स
नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । मंगलवार, 2 अप्रैल 2024

ग्रामीण क्षेत्र पर दबाव

वित्त वर्ष 2023-24 के आखिरी दिन आई यह खबर कई लिहाज से परेशान करने वाली है कि मनरेगा के तहत साल भर में मुहैया कराए गए कार्य दिवसों की कुल संख्या 305.2 करोड़ तक पहुंच गई, जो महामारी से पहले (2019-20) के लेवल से 40 करोड़ ज्यादा है। इससे संकेत मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दिक्कत ज्यादा है, जिससे वहां मनरेगा के तहत काम की मांग बढ़ी है। लोगों को वहां अच्छे रोजगार नहीं मिल रहे।

AI Image
मनरेगा पर निर्भरता बढ़ी

महामारी से पहले | मनरेगा ऐसी योजना है, जो देश के ग्रामीण इलाकों में अकुशल श्रमिकों के लिए आजीविका की आखिरी उम्मीद मानी जाती है। साल 2019-20 के दौरान इस योजना में लोगों की भागीदारी बारिश, मॉनसून, सूखा जैसे सामान्य मौसमी कारकों से प्रभावित हुई थी। उस साल इस योजना के तहत 265.3 करोड़ कार्यदिवस दर्ज हुए थे।

असाधारण पलायन | उसके बाद महामारी और लॉकडाउन के दौरान देश में शहरों से गांवों की ओर असाधारण पलायन हुआ जिसका प्रभाव मनरेगा समेत जीवन के तकरीबन हर क्षेत्र में देखा गया। लेकिन महामारी की लहरें शांत होने के बाद जैसे-जैसे इकॉनमी उस झटके से उबरती गई, यह उम्मीद बढ़ी कि ग्रामीण क्षेत्रों के अनस्किल्ड लेबर को विभिन्न क्षेत्रों में आजीविका मिलती जाएगी। लेकिन अभी भी वहां यह दबाव बना हुआ है जिसका अर्थ है कि या तो लोगों को शहरों में अच्छा काम मिलने की उम्मीद नहीं है या वे गांव छोड़कर शहर जाना नहीं चाहते।

बढ़ता गया अंतर | 2022-23 में भी इस योजना के तहत 293.7 करोड़ कार्यदिवस दर्ज हुए, जो 2019-20 के मुकाबले 28.4 करोड़ ज्यादा थे। यही नहीं, इस साल यानी 2023-24 में यह अंतर बढ़कर 40 करोड़ तक पहुंच गया। ध्यान रहे इस संख्या में संशोधन अपेक्षित है। इस महीने के आखिर तक अंतिम संख्या आएगी और माना जाता है कि वह इससे और ज्यादा होगी।

ग्रामीण क्षेत्र पर दबाव | यह स्थिति खास तौर पर ध्यान देने लायक इस लिहाज से भी है कि इस दौरान इकॉनमी में ग्रोथ की रफ्तार अच्छी रही है। भारत आज भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। लेकिन यह वृद्धि अनस्किल्ड लेबर के सबसे कमजोर हिस्सों के लिए कोई राहत लेकर नहीं आई। ग्रामीण क्षेत्र पर दबाव बना हुआ है।

चुनावी प्रक्रिया | आम चुनावों के दौरान शुरू होने वाली गतिविधियों में जरूर इस श्रम शक्ति के एक हिस्से को कुछ रोजगार मिल सकता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी। इन क्षेत्रों में कुछ पैसा पहुंचने की भी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन इसका स्वरूप अस्थायी होगा। ऐसे में तात्कालिक राहत मिल भी जाए तो उसे समस्या का हल नहीं माना जा सकता। जाहिर है, चुनावों के बाद नई सरकार को इस मोर्चे पर ठोस और टिकाऊ नतीजे देने वाले सुविचारित कदम उठाने होंगे।

धूप-छांव
छुपी हुई बीमारी

प्रणव प्रियदर्शी

पिछले दिनों राजधानी दिल्ली में JNU स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव नतीजे आने पर मीडिया में यह बात प्रमुखता से प्रचारित हुई कि कैसे पहली बार कोई दलित इस प्रतिष्ठित स्टूडेंट्स यूनियन का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ है। सवाल फिर उठा कि आखिर खबरों में इन जीते हुए प्रत्याशियों की जाति के पहलू को उभारना क्या जरूरी था? क्या इनके अधिकारों में इस आधार पर कोई कटौती या बढ़ोतरी होने वाली है? सवालों के पीछे छुपा आशय यह था कि इस तरह की कवरेज के पीछे दरअसल मीडिया का अपना जातीय पूर्वाग्रह काम कर रहा होता है।

इन सवालों और आपत्तियों के बीच मेरी आंखों के सामने कुछ साल पहले का वाकया घूम गया। मैं दिल्ली में ही एक पत्रिका के न्यूजरूम में बैठा था। टीवी पर यूपी विधानसभा चुनावों के नतीजे आ रहे थे और धीरे-धीरे यह स्पष्ट होता जा रहा था कि इस बार राज्य में सत्ता बदलेगी। नई आई एक युवा ट्रेनी जर्नलिस्ट विस्फारित नेत्रों से टीवी की ओर देख रही थी। किसी को संबोधित किए बगैर जैसे खुद में ही बुदबुदा रही थी, 'यार, ऐसे दिन आ गए। अब तो ये लोग राज करेंगे। अब तो हम लोगों को इनके घरों में झाड़ू लगाना पड़ेगा।' उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी बातें कुछ सीटों की दूरी पर बैठी एक अन्य युवा पत्रकार (जिसके पास कुछ वर्षों का अनुभव था) के चेहरे पर तिलमिलाहट के भाव ला रही थीं। वह खुद को मुश्किल से जब्त किए हुए थी।

मैं ऐसी जगह बैठा था जहां से दोनों की तकलीफ, दोनों की पीड़ा मुझे न केवल दिख रही थी, बल्कि समझ में भी आ रही थी। आखिर यह दूसरी लड़की अपनी सीट से उठी और उस नई लड़की के करीब जाकर मुलायम शब्दों में उसे समझाया कि 'दफ्तर में इस तरह नहीं बोलना चाहिए। तुम भी एक महिला हो, जानती हो कि समाज में या राजनीति में किसी महिला का आगे बढ़ना कितना मुश्किल होता है। फिर भी तुम्हें एक महिला का मुख्यमंत्री निर्वाचित होना कोई बड़ी बात नहीं लग रही, बल्कि दूसरी चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण लग रही हैं तो आखिर क्यों? इस पर सोचना और आगे से दफ्तर में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए थोड़ा सतर्क रहना क्योंकि यह घर नहीं है कि सब एक ही तरह के लोग बैठे हों।'

बात वहीं खत्म हो गई। नई लड़की ने दूसरी लड़की की वरिष्ठता का सम्मान किया। हां, बाद में टी ब्रेक के दौरान अपने करीबियों से दोनों ने अपने भाव ज्यादा स्पष्ट रूप में शेयर किए। बड़ी लड़की ने थोड़ी शिकायत और हैरत के लहजे में सवाल था कि कैसी-कैसी सोच लिए लोग पत्रकारिता में आ रहे हैं। दूसरी ओर नई लड़की की सफाई थी कि 'यार मैं तो उसके पास गई भी नहीं थी, मैंने उससे कुछ कहा ही नहीं था।' फिर आंखों में संदेह और होठों पर हल्की सी मुस्कान के साथ आई यह टिप्पणी कि 'शायद वह भी उन्हीं लोगों में होगी।'

बोल वचन
जी का जंजाल

राहुल पाण्डेय

भगवान हों या इंसान, महान हों या अनजान, हमारी बोलचाल की परंपरा में है कि हम उनके आखिर में जी जरूर लगाते हैं। राम जी, श्याम जी, गांधी जी या अनजान हुए तो भाई जी। जी एक ऐसी तमीज है, जो एक बार अगर हट जाए तो जाकर सीधे बदतमीजी में बैठ जाती है। हिंदुस्तानी बोलचाल में ऐसे बहुत से शब्द हैं, जिनके कभी एक अर्थ नहीं होते, बल्कि वो वाक्यों और शब्दों के साथ जुड़कर अपने अर्थ बनाते हैं। या फिर अपने बोलने की टोन पर। 'जी' भी एक ऐसा ही शब्द है। और यह सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ऐसा जंजाल है, जो दिल और जान, आत्मा और खुद इंसान तक फैला हुआ है। जी सवाल भी है तो जी ही जवाब है। किसी ने पूछा, पूड़ी खाओगे? हमने कहा जी और हो गई हां। किसी ने कहा, आगे जाकर दाएं मुड़ जाना। हमने कहा, जी? और हो गया सवाल। जी चाहता है नाम से जो मूवी आई थी, उसके नाम में तमन्ना नहीं है तो और क्या है? जी हमारा मन भी है, चित्त भी। अवगुण चित न धरो और अवगुण जी न धरो में कोई फर्क नहीं है। हिंदुस्तानी "जी" का अर्थ देने के लिए इंग्लिश को दर्जन भर से भी अधिक शब्द यूज करने पड़ते हैं, मगर कोई जी के करीब तक नहीं फटकता। इंग्लिश में जी के लिए yes, heart, honoured, wish जैसे कई शब्द हैं। और हां, नाम के बाद हम जो जी लगाते हैं, उसके लिए नाम के पहले लगाने के लिए mr., miss, madam, sir जैसे शब्द अलग से हैं। इन शब्दों की लाइन लगी देखकर उनके बेचारों पर ही जी घबरा जाता है। हमारा तो एक शब्द से ही काम चल जाता है, उन बेचारों को कितने ढेर सारे शब्द यूज करने पड़ते होंगे! जी नहीं भन्ना जाता होगा उनका! कहीं ऐसा तो नहीं कि बरतानिया हुकूमत ने हम पर जो जुल्म ढाए, उसमें एक हिस्सा उनकी भाषा की भन्नाहट का भी था?

AI Image

नॉर्थ-ईस्ट के मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में समाज ने की है सराहनीय पहल
क्या है चुनाव सुधार का मिजोरम मॉडल

उमेश चतुर्वेदी

चाहे पंचायती चुनाव हों या विधानसभाओं के या फिर आम चुनाव, पैसे का बोलबाला बढ़ा है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक बयान ने चुनावों में होने वाले बेहिसाब खर्च के मुद्दे को फिर से केंद्र में ला खड़ा किया है। सीतारमण ने कहा कि BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें आंध्र या तमिलनाडु की किसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं।

खर्च की सीमा | चुनाव आयोग ने इस बार लोकसभा चुनाव के लिए प्रति प्रत्याशी खर्च की सीमा 70 लाख रुपये रखी है। लेकिन हकीकत यह है कि शायद ही कोई गंभीर प्रत्याशी ऐसा होगा, जो आयोग द्वारा निर्धारित इस खर्च सीमा में चुनाव लड़ेगा। पार्टियों और प्रत्याशियों के असल खर्च इस सीमा से कहीं ज्यादा होंगे। यह ऐसा सच है, जिसे सब जानते हैं। फिर भी सब चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित खर्च के दायरे में चुनाव लड़ने का दिखावा करते हैं।

लोकतंत्र के खिलाफ | पैसे की कमी के कारण आम हैसियत वाला व्यक्ति गंभीरतापूर्वक चुनाव लड़ने की सोच भी नहीं सकता। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए अक्सर सुझाव दिए जाते रहे हैं। एक सुझाव यह भी आया कि चुनावों का पूरा खर्च सरकारी स्तर पर उठाया जाना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए समाज को खुद आगे आना चाहिए।

खर्च पर कैसे लगा अंकुश
- समाज की ओर से हुई पहल
- पोस्टर-बैनर नहीं लगाए जाते
- हर प्रत्याशी को मिलते हैं 20 मिनट

समाज का हस्तक्षेप | लेकिन ये विचार हकीकत नहीं बन पाते। फिर भी एक राज्य ऐसा है, जहां के समाज ने ही चुनाव सुधार को लागू करके दिखा दिया है। उत्तर-पूर्वी राज्य मिजोरम में समाज ने चुनाव को लेकर ऐसी पारदर्शी और मजबूत व्यवस्था बना दी है, जिसका उल्लंघन करने का साहस न तो कोई राजनीतिक दल कर पाता है और न कोई प्रत्याशी। मिजोरम के राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के लिए चुनाव आयोग के नियमों के बजाय 'मिजो पीपल फोरम' के बनाए नियमों का पालन करते हैं।

न पोस्टर, न लाउडस्पीकर | मिजोरम के चुनाव प्रचार में देश के दूसरे हिस्सों की तरह ना तो पोस्टरबाजी होती है, ना ही पैसे खर्च होते हैं। लाउडस्पीकर का प्रयोग वैसे तो चुनाव आयोग के कड़े नियमों की वजह से देशभर में सीमित हो चुका है, लेकिन मिजोरम में इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। वहां चुनाव प्रचार की निगरानी 'मिजो पीपल फोरम' करता है।

AI Image

बीस-बीस मिनट का वक्त | प्रत्याशियों को अपना पक्ष रखने के लिए बीस-बीस मिनट का वक्त दिया जाता है। इस दौरान वहां वोटर भी जुटते हैं और वे मुद्दों पर प्रत्याशियों से सवाल-जवाब करते हैं। जिन्होंने दिल्ली के जेएनयू के छात्रसंघ चुनाव की प्रेसिडेंशल डिबेट देखी-सुनी है, उन्हें पता है कि किस तरह हर प्रत्याशी अपनी राय रखता है और अपने मुद्दों पर समर्थन जुटाने की कोशिश करता है। मिजोरम के प्रत्याशी भी कुछ वैसा ही करते हैं।

2006 से शुरुआत | दरअसल, साल 2006 के मिजो विधानसभा चुनावों में काफी गड़बड़ियां हुई थीं। इससे आहत मिजो यंग असोसिएशन ने चुनावों को कदाचार मुक्त बनाने का बीड़ा उठाया। उसी की कोशिशों से यहां के सात स्वयंसेवी संगठनों ने मिलकर 'मिजो पीपल फोरम' नाम से साझा मंच बनाया और राज्य में चुनावों को कदाचार मुक्त बनाने की तैयारी की। मिजोरम की करीब 85% आबादी ईसाई है। जाहिर है, इस फोरम को भी ईसाई संगठनों का समर्थन है।

कोई बड़ी रैली नहीं | यह फोरम इतना प्रभावशाली है कि उसके बनाए नियमों का अगर कोई प्रत्याशी उल्लंघन करता है तो उसे मतदाताओं का गुस्सा झेलना पड़ता है। मिजोरम के चुनावों में साल 2006 के बाद से बड़ी-बड़ी रैलियां नहीं हो रहीं। शोर-शराबे का सवाल ही नहीं उठता। वोटरों की खरीद-फरोख्त या निजी लालच की कोई सोच भी नहीं सकता।

दूसरे राज्यों के लिए मिसाल | डेढ़ दशक पहले तक मिजोरम भी अशांत रहा। सवाल है कि जब अशांत रहे किसी एक राज्य का समाज अपने दम पर चुनाव सुधार लागू कर सकता है तो देश के दूसरे इलाकों में समाज ऐसी कोशिश क्यों नहीं कर सकता? सवाल यह भी है कि मिजोरम के इस चुनाव मॉडल को चुनाव आयोग प्रचारित क्यों नहीं करता?

चुनाव सुधार के सुझाव | देश में चुनाव सुधार के लिए संथानम समिति, दिनेश गोस्वामी समिति और एनएन वोहरा समिति ने समय-समय पर सुझाव दिए। लेकिन ज्यादातर सुधार सुप्रीम कोर्ट के फैसले और चुनाव आयोग के बनाए नियमों के हिसाब से हुए। जिन नेताओं को इन चुनावों के जरिए संवैधानिक पद हासिल होते हैं, उनके हाथों संचालित होने वाली विधायिका चुनाव सुधारों की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठाने से हिचकती रही है। ऐसे में समाज से ही उम्मीद की जा सकती है।

सर्वसम्मति पर जोर | मिजोरम के समाज को इस लिहाज से उदाहरण के रूप में पेश किया जा सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर्वसम्मति पर भी जोर रहा है। भारत की पारंपरिक पंचायती व्यवस्था में आज की तरह चुनाव नहीं होते थे, पंचों का चुनाव सर्वसम्मत तरीके से होता था। उसी तर्ज पर मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी कुछ इलाके ऐसे हैं, जो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव सर्वसम्मति से करते हैं। इस समय अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। वहां साठ में से दस सीटों पर सर्वसम्मत निर्वाचन हो चुके हैं।

चुनाव आयोग करे पहल | उत्तर-पूर्व के राज्यों को मुख्यधारा से दूर माना जाता है। लेकिन यहां का समाज मुख्यधारा के समाजों की तुलना में कहीं ज्यादा अनुकरणीय उदाहरण पेश कर रहा है। बेहतर होता कि मिजोरम और अरुणाचल के मॉडल को चुनाव आयोग प्रोत्साहित करता और पूरे देश का नागरिक समाज इस दिशा में सोचना शुरू करता। लोकतंत्र को सच्चे अर्थों में ऐसे ही उपायों से लोकतंत्र बनाया जा सकता है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

इलेक्शन बोले तो नोट छापने का सीजन

जबी तुम तिकिट मांगने का वास्ते कोई पार्टी का पास जाएंगा तो तुमारा लायकी कोई नईं पूछेंगा। तुमारा डिग्री-बिग्री गया तेल लेने। पैले पूछेंगा- 'तुमारा पास रोकड़ा कित्ता होएंगा?'

दीपक पाचपोर

अबी अपुन का कंट्री का भीतर भौत सा आईटम बदली करना मांगताए। बोले तो अक्खा लोग पुराना रिकार्ड बजाताए। जूना बखत का छोकरा लोग स्कूल में जैसा पढ़ाई करेला, वईसाईच अबी का नवा-नवा छोकरा लोग बी करताए। जूना जनरेशन अबी बाप बनेला, टाइम बी टोटल चेंज हुएला पन स्कूल का सिलेबस बोले तो वोईच होताए। अबी बी बताएंगा कि 'इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री'। कोई क्या समझेंगा कि इदर खाली गाव-खेड़ा होएंगा। पन सच्ची में देखेंगा तो अक्खा बाजू हाउसिंग सोसायटी मिलेंगा, फोर लेन रस्ता होएंगा।

अबी स्कूल-कॉलेज का किताब का भीतर क्या लिखेलाए कि 'ऑनेस्टी इज दी बस्ट पॉलिसी'। बोले तो ईमानदारी से काम करने का। तुम दिल पे हात रखके बोलने का, ब्रादर! तुम ईमानदारी से काम करेंगा तबी तुमारा वाट नईं लग जाएंगा?

अपुन कूं खाली इत्ताईच बताने का तुमकूं कि तुम पुराना सिलेबस पढ़ेंगा तबी लाइफ का भीतर कुछ बी नवा नईं करने कूं सकताए। इस करके नवा सिलेबस पढ़ने का। नवा सिलेबस बोले तो उसका भीतर अईसा लिखने का कि 'इंडिया इज ए हाईराइज कंट्री' नईं तो 'इंडिया इज ए हाईवे कंट्री'। 'इंडिया इज ए फोर लेन-सिक्स लेन कंट्री' नईं तो 'इंडिया इज ए फ्लाईओवर कंट्री' अईसा बोलने का।

अबी जईसा-जईसा इलेक्शन नजीक आएला, अक्खा लोग पईसा का बात करताए। सबका बोले तो एकईच टेंशन- 'पईसा किदर से आएंगा?' कोई-कोई श्याणा लोग इलेक्शन जितेंगा अऊर दूसरा दिन से पईसा इकट्ठा करना सुरु कर देंगा। उसकूं पताए कि पांच बरस अईसा ताबड़तोड़ निकलेंगा कि अगला बखत उसका पास पईसा का जुगाड़ करने का फुरसत नईं मिलेंगा। जबी तुम तिकिट मांगने का वास्ते कोई पार्टी का पास जाएंगा तो तुमारा लायकी कोई नईं पूछेंगा। तुमारा डिग्री-बिग्री गया तेल लेने। पैले पूछेंगा- 'तुमारा पास रोकड़ा कित्ता होएंगा?' बोले तो उदर सीदा कंपीटिशन होएंगा। कोई दस करोड़ खर्चा करने का बात कहेंगा, तभी कोई 20 का बात बोलेंगा नईं तो 50-50 खोखा का बी बात होएंगा। आईपीएल का माफिक। पार्टी का लीडर लोग साफ बोलेंगा कि 'तुमकूं पब्लिक का बीच जाने काए तबी नोट का बंडल लेके जाने का।' रोड शो करेंगा, रैली करेंगा, वर्कर लोग को चा-पानी, नाष्टा-बिष्टा लगताए, रात कूं एनर्जी ड्रिंक का खर्चा होताए। तुम सोचेंगा कि खाली फोकट में वो तुमारा यारी-दोस्ती का खातिर दिन भर इस गल्ली से उस गल्ली 'जिंदाबाद मुर्दाबाद' कहके रखडेंगा- तो इलेक्शन का बात भूल जाने का।

AI Image

खाली पीली

अबी ये बोले तो कैंडिडेट लोग का टेंशन! तुम सोचता होएंगा कि जो चुनाव नईं लड़ता होएंगा उसकूं कोई टेंशन नईं होता होएंगा। पन ऐसा नईं। पार्टी जबी अपना स्टार लीडर कूं अक्खा इंडिया में घुमाएंगा तबी उनका खर्चा-पानी निकालना पड़ेंगा। वो हमारा-तुमारा माफिक लोकल ट्रेन में नईं रखडेंगा। उसकूं हैलीकाप्टर मांगताए रे! फिर पार्टी कूं अक्खा तरफ जाहिरात देना पड़ेंगा। पेपर, सोशल मीडिया का भीतर, अक्खा तरफ तुमकूं बड़ा-बड़ा विज्ञापन दिखेंगा।

अबी तुम सोचेंगा कि इलेक्शन बोले तो खाली पईसा खरचा करने का टाइम होताए। अईसा नईं। अपुन का फ्रेंड बाबूराव कहताए कि डेढ़ श्याणा लोग का वास्ते ये नोट छापने का सीजन होताए। जईसा बाकी सीजन हर बरस दो-तीन बखत आएंगा, पन इलेक्शन का सीजन बोले तो पांच साल का भीतर खाली एकईच बार आताए। इस करके फुल पॉवर लगाके पईसा बनाने का।

अबी तुम सोचेंगा कि नोट कईसा बनाएंगा, तो अपुन बताता है तुमकूं। ध्यान देके सुनने का! अक्खा पार्टी का भीतर किसी कूं टिकट दिलाने वाला बी पईसा बनाता है। कोई अपना जात-सगा वाला का तरफ से बयान दिलाएंगा कि 'भाई चुनाव लडेंगा।' चार लोग बईठने का, नाम वापस लेने का वास्ते रोकड़ा देके जाएंगा। लफड़ा में पड़ना नईं, मचमच से दूर रहके नोट छापने का अऊर इलेक्शन का मजा लेने का, बॉस!

शेयर करें अपने अनुभव
आम मुंबइया भाषा में यह लेख कैसा लगा हमें बताएं
nbtreader@timesgroup.com पर,
और सब्जेक्ट में लिखें-'**खाली पीली**'

जयललिता की तारीफ क्यों

इस बार BJP सबसे अधिक दांव तमिलनाडु पर लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल के समय में सबसे अधिक चुनावी रैलियां भी वहीं की हैं। दिलचस्प है कि चुनावी सीजन में नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के टीवी चैनल को ही अपना सबसे पहला डीटेल्ड इंटरव्यू दिया। हालांकि वहां पार्टी से AIADMK के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन न हो पाना जरूर झटका माना गया। जानकारों के अनुसार, खुद पीएम मोदी भी चाहते थे कि AIADMK के साथ गठबंधन हो। उनकी यह मंशा इंटरव्यू में भी दिखी, जब उन्होंने जयललिता की खूब तारीफ की। उन्होंने यहां तक कहा कि 2002 में गुजरात दंगे के बाद देश के तमाम दूसरे नेताओं ने उनसे दूरी बना ली थी, तब सिर्फ जयललिता थीं जो गुजरात आईं। कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जयललिता की विरासत से खुद को जोड़कर तमिलनाडु में AIADMK वोटरों को भी टारगेट कर रहे हैं। BJP ने पार्टी के नेताओं से भी कहा है कि वे जयललिता पर कोई नकारात्मक कमेंट न करें। BJP का आकलन है कि अगर जयललिता से जुड़ी विरासत का वोट BJP को मिला, तो पार्टी इस बार सभी को चौंका सकती है।

विशुद्ध राजनीति
पॉलिटॉक

अमेठी से कौन

उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट पर इस बार कांग्रेस को लेकर एक बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है कि इस बार अमेठी से राहुल गांधी कांग्रेस उम्मीदवार होंगे या नहीं। रायबरेली से सोनिया गांधी के नहीं लड़ने के एलान के बाद वहां से प्रियंका गांधी के चुनावी मैदान में उतरने की अटकलें भी लग रही हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों की मानें तो प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की संभावना कम ही है। ऐसे में अब फोकस अमेठी पर शिफ्ट हो गया है। कांग्रेस के अंदर अधिकतर नेताओं की आम राय है कि अगर राहुल गांधी वहां से खुद नहीं लड़ेंगे, तो इसका बहुत नकारात्मक संदेश जाएगा। ऐसे में कांग्रेस के अधिकतर नेताओं की ओर से राहुल गांधी पर एक तरह का दबाव भी है। यह बात पार्टी में अलग-अलग स्तरों पर कही जा रही है कि यूपी में पार्टी को गंभीरता से लिया जाए इसके लिए राहुल गांधी का अमेठी से लड़ना जरूरी है। लेकिन सभी जानते हैं कि वहां से चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना, यह फैसला खुद राहुल गांधी ही करेंगे। यही वजह है कि पार्टी की ओर से वहां उम्मीदवार तय करने में लगातार देरी हो रही है, और सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा।

BJP करा रही होमवर्क

BJP ने इस बार आम चुनाव में टिकट देने को लेकर कई प्रयोग किए हैं। अलग-अलग क्षेत्रों से पार्टी ने कई नामों को मैदान में उतारा है। इसी कड़ी में सिने-कला जगत से जुड़े दो चर्चित नामों को टिकट दिया गया। दोनों टिकट मिलने के बाद उत्साहित हैं और अपने-अपने संसदीय क्षेत्र में सियासी मुकाबले के लिए उतर चुके है। लेकिन BJP को एक चिंता भी है। दोनों अपने हिसाब से कई बार बेबाक बोलने के लिए जाने जाते हैं। ऐसा भी बोल देते हैं, जिससे राजनीतिक रूप से नुकसान हो सकता है। इस मामले में खासकर एक नाम पर अधिक चिंता है। उन्हें टिकट देने से पहले कई स्तर पर मंथन भी हुआ। पार्टी के अंदर उन्हें टिकट देने पर पूरी तरह एक राय नहीं थी। उनके ट्रैक रेकॉर्ड को देखते हुए BJP अब टिकट देने के बाद कवर भी अपने स्तर से दे रही है। दोनों उम्मीदवारों के लिए मुद्दों की तलाश से लेकर कब कहां किससे क्या बोलना है, उसका होमवर्क पार्टी की टीम ही कर रही है। पार्टी की ओर से दोनों उम्मीदवारों को कम्युनिकेशन टीम भी उपलब्ध कराई गई है। सोशल मीडिया अकाउंट पर भी नजर रखी जा रही है। दरअसल, BJP की मंशा है कि इस बार चुनाव में ऐसा कोई विवाद न हो, जिससे उनका कैंपेन किसी तरह प्रभावित हो।

माया मिली, न राम

बिहार में इस बार दो छोटे दलों के नेताओं के लिए 'दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम' वाली हालत हो गई है। एक हैं पशुपति कुमार पारस, और दूसरे हैं मुकेश सहनी। दोनों नेताओं की कोशिश रही कि बारगेन कर अधिक से अधिक सीटें लें, पर इस कोशिश में दोनों कहीं के नहीं रहे। चिराग पासवान से समझौता करने के बाद BJP ने पारस को एक पैकेज ऑफर दिया, लेकिन वह RJD के साथ बारगेन करने लगे और वहां अधिक सीटों की मांग करने लगे। इसी कोशिश में वक्त बीत गया और उन्हें कहीं कुछ नहीं मिला। अब पारस एकतरफा NDA को समर्थन देने की बात कर रहे हैं ताकि चुनाव के बाद कुछ मिल सके। वहीं मुकेश सहनी के बारे में कहा गया कि वह एक ही दिन अलग-अलग समय दोनों गठबंधन से बात कर रहे थे। इसका पता दोनों गठबंधनों को चल गया तो उनसे सबने नमस्ते कर ली।

'विलेन' कौन

अभी सबसे अधिक सियासी उत्सुकता उस वजह का पता लगाने की है, जिसके तहत ओडिशा में BJP और BJD का चुनाव पूर्व गठबंधन होते-होते रुक गया। वह भी तब, जब BJP में नरेंद्र मोदी और BJD में खुद नवीन पटनायक की सहमति से गठबंधन की बात शुरू हुई थी। चर्चा है कि BJD की ओर से नवीन पटनायक के करीबी ब्यूरोक्रेट ने गठबंधन की बात शुरू की थी। इस पूर्व ब्यूरोक्रेट को नवीन पटनायक के उत्तराधिकारी के रूप में भी देखा जा रहा है। वहीं BJP में भी ब्यूरोक्रेट से नेता बने एक मंत्री ने कमान संभाली थी। लेकिन BJP के अंदर एक बड़ा वर्ग BJD विरोधी भी है। वैसे ही BJD के अंदर एक वर्ग BJP विरोधी है। इन दोनों ने अपनी-अपनी पार्टियों पर दबाव बनाया। लेकिन दोनों पार्टियों को लगा कि इससे न सिर्फ उनकी पार्टी में टूट हो सकती है, बल्कि उसका लाभ कांग्रेस को मिल सकता है, जो राज्य में तीसरे नंबर पर कमजोर स्थिति में है। लेकिन गठबंधन न हो पाने के बाद अब दोनों दल चुनाव में एक-दूसरे के खिलाफ किस तरह उतरेंगे, इसे लेकर संशय है। BJP को लगता है कि अगर वह BJD पर नरम पड़ी, तो कहीं विधानसभा के साथ लोकसभा चुनाव में भी नुकसान न हो जाए। इसका ठीक उलटा संशय BJD को भी सता रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान दोनों दल एक-दूसरे के खिलाफ कितना टफ या सॉफ्ट रुख अपनाते हैं।

AI Images

रीडर्स मेल
www.edit.nbt.in

■ एकजुटता के संकेत
1 अप्रैल का संपादकीय 'विपक्षी रैली का संदेश' पढ़ा। दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी खेमे I.N.D.I.A. की 'लोकतंत्र बचाओ' रैली में देश के तमाम विपक्षी नेताओं की एकजुटता से लगा कि आम चुनाव का रंग पूरी तरह चढ़ गया है। इसके साथ ही इस जुटान ने एक नया संदेश दिया है। विपक्षी गठबंधन बनने के बाद से ही बिखराव के संकेत मिलने लगे थे। सीट शेयरिंग के मामले में भी कहीं न कहीं पीड़ा और स्वार्थ के संकेत मिल रहे थे। रविवार की रैली से लगा कि ये दल थोड़े गंभीर हैं। हालांकि सत्ता पक्ष के खिलाफ लामबंद हुए इन विपक्षी दलों की आंतरिक मंशा में लोकतंत्र बचाना प्रमुख है या चुनावी लाभ उठाना यह वक्त बताएगा। फिर भी यह गंभीरता बनी रहे तो अच्छा।
नीलमणि रावत, ईमेल से

■ कनफ्यूज नहीं होने का
यह पत्र 'खाली पीली' कॉलम में 19 मार्च को प्रकाशित लेख 'वोट देके अगला इलेक्शन का वेट करने का' से संबंधित है। **खाली पीली** मुंबइया बोली में प्रकाशित लेख पढ़ने में थोड़ा असहज लगा, क्योंकि यह हिंदी से थोड़ी अलग है। लेकिन दो-तीन बार पढ़ने के बाद बात भेजे में घुस गई। लेख में टीवी पर दिखाए जाने वाले ओपिनियम पोल के बारे में सही कहा गया है कि सर्वे एजेंसी वाला तुमकूं क्या दिखाताए? खाली एकईच आइटम। यानी लेखक ने साफ कर दिया है कि कनफ्यूजन वाली बात पर नहीं जाना है। आंख-कान खुला रखकर फैसला लेना है।
पैंथर तोमर, किशन गंज

■ ताकि चुनावी खर्च बचे
भारत में एक साथ लोकसभा, विधानसभा, महानगरपालिकाओं के चुनाव करवाना समय की मांग है। भारत जैसे विशाल देश में लगातार चुनाव कराना संसाधनों की बर्बादी है। चुनाव में लाखों करोड़ रुपये का खेल हो जाता है। आखिर यह पैसा आता है कहां से? अलग-अलग चुनावों से सरकारें स्वच्छंद होकर कार्य नहीं कर पाती हैं। वे अगला चुनाव जीतने के लिए लालच, प्रलोभन, तुष्टिकरण की नीति अपनाती हैं और देश का विकास रुक जाता है। सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर चुनाव सुधार पर जोर देना चाहिए ताकि देश को अनावश्यक खर्च से बचाया जा सके।
रामलाल एल. राम, ईमेल से

nbtedit@timesgroup.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र
बड़ी कंपनियों की GST जांच से पहले मंजूरी जरूरी - एक खबर
- बड़ी कंपनियों पर करम और छोटी पर सितम!
प्रमोद गुप्ता

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
hindi.speakingtree.in

मन का खराब होना जीवन की सबसे बड़ी समस्या है

जे. कृष्णमूर्ति

पत्तियों के बीच से झांकता हुआ वह चांद कितना प्यारा लग रहा है! शाम की ढलती रोशनी में अपने घोंसले की तरफ लौटते परिंदों का कलरव कितना अच्छा लगता है! इन दृश्यों का आनंद लीजिए। मान लीजिए कि कल किसी ने कठोर शब्दों में कुछ ऐसी बातें कहीं, जो सच नहीं हैं। उसने जो कुछ कहा, वह मन में दर्ज हो गया। उन बातों के साथ ही मन उस व्यक्ति की पहचान भी नत्थी कर लेता है। उस अपमान, उन कटु वचनों, उस झूठी बात के साथ रिश्ता बुनकर मन वैसा ही बर्ताव करने लगता है। लेकिन मेरी नजर में जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है- संबंध।

संबंधविहीन जीवन में अव्यवस्था का होना निश्चित है। जो मन व्यवस्था में रहता है, वह एक मिनट के लिए भी अव्यवस्था का साया अपने ऊपर नहीं पड़ने देता है। और वह अव्यवस्था तो जन्म ही तब लेती है जब मन संबंध में अतीत के ज्ञान के आधार पर बर्ताव करता है। तो यह कैसे हो कि मन यह तो जाने कि अपमान हुआ है, या सम्मान हुआ है, पर उसे दर्ज न करे? क्या यह हो सकता है कि मन हमेशा निर्मल, साफ-सुथरा, स्वस्थ रहे, संबंध में परिपूर्ण रहे? क्या इसमें आपकी दिलचस्पी है? आप जानते हैं कि मन का खराब होना जीवन की सबसे बड़ी समस्या है? यदि आपकी इसमें वाकई दिलचस्पी है कि संबंध में कैसे जिया जाए कि मन को कभी ठेस न लगे, मन में कभी विकार-विकृति न आए। ऐसा सोचना ही प्रेम है।

वह मन जो कोई मान-अपमान दर्ज नहीं करता, वही जानता है कि प्रेम क्या होता है। यदि संभव हो जाता है कि किसी के मान-अपमान को दर्ज न करें, तो मानो हमने संबंध की समस्या को सुलझा लिया है। हम संबंध में जीते हैं। संबंध कोई दिमागी सोच या वैचारिक उपज नहीं है। यह तो दिन-प्रतिदिन के जीवन का एक तथ्य है, वास्तविकता है। चाहे आप अपने काम पर जाते हों और लौटकर अपनी पत्नी के साथ झगड़ते हों या उसके साथ प्यार से रहते हों, आप हमेशा किसी न किसी संबंध से जुड़े हैं। और यदि आपके और दूसरे के बीच, या आपके और बहुतों या एक के बीच के संबंध में व्यवस्था नहीं है, तो आप एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करेंगे जो अंत में अव्यवस्था ही पैदा करेगी। यही आजकल हो रहा है।

यह जानने की कोशिश करना परम आवश्यक है कि अपमान, ठेस, दुर्व्यवहार या कटुता व कठोरता मिलने पर भी क्या मन एक पल के लिए भी उसे बिना थामे रह सकता है? जिस भी पल हम उसे थामते हैं, वह तुरंत दर्ज हो जाती है, मस्तिष्क में अपनी छाप छोड़ जाती है। इस प्रश्न की जटिलता को देखिए। क्या मन ऐसा कर सकता है कि वह पूरी तरह निर्मल और अबोध बना रहे? निर्मल व अबोध मन वह होता है जिसे ठेस लग ही नहीं सकती है। क्योंकि जिसे ठेस नहीं लगती है, वह किसी दूसरे को भी ठेस नहीं पहुंचाएगा।

इस आयाम तक आने के लिए यह देखना और जानना होगा कि प्रेम क्या है। क्या प्रेम विचार की उपज है? क्या प्रेम समय के दायरे में आता है? क्या प्रेम सुख-विलास है? क्या प्रेम एक स्वाद का वही सुख है, जिसे फिर से चाहने लगता हूं, या उससे भी बढ़िया? मन जिसे दर्ज कर लेता है और फिर उसे ही बार-बार चाहने लगता है। यही तो प्रेम है।

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा में मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्सः 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

जारी है दलितों से भेदभाव

भारत में दलितों से जाति व्यवस्था के कारण क्रूर हिंसा और उत्पीड़न होता रहा है। तमाम कानूनों के बावजूद देश में आज भी दलितों से भेदभाव की घटनाएं सामने आ जाती हैं। इतिहास को देखें तो महाभारत लिखने वाले वेदव्यास भी मछुवारे थे परंतु वह महर्षि बन गए और गुरुकुल चलाते थे। विदुर जिन्हें महापंडित कहा जाता है वो एक दासी के पुत्र थे। वह हस्तिनापुर के महामंत्री बने और उनकी लिखी हुई विदुर नीति राजनीति का महाग्रंथ है। भगवान श्रीराम के साथ बनवासी निषादराज भी राज गुरुकुल में पढ़ते थे। उनके पुत्र लव-कुश महर्षि वाल्मीकि के गुरुकुल में पढ़े। वैदिक काल की बात करें तो कोई किसी का शोषण नहीं करता था। सबको शिक्षा का अधिकार था। कोई भी अपनी योग्यता के अनुसार पद पर पहुंच सकता था। आखिर जन्म आधारित जातीय व्यवस्था कैसे शुरू हुई इस पर तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है लेकिन यह वास्तविकता है कि स्वार्थी नेताओं ने जातिवाद का पूरी तरह से राजनीतिकरण कर दिया और यह आज तक जारी है। राजस्थान के अलवर जिले में 8 साल के एक दलित बच्चे की बेरहमी से पिटाई की गई क्योंकि उसने ऊंची जाति के शख्स की पानी की बाल्टी को छू लिया था। इतना ही नहीं मारपीट करने वाले ने बच्चे के पिता और परिवार के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया। चौथी क्लास का बच्चा गांव के सरकारी स्कूल में लगे हैंडपम्प पर पानी पीने गया था तब उसने पानी की बाल्टी को छू लिया था। बच्चा इतना भयभीत हो गया कि अब वह स्कूल जाने से भी डर रहा है। पुलिस ने एससी-एसटी कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

यद्यपि आज के आधुनिक दौर में जातिवाद कम हुआ है लेकिन विभिन्न शोध आज भी इस भ्रम को तोड़ते नजर आते हैं। माना जा रहा है कि शहरीकरण और आधुनिकीकरण के साथ जाति और गौत्र जैसी प्राचीन और परम्परागत पहचान धूमिल हो रही है लेकिन वास्तविकता यह है कि शहरों में बस्तियां जातियों के आधार पर बसी हुई हैं और सवर्णों के मोहल्लों में दलितों को अक्सर ठिकाना नहीं मिलता। गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कई शहरों में ऐसा देखा गया है। बेंगलुरू शहर में आईटी क्रांति के बाद बसी आधुनिक बस्तियों में भी दलितों के न होने का चलन दिखाई देता है। आधुनिक अपार्टमैंटों में दलित बेहद कम हैं।

यद्यपि आज के आधुनिक दौर में जातिवाद कम हुआ है लेकिन विभिन्न शोध आज भी इस भ्रम को तोड़ते नजर आते हैं। माना जा रहा है कि शहरीकरण और आधुनिकीकरण के साथ जाति और गौत्र जैसी प्राचीन और परम्परागत पहचान धूमिल हो रही है लेकिन वास्तविकता यह है कि शहरों में बस्तियां जातियों के आधार पर बसी हुई हैं और सवर्णों के मोहल्लों में दलितों को अक्सर ठिकाना नहीं मिलता। गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कई शहरों में ऐसा देखा गया है। बेंगलुरू शहर में आईटी क्रांति के बाद बसी आधुनिक बस्तियों में भी दलितों के न होने का चलन दिखाई देता है। आधुनिक अपार्टमैंटों में दलित बेहद कम हैं।

कोलकाता के बारे में ये माना जाता है कि ये आधुनिकता की भूमि है और यहां के लोग काफी आधुनिक हैं, ये सामाजिक नवजागरण का भी केन्द्र रहा है। लंबे समय तक वहां वामपंथियों का भी शासन रहा फिर ऐसी क्या वजह है कि कोलकाता के भद्रलोक मोहल्लों में दलित अनुपस्थित हैं। शोध का विषय ये भी है कि कोलकाता में सिर्फ 5 फीसदी दलित क्यों हैं जबकि पश्चिम बंगाल में 23 फीसदी से ज्यादा दलित हैं। वहीं गुजरात में ये देखा जाना चाहिए कि जिस राज्य के बारे में ये मिथक है कि यहां हिन्दू और मुसलमान अलग-अलग रहते हैं उस राज्य में दलितों को शहरी मोहल्ले से दूर रखने का चलन सबसे ज्यादा क्यों है? गुजरात का जातिवाद इतने लम्बे समय से छिपा हुआ क्यों रहा?

राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के कई शहरों में सवर्णों के मोहल्लों में आज भी दलित दूल्हे घोड़ी पर सवार होकर बारात नहीं ले जा सकते। अनेक घटनाएं सामने आती हैं जो शर्मसार कर देने वाली हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दलित लड़कियों से बलात्कार, उन्हें जिंदा जलाने की घटनाएं सामने आती रही हैं, कभी दलितों की पीट-पीट कर हत्या कर दी जाती है, कभी मंदिरों में आयोजित प्रतिभोज के दौरान उनके अलग बैठने की व्यवस्था की जाती है। दलित महिलाओं के साथ दूसरे या तीसरे नागरिक की तरह व्यवहार किया जाता है। केवल यह कहना कि देश में जातिवाद केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही है उचित नहीं है। शहरों में भी दलितों के साथ कहीं न कहीं भेदभाव हो रहा है। दलितों के पास जमीनें बहुत कम हैं या नहीं के बराबर हैं। अगड़ी जाति के लोगों ने उनकी जमीनें हड़प ली हैं। सरकारों के पास उनकी जमीन देने की क्षमता नहीं है और न ही उन्हें नौकरियां मिल रही हैं। 2018 में हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद अन्याय, उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ दलितों का मुखर आंदोलन शुरू हुआ था और हैदराबाद से सुलगी चिंगारी गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में देखते ही देखते फैल गई थी। संविधान में सभी नागरिकों को बराबर माना जाता है लेकिन आज भी उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं मिला है। दलितों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति अभी भी खराब है। दलित परिवार अपने बच्चों को दिहाड़ी, मजदूरी करके सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहा है। जाहिर है दलित बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की बराबरी नहीं कर पाएंगे। दलितों को समाज में सम्मानजनक स्थान पर पहुंचाना आसान काम नहीं है। अगड़ी जातियों के लोग आज भी अपना दबदबा और अपनी मूंछ ऊंची रखने के लिए दलितों का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न कर रहे हैं।

इनके उत्थान के लिए जरूरी है कि पर्याप्त संसाधन और सामाजिक सुरक्षा दी जाए अन्यथा वे समाज के प्रभावशाली वर्ग की दया पर ही निर्भर रहेंगे। किसी समाज के विकास और उन्नति के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है। दूसरे तबके से मुकाबला करने के लिए जरूरी है कि दलित बच्चों को शिक्षा के तमाम अवसर मुहैया कराए जाएं हालांकि आजादी के बाद छुआछूत से राहत मिली है। आरक्षण के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधान से भी कुछ हद से मदद मिली लेकिन पूरे दलित समाज को लाभ नहीं मिला, संसाधानों के स्वामित्व पर असर नहीं पड़ा। यानी संसाधनों का वितरण अपरिवर्तित ही रहा। अब भी उनका संघर्ष मूलभूत जरूरतों और अस्मिता की लड़ाई के लिए ही चल रहा है।

आदित्य नारायण चोपड़ा

Adityachopra@punjabkesari.com

अब दुर्लभ ही सुनने को शुभ...

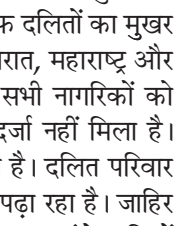

गीता पाढा

खून से सने हुए अब अखबार मिलते हैं,
आधे से ज्यादा युवा बेरोजगार मिलते हैं,
कहीं दुष्कर्म, अपहरण की शर्मनाक खबरें तो कहीं गैंगवार मिलते हैं,
अब दुर्लभ ही सुनने को शुभ समाचार मिलते हैं..!!

अब बांग्लादेश में 'इंडिया आउट'...?

डा. विजय दर्डा

संपादक : लोकमत समूह

पूर्व राज्यसभा सांसद

तेजी से तरक्की कर रहे बांग्लादेश में पिछले महीने जब अचानक इंडिया आउट के नारे सुनाई दिए तो सभी का चौंकना स्वाभाविक था। अभी-अभी यही राग तो मालदीव के राष्ट्रपति मो. मुइज्जू अलाप रहे थे। फिर यह राग बांग्लादेश में कैसे और क्यों शुरू हो गया? क्या यह केवल बांग्लादेश के विरोधी दलों का आंदोलन है या फिर इसके पीछे चीन की चाल है? चीन पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि इस पूरे प्रसंग में चीन का हाथ है। सुकून की बात है कि चीन की कूटनीति सफल नहीं हो रही है क्योंकि भारत की नीति संस्कृति रिश्तों को संभालने की रही है। चीन की लुभावनी चाल में फंसने वाले हमारे पड़ोसी भी जानते हैं कि भरोसेमंद साथी तो भारत ही है।

बांग्लादेश के प्रमुख विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) को यह लगता रहा है कि भारत अवामी लीग का समर्थन करता है। वैसे इसमें कोई दो राय है भी नहीं कि अवामी लीग की सर्वोच्च नेता और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ भारत के रिश्ते बहुत मजबूत हैं। उन्होंने बांग्लादेश को तरक्की की राह पर तो तेजी से बढ़ाया ही है, वहां कट्टरपंथ के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति भी अपना रखी है। यहां तक कि इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा के सहयोगी संगठन हिज्ब-उत-तहरीर (एचयूटी), जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश और अंसारुल्ला बांग्ला टीम जैसे समूहों के आतंकवादियों को फांसी के फंदे पर भी लटकाया है।

चीन के लिए बांग्लादेश की विपक्षी पार्टियां और ये आतंकी संगठन मददगार साबित हुए हैं। इन्हीं के माध्यम से बांग्लादेश में 'इंडिया आउट' का अभियान शुरू हुआ है, जिसकी गूंज सोशल मीडिया पर ज्यादा सुनाई दे रही है। भारतीय उत्पादों के बायकॉट की बात कही जा रही है लेकिन शेख हसीना की सरकार का स्पष्ट तौर पर कहना है कि इस तरह की अपील का असली मकसद बांग्लादेश के बाजार को अस्थिर करना है। बांग्लादेश का बाजार यदि अस्थिर होता है तो निश्चय ही इसका फायदा चीन उठाएगा। इसके साथ ही वह बांग्लादेश को उसी तरह अपने चंगुल में फंसा लेगा जिस तरह से उसने पाकिस्तान, श्रीलंका और अब मालदीव को फंसाया है, नेपाल और भारत के संबंधों की मिठास को वह पहले ही कड़वा बना चुका है।

म्यांमार और भूटान को भी उसने भारत से दूर करने की कोशिश की है लेकिन भारत के प्रति पड़ोसियों का भरोसा होने के कारण चीन ज्यादा सफल नहीं हो पाया है। अब बांग्लादेश को हमसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। यदि आप भौगोलिक मानचित्र देखें तो चीनी कब्जे वाले तिब्बत और बांग्लादेश के बीच हमारे पूर्वोत्तर के राज्य स्थित हैं, हमारे इन राज्यों में आतंकी समूहों को वह हथियार और ड्रग्स देकर हमें परेशान करने की हरसंभव कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि किसी भी तरह बांग्लादेश से भारत के रिश्ते कड़वे हो जाएं और बांग्लादेश उसकी गोद में जा बैठे, अच्छी बात यह है कि शेख हसीना इस बात को अच्छी तरह समझती हैं, वे चीन की हर चाल के आगे अडिग खड़ी दिख रही हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि जब विपक्षी नेता अपनी पत्नियों के पास मौजूद भारतीय साड़ियों को जलाएंगे तब ही ये साबित होगा कि विपक्ष वाकई भारतीय उत्पादों के बहिष्कार के लिए प्रतिबद्ध है।

वैसे भी दुनिया यह जानती है कि बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी बीएनपी हमेशा ही भारत विरोधी रही है। बांग्लादेश की आजादी की स्वर्ण जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ढाका दौरे के खिलाफ बांग्लादेश में होने वाले हिंसक विरोध में बीएनपी शामिल थी। बीएनपी की नेता खालिदा जिया दोहरी चाल भी चलती नजर आती हैं। बीएनपी एक ओर भारत की मुखालफत करता है तो दूसरी ओर बीएनपी का एक गुट भारत से अच्छे संबंधों की वकालत भी करता है, मगर हावी कट्टरपंथी ही होते हैं। माना जाता है कि इस चाल के पीछे खालिदा जिया का ही दिमाग है। सवाल यह है कि क्या खालिदा जिया और चीन के बीच कोई समझौता हो चुका है? यह शंका तो पैदा होती है। हालांकि पिछले चुनाव में चीन ने उनका साथ नहीं दिया था क्योंकि जिया के समर्थन में अमेरिका खड़ा था। शायद चीन को यह उम्मीद रही हो कि वह शेख हसीना को अपने पाले में कर लेगा।

यहां इस बात पर भी गौर करना जरूरी है कि चीन को यह बात समझ में आ गई है कि वह भारत को सैन्य शक्ति से नहीं दबा सकता। गलवान में भारत के मुंहतोड़ जवाब से उसे भारत के रवैये का पूरा अंदाजा हो चुका है, वह भारत को हर हाल में कमजोर करना चाहता है क्योंकि उसे इस बात का डर है कि आने वाले वर्षों में भारत उससे बड़ी आर्थिक ताकत न बन जाए।

1978 में अर्थव्यवस्था के दरवाजे बाहरी दुनिया के लिए खोलने के बाद से उसकी अर्थव्यवस्था औसतन 9 प्रतिशत की तेज गति से बढ़ी मगर कोविड ने उसे 2.2 पर ला दिया। वापस वह 8 प्रतिशत पर आया लेकिन 2023 में चीन केवल 5.2 प्रतिशत की रफ्तार ही हासिल कर पाया जबकि इस अवधि में भारत की अर्थव्यवस्था 7.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी। भारत की इस रफ्तार ने चीन को चिंतित कर रखा है, एक पुरानी कहावत है कि यदि खुद की बड़ी लकीर नहीं खींच सकते तो दूसरे की लकीर को मिटाओ। चीन यही कर रहा है, वह भारत को इतना उलझा देना चाहता है कि हमारे विकास की रफ्तार थम जाए लेकिन उसे यह समझ लेना चाहिए कि भारत उसकी चाल को अच्छी तरह समझता है। भारत की रफ्तार अब कोई नहीं रोक सकता, भारत पलटवार करना जानता है।

जरूरी है शेख हसीना का सरताज होना

आर.के. सिन्हा

पूर्व राज्यसभा सांसद

कोई चाहे तो बांग्लादेश के विपक्ष से एहसान फरामोशी सीख सकता है। जिस भारत ने बांग्लादेश को, या यूं कहें कि 1970 तक के पूर्वी पाकिस्तान, की प्रताड़ित और पीड़ित आम जनता के हितों की रक्षा के लिए पाकिस्तान से युद्ध मोल लिया, उस बांग्लादेश के प्रमुख विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलती रहती है।

उसके जहरीले अभियान से पड़ोसी मुल्क के कठमुल्लों को भी भारत और अपने ही बांग्लादेश के हिन्दुओं के खिलाफ हिंसा करने का मौका मिल जाता है। बांग्लादेश में बीएनपी ने हाल ही में भारत के उत्पादों के बॉयकाट का आह्वान भी किया हुआ है। इसके चलते वहां प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद की सरकार और विपक्ष आमने-सामने है। मुस्लिम बहुल बांग्लादेश में भारत विरोधी भावना कोई नई बात नहीं है। पिछले साल क्रिकेट विश्व कप में भारत की हार के बाद ढाका और वहां के कई शहरों में जश्न मना था। मैं तो स्वयं 1970 के भारत-पाक युद्ध में 'युद्ध संवाददाता' के हैसियत से बांग्लादेश में भारतीय सेना के साथ रहा था । युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने लाखों बांग्ला भाषी मुसलमान भाइयों को क़त्लेआम से बचाया, हजारों बंगाली बेटियों और बहनों को पाकिस्तानी सेना द्वारा किए जा रहे बलात्कार से रक्षा की। इन सभी अत्याचारों का मैं प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूं लेकिन, बांग्लादेश की आज़ादी के बाद जब बंगबंधु शेख़ मुज़ीबुर रहमान ने सभी युद्ध संवाददाताओं के साथ-साथ वरिष्ठ संपादकों को एक विशेष ट्रेन भेजकर बुलाया, तभी जगह-जगह "इंडियाज़ जिनीस- पत्तर भालो नेई" के वाल पेंटिंग देखने को मिले। जब मैंने शेख़ मुजीब के पीआरओ से पूछा कि भारत ने तो युद्ध के बाद लाखों बांग्लादेशियों को भुखमरी से बचाया, हज़ारों मकान बनवाये, फिर यह क्या चल रहा है?" तब पीआरओ ने कहा, "आप चिंता मत कीजिए। कुछ हिंदू विरोधी कट्टरपंथी हैं, उन्हें ठीक करने में सरकार लगी हुई है।'' लेकिन वे तो आज भी बने हुए हैं, बल्कि कई गुना बढ़ गये हैं।

बांग्लादेश में भारत के कथित हस्तक्षेप को लेकर विरोध और असहमति 1990 के दशक से देखी जा रही है लेकिन हाल के वर्षों में विरोध के ये सुर कहीं ज्यादा मुखर हुए हैं। आपको याद ही होगा कि बीएनपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने देश में बीती जनवरी में हुए आम चुनाव का बहिष्कार किया था। इस चुनाव में जीत के बाद शेख़ हसीना चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी थीं। आप कह सकते हैं कि आम चुनाव के बाद से बीएनपी के अधिकांश नेता ये माहौल बनाने में जुटे हुए हैं कि बांग्लादेश के एकतरफ़ा चुनाव को सिर्फ़ भारत की वजह से वैधता मिली है और इसलिए लोगों को भारत और उसके उत्पादों का बहिष्कार करना चाहिए। बांग्लादेश से आ रही खबरों से संकेत मिल रहे हैं कि बीएनपी की विदेश मामलों की कमेटी (एफ़आरसी) चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध प्रगाढ़ करना चाह रही है। संकेत बहुत साफ है कि बीएनपी भारत से नफरत करती है। हालांकि उसकी नफरत की वजह समझ से परे है।

> **बांग्लादेश की स्थापना के बाद लग रहा था कि वहां पर हिन्दुओं की स्थिति सुधर जाएगी। उन्हें इंसान समझा जाएगा, पर यह हो न सका। भारत की चाहत रही है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना सत्तासीन रहें। यानी वहां पर अवामी लीग के नेतृत्व वाली सरकार रहे। निश्चित रूप से बांग्लादेश में शेख हसीना का सत्ता पर काबिज होना भारत और वहां के हिन्दुओं के हित में है।**

भारत का 1947 में बंटवारा हुआ। पंजाब और बंगाल सूबों के कुछ हिस्से पाकिस्तान में चले गए। आगे चलकर पाकिस्तान का वह भाग, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, 1971 में एक स्वतंत्र देश के रूप में विश्व मानचित्र पर उभरा। नए देश का नाम बांग्लादेश के रूप में जाना गया। उसकी स्थापना में भारत का योगदान रहा। पर, वहां पर शुरू से ही घनघोर कठमुल्ले छाए रहे। उनकी जहालत की एक तस्वीर लगातार देखने को मिलती रहती है। वहां पर हिन्दुओं और प्राचीन हिन्दू मंदिरों पर हमले लगातार होते रहते हैं। कुछ साल पहले बांग्लादेश में अमेरिकी ब्लॉगर अविजित रॉय की निर्मम हत्या और उनकी पत्नी के ऊपर हुए जानलेवा हमले से वहां पर कठमुल्लों की बढ़ती ताकत का पता चलता है। वहां पर धर्मनिरपेक्ष ताकतों के लिए स्पेस जीवन के सभी क्षेत्रों में घट रहा है।

तस्लीमा नसरीन ने भी अपने उपन्यास "लज्जा" में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की दर्दनाक स्थिति पर विस्तार से लिखा है। इसलिए ही उनकी जान के दुश्मन हो गए यह कठमुल्ले। उसी विरोध के कारण तस्लीमा को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। तस्लीमा नसरीन का उपन्यास 'लज्जा' 1993 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। वह लज्जा में साम्प्रदायिक उन्माद के नृशंस रूप को सामने लाती है। लज्जा के आने के बाद कट्टरपंथियों ने उनके खिलाफ फतवा जारी किया था। जिस कारण से वह अमेरिका चली गईं थीं। अपनी जान बचाने की गरज से तस्लीमा स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका में भी रहीं। वह 2004 में कोलकाता आ गईं थीं। उन पर 2007 में हैदराबाद में भारत के कठमुल्लों ने हमला किया।

भारत का विरोध करने वालों से कोई पूछे कि क्या जब भारत ने पाकिस्तान की जालिम फौजों से पूर्वी पाकिस्तान को बचाया था तब उसका कोई निजी हित-स्वार्थ था। भारत ने तब मानवता के आधार पर पूर्वी पाकिस्तान की जनता की मदद की थी। लाखों बांग्लादेशियों को अपने यहां शरण भी दी थी। पर अगर कोई इंसान या समाज एहसान फरोमोशी पर उतर आए तो आप क्या कर सकते हैं।

बीएनपी की नेता खालिदा जिया तो घनघोर भारत विरोधी रही हैं। वह जब अपने देश की प्रधानमंत्री थीं तब वहां टाटा ग्रुप की इनवेस्टमेंट करने की योजना का कसकर विरोध हुआ था। उसे हवा बीएनपी ही दे रही थी। टाटा ग्रुप की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से की जा रही थी। टाटा ग्रुप को ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा बताने वाले भूल गए थे कि टाटा ग्रुप भारत से बाहर दर्जनों देशों में कारोबार करता है। वहां पर तो उस पर कभी कोई आरोप नहीं लगाता।

खैर, बीएनपी के भारतीय माल के बहिष्कार के अह्वान का प्रधानमंत्री शेख हसीना ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा "जब बीएनपी सत्ता में थी तब मंत्रियों की पत्नियां भारत जाया करती थीं। वे वहां साड़ियां खरीदती थीं और इधर-उधर घूमा करती थीं...वो एक सूटकेस के साथ जाती थीं और छह-सात बक्सों के साथ लौटती थीं।" शेख हसीना भी भारतीय साड़ियां पहनना पसंद करती हैं। बांग्लादेश की स्थापना के बाद लग रहा था कि वहां पर हिन्दुओं की स्थिति सुधर जाएगी। उन्हें इंसान समझा जाएगा, पर यह हो न सका। भारत की चाहत रही है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना सत्तासीन रहें। यानी वहां पर अवामी लीग के नेतृत्व वाली सरकार रहे। निश्चित रूप से बांग्लादेश में शेख हसीना का सत्ता पर काबिज होना भारत और वहां के हिन्दुओं के हित में है।

चुनाव में सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं : डीजीपी

कठुआ/जम्मू, (पंजाब केसरी): जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) आर.आर. स्वैन ने सोमवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल सभी हितधारकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं।

स्वैन ने कठुआ में महिला पुलिसकर्मियों की पासिंग आउट परेड से इतर संवाददाताओं से कहा-चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। हम सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं। मतदाताओं, रैलियों और उम्मीदवारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारे अधिकारी और बल 24 घंटे योजना और कार्यान्वयन में जुटे हुए हैं।'' उन्होंने बताया कि पुलिस केंद्र और उसकी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किए हुए हैं।

उन्होंने कहा-पुलिस नेतृत्व महिलाओं की भागीदारी के प्रति संवेदनशील है। हमारी सेनाओं में महिलाओं की उपस्थिति मात्र छह प्रतिशत है। हम इसे और बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि सोमवार को 922 महिला कांस्टेबल बल में शामिल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस बल के विस्तार पर फैसला सरकार के क्षेत्राधिकार का मामला है।

स्वैन ने कहा-हम इसके बारे में सरकार को अवगत कराएंगे। हम कानून-व्यवस्था, जांच और खुफिया संग्रह के तंत्र को और मजबूत करेंगे। जम्मू-कश्मीर में लोकसभा चुनाव पांच चरणों में होंगे, जिसके तहत 19 अप्रैल (उधमपुर), 26 अप्रैल (जम्मू), 7 मई (अनंतनाग-राजौरी), 13 मई (श्रीनगर) और 20 मई (बारामूला) को मतदान होगा। मतगणना चार जून को होगी।

इसके अलावा, डीजीपी ने कहा-हम वादा करते हैं कि प्रौद्योगिकी जैसे सीसीटीवी, 'सिक्योरिटी लाइट' और सेंसर जैसे बुनियादी ढांचे के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। स्वैन ने कहा कि सुरक्षा को ''एक हैसियत नहीं, बल्कि एक जरूरत'' के रूप में देखा जाना चाहिए। अपने आवास और सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों की सुरक्षा में कटौती की योजना के बारे में एक सवाल के जवाब में डीजीपी ने कहा-दो पहलू हैं -पहला, सुरक्षा परिस्थितियों में बदलाव और दूसरा, पेशेवर दृष्टिकोण के आधार पर सुरक्षा मुहैया करना। इससे पहले रविवार को, अधिकारियों ने कहा था कि डीजीपी स्वैन के जम्मू आवास पर सुरक्षा कर्मचारियों की संख्या में एक तिहाई तक कमी की जाएगी।

डीजीपी ने कहा-यह साफ है कि यदि जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और इलाकों को सुरक्षित करने के लिए पुलिस बल को तैनात किया जाता है तो व्यक्ति विशेष की सुरक्षा के लिए तैनाती की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

सरकार पर कच्चातिवु को लेकर रुख बदलने का आरोप लगाया

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): विपक्ष के कई नेताओं ने वर्ष 2015 में सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत दिए गए आवेदन के जवाब का हवाला देते हुए सोमवार को कच्चातिवु द्वीप के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर पलटवार किया और आरोप लगाया कि इस द्वीप के मामले में मोदी सरकार ने अपने रुख में बदलाव किया है। आरटीआई के इस जवाब में कहा गया था कि 1974 और 1976 के समझौतों में भारत से संबंधित क्षेत्र का अधिग्रहण या उसे छोड़ना शामिल नहीं था।

विपक्ष ने आरटीआई के जवाब का हवाला दिया

विपक्ष की प्रतिक्रिया विदेश मंत्री एस जयशंकर के सोमवार के उस दावे के बाद आई है कि कांग्रेस से संबंध रखने वाले प्रधानमंत्रियों ने कच्चातिवु द्वीप के बारे में उदासीनता दिखाई और इसके विपरीत कानूनी विचारों के बावजूद भारतीय मछुआरों के अधिकारों को छोड़ दिया।

जयशंकर ने यह टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देने के एक दिन बाद की, जिसमें कहा गया था कि नए तथ्यों से पता चलता है कि कांग्रेस ने ''कच्चातीवू द्वीप'' श्रीलंका को दे दिया।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ''जैसे को तैसा पुरानी बात है। ट्वीट के बदले ट्वीट नया हथियार है। क्या विदेश मंत्री जयशंकर कृपया 27-1-2015 के आरटीआई जवाब का संज्ञान लेंगे...उस उत्तर में उन परिस्थितियों को उचित ठहराया गया जिसके तहत भारत ने स्वीकार किया कि एक छोटा द्वीप श्रीलंका का है।''

चिदंबरम ने सवाल किया कि विदेश मंत्री और उनका मंत्रालय अब कलाबाज़ी क्यों खा रहे हैं?

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83

पंजाब केसरी

दिल्ली कार्यालय :

फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

ठोस आर्थिक आधार

पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य आयामों की मजबूती को देखते हुए वित्त वर्ष 2024-25 में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद बढ़ी है. नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की मासिक आर्थिक समीक्षा के अनुसार, फरवरी में परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स बढ़कर 56.9 हो गया, जो मैनुफैक्चरिंग में निरंतर वृद्धि को इंगित करता है. इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित आठ मुख्य क्षेत्रों में फरवरी में वृद्धि 6.7 प्रतिशत रही, जो तीन माह में सर्वाधिक है. ऐसा लगता है कि बीते वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर आठ प्रतिशत के आसपास रहेगी. विभिन्न वित्तीय एवं रेटिंग एजेंसियों के साथ-साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी ऐसी आशा जतायी है. अर्थव्यवस्था के आकार दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में उल्लेखनीय बढ़ोतरी. फरवरी में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का संग्रहण 1.7 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया, जो फरवरी 2023 की तुलना में 12.5 प्रतिशत अधिक है. जीएसटी ई-वे बिल का संग्रहण भी 18.9 प्रतिशत बढ़ा है. इसी प्रकार आयकर और कॉर्पोरेट कर संग्रहण में भी उत्साहजनक बढ़ोतरी दर्ज की गयी है. ये आंकड़े इंगित करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था न केवल महामारी के साये से बाहर निकल चुकी है, बल्कि भू-राजनीतिक संकटों तथा वैश्विक संघर्षों का भी असर भी न के बराबर रहा है. अन्य अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में ऐसा नहीं कहा जा सकता है. कर संग्रहण बढ़ने का सीधा अर्थ है कि औद्योगिक एवं आर्थिक गतिविधियों में लगातार तेजी आ रही है. इस स्थिति में भविष्य को लेकर लोगों में आशा का बढ़ना स्वाभाविक है. इसका संकेत हमें व्यक्तिगत ऋण, सेवा क्षेत्र, कृषि आदि क्षेत्रों के विकास से मिलता है. रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि बैंकों के ऋण में वृद्धि की दर 20.5 प्रतिशत बनी हुई है. विभिन्न कारणों से मुद्रास्फीति एक बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है, पर कुछ महीने से इस मोर्चे पर राहत की स्थिति है. इसी कारण से ऐसी उम्मीद जतायी जा रही है कि आगामी महीनों में ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है. चालू घाटा खाता संतोषजनक है तथा बाहर कार्यरत भारतीयों ने अपनी कमाई के रूप में 31.4 अरब डॉलर की राशि भेजी है. सेवा क्षेत्र के निर्यात में मुनाफा बना हुआ है. बाहरी निवेशक भी भारत पर भरोसा जता रहे हैं. इन कारकों के चलते हमारा विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 650 अरब डॉलर के स्तर पर है. यदि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हो जाए तथा आर्थिक लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, तो अर्थव्यवस्था को और गति मिल सकती है.

भारतीय अर्थव्यवस्था न केवल महामारी के साये से बाहर निकल चुकी है, बल्कि भू-राजनीतिक संकटों तथा वैश्विक संघर्षों का भी असर न के बराबर रहा है.

चिंताजनक है भोजन की बरबादी

देविंदर शर्मा
कृषि विशेषज्ञ
hunger55@gmail.com

भोजन की बरबादी को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है. रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया में प्रतिदिन लगभग एक अरब थालियां बरबाद होती हैं, यानी हर व्यक्ति एक वर्ष में औसतन 79 किलो खाना बर्बाद करता है. जो चिंता का विषय है. यह भी माना जाता है कि दुनिया में कुल पैदावार का लगभग 30 प्रतिशत बरबाद हो जाता है. अकेले अमेरिका में जितना भोजन बरबाद होता है, वह उप-सहारा अफ्रीका की भोजन की जरूरतों को पूरा कर सकता है. वहीं इटली में होने वाली बरबादी से इथियोपिया में भोजन की कमी पूरी हो सकती है. खाने की यह बरबादी कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में एक-तिहाई का योगदान देती है. रिपोर्ट में भोजन की बरबादी के कारण उत्सर्जित होने वाली ग्रीन हाउस गैसों का जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और पोषण पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी चर्चा है. यह अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा के साथ पर्यावरण बचाने की बात भी हो रही है.

उपरोक्त चर्चा के साथ हमें दुनिया में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता के बारे में भी जानने की आवश्यकता है. अभी दुनिया में करीब 7.8 अरब लोग हैं, जिनके 2050 तक नौ अरब तक पहुंचने का अनुमान है और दुनिया में जो पैदावार हो रही है, वह 14 अरब लोगों के लिए पर्याप्त है. इसका अर्थ हुआ कि आज हम अपनी जरूरत से दोगुना उत्पादन कर रहे हैं. यह अलग बात है कि समाज के एक हिस्से को इसकी अधिक मात्रा उपलब्ध है, जबकि दूसरा इसकी कमी से जूझ रहा है. जहां 30 प्रतिशत बच्चे मोटापे से ग्रस्त हैं, वहीं दुनिया की 12 प्रतिशत जनसंख्या के पास पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं है. इसे समझने के बाद हमें इस समस्या के समाधान के लिए दो तरह से प्रयास करने होंगे. पहली, दुनिया के बिगड़ते पर्यावरण को देखते हुए हम पैदावार उपजाने पर कम जोर दें और दूसरी, भोजन की बरबादी रोकने का प्रयास करें. इससे हम दुनिया की जरूरत को तत्काल पूरा कर सकते हैं. इस प्रकार भोजन की बरबादी भी कम होगी और हमें जरूरत से अधिक पैदावार भी नहीं उपजाना पड़ेगा. यहां हरित क्रांति की तरह ही एक और क्रांति की जरूरत है. जिस तरह हम हरित क्रांति लाये, उसी तरह भोजन की बरबादी रोकने के लिए क्रांति लाने की जरूरत है. यदि यह क्रांति होती है तो धरती, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जैव-विविधता, वन भूमि, सभी को पहुंचने वाला नुकसान कम हो सकता है. इस कार्य में सभी देशों को सहभागिता करनी होगी, विशेषकर विकासशील देशों को, क्योंकि यहां अधिक क्षति पहुंच रही है.

जिस तरह हम हरित क्रांति लाये, उसी तरह भोजन की बरबादी रोकने के लिए क्रांति लाने की जरूरत है. यदि यह क्रांति होती है तो धरती, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जैव-विविधता, वन भूमि, सभी को पहुंचने वाला नुकसान कम हो सकता है. इस कार्य में सभी देशों को सहभागिता करनी होगी, विशेषकर विकासशील देशों को, क्योंकि यहां अधिक क्षति पहुंच रही है.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भोजन की जो बरबादी होती है, उसमें 60 प्रतिशत घरेलू स्तर पर, 13 प्रतिशत आपूर्ति-शृंखला में होती है. सबसे कम बरबादी रिटेल, यानी दुकानों में होती है. ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन की सबसे कम बर्बादी की बात भी रिपोर्ट में है. इसका कारण हमारा धर्म है, जो हमें बताता है कि हम अपने साथ-साथ पशु-पक्षियों के भी भोजन का ध्यान रखें. वास्तव में जब हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं, तो इसमें मनुष्य के साथ पशु-पक्षी भी शामिल होते हैं. गांवों में लोग मनुष्यों के साथ गाय, कुत्ते, पक्षी आदि की खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं. इतना ही नहीं, यहां खाद्य पदार्थों के न खाये जाने वाले भाग समेत बचा हुआ भोजन भी बर्बाद नहीं होता, बल्कि उनका कंपोस्ट बना दिया जाता है. ऐसे में हमें भोजन की बरबादी रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्र से सीखने की आवश्यकता है. शहरों की मानसिकता में पशु-पक्षियों को खिलाने की बात है ही नहीं. वास्तव में, गांवों में मनुष्य और पशु-पक्षियों के बीच का संबंध घनिष्ठ होता है. यह भी कहा जाता है कि खाने की बरबादी गरीब लोग करते हैं, जो सच नहीं है. बरबादी वो करते हैं, जो शहरों में रहते हैं, जो पढ़े-लिखे हैं. गरीब, ग्रामीण तो अपना बचा रहा है. रिपोर्ट में जी-20 के देश (ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, अमेरिका) और यूरोपीय संघ द्वारा भोजन की बरबादी को घरेलू स्तर पर रोकने में सफलता प्राप्त करने की भी चर्चा है. कनाडा और सऊदी अरब ने भी इस मामले में अच्छी सफलता प्राप्त की है. बाकी के देशों को अभी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है.

इन बातों के अलावा यहां कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा जरूरी है. पहली बात, हमारे यहां कहा जाता है कि देश का 40 प्रतिशत भोजन बरबाद हो जाता है. तीस वर्ष पूर्व भी यही बात कही जाती थी और आज भी यही बात कही जा रही है. पर किसी को नहीं पता कि इस आकलन का आधार क्या है. लुधियाना स्थित आइसीएआर के संस्थान सीफेट (सीआइपीएचइटी) द्वारा भारत में भोजन की बर्बादी पर किये गये एक अध्ययन में सामने आया है कि खाद्यान्न के भंडारण में सबसे कम नुकसान धान और गेहूं का होता है. सबसे अधिक बरबादी फल और सब्जियों की होती है. इसमें भी कुछ फल, जैसे अमरूद का सबसे अधिक नुकसान होता है, क्योंकि उसे पक्षी बहुत खाते हैं. इसी तरह टमाटर भी बहुत बरबाद होता है. इससे पता चलता है कि हमारे देश में 40 प्रतिशत का जो आंकड़ा है, वह गलत है. दूसरी बात, शहरों में बरबादी को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने की ओर भी ध्यान देना होगा. इसमें मीडिया की भूमिका और सेलिब्रिटीज- विशेषकर फिल्म स्टार, क्रिकेटर- की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. उन्हें समाज को जागरूक करना चाहिए कि भोजन को बरबाद होने से कैसे बचाया जाए. रही बात सरकार की, तो वह अपनी नीतियों में फूड वेस्टेज रोकने की बातें तो करती है, परंतु उसे दूसरी वेस्टेज की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है. खाद्य पदार्थों की बर्बादी दो तरीके से होती है. एक जो भोजन खाने के बाद बर्बाद हुआ. दूसरी बरबादी आपूर्ति-शृंखला में होती है, उसे रोकने के लिए भी कदम उठाने की जरूरत है.

तीसरी बात, प्रोसेसिंग के समय खाद्य पदार्थों के बर्बाद होने से तो अपशिष्ट उत्पन्न होते ही हैं, जिस पैकेट में ये पदार्थ बिक्री के लिए रखे गये होते हैं, वे भी अपशिष्ट ही बनते हैं. जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता है. इन्हें कैसे रोका जाए, इसे लेकर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. कुल मिलाकर देखा जाए, तो संयुक्त राष्ट्र ने एकदम समय पर यह चेतावनी दी है. मुझे लगता है कि हमें अपनी नीतियों में परिवर्तन करना चाहिए, विशेषकर पोषण सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन को लेकर. अंत में, हमें पैदावार बढ़ाने पर जोर देने की जरूरत नहीं है. आज हम जितनी फसल उपजा रहे हैं, अगर उसी को सहेज लें, तो दूसरी हरित क्रांति की जरूरत ही नहीं पड़ेगी.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

सियासत के मंच पर फिल्मी सितारे

उमेश चतुर्वेदी
वरिष्ठ पत्रकार
uchaturvedi@gmail.com

भाजपा ने कंगना राणावत को हिमाचल प्रदेश में मंडी से चुनावी मैदान में क्या उतारा, राजनीति में फिल्मी सितारों की मौजूदगी को लेकर चर्चा तेज हो गयी. वैसे कंगना कोई पहली स्टार नहीं हैं, जिन्हें किसी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है. लोकतांत्रिक समाज में चुनावी मैदान को पूर्णकालिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए ही सीमित करना संभव नहीं है. परंतु यह सवाल जरूर उठता रहा है कि चुनाव में सिनेमाई सितारों का उतरना कितना जायज है. इसकी वजह है, राजनीति में उनकी कम सक्रियता. चुनाव जीतने वाला व्यक्ति अपने क्षेत्र की जनता का संसद में प्रतिनिधि होता है. इस नाते उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने क्षेत्र के विकास और भलाई के लिए काम करे, विभिन्न मंचों पर उनकी आवाज बने. राजनीति में सितारों के छाने की प्रक्रिया का विश्लेषण करें, तो दो तरह की प्रवृत्तियां सामने आती हैं.

दक्षिण भारत में फिल्मी दुनिया के सितारे अपने राजनीतिक आसमान के लिए महज चमकते हुए सितारे ही साबित नहीं हुए, बल्कि जमीनी स्तर पर भी उन्होंने खूब प्रभावित किया. तमिलनाडु के दोनों प्रमुख दलों की मुखिया रही शख्सियतें इसका उदाहरण हैं. द्रमुक के प्रमुख रहे एम करुणानिधि तमिल फिल्मों के पटकथाकार रहे थे, लेकिन राजनीति में जब वे आये, तो राजनीति के ही होकर रह गये. देखते ही देखते वे राजनीति का ऐसा चेहरा बन गये, जिनके बिना तमिलनाडु की राजनीति की कल्पना भी नहीं की जा सकती. ऐसी ही स्थिति अन्ना द्रमुक के प्रमुख रहे एमजी रामचंद्रन और जे जयललिता की भी रही. एमजी रामचंद्रन तमिल फिल्मों के सुपर स्टार थे, कुछ ऐसा ही जयललिता के साथ था. लेकिन राजनीति में आने के बाद यह जोड़ी भी राजनीति की ही होकर रह गयी. आंध्र प्रदेश की राजनीति में ऐसा ही नाम नंदमूरि तारक रामाराव का रहा. अस्सी के दशक में उन्होंने तेलुगू बिड्डा नाम से कांग्रेस विरोधी अभियान शुरू किया और आंध्र के सियासी आसमान पर छा गये. वर्ष 1989 की केंद्रीय राजनीति में भी उनकी बड़ी भूमिका रही. उत्तर भारतीय राजनीति में सिनेमाई हस्तियों के साथ हालात अलग रहे. मुंबइया सिनेमा के हीरो की सिनेमाई पर्दे पर 'लार्जर दैन लाइफ' छवि रही, लेकिन राजनीति की पथरीली जमीन पर यह छवि पस्त पड़ती रही. इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए 1984 के आम चुनाव में कांग्रेस ने हिंदी सिनेमा की तीन बड़ी शख्सियतों- अमिताभ बच्चन, सुनील दत्त और वैजयंतीमाला बाली- को उम्मीदवार बनाया था, तीनों को जीत भी मिली. लेकिन सिर्फ सुनील दत्त ही मैदान में बने रहे. उनकी राजनीतिक यात्रा 25 मई 2005 को उनके निधन तक जारी रही. पर बोफोर्स मामले में नाम आने के बाद अमिताभ ने राजनीति से तौबा कर ली. वैजयंतीमाला भी बाद में राजनीति से अलग हो गयीं. बाद में हिंदी सिनेमा के दो और नाम आये- कांग्रेस से राजेश खन्ना और भाजपा से शत्रुघ्न सिन्हा. शत्रुघ्न राजनीति में रम पाये, जो अब तृणमूल कांग्रेस के साथ हैं.

सुनील दत्त और शत्रुघ्न सिन्हा की परंपरा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी रखा जा सकता है. अब राजनीति ही उनका ओढ़ना-बिछौना है. केंद्रीय मंत्रालयों का जिम्मा संभालने की बात हो या भाजपा का पक्ष रखना हो, दोनों ही भूमिकाओं में वे दूसरे सितारों से कहीं ज्यादा गंभीर हैं. राजनीति में जयाप्रदा और जया बच्चन ने भी समाजवादी पार्टी के जरिये कदम रखा. जयाप्रदा लोकसभा में रहीं, तो जया बच्चन लगातार राज्यसभा में हैं. अरसे से भाजपा में हेमा मालिनी सक्रिय हैं. वे दो बार से मथुरा से सांसद हैं. वे राज्यसभा में भी रह चुकी हैं. उनके पति धर्मेंद्र राजस्थान के बीकानेर से सांसद रहे, तो धर्मेंद्र के बेटे सन्नी देओल पंजाब के गुरदासपुर से, लेकिन दोनों को राजनीति रास नहीं आयी. रामायण सीरियल की लोकप्रियता के दौर में भाजपा ने 1991 में दीपिका चिखलिया और अरविंद त्रिवेदी को गुजरात से मैदान में उतारा. बाद में दोनों ही राजनीति से दूर हो गये. इस बार पार्टी ने राम की भूमिका निभाकर लोकप्रिय हुए अरुण गोविल को मेरठ से उम्मीदवार बनाया है.

विनोद खन्ना पंजाब से सांसद रहे और वाजपेयी सरकार में उन्हें राज्य मंत्री भी बनाया गया था. भाजपा से मनोज तिवारी, दिनेश यादव निरहुआ और रवि किशन जैसे भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता सांसद हैं. अभिनेत्री किरण खेर चंडीगढ़ से सांसद हैं. पश्चिम बंगाल से पार्टी रूपा गांगुली को राज्यसभा भेज चुकी है, तो लोकसभा में बांग्ला की अभिनेत्री लॉकेट चटर्जी पार्टी की सांसद हैं. तृणमूल कांग्रेस ने पिछली बार अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां को संसद भेजा था. पहले यहीं से भाजपा ने फिल्मी गायक बाबुल सुप्रियो को संसद भेजा, बाद में वे तृणमूल में शामिल हो गये और अभी राज्य में मंत्री हैं. सियासत की दुनिया में सिनेमाई सितारों की फेहरिस्त लंबी है. पर दक्षिण को छोड़ दें, तो ज्यादातर सितारों का चयन इसलिए नहीं हुआ कि वे राजनीतिक भूमिका निभा पायेंगे, बल्कि उन्हें जिताऊ चेहरे के तौर पर मौका मिला. उनमें से कुछ ही जमीनी स्तर पर राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर पाये. ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर लोकतंत्र की दुनिया में चमक ज्यादा अहमियत रखती है या लोक के प्रति जवाबदेही. **(ये लेखक के निजी विचार हैं.)**

सियासत की दुनिया में सिनेमाई सितारों की फेहरिस्त लंबी है. पार्टी चाहे जो हो, पर दक्षिण को छोड़ दें, तो ज्यादातर सितारों का चयन इसलिए नहीं हुआ कि वे राजनीतिक भूमिका निभा पायेंगे, बल्कि उन्हें जिताऊ चेहरे के तौर पर मौका मिला. उनमें से कुछ ही जमीनी स्तर पर राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर पाये.

देश दुनिया

अफ्रीका की मदद को लेकर रूस पर उठते सवाल

विनाशकारी सूखे से निपटने के लिए मानवीय मदद के तौर पर रूस की ओर से जिंबाब्वे को 25,000 मीट्रिक टन गेहूं और 23,000 टन उर्वरक भेजा गया है. अल नीनो के कारण 2023-24 के दौरान अधिकांश फसलें खत्म हो गयीं, जिसके चलते 30 लाख से ज्यादा लोगों पर भुखमरी का खतरा मंडराने लगा है. संयुक्त राष्ट्र का विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) पर्याप्त खाद्य मदद के लिए जूझ रहा है. डब्ल्यूएफपी जिंबाब्वे से जुड़ी शेरिता मानयिका बताती हैं कि फंडिंग की चुनौती है और बनी रहेगी. डब्ल्यूएफपी पूरी तरह स्वैच्छिक दान से फंड हासिल करता है. वर्ष 2023 की रूस-अफ्रीका शिखर बैठक के दौरान अफ्रीकी देशों को दो लाख टन अनाज देने का अपना संकल्प पूरा करते हुए रूस ने ताजा मदद भेजी, जो जिंबाब्वे के लिए डूबते को तिनके का सहारा जैसी थी. जिंबाब्वे उन छह अफ्रीकी देशों में है, जिन्हें रूस से अनाज मिला है. इसके अतिरिक्त बुर्किना फासो, माली, इरिट्रिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और सोमालिया हैं. अनाज की मदद जिंबाब्वे के लिए एक राहत है, पर कुछ जानकार इसे अफ्रीका में रूसी इरादों से जोड़कर देखने लगे हैं. लंदन स्थित चैटम हाउस में अफ्रीका प्रोग्राम के निदेशक एलेक्स वाइंस का कहना है कि रूसी दान मानवीय आधार पर उतना नहीं, जितना राजनीतिक रणनीति से प्रेरित हो सकता है. वाइंस की मानें, तो यह अफ्रीका में रूस की कसती कूटनीति नहीं है. यह रूस के बेहतरीन मित्रों को पुरस्कृत करना है, या उन देशों को, जिनके साथ रूस अपनी सक्रियता बढ़ाना चाहता है. ऐसे कई अफ्रीकी देश जिन्हें मदद की शायद ज्यादा जरूरत है, इस अनाज के करार में शामिल नहीं किये गये थे, ऐसे में यह मानवीय मदद की अपेक्षा एक राजनीतिक कदम है. रूसी मदद की खेप जारी है. इसके साथ ही, अफ्रीका के साथ रूस के जुड़ाव के दूरगामी निहितार्थों के बारे में भी सवाल उठने लगे हैं. **-प्रिविलेज मुसवानहिरि**

Deutsche Welle

बोधि वृक्ष

चित्त का समर्पण

'जो हुआ, अच्छा हुआ, जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, जो होगा, अच्छा ही होगा. तुम भूत का पश्चाताप न करो. भविष्य की चिंता न करो. वर्तमान चल रहा है.' श्रीमद्भगवद्गीता के इस सार रूपी सीख से विश्व के अधिकांश लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं. किंतु हममें से कितने लोग इस बात को जानते होंगे की श्रीमद्भगवद्गीता का सार केवल एक शब्द में ही समझा जा सकता है. जी हां! 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में बोला गया वह शब्द है 'मनमनाभव', अर्थात 'अपने चित्त को पूरी तरह मुझे समर्पित कर दो, केवल मेरे लिए कर्म करो और श्रद्धापूर्वक अपने सभी कार्य मुझे अर्पण करो, तो तुम मुझे ही प्राप्त होगे.' यह श्लोक परमात्मा के दृढ़ आश्वासन के साथ समाप्त होता है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति अपने मन को स्थिर कर स्वयं को उस सर्वशक्तिमान को सच्चे मन से समर्पित करता है, वह निश्चित रूप से पंच महाभूतों के बने इस शरीर एवं उससे उत्पन्न होने वाले सभी बंधनों से मुक्त हो जायेगा. प्रत्येक मनुष्य के दुख का मूल कारण उसका शरीर, उसके शारीरिक संबंधियों, उसकी संपत्ति, अपने देश एवं भाषा आदि को लेकर अति मोह व बुद्धियोग है. यदि मनुष्य सभी तरफ से अपना बुद्धियोग हटाकर उस एक ज्योति बिंदु में लगाकर 'मैं' और 'मेरे' के बनाये अपने जंजाल से बाहर निकलकर स्वयं को उस एक के प्रति समर्पित कर देता है, तो वह सही अर्थों में सभी उलझनों से मुक्त हो जाता है. श्रीमद्भगवद्गीता के माध्यम से सर्वशक्तिमान परमात्मा स्नेहभाव से हम सभी वत्सों को उनके द्वारा प्रतिपादित पवित्र सिद्धांतों को, जिसे 'श्रीमत' कहते हैं, उसका पालन करने की सलाह देते हैं. यह श्रीमत अपने प्रिय वत्सों के प्रति परमेश्वर की शुभ इच्छा को दर्शाता है. अतः जो अपने मन की मत, अर्थात मनमत को छोड़ श्री की दी हुई मत, अर्थात श्रीमत को अपनाकर स्वयं को परमात्मा का दिव्य साधन समझकर हर कर्म करता है, उसके भीतर सभी आंतरिक संघर्ष समाप्त हो जाते हैं और वह अतींद्रिय सुख के झूले में आनंदित होकर झूलता रहता है.

-ब्रह्माकुमार निकुंज जी

कुछ अलग

जीवन के एग्जाम के टॉपर

मुकुल श्रीवास्तव
टिप्पणीकार
srivastava_mukul@lkouniv.ac.in

प्रिय बेटा,

तुम्हारा गुस्सा भरा ई-मेल मिला. जिसमें तुमने नाराजगी जतायी है कि जब सारे पास हुए बच्चों के पेरेंट्स उनके मार्क्स के साथ सोशल मीडिया पर उनकी फोटो डाल रहे हैं, तो मैंने तुम्हारी फोटो क्यों नहीं लगायी. तुम जानते हो, मैंने तुम्हें हमेशा नंबर गेम से बचने की सलाह दी है. मैं कहता था की सम्मानजनक तरीके से पास हो जाओ. मेरे लिए पढ़ाई के एक्जाम में पास होना उतना मायने नहीं रहता, जितना जिंदगी के इम्तिहान में पास होना. अब तुम बड़े हो गये हो, सोचा अपनी लाइफ के कुछ अनुभव शेयर कर लूं. बचपन में जब तुम चोट लगने पर रोते थे. तब मैं एक ही बात कहता था कि चोट तुम्हें लगी है, तो इसका दर्द भी तुम्हें ही झेलना होगा. हम अधिक से अधिक इसे कम करने की कोशिश कर सकते हैं. जिंदगी भी ऐसी ही है.

मुझे याद है, दसवीं से पहले तक तुम्हारे कभी भी 60 परसेंट से ऊपर नंबर नहीं आये. कभी-कभी मैं भी थोड़ा दुखी हो जाता था, पर एक चीज मुझे हमेशा हौसला देती रही कि तुम हमेशा एक अच्छे बेटे की तरह बढ़ते रहे, दादी-बाबा का ख्याल रखने वाले. भले कितनी भी परेशानी मन में हो, हमेशा खुश रहने वाले और सबको हंसाने वाले. तुम्हारी संवेदनशीलता देख कर लगता है कि तुम अपने आसपास के लोगों से जुड़े रहोगे. सड़क पर यदि कोई आवारा पशु बीमार दिखता तो तुम मुझे फोन करके तंग करते रहते. अपनी पॉकेट मनी से कुत्ते के बच्चों को दूध चुपचाप पिलाना और कई दिन बाद धीरे से मम्मी को बता देना. तुमने कभी कोई बात नहीं छुपाई. तुम खुशनसीब हो, कड़ी धूप में पतंग उड़ाने, बारिश में छत पर घंटों नहाने का क्या अर्थ होता है, यह तुम जानते हो. तोड़ देने का दुख भी झेला है. हारना क्या होता है, यह तुम बेहतर जानते हो. कभी जिंदगी में जीतोगे, तो तुम्हारे पैर हमेशा जमीन पर रहेंगे.

बेटा पढ़ाई के एग्जाम से ज्यादा कठिन है जिंदगी का इम्तिहान, जिसकी अभी शुरुआत हो रही है. मैं चाहता हूं कि तुम जिंदगी के एग्जाम में टॉप करो. मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम क्लास में टॉप करो. जरा सोचो, एग्जाम्स के टॉपर्स को हम लोग कितनी जल्दी भूलते हैं. जिंदगी के टॉपर्स हिस्ट्री बनाते हैं. तुम्हें फिल्म और क्रिकेट का बहुत शौक है. विराट एक महान खिलाड़ी हैं. क्या वह कभी जीरो पर नहीं आउट हुए? अमिताभ बच्चन क्या बगैर फ्लॉप फिल्में दिये सदी के सितारे बन गये. सफल होने के लिए असफल होना ही पड़ता है. जिंदगी में आप लगातार सफल नहीं हो सकते. असफलता का स्वाद जिंदगी में जितनी जल्दी मिल जाए, उतना अच्छा. मां तुमको प्यार दे रही है.

प्यार
तुम्हारा पॉप्स

आपके पत्र

प्रकृति की मार झेल रहे किसान

पिछले दो-तीन वर्षों से किसान दोहरी मार झेल रहे हैं. मॉनसून के कमजोर पड़ने से कई जिलों में सूखा पड़ गया था. इधर, अचानक मौसम में आये बदलाव के कारण हुई बारिश से किसानों की तैयार फसल खराब हो गयी. मार्च महीने में हुई बारिश से तेलहन व दलहन की खड़ी फसल चौपट हो गयी. कई किसानों की पूंजी भी डूब गयी. उन्हें आगे खेती करने की चिंता सता रही है. बेमौसम बारिश प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा है. यदि समय रहते नहीं चेते, तो आगे और भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.

राजकुमार चौधरी, मुजफ्फरपुर

रोजगार के अवसर हुए कम

देश में 100 लोगों में 83 युवा बेरोजगार हैं. यह आंकड़ा बताता है कि रोजगार के अवसर कम हुए हैं. भारत में बेरोजगारी चरम पर है. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन की रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में कुल बेरोजगारों में से 83% युवा हैं. आइएलओ ने इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ मिलकर 'इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024' पब्लिश की है. इसके हिसाब से अगर भारत में 100 लोग बेरोजगार हैं, तो उसमें से 83 लोग युवा हैं. इसमें भी अधिकतर युवा शिक्षित हैं. पढ़े-लिखे बेरोजगारों की संख्या 2000 के मुकाबले दोगुनी हो गयी है.

प्रसिद्ध यादव, बाबूचक (पटना)

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 39

रिजर्व बैंक के लिए आगे की राह

सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 90वें वर्ष में प्रवेश करने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उचित ही कहा कि बैंक ने देश को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाई है। दीर्घावधि की आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए वित्तीय स्थिरता एक अनिवार्य शर्त है। इस समय रिजर्व बैंक इस महत्त्वपूर्ण पड़ाव का जश्न मना रहा है और यह उचित अवसर है कि संस्थान न केवल अपनी अतीत की उपलब्धियों को सामने रखे बल्कि भविष्य के लिए अपनी योजनाएं भी प्रस्तुत करे। यह इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि वृहद आर्थिक स्थिति और नियामकीय चुनौतियों में निरंतर बदलाव आ रहा है। साफ कहें तो केंद्रीय बैंक बीते दशकों में अपने दायित्वों और कार्यों के साथ निरंतर विकसित हुआ है। समय-समय पर मतभेद के बावजूद सरकार ने इस सफर में रिजर्व बैंक को विधिक और सांस्थानिक सहायता मुहैया कराई है। इन बातों का यह आशय कतई नहीं है कि भारत की व्यवस्थाएं पूरी तरह खामी रहित हैं लेकिन बीते वर्षों में जो विकास हुआ है वह भी सकारात्मक दिशा में है।

हाल के वर्षों के सबसे अहम घटनाक्रम में एक रहा है आरबीआई अधिनियम में संशोधन करना ताकि उसे मुद्रास्फीति को लक्षित करने वाले केंद्रीय बैंक में बदला जा सके। विभिन्न धड़ों के विरोध के बावजूद सरकार मौद्रिक नीति ढांचे को मजबूत बनाने के विचार पर सहमत है। इस बात ने मौद्रिक नीति के संचालन को अधिक पारदर्शी बनाया है और निवेशकों के आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद की है। हाल के समय में कुछ भ्रम की स्थिति बनने पर रिजर्व बैंक ने यह दोहरा कर सही किया कि वह मुद्रास्फीति को लक्षित करने के विधिक अधिदेश का पालन करेगा। इसके अलावा वृहद आर्थिक स्थिरता में सुधार की एक वजह रिजर्व बैंक द्वारा बाह्य क्षेत्र का कुशल प्रबंधन भी है। उसने अवसरों का लाभ लेकर बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार खड़ा किया जिसने मौद्रिक अस्थिरता को समाप्त किया।

रिजर्व बैंक ने वृहद आर्थिक प्रबंधन को लेकर हाल के वर्षों में अच्छा प्रदर्शन किया है। बहरहाल, बैंकिंग नियमन और निगरानी में सुधार की गुंजाइश है। यह अच्छी बात है कि बैंकिंग क्षेत्र में फंसे हुए कर्ज में कमी आई है तथा इस समय यह क्षेत्र तकरीबन एक दशक में सबसे बेहतर स्थिति में है। परंतु यह तथ्य बरकरार है कि बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय संकट के पहले और बाद में रिजर्व बैंक की निगरानी में अतियों की स्थिति बनी। हालांकि यह सही है कि रिजर्व बैंक के पास सरकारी बैंकों के नियमन के मामले में सीमित शक्ति है। इसे जरूरी कानूनी बदलावों की मदद से हल करने की आवश्यकता है। हाल ही में येस बैंक और इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनैंशियल ओवरसाइट सर्विसेज लिमिटेड जैसे दो उदाहरण बताते हैं कि हमें अपनी निगरानी व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है। विनियमित संस्थाओं से निपटने के मामले में पारदर्शिता को लेकर भी चिंताएं हैं। उदाहरण के लिए नियामक पेटीएम पेमेंट्स बैंक के मामले में आगे बढ़कर सूचनाएं दे सकते थे। बल्कि ऐसी संस्थाओं से निपटना आने वाले वर्षों में एक बड़ी चुनौती बनेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने तकनीक को अपनाने की सुविधा देने के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। भारत पेमेंट सॉल्युशंस के मामले में दुनिया में अग्रणी देश है लेकिन उसे नए दौर की फिनटेक कंपनियों द्वारा तकनीक का इस्तेमाल करने से उत्पन्न होने वाले अनचाहे परिणामों से निपटने के लिए भी तैयार रहना होगा। कुछ इस तरह जिससे नवाचार प्रभावित न हो। रिजर्व बैंक ने केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी की दिशा में भी पहल की है, हालांकि यह देखना होगा कि इसे किस हद तक अपनाया जाता है। रिजर्व बैंक औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र केंद्रीय बैंक नहीं है। सरकार को उसे स्वायत्त रूप से काम करने देना चाहिए और उसकी सांस्थानिक स्थिति का सम्मान करना चाहिए। उसके कामकाज को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार को जरूरी कानूनी बदलावों पर विचार करना चाहिए ताकि बैंकिंग नियमन में उसे मजबूती दी जा सके। सरकार के लिए यह भी आवश्यक है कि वह राजकोषीय घाटे में कमी लाए ताकि मौद्रिक नीति के संभावित राजकोषीय दबदबे के जोखिम को कम किया जा सके।

भारत-ब्रिटेन व्यापार सौदे के संभावित परिणाम

भारत के सामने भविष्य में कुछ जटिल वार्ताएं हैं जो घरेलू नीतिगत गुंजाइश और आर्थिक हितों को सीमित कर सकती हैं। ब्रिटेन के साथ एफटीए को ध्यान में रखते हुए इस विषय में बता रहे हैं अजय श्रीवास्तव

गत 12 मार्च को टेलीफोन पर बातचीत में भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस बात पर सहमत हुए कि वे साझा लाभ वाले मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को जल्दी अंजाम तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। हम आशा कर सकते हैं कि चुनाव के बाद देश में नई सरकार बनते ही भारत-ब्रिटेन एफटीए पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद ब्रिटेन के लिए एफटीए नई व्यापार साझेदारियां स्थापित करने की रणनीति का हिस्सा है। इस बीच भारत भी तेजी से नए एफटीए को अंजाम दे रहा है मानो वह अपनी संरक्षणवादी छवि में बदलाव कर रहा हो। यह बदलाव तब आया जब नवंबर 2019 में भारत अचानक 16 देशों वाली क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) वार्ता से बाहर हो गया।

बीते चार वर्षों में भारत ने मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (एफ्टा) के देशों मसलन स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिक्टनस्टाइन के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्रिटेन के साथ एफटीए आरसेप से बाहर आने के बाद भारत का पांचवां एफटीए होगा। भारत के एफटीए साझेदारों ने तेज वार्ता की रणनीति पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है क्योंकि भारत के साथ एफटीए उन्हें एक बड़े उभरते बाजार तक पहुंच प्रदान करता है वह भी उच्च टैरिफ से बचकर।

माना जा रहा है कि एफटीए से द्विपक्षीय व्यापार बढ़ेगा। वित्त वर्ष 2023 में भारत और ब्रिटेन का आपसी व्यापार 57 अरब डॉलर से अधिक हो गया। भारत ने जितना खर्च किया उससे 13.34 अरब डॉलर अधिक की राशि अर्जित की। भारत ने 11.40 अरब डॉलर की वस्तुओं और 23.80 अरब डॉलर की सेवाओं का निर्यात ब्रिटेन को किया और उससे 8.96 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुओं और 12.90 अरब डॉलर मूल्य की सेवाओं की खरीद की।

दोनों देशों ने जनवरी 2022 में एफटीए को लेकर बातचीत शुरू की। इस वार्ता में 26 विषय शामिल हैं जिसमें वस्तु एवं सेवा व्यापार, बौद्धिक संपदा, सरकारी खरीद, स्रोत के नियम, व्यापार और टिकाऊ विकास, श्रम, लिंग और डिजिटल व्यापार आदि हैं। बातचीत के प्रमुख विषयों में से कुछ के अनुमानित परिणाम इस प्रकार हैं:

वाणिज्यिक उत्पाद व्यापार: भारत ब्रिटेन को जो निर्यात करता है उसका आधा से अधिक हिस्सा यानी करीब 6 अरब डॉलर मूल्य का निर्यात पेट्रोलियम, औषधि, हीरे, मशीनों के कलपुर्जे, विमान और लकड़ी के फर्नीचर आदि पहले ही बिना आयात शुल्क के ब्रिटेन जाते हैं। ऐसे में इन निर्यातों को शुल्क दरों में संभावित कमी का कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा। बहरहाल करीब 5 अरब मूल्य का अन्य निर्यात जिमसें वस्त्र, कपड़ा, जूते-चप्पल, कालीन, कारें, समुद्री भोजन, अंगूर और आम शामिल हैं, उन्हें लाभ होगा क्योंकि अभी उन पर शुल्क चुकाना होता है।

इस व्यापार में ब्रिटेन को अधिक लाभ होगा क्योंकि भारत आने वाले उसके 91 फीसदी उत्पादों पर औसत से उच्च आयात शुल्क लगता है। ऐसे अधिकांश उत्पादों को भारत द्वारा शुल्क हटाए जाने का लाभ मिलेगा। भारत ब्रिटेन से आने वाली कारों पर आयात शुल्क को 100 फीसदी से कम करके 50 फीसदी कर सकता है तथा कुछ कारों को वह 25 फीसदी की न्यूनतम शुल्क दर पर भी आने दे सकता है।

इलेक्ट्रिक वाहनों पर भारत पहले ही शुल्क दर कम कर चुका है और उसे 100 फीसदी से कम करके 15 फीसदी तक कर दिया गया है। इससे संकेत मिलता है कि भारत ब्रिटेन को बेहतर पेशकश कर सकता है। इसी प्रकार वाइन के मामले में भारत आयात शुल्क को अगले 10 वर्ष में 150 फीसदी से कम करके 25 फीसदी कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया और स्विस वाइन के मामले में ऐसा हो चुका है। यानी कुछ सालों में 90 फीसदी द्विपक्षीय व्यापार शुल्क मुक्त हो जाएगा और व्यापार बढ़ेगा।

सेवा: भारत अपनी सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए अधिक बाजार पहुंच चाहता है। उसने ब्रिटेन से अनुरोध किया है कि वह भारतीय पेशेवरों को अल्पकालिक कामों के लिए प्राथमिकता पर वीजा प्रदान करे। बहरहाल, बड़ी तादाद में अल्पकालिक कामकाजी वीजा पाना मुश्किल हो सकता है क्योंकि ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन में प्रवासियों को लेकर चिंता बढ़ी है। ब्रिटेन दूरसंचार, विधिक और वित्तीय सेवा क्षेत्र को विदेशी प्रतिस्पर्धा के लिए खोलने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दे सकते हैं।

ब्रिटेन के उत्पादकों को भारत सरकार के खरीद वाले क्षेत्रों को बिक्री की इजाजत देना उन्हें भारतीय कंपनियों के समकक्ष बना देगा। वहीं भारतीय कंपनियों को ब्रिटेन में सरकारी खरीद बाजार में तगड़ी प्रतिस्पर्धा और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र में भारत को सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

गैर कारोबारी मुद्दों पर होने वाली बातचीत में कई जटिल क्षेत्र शामिल हैं जो भारत के घरेलू नीतिगत क्षेत्र और आर्थिक हितों को प्रभावित कर सकते हैं। उनमें से प्रमुख हैं:

1. भारत अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्टार्टअप को बचाने के लिए डेटा को स्थानीय रूप से रखने का हिमायती है जबकि ब्रिटेन के अबाध डेटा प्रवाह चाहता है और डिजिटल कारोबार के लिए न्यूनतम बाधाएं।

2. एक विकसित देश के रूप में ब्रिटेन को एफटीए में पर्यावरण और श्रम के क्षेत्र में उच्च मानकों को शामिल करना होगा। भारत सख्त प्रावधानों को लेकर सतर्क है क्योंकि वे उस पर आर्थिक बोझ डाल सकते हैं या उसकी प्रतिस्पर्धी बढ़त पर असर डाल सकते हैं।

3. भारत इस बात से अवगत है कि एफटीए में अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं मसलन अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन समझौते, पेरिस समझौते आदि का पालन भी पुरानी गैर बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं को प्रवर्तनीय दायित्वों में बदल सकता है। इससे नीति निर्माण का लचीलापन कम हो सकता है और ब्रिटेन द्वारा भारत के कपड़ों और अन्य श्रम आधारित निर्यात पर गैर टैरिफ अवरोध लगाने को उचित ठहराया जा सकता है।

4. भारत ट्रिप्स प्लस मानकों को अपनाने को लेकर भी सतर्क है और यह बात जेनेरिक दवा उद्योग तथा दवाओं तक पहुंच को प्रभावित कर सकती है। ब्रिटेन डेटा की विशिष्टता को लेकर ऐसे प्रावधान चाहता है जो जेनरिक दवा बनाने वालों को एक खास समय के लिए मूल कंपनियों द्वारा प्रस्तुत चिकित्सकीय परीक्षण के डेटा पर भरोसा करने से रोकता है। भारत इस पर सहमत नहीं हो सकता है क्योंकि डेटा विशिष्टता जेनेरिक दवाओं की राह में देरी का सबब बन सकती है। इससे भारत और वे देश प्रभावित हो सकते हैं जो भारत की सस्ती जेनेरिक दवाओं पर निर्भर हैं।

5. एक और दिक्कत यह है कि भारत पहले ही टिकाऊपन, श्रम और बौद्धिक संपदा अधिकारों को लेकर ईएफटीए देशों के साथ एफटीए में कई प्रतिबद्धताएं जता चुका है। अब उसे और महत्त्वाकांक्षी प्रतिबद्धताओं को अपनाने का दबाव झेलना पड़ सकता है।

6. भारत और ब्रिटेन द्विपक्षीय निवेश समझौते पर भी बातचीत कर रहे हैं। ब्रिटेन बिना उसे अंतिम रूप दिए एफटीए पर हस्ताक्षर करने का अनिच्छुक है। दोनों देशों के रवैये में बहुत अंतर है लेकिन एफटीए को पूरा करने के लिए वे सहमत हो सकते हैं।

7. ब्रिटेन की कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) व्यवस्था जनवरी 2026 से लागू हो सकती है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। सीबीएएम के साथ ब्रिटेन के उत्पाद बिना शुल्क के भारत आ सकते है लेकिन ब्रिटेन जाने वाले भारतीय उत्पादों को 12-24 फीसदी तक का शुल्क देना पड़ सकता है। भारत को इसे स्पष्ट करना चाहिए।

ब्रिटेन के साथ एफटीए भारत की 15वीं व्यापक व्यापार संधि होगी और अब वक्त आ गया है कि सरकार इस बात पर प्रकाश डाले कि एफटीए ने किस तरह निर्यात, आयात, निवेश और अन्य क्षेत्रों को प्रभावित किया है। ये जानकारियां कंपनियों को उल्लेखनीय जानकारी दे सकती हैं और मौजूदा व्यापार चर्चाओं को आकार देने में मददगार साबित हो सकती हैं।

(लेखक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनीशिएटिव के संस्थापक हैं)

चुनावी बॉन्ड से चंदे पर शेयरधारक क्यों अंधेरे में?

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने पिछले दिनों चुनावी बॉन्ड पर दो दस्तावेज में जानकारियां सौंपी। चुनावी बॉन्ड खरीदना पूरी तरह कंपनियों एवं उद्यमियों की इच्छा पर निर्भर था मगर प्रश्न यह है कि कोई कंपनी या इकाई अपनी मेहनत की कमाई स्वार्थ सिद्धि करने वाले राजनीतिज्ञों को क्यों दे? कंपनियां तभी ऐसा करती हैं जब उन पर दबाव डाला जाता है या कोई विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है। चुनावी बॉन्ड के जरिये आया स्वैच्छिक चंदा अधिक नहीं माना जा सकता। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है कि बड़ी कंपनियों के नाम चंदा देने वाली इकाइयों की सूची से नदारद थे। इन दिनों भारत के उद्योग जगत की ज्यादातर बड़ी कंपनियां शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं। मगर कुछ क्षेत्रों की लगभग 100 कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड के जरिये राजनीतिक दलों को चंदा दिया। चंदा देने वाली कंपनियों की सूची में कुछ ही बड़ी कंपनियां (निफ्टी 200 शेयर) शामिल थीं।

दानकर्ता कंपनियों की सूची में वेदांत (400 करोड़ रुपये से अधिक), भारती एयरटेल (198 करोड़ रुपये), टॉरंट पावर (106 करोड़ रुपये) और यूनाइटेड फॉस्फोरस (60 करोड़ रुपये) शामिल हैं। मगर इसमें शामिल ज्यादातर कंपनियों ने अपने मुनाफे की तुलना में काफी कम रकम चंदे के तौर पर दी है। उदाहरण के लिए सन फार्मास्युटिकल्स ने पिछले साल 8,900 करोड़ रुपये शुद्ध मुनाफा अर्जित किया था मगर उसने मात्र 31.50 करोड़ रुपये (महज 0.3 प्रतिशत) राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के जरिये दिए। महिंद्रा ऐंड महिंद्रा ने लगभग इतनी ही रकम (25 करोड़ रुपये) चंदे के रूप में दी। अन्य कंपनियों में बजाज फाइनैंस (20 करोड़ रुपये), बजाज ऑटो (18 करोड़ रुपये), हीरो मोटर्स (20 करोड़ रुपये), टीवीएस मोटर्स (26 करोड़ रुपये), अल्ट्राटेक (35 करोड़ रुपये), मारुति सुजूकी (20 करोड़ रुपये) और पीरामल एंटरप्राइजेज (48 करोड़ रुपये) के नाम सूची में दर्शाए गए हैं। इससे अधिक दिलचस्प बात यह है कि सूचीबद्ध बड़ी कंपनियों में एक बड़ी संख्या उनकी है जिन्होंने चुनावी बॉन्ड के जरिये चंदा नहीं दिया। इनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाइटन और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस (टीसीएस), इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो जैसी कंपनियां शामिल हैं। इस सूची में किसी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम नहीं है और न ही निर्माण क्षेत्र की दिग्गज कंपनी लार्सन ऐंड टुब्रो दिखाई देती है। यह अलग बात है कि निर्माण क्षेत्र की कुछ कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड के जरिये चंदा दिया है।

एक और प्रश्न यह है कि जिन कंपनियों ने चंदा दिया है उन्होंने शेयरधारकों को इसकी स्पष्ट जानकारी दी है या नहीं? मौजूदा समय में बाजार नियामक और स्टॉक एक्सचेंज अधिक से अधिक पारदर्शिता पर जोर दे रहे हैं जिसे देखते हुए चंदा देने वाली कंपनियों को स्पष्टीकरण के साथ इससे जुड़ी जानकारी अनिवार्य रूप से अपने शेयरधारकों को देनी चाहिए। महिंद्रा ऐंड महिंद्रा, सिप्ला, भारती एयरटेल, पीरामल एंटरप्राइजेज जैसी बड़ी कंपनियों की वित्त वर्ष 2022-23 की सालाना रिपोर्ट का विश्लेषण करें तो इनमें चुनावी बॉन्ड का कहीं जिक्र नहीं है। वेदांत ने चंदे में दी रकम को 'अन्य व्यय' में दिखाया है मगर एक फुटनोट लिखा है जिससे यह पता चलता है कि रकम चुनावी बॉन्ड खरीदने पर खर्च की गई है। शेयरधारकों के समक्ष पूरी पारदर्शिता बरतना उन कंपनियों के मामले में और भी आवश्यक हो जाता है जो आरोपों या किसी जांच का सामना कर रही हैं। कई बड़ी कंपनियों के नाम चंदा देने वाली इकाइयों की सूची में नहीं हैं मगर दिलचस्प है कि सभी सूचीबद्ध दवा कंपनियां और कई अन्य गैर-सूचीबद्ध कंपनियां के नाम सूची में शामिल हैं। इनमें कई कंपनियां कर वंचना, खराब गुणवत्ता वाली दवाओं या अधिक कीमत वसूलने के लिए कार्रवाई (कुछ वाजिब तो कुछ कथित रूप से गैर-वाजिब) का सामना कर रही हैं। चुनावी बॉन्ड से चंदा देने वाले बड़े नामों में दिवीज लैबोरेट्रीज (55 करोड़ रुपये), सिप्ला (39.20 करोड़ रुपये), एल्केम लैबोरेटरीज (15 करोड़ रुपये), डॉ. रेड्डीज (84 करोड़ रुपये), सन फार्मा और मैनकाइंड फार्मा (24 करोड़ रुपये) शामिल हैं। इनमें किसी भी कंपनी ने चुनावी बॉन्ड के बारे में अपने शेयरधारकों के समक्ष बड़े खुलासे नहीं किए हैं।

देवाशिष बसु

चुनावी बॉन्ड के गहन विश्लेषण से पता चलता है कि कंपनियां डर या किसी तरह के फायदे-प्रोत्साहन (ठेका, परियोजना या ऑर्डर मिलने में सहूलियत) के लिए चंदा दे रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि राजनीतिक दलों और कंपनियों के बीच अव्यवस्थित बातचीत की वजह से यह आसानी से पता नहीं चलता कि चंदा दबाव या प्रोत्साहन के कारण दिया गया है। कारण जो भी हो किसी भी सूरत में शेयरधारक और नागरिक दोनों ही अंधेरे में रखे जाते हैं। उदाहरण के लिए सरकार के पूंजीगत व्यय पर विचार करते हैं। केंद्र सरकार सड़क, पुल, स्वच्छता, पेयजल, रेल आधुनिकीकरण और ऊर्जा पर भारी भरकम पूंजीगत व्यय कर रही है। इन परियोजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया कुछ निश्चित मानदंडों पर आधारित होती हैं मगर सदैव इनका अनुपालन नहीं होता है। कंपनियां पूंजी के रूप में बड़े पैमाने पर नकद रकम का इस्तेमाल भी करती हैं। मेघा इंजीनियरिंग (1,200 करोड़ रुपये) की अगुआई में पिची रेड्डी की चार कंपनियां इस सूची में दूसरी सबसे बड़ी दाता के रूप में सामने आई हैं। ऐसी खबरें हैं कि मेघा इंजीनियरिंग ने कई मौकों पर चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। ये सभी बड़ी परियोजनाओं का ठेका लेने से ठीक पहले खरीदे गए हैं। सूची में निर्माण क्षेत्र की एक अन्य बड़ी कंपनी बी जी शिरके कंस्ट्रक्शन ने चुनावी बॉन्ड खरीद कर 117 करोड़ रुपये दान में दिए। कंपनी को महाराष्ट्र में एक बड़ी सस्ती आवास परियोजना और दूसरे सौदे प्राप्त हुए। तो खुलासे को लेकर क्या किया जा सकता है, कम से कम सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में? आईएफबी एग्रो ने अपनी सालाना रिपोर्ट 2022-23 में पूरी पारदर्शिता बरती है। ऐसे उदाहरण यदा-कदा ही मिलते हैं। कंपनी ने कहा है, 'कारोबार को लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पहले भी इसका उल्लेख किया गया है। कारोबार में निरंतरता बनाए रखने और सभी शेयरधारकों के हितों की रक्षा के लिए कंपनी ने इस साल चुनावी बॉन्ड खरीदने पर 18.30 करोड़ रुपये खर्च किए। कंपनी ने अप्रैल 2023 में चुनावी बॉन्ड खरीदने पर 15 करोड़ रुपये और खर्च किए। कुल मिलाकर 2021 से आईएफबी एग्रो ने चुनावी बॉन्ड के मद में 92 करोड़ रुपये दिए हैं।'

आईएफबी एग्रो पश्चिम बंगाल में परिचालन करती है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक रूप से ताकतवर लोगों का समूह कारोबारी गतिविधियों को अपनी मर्जी के अनुसार चलाता है। इनमें कर्मचारियों की नियुक्ति, ठेकेदार और आपूर्तिकर्ताओं का चयन और नियमित भुगतान संग्रह आदि शामिल हैं। 26 जून 2020 को और फिर 22 दिसंबर 2020 को आईएफबी एग्रो ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि 24 परगना जिले में इसकी डिस्टलरी पर लगभग 150 गुंडों ने हमला किया था। उन्होंने डिस्टिलरी को जबरन बंद करा दिया, कर्मचारियों को पीटा और उन्हें बंधक बनाया। पुलिस से इस घटना की शिकायत की गई मगर कुछ नहीं हुआ। कंपनी ने कहा कि उसके एल्कोहल कारोबार को इसलिए नुकसान पहुंचाया गया क्योंकि वह 'कुछ उत्पाद कर अधिकारियों की अनुचित मांगों' के आगे नहीं झुकी।

चूंकि, कंपनी की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई इसलिए आईएफबी एग्रो ने चंदा देने के कारण का सार्वजनिक रूप से खुलासा कर दिया। दूसरी सूचीबद्ध कंपनियां भी आईएफबी एग्रो की तरह साहस क्यों नहीं दिखा सकतीं? अगर सूचीबद्ध कंपनियां अपने कारण नहीं बताना चाहतीं तो उनके पास एक और विकल्प उपलब्ध है और वह है किरण मजूमदार शॉ की राह पर चलना। शॉ दो सूचीबद्ध कंपनियों (सिनजीन और बायोकॉन) का संचालन करती हैं। दोनों ही कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड नहीं खरीदे हैं। मगर शॉ ने अपने व्यक्तिगत खाते से 6 करोड़ रुपये का चंदा दिया। प्रवर्तक-प्रबंधक स्वयं को करोड़ों रुपये वेतन के रूप में लेते हैं इसलिए उनके लिए व्यक्तिगत रूप से चंदा देना मुश्किल नहीं है। ऐसा कर वे शेयरधारकों की रकम तो बचाते ही हैं, साथ ही उन्हें अंधेरे में भी नहीं रखते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

आपका पक्ष

भोजन की बढ़ती बरबादी चिंता का विषय

संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम रिपोर्ट दुनिया भर में पर्याप्त खाद्य उत्पादन और उपलब्धता के बावजूद भोजन बरबाद करने की आदतों के कारण इसके दुरुपयोग के बारे में कुछ आवश्यक पहलुओं को रेखांकित करती है। वर्ष 2022 में 1.05 अरब टन भोजन की बरबादी सामने आई है, जो प्रति व्यक्ति 132 किलोग्राम है यानी उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कुल भोजन का लगभग पांचवां हिस्सा बरबाद हो जाता है। यह चिंताजनक है और अधिक मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यदि हम अपनी भावी पीढ़ियों को पर्यावरण के अनुकूल और भोजन सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो ऐसी प्रवृत्तियों को कम करना हमारा नैतिक दायित्व है। लगभग 78.3 करोड़ लोग भूख से जूझते हैं और 19 फीसदी खाना बरबाद हो जाता है। रिपोर्ट ने खाद्य अपशिष्ट की ट्रैकिंग और सक्षम निगरानी के लिए

साल 2022 में 1.05 अरब टन भोजन की बरबादी हुई, जो प्रति व्यक्ति 132 किलोग्राम है यानी भोजन का पांचवां हिस्सा बरबाद हो जाता है

बुनियादी ढांचे के विस्तार और मजबूत करने के महत्त्व पर जोर दिया। रिपोर्ट ने कुछ रूढ़िवादिता को भी तोड़ा जैसे कि भोजन की बरबादी एक समृद्ध देश की समस्या है। रिपोर्ट में भोजन की बरबादी और जलवायु परिवर्तन के बीच गायब लिंक पाया गया क्योंकि उत्पन्न अपशिष्ट वार्षिक वैश्विक ग्रीनहाउस गैसों (जीएचजी) उत्सर्जन का 8 से 10 हिस्सा था। 2030 तक एसडीजी की बैठक वैश्विक और व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से ही संभव है जहां एनजीओ, निजी और विभिन्न हितधारक कीमती संसाधनों को बचाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं। भारत संसाधनों तक गैर-बराबरी की पहुंच से भी जूझ रहा है जिसके परिणामस्वरूप भोजन का एक तिहाई हिस्सा उपभोग से पहले बरबाद या खराब हो जाता है क्योंकि बाद की प्रवृत्ति उनके ग्रामीण समकक्षों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट है। प्रति घर 50 किलोग्राम भोजन बर्बाद हो जाता है। खाद्य स्थिरता सूचकांक रिपोर्ट फरवरी 2016 में अग्रणी खाद्य अपशिष्ट कानून अपनाने और लागू करने में फ्रांस सबसे आगे बताया गया है और 2025 तक अपने खाद्य अपशिष्ट को आधा करने का उसका लक्ष्य है। लोगों को भोजन की बरबादी के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया जाता है। इससे दुनिया को अपशिष्ट रोकने के लिए सामूहिक कदम उठाने के लिए प्रेरित होना चाहिए।

विजय सिंह अधिकारी, नैनीताल

एक ही तरह की सरकार के निरंकुश होने की आशंका

केंद्र का चुनाव जहां राष्ट्रीय मुद्दों पर आधारित होता है वहीं राज्यों के चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दे प्रभावशाली होते हैं। कई बार सहानुभूति लहर, जातिवाद और क्षेत्रवाद भी मतदान को प्रभावित करते हैं जिससे मतदाता सही निर्णय नहीं ले पाता। केंद्र और राज्य दोनों में एक ही तरह की सरकार होने से वह निरंकुश हो सकती है और विपक्ष काफी कमजोर हो सकता है। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष ही लोकतंत्र का रखवाला होता है। केंद्र और अधिकतर राज्यों में त्रिशंकु सरकार होने की स्थिति में यह प्रणाली कैसे काम करेगी यह भी विचारणीय है।

रवींद्र जोशी, अंबाला, हरियाणा

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

सोमवार को नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रॉयल थाई नौसेना के कमांडर-इन-चीफ एडमिरल एडुंग फान-इयाम (दाएं) का स्वागत करते नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार।

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

सियासी बहिष्कार

मालदीव के बाद बांग्लादेश में भी भारत के बहिष्कार का जो अभियान कुछ लोग चला रहे हैं, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ऐसे लोगों को न तो अपने देश का इतिहास मालूम है और न भारत के योगदान का उन्हें कोई ज्ञान है। मालदीव के सत्ताधारी नेताओं और बांग्लादेश के कुछ विपक्षी नेताओं को अपनी स्वार्थपूर्ण राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा है। माले के अब बाद ढाका में भी भारत विरोध की राजनीति का गरम होना हमें सोचने पर बार-बार विवश करता है। विपक्षी बांग्लादेश नेशनल पार्टी (बीएनपी) लंबे समय से नागरिकों को भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। दरअसल, इस प्रमुख विपक्षी दल को लगता है कि भारत सत्तारूढ़ अवामी लीग का समर्थक है और अवामी लीग की जीत में भारत की बड़ी भूमिका है। यह दरअसल, बांग्लादेश के विपक्षी दल की एक बड़ी गलतफहमी है कि भारत सरकार बांग्लादेश में हस्तक्षेप कर रही है। हां, यह जरूर है कि बांग्लादेश की तरक्की में भारत ने यथासंभव सहयोग दिया है और ऐसे समय में बांग्लादेश में जो भी सरकार होगी, वह स्वाभाविक रूप से मजबूत होगी। बांग्लादेश के विपक्षी नेता शायद भूल गए हैं कि जब बांग्लादेश में सैन्य प्रभुत्व बढ़ा था, तब भी भारत ने वहां की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया था।

बहरहाल, बांग्लादेश की सरकार या प्रधानमंत्री ने भारत का बचाव किया है और विपक्षियों के दोहरे रवैये की निंदा की है। दरअसल, बांग्लादेश अगर चाहे भी, तो भारत का बहिष्कार नहीं कर सकता, क्योंकि वहां भारतीय उत्पादों की भरमार है। भारतीय उत्पादों का विरोध व्यावहारिक और सैद्धांतिक, दोनों ही रूपों में अनुचित है। फिर भी न जाने कैसा सियासी लाभ सोचते हुए बीएनपी के वरिष्ठ नेता कबीर रिजवी ने पिछले दिनों अपने कंधे पर पहना हुआ भारतीय शॉल उतार फेंका। भारतीय-कश्मीरी शॉल को फेंकने से पहले उन्होंने यह नहीं सोचा कि वह किस तरह की लड़ाई को बढ़ावा दे रहे हैं। 'हैशटैग इंडियाआउट' और 'बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स' के नाम पर राजनीति सिवाय गंभीर गलती के और क्या है? विपक्ष के इस अभियान के जवाब में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने विपक्षी नेताओं को चुनौती दी है कि जिस दिन आप (बीएनपी) कार्यालय के सामने अपनी पत्नियों की तमाम भारतीय साड़ियों को जला देंगे, उस दिन मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप वास्तव में भारतीय सामान का बहिष्कार कर रहे हैं। बेशक, भारतीय साड़ियों के प्रति बांग्लादेश में स्वाभाविक लगाव है, इससे बचा नहीं जा सकता, मगर बहिष्कार के लिए किसी को भी किसी तरह से उकसाना सही नहीं है। वहां सत्ता पक्ष व विपक्ष, दोनों को समझदारी का परिचय देना चाहिए, ताकि भारतीयों की भावना को किसी भी प्रकार से ठेस न पहुंचे।

बांग्लादेश की सरकार या प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी भारत का बचाव किया है और विपक्षियों के दोहरे रवैये की निंदा की है। सियासत में समझदारी जरूरी है।

मालदीव के सत्ताधारी नेता हों या बांग्लादेश के विपक्षी नेता, दोनों को तार्किक ढंग से अपनी शिकायत सामने रखनी चाहिए, ताकि शालीनता के दायरे में भारत पड़ोसी धर्म के अनुकूल सुधार कर सके। किसी अन्य भारत विरोधी देश के इशारे पर फैसला करने के बजाय इन देशों को अपना अतीत, वर्तमान और भविष्य देखना चाहिए। संबंधों में हल्कापन नहीं आए। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। ऐसे में, वहां भारत कदापि राजनीति का विषय न बने। मालदीव की तरह नहीं होना चाहिए कि आप इंडिया आउट का नारा लगाते रहें और आपको भारत से उदार आर्थिक मदद भी चाहिए।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 02 अप्रैल, 1949

मद्रास मंत्रिमंडल

मद्रास मंत्रिमण्डल ने अस्थिरता के लिए अच्छी ख्याति हासिल कर ली है। प्रायः हर वर्ष कांग्रेस पार्टी के नेता को बदल दिया जाता है और उसके फलस्वरूप मंत्रिमण्डल भी बदलता है। यह आये दिन का परिवर्तन स्थिर और अच्छे शासन की निशानी नहीं समझा जा सकता। मद्रास भारत का एक बड़ा प्रान्त है। प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमण्डल ने, जो श्री राजगोपालाचार्य के नेतृत्व में सन् १९३७ में बना था, लोकहित के ठोस और अच्छे काम किये थे। मद्रास का मंत्रिमण्डल अन्य प्रान्तों के लिए नमूने के तौर पर पेश किया जाता था। द्वितीय महायुद्ध के आ जाने के कारण उस मंत्रिमण्डल को बीच में ही त्यागपत्र देना पड़ा, उसके बाद से आज तक मद्रास में स्थिर मंत्रिमण्डल नहीं बन पाया। महायुद्ध की समाप्ति के बाद कांग्रेस ने जब पुनः प्रान्तों में पदग्रहण किया तो कांग्रेस की उच्च सत्ता की यह इच्छा थी कि श्री राजगोपालाचार्य पुनः प्रान्त के शासन की बागडोर सम्हालें। किन्तु मद्रास धारा सभा के कांग्रेसी सदस्यों ने बुरी तरह उस इच्छा को ठुकराया। आन्ध्र के पुराने कांग्रेसी नेता श्री प्रकाशम मद्रास के प्रधानमन्त्री बने। (उन दिनों सूबों के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था) ...किन्तु श्री प्रकाशम अपनी कुर्सी को कायम नहीं रख पाये। उन्हें अव्यावहारिक घोषित किया गया। जिस दलबन्दी के आधार पर वह प्रधानमन्त्री बने थे, उसी ने उनको उस पद से च्युत होने के लिए बाध्य कर दिया।

मद्रास के वर्तमान प्रधानमन्त्री श्री ओ.ही. रामस्वामी रेड्डियर पिछले वर्ष तीव्र चुनावी संघर्ष के बाद चुने गये। उनके चुन लिये जाने के बाद कांग्रेस दल के प्रतिद्वन्द्वी गुटों ने उन्हें सहयोग का आश्वासन दिया था। ...किन्तु यह राजनीतिक दलबन्दी की विचित्रता है कि उन्हें भी अपने पद से हटना पड़ रहा है। उन्होंने अपने आचरण से सिद्ध कर दिया कि वह पद के भूखे अथवा लोभी नहीं हैं। पहले तो उन्होंने धारा सभा के कांग्रेसी सदस्यों से अपील की कि वे दल की एकता को खतरे में न डालें और यदि मंत्रिमण्डल में कुछ परिवर्तन करना आवश्यक समझा जाये तो वह स्वयं ऐसा करने को प्रस्तुत हैं। किन्तु जब इस अपील का कोई नतीजा नहीं निकला, तो उन्होंने समय से पहले ही अपने को उससे अलग कर लिया और घोषित कर दिया कि वह नेता पद के लिए उम्मीदवार खड़े न होंगे।

एक मनबढ़ किशोर का बाहुबली बनना

राय की राय
यहां स्कैन करें

विभूति नारायण राय | पूर्व आईपीएस अधिकारी

मुख्तार अंसारी नाम के एक बाहुबली की गाथा के जरिये हम भारतीय राजनीति के उस पंक को खंगाल सकते हैं, जिनमें बिना किसी अपवाद लगभग सभी दल आकंठ डूबे हुए हैं।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के माफिया गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में हुई मृत्यु से जितने प्रश्न सुलझे, उससे ज्यादा खड़े हो गए हैं। यदि यह रॉबिनहुड की छवि वाले सिर्फ एक अपराधी की मृत्यु का मसला होता, तो शायद इतने प्रश्न अपने पीछे नहीं छोड़ता और न ही ये प्रश्न हमें इस कदर बेचैन करते।

पहला प्रश्न हमारी लचर न्याय व्यवस्था को लेकर खड़ा होता है। मुख्तार ने पहला अपराध तब किया था, जब वह बालिग भी नहीं हुआ था। साठ से अधिक मुकदमों वाले इस अपराधी को अपने किए की पहली सजा पहले दर्ज प्रकरण के 40 साल बाद मिली। कल्पना की जा सकती है कि अगर एक मनबढ़ किशोर को उसके पहले या दूसरे अपराध के लिए तत्काल सजा मिल गई होती, तो शायद समाज से अधिक उसका अपना भला हो जाता। क्रिकेट का शौकीन युवा दुर्दांत अपराधी की जगह खिलाड़ी बन सकता था।

मुख्तार को रॉबिनहुड वाली छवि बनाने में लचर तंत्र ने भी मदद की थी। उसके दरबार में जुटने वाले फरियादियों की संख्या जिले के कलक्टर या कप्तान से अधिक होती और वे जिन छोटे-बड़े प्रकरणों के लिए वहां आते, उनका समाधान तो किसी कानून-कायदे वाले समाज में सहज स्वाभाविक रूप से हो जाना चाहिए, पर हमारा लचर और अमानवीय तंत्र अपने चक्कर में फंस जाने वाले फरियादी को ही अपराधी होने का एहसास कराता रहता है। ऐसे में, इन दुखियारों को त्वरित न्याय मिलता और वे उसकी जय-जय करते जाते। अपने छोटे निजी स्वार्थों में मस्त वे माफिया के उन कुकृत्यों को नजरंदाज कर देते, जिनके बल पर वह अपहरण कर फिरौती वसूल रहा होता, संपत्तियों पर बलात कब्जा कर रहा होता, चुनावों में बूथ कब्जिया रहा होता या विरोधियों की हत्या करा रहा होता।

एक बाहुबली की गाथा के जरिये हम भारतीय राजनीति के उस पंक को खंगाल सकते हैं, जिनमें बिना किसी अपवाद सभी दल आकंठ डूबे हुए हैं। मुख्तार और उसके परिवार के सदस्यों ने अलग-अलग चुनाव कई राष्ट्रीय दलों के बैनर तले लड़े। न तो इन दलों को इसमें कोई धर्म संकट महसूस हुआ और न ही हर चुनाव में बदलते चुनाव चिह्न को लेकर मतदाताओं ने सवाल पूछे। सबसे दिलचस्प तथ्य- कई साल तो वह एक फर्जी मुकदमे के चलते पंजाब की जेल में 'शरण' लिए रहा और इंतजार करता रहा कि उत्तर प्रदेश में उसकी मित्र सरकार आए और वह लौटे। मुख्तार की कथा के जरिये हम बाहुबल और उससे अर्जित धन का उपयोग करने में अपने राजनीतिक दलों की आतुरता को भी रेखांकित कर सकते हैं।

पिछले कुछ महीनों से मुख्तार और उसके परिवारीजन आरोप लगा रहे थे कि उसे जेल के भोजन में धीमा जहर दिया जा रहा है। अदालत में भी इस आशय का प्रार्थनापत्र दिया गया था। मरने के एक दिन पहले के एक ऑडियो क्लिप में भी उसकी गंभीर स्थिति का वर्णन है, फिर क्यों नहीं उसे अस्पताल में रखा गया? वैसे भी, उसे एक बार पहले हृदयाघात पड़ चुका था। कुछ दिनों से उसे बांदा मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में ले जाया जाता था और फिर कुछ घंटों में जेल की बैरक वापस भेज दिया जाता था। क्या मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों पर इसके लिए कोई दबाव था? किसी भी सभ्य समाज में यह एक समादृत नियम है कि हिरासत में आए व्यक्ति की जान की रक्षा राज्य की जिम्मेदारी होती है। सम्यक न्यायिक कार्यवाही के बिना उसकी जान नहीं ली जा सकती। यहां तक कि युद्ध बंदियों को भी यह अधिकार हासिल है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण हृदयाघात बताया गया, लेकिन चूंकि परिजन पहले से ही जहर देने की आशंका जता रहे थे, इसलिए राज्य को अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए इस मामले की जांच करानी चाहिए और स्वयं को निर्दोष साबित कराना चाहिए। यह राज्य की साख का प्रश्न है।

अपराध की दुनिया का एक दिलचस्प तथ्य आम तौर से उसका धर्मनिरपेक्ष होना है। मुंबई के दो बड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहीम और छोटा राजन शायद अपवाद ही होंगे, जिन्होंने धर्म को अपनी गतिविधियों का कारण बनाया, वरना यह दुनिया धर्मनिरपेक्ष स्वार्थों व वफादारियों से संचालित होती है। मुख्तार अंसारी को भी हिंदुओं और मुसलमानों, दोनों का समर्थन हासिल था। जिन चुनाव क्षेत्रों से वह या उसके परिवारीजन जीतते रहे हैं, उनमें मुसलमानों से अधिक हिंदुओं की आबादी है। अपने प्रतिद्वंद्वी कृष्णानंद राय की हत्या के लिए जो टीम उसने भेजी थी, उसमें हिंदू और मुसलमान, दोनों थे। उसके गिरोह के दो सबसे खूंखार अपराधी मुन्ना बजरंगी और संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा हिंदू थे और इन दोनों की हाल में हत्या हुई है। यह जानना रोचक रहेगा कि मुख्तार ने कौमी एकता के नाम से एक राजनीतिक दल भी बनाया था और उसके निशान पर कुछ लोग चुनाव भी जीते थे। मुख्तार के विरोधियों ने उसके खिलाफ हिंदू मतदाताओं को गोलबंद करने के लिए उसे मुसलमानों का मसीहा साबित करने के लिए जो प्रयास किए, उनमें से सिर्फ एक का उल्लेख करना पर्याप्त होगा।

आधुनिक विमर्शों में आख्यान गढ़े जाते हैं और फिर उनसे समझ निर्मित होती है। मुख्तार के खिलाफ ऐसा ही एक नैरेटिव 2005 के मऊ दंगों को लेकर निर्मित किया गया था। इन दंगों का एक वीडियो तमाम चैनलों पर गर्दिश कर रहा है, इसमें एक खुली जीप में अपने पुलिस एस्कॉर्ट के साथ मुख्तार भागती हुई भीड़ के पीछे-पीछे जा रहा है और साथ चल रही कमेंट्री में 'आतंक' के पर्यायवाची मुख्तार के दुस्साहस का जिक्र चल रहा है कि कैसे पुलिस की मौजूदगी के बावजूद उसके आतंक के चलते लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। क्या आपने गौर किया है कि हजारों बार दिखाए जाने वाले इस वीडियो में मुख्तार का मुंह तो चल रहा है, पर उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। इन दंगों के फौरन बाद लखनऊ की मानवाधिकार एक्टिविस्ट रूपरेखा वर्मा के नेतृत्व में कुछ लोगों का एक दल मऊ गया था, जिसमें मैं भी था। हमें यह जानने की उत्सुकता थी कि भीड़ से मुख्तार कह क्या रहा है? बड़ी मुश्किल से एक कैसेट हाथ लगा, जिसमें मुख्तार की आवाज भी थी और हम सभी यह देखकर चकित हो गए कि मुख्तार तो भागती भीड़ से अपील कर रहा था कि वे भागे नहीं, शांति बनाए रखें और अफवाहों से बचें। यह सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे नैरेटिव विकसित होते हैं और कैसे वे जनसाधारण की समझ निर्मित करते हैं।

मुख्तार सिर्फ एक अपराधी चरित्र न होकर हमारे समाज में फैली तमाम विकृतियों को समझने के लिए एक अच्छी केस स्टडी हो सकता है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

कच्चातिवु जैसे इलाकों को लेने-देने की रवायत पुरानी

यहां स्कैन करें

स्मृति पटनायक | रिसर्च फेलो, एमपी-आईडीएसए

भारत में आम चुनाव की बढ़ती गरमी के बीच कच्चातिवु द्वीप अचानक सुर्खियों में आ गया है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित यह निर्जन द्वीप करीब डेढ़ किलोमीटर लंबा है और भारतीय तट से लगभग 33 किलोमीटर दूर है। इसका मालिकाना हक विवादित रहा है। यह पूरा इलाका पहले पुर्तगालियों के अधीन था, फिर ब्रिटेन का उपनिवेश बना, इसलिए 1947 में भारत के आजाद होने और भूमि-निर्धारण के बाद यहां भारत व श्रीलंका, दोनों के मछुआरे आते-जाते रहे। वे वहां अपने जाल सुखाते थे और फिर मछली पकड़ने निकल जाते। बाद के वर्षों में श्रीलंका ने इस पर अपना दावा किया, जिसके कारण सन् 1974 में समुद्री सीमा-निर्धारण के वक्त भारत ने अपना अधिकार छोड़ दिया। तब यही माना गया था कि ऐसा करने से दक्षिणी पड़ोसी से भारत के संबंध और मजबूत होंगे। हमारे लिए इस द्वीप का कोई सामरिक महत्व भी नहीं है। यहां पर अब भी सालाना कच्चातिवु त्योहार होता है, जिसमें भारत और श्रीलंका, दोनों देशों के मछुआरे भाग लेते हैं। अब आपसी सौहार्द बढ़ाने में इसकी अहमियत मानी जाती है।

भारत ने जमीनों के ऐसे लेन-देन दक्षिण एशिया के कई अन्य देशों के साथ किए हैं। इसका मूल मकसद आपसी विवाद को खत्म करना रहा है। कभी-कभी परिस्थितिवश भी ऐसा किया गया, जैसे बांग्लादेश के साथ। उसके साथ वर्ष 2015 में हमने भूमि-सीमा के निर्धारण का समझौता किया, जिसके तहत 111 सीमावर्ती एन्क्लेव हमने बांग्लादेश को सौंपे और बदले में 51 एन्क्लेव पर अपना अधिकार हासिल किया। यहां कोई कह सकता है कि हमने जितनी भूमि (करीब 17 हजार एकड़) बांग्लादेश को दी, उसकी तुलना में कम जमीन (लगभग सात हजार एकड़) पर कब्जा हासिल किया, पर सच यही है कि कई एन्क्लेव तक जाने के लिए हमें बांग्लादेश की सीमा में जाना पड़ता था। कुछ यही स्थिति बांग्लादेश की भी थी। चूंकि बांग्लादेशी एन्क्लेव तक बांग्लादेशियों की आवाजाही निर्बाध थी, इसलिए तस्करी का अंदेशा भी बना रहता था, इसलिए इसका समाधान आवश्यक था।

भारत ने जमीनों के ऐसे लेन-देन दक्षिण एशिया के कई देशों के साथ किए हैं। इसका मूल मकसद आपसी विवाद को खत्म करना रहा।

यहां न्यू मूर द्वीप की चर्चा भी प्रासंगिक है। इस पर कभी बांग्लादेश और भारत, दोनों अपना दावा जताते रहे, लेकिन बंगाल की खाड़ी का यह द्वीप अब इसलिए चर्चा में नहीं है, क्योंकि यह समुद्र में समा चुका है। उल्लेखनीय यह भी है कि 2014 में संयुक्त राष्ट्र न्यायाधिकरण ने बांग्लादेश को 25 हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक के समुद्री दावे में से लगभग 19 हजार वर्ग किलोमीटर का अधिकार दे दिया, जिसे भारत ने बिना किसी विरोध के स्वीकार किया, क्योंकि हम आपसी संबंधों को ज्यादा अहमियत देते रहे हैं।

हमारा एक सीमा विवाद पाकिस्तान के साथ कच्छ के रण को लेकर भी रहा है। 1965 के ताशकंद समझौते के तहत इस विवाद के निपटारे की पटकथा लिखी गई। यह समझौता हालांकि इसलिए याद रखा जाता है, क्योंकि 1965 के युद्ध में पाकिस्तान की पराजय के बाद इसी के तहत भारतीय सैनिकों को वापस बेड़े में बुलाया गया, लेकिन इस समझौते से कच्छ रण का विवाद भी सुलझा और 1969 में आपसी सहमति से कच्छ विवाद का समाधान हो गया। यहां भूटान का जिक्र भी लाजिमी है। हमने 1947 में आजाद होने के बाद भूटान को संप्रभु देश का दर्जा दिया और देओथांग सहित करीब 82 वर्ग किलोमीटर 'द्वार' (पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भूटान के इलाके) उसे वापस लौटा दिए, जिसे अंग्रेजों ने उससे हड़प लिया था।

सीमा-विवाद को लेकर भारत और नेपाल का मसला खासा अहम है और दूसरों से अलग भी। यहां भारत उस सुगौली संधि के तहत अपनी सीमा का दावा करता है, जिसको ब्रिटिश सरकार ने नेपाल के राजा के साथ 1814-16 के दौरान किया था। उस संधि के तहत नेपाल के कुछ मैदानी इलाके पराधीन भारत के पास आ गए थे। नेपाल इन पर अपना दावा जताता रहता है और इसे 'ग्रेटर नेपाल' का हिस्सा बताता है। फिलहाल, इसके निपटारे के प्रयास भी चल रहे हैं। स्पष्ट है, पड़ोसी देशों के साथ सौहार्द बढ़ाने के लिए जमीनों की अदला-बदली की जाती रही है। यह सीमा-विवाद के निपटारे की स्थापित रवायत है।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

मनसा वाचा कर्मणा

शांति तभी स्थापित होगी

यदि हमारे पास कोई विश्वास न हो, तो हमारा क्या होगा? क्या इस बात से हम सहम नहीं जाएंगे कि न जाने क्या होगा? यदि हमारे पास किसी विश्वास पर आधारित कर्म का कोई प्रारूप न हो, तो हम बिल्कुल असहाय से हो जाएंगे। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि यह विश्वास ईश्वर में है या साम्यवाद में; समाजवाद में है अथवा साम्राज्यवाद में; किसी प्रकार के तंत्र-मंत्र में है या फिर किसी धार्मिक मताग्रह में, जिससे हम संस्कारित हैं। और विश्वास का यह स्वीकार क्या हमारे कुछ न होने, खोखले होने के डर को छिपाने का ही प्रयास नहीं है? आखिर किसी प्याले का उपयोग तभी हो सकता है, जब वह खाली हो; ऐसा मन, जो विश्वासों से, रूढ़ियों से भरा हुआ है, सर्जनात्मकता से रहित मन है। वह केवल पुनरावृत्ति करने वाला, अनुकरण करने वाला मन है।

हम भयभीत हैं और इस भय से बचना चाहते हैं। हम खालीपन से भयभीत हैं, अकेलेपन से भयभीत हैं; हमें गतिहीन, अवरुद्ध हो जाने का भय है; हम भयभीत हैं कि कहीं ऐसा न हो कि हम लक्ष्य प्राप्त न कर सकें, सफलता न पा सकें, उपलब्धि से वंचित रह जाएं, कुछ बन न सकें, इन सबसे पलायन ही वह कारण है कि हम किसी भी विश्वास को व्यग्रता से अपना लेते हैं। लेकिन क्या विश्वास की स्वीकृति से हम स्वयं को समझ पाते हैं? होता ठीक इसके विपरीत है। विश्वास चाहे धार्मिक हो या राजनीतिक, निश्चय ही स्वयं को समझने में बाधक बनता है। यदि हम इन विश्वासों को हटा दें, तो क्या ऐसा कुछ रह जाएगा, जो देखा जा सके? दरअसल, जब हमारे पास ऐसा कोई विश्वास न हो, जिसके साथ मन ने तादात्म्य बिठा रखा हो, तब इस तादात्म्य से मुक्त होकर ही मन खुद का अवलोकन कर सकता है, और तभी अपने आप को समझने की शुरुआत होती है!

विश्वास और ज्ञान की यह समस्या वास्तव में दिलचस्प है। कितनी असाधारण भूमिका अदा करती है हमारे जीवन में यह समस्या! हमारे कितने सारे विश्वास हैं? बर्बर व्यक्तियों के आधुनिक जगत में अगणित अंधविश्वास हैं। जो अधिक विचारशील, सजग और सतर्क हैं, वे संभवतः कम विश्वासी होंगे। कारण यह है कि विश्वास बांधता है, अलग-थलग करता है और हम देखते हैं कि आर्थिक और राजनीतिक, दोनों स्तरों पर सारे विश्व में यही हो रहा है।...

जो सचमुच शांति चाहता है, और एक सुखी संसार का निर्माण करना चाहता है, वह किसी भी प्रकार के विश्वास व मत में उलझकर अपने को पृथक नहीं करेगा।

आप ब्राह्मण हैं, मैं नहीं हूं; आप ईसाई हैं और मैं मुसलमान या कुछ और। आप भाईचारे की बात करते हैं, मैं भी भ्रातृत्व की बात करता हूं, पर वास्तविकता यह है कि हम एक-दूसरे से अलग हो गए हैं; अपने आप को विभाजित करते जा रहे हैं। जो शांति चाहता है, सुखी संसार का निर्माण करना चाहता है, वह किसी प्रकार के विश्वास व मत में उलझकर अपने को पृथक नहीं करेगा।

जे कृष्णमूर्ति

जो बाइडन | अमेरिकी राष्ट्रपति

यहां ऐसे लोग भी हैं, जो अमेरिका को अतीत की ओर ले जाना चाहते हैं और ऐसे नागरिक भी हैं, जो इसे आगे ले जाना चाहते हैं। मेरी जिंदगी ने मुझे भविष्य को गले लगाना सिखाया है।

अब दूसरे देश भी हमें नसीहत देने लगे

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से जर्मनी, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, वह हमारे लिए आंखें खोलने वाली है। यह एक तरह से नसीहत है कि हमें अपने लोकतंत्र को दागदार होने से बचाने का उपाय करना ही होगा। हमें कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए कि किसी अन्य देश को हम पर उंगली उठाने का मौका नहीं मिले। हमें याद रखना होगा कि भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र का सम्मान हासिल है। यहां के लोकतांत्रिक मूल्यों को दुनिया भर के देश काफी इज्जत की नजर से देखते रहे हैं। ऐसे में, यदि किसी कारण से इन मूल्यों पर दाग लगते हैं, तो यह देश के लिए उचित नहीं है। इससे हमारी अंतरराष्ट्रीय छवि खराब होगी।

सवाल है कि आखिर कैसे हम अपने ऊपर उठ रहे सवालों से बचेंगे? सबसे पहले, तो हरेक सरकारी तंत्र को अपना काम ईमानदारी से करना होगा। हमें यह सोचना होगा कि आखिर क्यों किसी जांच एजेंसी को 'पिंजड़े का तोता' कहा जाता है। लोग साफ देख रहे हैं कि सरकारी जांच एजेंसियां विपक्ष के एक-एक नेता पर कार्रवाई कर रही हैं। उनको आनन-फानन में नोटिस दे दिया जाता है, और फिर पूछताछ के नाम पर उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। यहां तक कि मुख्यमंत्री तक को नहीं बख्शा जाता। क्या यह जांच करने का उचित तरीका है? इससे यदि देश के आम लोगों की ही नहीं, बल्कि अमेरिका, जर्मनी जैसे देशों की धारणा भी बदल रही है, तो हमें सचमुच सजग हो जाना चाहिए। आधुनिक विश्व व्यवस्था में अभी हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम विकसित देशों की सलाह को नजरंदाज करने की मनमर्जी कर सकें। अरविंद केजरीवाल के मामले में यदि वे चिंता जाहिर कर रहे हैं, तो हमें उनकी चिंताओं पर गौर करना चाहिए, न कि उनके राजदूतों को तलब करके उन पर दबाव बनाने की रणनीति अपनानी चाहिए। इसे वे अन्यथा भी ले सकते हैं।

अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बनाना मुश्किल काम है, लेकिन उसे तोड़ना क्षण भर का काम होता है, इसलिए हमें इन देशों के साथ अपने संबंधों की संवेदनशीलता को समझना चाहिए। वैसे भी, आज की विश्व व्यवस्था में कोई देश अपने बूते आगे नहीं बढ़ सकता, उसे अन्य राष्ट्रों का साथ चाहिए होता है। चूंकि हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनना चाहते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि हम अमेरिका, जर्मनी जैसे देशों के साथ अपने संबंध बनाकर रखें, उनसे बेवजह कटुता न पालें। लिहाजा, यदि दूसरे देश हमें कुछ कह रहे हैं, तो उस पर हमें गौर करना चाहिए।

ललिता मिश्र, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

बाहरी दखल

यह हमारे आंतरिक मामलों में दखल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हाल ही में हुई गिरफ्तारी के बाद देश के सभी राजनीतिक संगठनों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जो स्वाभाविक भी है, लेकिन भारत के आंतरिक मामलों में अन्य देशों की प्रतिक्रियाएं आना समझ से परे है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जिस तरह से जर्मनी, अमेरिका और अब संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिक्रिया दी है, वह निश्चित रूप से इस बात की ओर इशारा है कि दाल में कुछ काला अवश्य है या पूरी दाल ही काली है। अमेरिका जैसा विकसित देश, जो आज भी स्वयं को अश्वेतों के साथ नस्लीय भेदभाव से मुक्त नहीं कर पाया है, जहां अश्वेतों को उनके सांविधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, बीच सड़क पर गोरे पुलिस वाले उनसे निर्ममता करते हैं, वह भारत को लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है। यह अमेरिका ही है, जिसने अपने कूटनीतिक स्वार्थों के लिए समूचे विश्व को एकध्रुवीय बना रखा है, निस्संदेह, उसका भारत के आंतरिक मामलों में दखल देना उसकी कोई न कोई कूटनीतिक चाल ही है। भारत सरकार ने उचित ही इन देशों के राजदूतों को तलब करके जरूरी निर्देश दिया है।

पारस जैन, मेरठ

सलाखों के पीछे केजरीवाल

जब अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में नए-नए उभरे थे, तब मैं शायद उन मुट्ठी भर लोगों में एक रहा होऊंगा, जिन्होंने उन पर एक दिन के लिए भी विश्वास नहीं किया। मेरी पुस्तक 'विषैला वामपंथ' में एक प्रसंग है, जब मैंने कहा था कि केजरीवाल अमेरिकी एजेंट हैं, तब एक मित्र ने आपत्ति की थी कि एक तरफ तुम कहते हो कि केजरीवाल वामपंथी हैं और दूसरी तरफ कहते हो कि वह अमेरिकी एजेंट हैं... तब मुझे पहली बार यह बात समझ में आई कि ज्यादातर लोगों को वामपंथ के वैश्विक चरित्र की समझ नहीं है। वे इसे अमेरिका और रूस की बाइनरी के रूप में देखते हैं। भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार की घटनाएं नई नहीं हैं, न ही सत्ता में बैठे लोगों का भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाना कोई बड़ी बात। मगर यह पहली बार है कि भारत के किसी भ्रष्ट नेता के लिए विदेश से आवाज उठ रही है। वास्तव में, केजरीवाल भारत की राजनीति में वैश्विक वामपंथ का सबसे बड़ा निवेश हैं। उनके लिए पश्चिमी वामपंथ के पेट में मरोड़ यूं ही नहीं उठी है। आखिरकार उनका सबसे बड़ा मोहरा काटा गया है।
केजरीवाल को महज एक अन्य भ्रष्ट नेता समझने की भूल न करें। वह एक सोशल न्यूक्लियर बम हैं, जो भारत में प्लांट किए गए हैं और जिनको निष्क्रिय करने का प्रयास किया जा रहा है।

राजीव मिश्रा, लेखक

दैनिक जागरण

सही समय की प्रतीक्षा में बहुत समय व्यर्थ हो जाता है

जेल में केजरीवाल

आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल भेज दिए गए। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उनकी कस्टडी की मांग नहीं की थी, लेकिन यह शिकायत अवश्य की थी कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और अपने फोन का पासवर्ड देने से मना करने के साथ सवालों के गोलमोल जवाब दे रहे हैं। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने की जो जरूरत जताई, उसे न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया। इसका अर्थ है कि केजरीवाल के वकील अदालत को अपनी इन दलीलों से संतुष्ट नहीं कर सके कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को गलत फंसाया गया है और उनका शराब घोटाले से कोई लेना-देना नहीं। शराब घोटाले में केजरीवाल एक ऐसे समय तिहाड़ जेल पहुंचे हैं, जब उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह पहले से ही वहां हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य मामले में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी जेल में हैं। यह आश्चर्यजनक है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बजाय जेल से ही सरकार चलाने पर जोर दे रहे हैं। यह न तो आसान है और न ही व्यावहारिक, क्योंकि मुख्यमंत्री को केवल फाइलों पर हस्ताक्षर ही नहीं करने होते। उसे कैबिनेट बैठक करने के साथ अधिकारियों को लिखित और मौखिक आदेश-निर्देश भी देने पड़ते हैं। क्या यह संभव है कि वह जेल से पत्र जारी कर सरकार चलाते रहें? शायद वह ऐसी ही कोशिश करें, लेकिन इससे दिल्ली सरकार का कामकाज प्रभावित होना तय है।

यह सही है कि संविधान इस प्रश्न पर मौन है कि क्या कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकता है, लेकिन इसका कारण यह है कि संविधान निर्माताओं ने कभी यह कल्पना ही नहीं की थी कि यदि किसी मुख्यमंत्री के जेल जाने की नौबत आएगी तो वह इस्तीफा देने के स्थान पर जेल से सरकार चलाने की कोशिश करेगा। शराब घोटाले का सच जो भी हो, अरविंद केजरीवाल का अदालत के समक्ष ईडी की ओर से किए गए इस दावे का प्रतिकार न करना हैरान करता है कि उन्होंने उसे बताया था कि विजय नायर उन्हें नहीं, बल्कि उनके मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। ध्यान रहे कि शराब घोटाले में सबसे पहली गिरफ्तारी विजय नायर की ही हुई थी। उन्हें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का विश्वास पात्र माना जाता है। ईडी की मानें तो शराब घोटाले में पैसे का लेन-देन विजय नायर के जरिये ही हुआ। पता नहीं सच क्या है, लेकिन यदि अब आतिशी और सौरभ भी ईडी की जांच के दायरे में आ जाएं तो हैरानी नहीं। ईडी का आरोप है कि शराब नीति बदलकर शराब कंपनियों से रिश्वत के रूप में जो करोड़ों रुपये लिए गए, उनका इस्तेमाल गोवा और पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए किया गया। चूंकि गोवा की चुनाव प्रभावी आतिशी थीं, इसलिए बहुत संभव है कि ईडी जल्द ही उन्हें पूछताछ के लिए तलब करे।

सतर्कता आवश्यक

झारखंड में साइबर ठगों का मनोबल कुछ इस हदतक बढ़ गया है कि अब वे शासन-प्रशासन में उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों तक को फांसने में भी बाज नहीं आ रहे हैं। रांची और लातेहार के उपायुक्त का फर्जी वाट्सएप अकाउंट बनाया जाना उनके दुस्साहस को दर्शाता है। ये अपराधी न सिर्फ तकनीकी तौर पर काफी समृद्ध हैं, बल्कि भावनात्मक तौर पर भी लोगों को फांसने में माहिर है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से पूरी तरह से अपडेट ये ठग लोगों को ठगने के नए-नए हथकंडे अपना रहे हैं। जो इन ठगों के चाल को समझने में सफल नहीं हुए, उनके बैंक खाते देखते ही देखते ये ठग खाली कर दे रहे हैं। ठगी के कुछ ऐसे मामले भी आए हैं, जिनमें बच्चों की आवाज का क्लोन तैयार कर अपराधी उनके अभिभावकों से पैसे की मांग करते हैं। झारखंड में ऐसे मामलों की संख्या एक दर्जन के करीब हो चुकी है। ऐसा भी नहीं है कि शासन-प्रशासन की नजर में ऐसे मामले नहीं आ रहे हैं।

ये साइबर ठग न सिर्फ तकनीकी तौर पर काफी समृद्ध हैं, बल्कि भावनात्मक तौर पर भी लोगों को फांसने में माहिर हैं

इससे निपटने के लिए प्रशासन बड़े पैमाने पर साइबर सतर्कता से संबंधित कार्यक्रम चला रहा है। इसके बावजूद आए दिन साइबर अपराध के नए-नए मामले सामने आ रहे हैं। आवश्यकता है कि पुलिस प्रशासन और सरकार ऐसे मामलों को और भी गंभीरता से ले और इससे संबंधित जागरूकता कार्यक्रम गांव स्तर तक पर चलाए। बेहतर तो यह होगा कि इस कार्य में पंचायत स्तर तक के जनप्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों आदि की भी सहभागिता सुनिश्चित हो। साइबर ठगों पर नकेल समेकित प्रयास से ही संभव है।

विकसित देशों से सीख ले भारत

शिवकांत शर्मा

विकसित देशों में राजनीतिक दल सरकारी नौकरियां बढ़ाने की जगह उद्योग-धंधों को बढ़ावा देकर रोजगार पैदा करने की बात करते हैं, लेकिन भारत में उलटी कहानी है

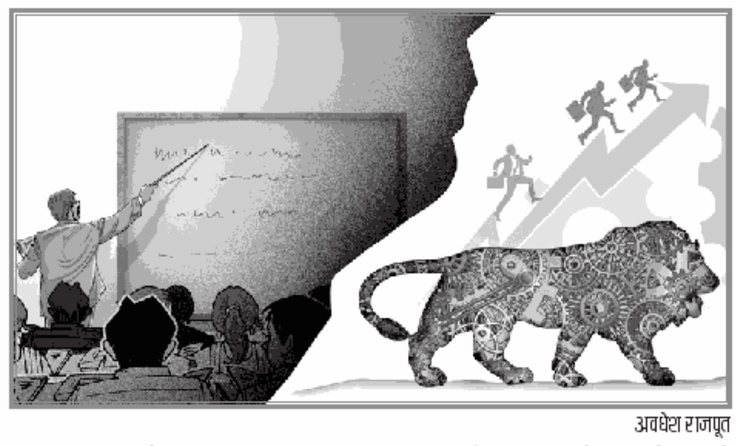

अवधेश राजपूत

अपने उत्कर्ष के दिनों में भारत एक उद्यम प्रधान और कारोबारी देश रहा है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में आए यूनानी सम्राट सेल्यूकस के राजदूत मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक 'इंडिका' में भारतीय समाज के सात वर्गों का उल्लेख किया है। इनमें अधिकांश लोग बुद्धिजीवी, किसान, कारोबारी, शिल्पकार और सैनिक वर्गों के थे। बहुत कम लोग सेवक थे और नौकरी करते थे। नौकरी को निर्भरता और पराधीनता वाला काम होने की वजह से हेय समझा जाता था। आर्थिक इतिहासकार एंगस मैडिसन ने भी विश्व अर्थव्यवस्था के इतिहास में इसकी पुष्टि की है, परंतु सदियों की गुलामी के बाद आजाद हुए भारत में परिस्थितियां पूरी तरह बदल गई हैं। आज लोगों को वेतन की सुरक्षा वाली नौकरी की पराधीनता आर्थिक असुरक्षा वाले कारोबारी उद्यम से बेहतर लगने लगी है। विशेष रूप से सरकारी नौकरी जिसे काम की सुरक्षा और पेंशन की वजह से सर्वोपरि माना जाता है। कारोबारी उद्यम को आर्थिक असुरक्षा के साथ-साथ मुनाफाखोरी के काम के रूप में देखा जाता है। इसकी बड़ी वजह हमारी उपनिवेशकालीन शिक्षा प्रणाली है जो उद्यम, सृजनशीलता और गवेषणा का कौशल एवं अनुभव देने की जगह रटने वाली पढ़ाई पर केंद्रित है। इससे शिक्षित स्नातक उद्यम, श्रम और गवेषणा से विमुख होकर दफ्तरी या मशीनी काम करने योग्य बनते हैं। उनकी उपादेयता खत्म होती जा रही है, क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) के विकास के कारण मशीनें कई कामों को अधिक कुशलता और गति से कर सकती हैं। इसीलिए गांधी जी ने अपनी 'नई तालीम' में शिक्षा को श्रम से जोड़ने की बात की थी।

शिक्षाशास्त्री अनिल सद्गोपाल की अध्यक्षता में बनी समिति की रिपोर्ट में कहा गया था कि शिक्षा को काम के साथ जोड़ना बच्चों को समाज से जोड़ने जैसा है। इससे उनमें श्रम के प्रति श्रद्धा पैदा होती है और अनुभूतिजन्य ज्ञान भी मिलता है। श्रम और बौद्धिकता के इस संतुलन को प्रयोगिक रूप देने के लिए रांची के पास नेतरहाट में एक प्रायोगिक विद्यालय खोला भी गया, लेकिन उसकी सफलता के बावजूद उसे देश भर में नहीं फैलाया गया। नतीजा सबके सामने है। इस पर बहस हो सकती है कि देश में 21-30 के बीच किस आयु वर्ग के शिक्षितों में बेरोजगारी की दर सबसे ऊंची रहती है, किंतु वास्तविकता यह है कि उत्तर प्रदेश में सिपाहियों की लगभग 60 हजार नौकरियों के लिए 50 लाख से भी अधिक स्नातकों ने आवेदन किए और परीक्षा में जाने के लिए रेलगाड़ियों में जगह तक नहीं मिली। यह भी किसी से छिपा नहीं कि मुट्ठी भर नागरिक सेवाओं के लिए कैसे लाखों स्नातक कोटा और पुणे जैसे शहरों के कोचिंग संस्थानों में जाकर कई साल तक तैयारी करते हैं। यह सब इसलिए हो रहा है, क्योंकि भारत में हर साल औसतन 15 लाख इंजीनियरों समेत करीब एक करोड़ छात्र स्नातक बनते हैं। योग्यता सर्वेक्षणों के अनुसार इनमें से केवल 25 प्रतिशत एमबीए स्नातक, 20 प्रतिशत इंजीनियर और मात्र 10 प्रतिशत सामान्य स्नातक ही काम के योग्य होते हैं। बाकी को या तो नए सिरे से प्रशिक्षित करना पड़ता है या ऐसा काम देना पड़ता है, जिसके लिए वे मानसिक रूप से तैयार नहीं होते।

काम-धंधों को लेकर सामाजिक सोच इतना नकारात्मक है कि यदि कोई नेता रोजगार के लिए उनकी मिसाल भी दे तो हंसी का पात्र बना दिया जाता है। कारोबारी उद्यम और काम-धंधों के लिए बाजार में प्रतिस्पर्धा भी कड़ी होती जा रही है। 10 करोड़ से अधिक किसान दूसरे काम-धंधों की तलाश में हैं। दस्तकारी और कारीगरी जैसे काम-धंधों की पुश्तैनी परंपरा या तो टूट चुकी है या मशीनों के माल के सामने टिक नहीं पाती है। इन सभी को रोजगार के लिए प्रशिक्षण, पूंजी और बाजार की जरूरत है। बेरोजगारी का मुद्दा हर चुनाव में चर्चा पाता है। इस बार कांग्रेस ने 30 लाख सरकारी नौकरियां, हर स्नातक और डिप्लोमा धारक को एक लाख रुपये प्रति वर्ष का भत्ता एवं प्रशिक्षण और युवाओं को जिला स्तर पर स्टार्टअप फंड देने की घोषणा को युवा न्याय गारंटी का नाम दिया है। भाजपा समेत अन्य दल भी आने वाले दिनों में ऐसी ही घोषणाएं करेंगे, लेकिन शिक्षा प्रणाली को कारोबारी उद्यम और अनुसंधानमुखी बना समस्या के समाधान की बात शायद ही कोई करे।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत में रोजगार का मतलब नौकरी ही माना जाता है। जब भी कोई दल रोजगार की बात करता है तो सरकारी नौकरियां बढ़ाने या भरने की बात ही करता है। उद्योग-धंधे, कारोबार और काम-धंधे बढ़ाकर रोजगार सृजन की बात कम होती है। यूरोप, अमेरिका और जापान में ऐसा नहीं होता। वहां पार्टियां सरकारी नौकरियां बढ़ाने की जगह उन्हें घटाकर खर्च बचाने और बचे पैसों से उद्योग और कारोबार को बढ़ावा देकर रोजगार पैदा करने की बात करती हैं। सरकारी नौकरियों को रोजगार नहीं, बल्कि रोजगार टैक्स के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उनका वेतन टैक्स के पैसे से दिया जाता है। नौकरियों से आज तक कोई देश उन्नत नहीं हुआ। उन्नति उद्योग-धंधों से ही होती है। इसलिए विकसित देशों में पार्टियां सरकारी खर्च घटाने और उद्योगों-कारोबारों को फैलाकर आमदनी बढ़ाने की बात करती हैं।

असली रोजगार सृजन उद्योग और कारोबार ही कर सकते हैं। वे रोजगार भी देते हैं और टैक्स भी। कांग्रेस की 30 लाख सरकारी नौकरियां देने की घोषणा को ही लें। इस समय केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या लगभग 33 लाख है, जिनके वेतन पर 3.25 लाख करोड़ खर्च होता है। यदि इनमें 30 लाख और जोड़ दिए गए तो वेतन पर होने वाला खर्च तीन लाख करोड़ और बढ़ जाएगा। इसी पैसे को यदि उद्योग-धंधों को बढ़ावा देने पर खर्च किया जाए तो रोजगार भी बढ़ सकते हैं और टैक्स की आमद भी। लोगों को बिना काम किए भत्ते और मुफ्त की बिजली देना और सरकारी नौकरियां भरते जाना सामाजिक न्याय नहीं, बल्कि उसके नाम पर किया जाने वाला अनुत्पादक खर्च है। सरकार का दायित्व करदाता की पाई-पाई को उत्पादक कामों में लगाना है, जिससे अर्थव्यवस्था का विकास हो। वोटों के लिए अनुत्पादक फिजूलखर्ची करना नहीं। मतदाताओं को यह बात समझकर और स्वावलंबी बनकर आर्थिक रूप से जिम्मेदार प्रतिनिधियों के चुनाव को प्राथमिकता देनी होगी।

(लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं)

response@jagran.com

सच के साथ खड़ा होता मुस्लिम समाज

रमिश सिद्धैकी

इस बार मुस्लिम समाज उन नेताओं के बहकावे में नहीं आया, जो सीएए को लेकर उसे उकसा रहे हैं

इस बार बेअसर रहा सीएए का विरोध। फाइल

केंद्र सरकार की ओर से नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के नियमों को अधिसूचित करने के साथ ही उस पर अमल की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हालांकि कुछ नेता इसका विरोध करने में लगे हुए हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने बीते रविवार को एक रैली में फिर से यही दोहराया कि यह कानून देश के वैध नागरिकों को विदेशी बनाने की एक साजिश है। मुसलमानों को बरगलाने के लिए इसी तरह की आधारहीन बातें तब की गईं थी, जब यह कानून संसद से पारित हुआ था। कुछ राज्य सरकारों ने तो इस कानून के खिलाफ अपनी विधानसभा में प्रस्ताव तक पारित किए थे। वह भी तब जबकि नागरिकता के विषय का राज्यों से कोई लेनादेना तक नहीं। उस समय एक ऐसा माहौल बनाया गया कि तमाम लोगों और संगठनों ने सड़कों पर उतरकर इस कानून का उग्र विरोध किया था। इनमें मुसलमानों की अच्छी-खासी भागीदारी थी। इस बार वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा तो इसका यही मतलब है कि पहले मुस्लिम समाज का एक तबका दुष्प्रचार के चलते गुमराह हो गया था।

यह महत्वपूर्ण है कि इस बार मुस्लिम समाज में नागरिकता कानून का कोई खास विरोध देखने को नहीं मिला। इसका कारण यह है कि मुस्लिम समाज को यह सच समझ आ गया कि कैसे कुछ दल और नेता उसे मात्र एक वोट बैंक के रूप में देखते हैं और उसे बरगलाते हैं। सीएए का संबंध केवल केंद्र सरकार से है, लेकिन अनेक राज्य सरकारों ने कहा कि वे इस कानून को अपने राज्यों में लागू नहीं होने देंगे। ऐसे बयानों का मकसद केवल मुस्लिम समाज को यह दिखाना है कि वे तो उनके साथ हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनके खिलाफ है। सीएए पर मुसलमानों को उकसाने की कोशिश कर रहे नेता यह जानते हैं कि वे केवल लफ्फाजी कर रहे हैं। वे यह भी जानते हैं कि इस कानून का संबंध भारत के मुसलमानों तो क्या, देश के किसी भी नागरिक से नहीं है। आजादी के बाद से भारतीय मुस्लिम समाज को कई बार इसी तरह झूठ का सहारा लेकर डराया गया और उसे सड़कों पर उतारा गया, फिर चाहे वह शाहबानो का मामला हो या सीएए का मसला। इससे मुस्लिम समाज को कोई लाभ नहीं मिला। लाभ मिला तो चंद मजहबी और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेताओं को। ये वे नेता हैं, जिन्हें मुस्लिम समाज के हितों से कोई लगाव नहीं।

यह शुभ संकेत है कि आज की युवा मुस्लिम पीढ़ी यह समझने लगी है कि मुस्लिम समाज को बरगलाने वाले मजहबी और सियासी नेता उनके समाज को केवल वोट बैंक के रूप में देखते हैं और वे उनके सच्चे हितैषी नहीं। आज जब संपूर्ण विश्व भारत की ओर देख रहा है, तब भारत की मुस्लिम आबादी, जो सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी है और यहां तक कि उनकी संख्या यहां कई इस्लामी देशों से भी अधिक है, को हर मुद्दे पर सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। अज्ञानता किसी भी समाज की सबसे बड़ी शत्रु होती है। इसी अज्ञानता का लाभ उठाकर कुछ नेता मुस्लिम समाज को गुमराह करते हैं। ऐसे लोग सफल न होने पाएं, यह मुस्लिम समाज को सुनिश्चित करना होगा। मुस्लिम समाज को इससे अवगत होना चाहिए कि नागरिकता कानून में 2019 में जो संशोधन किए गए, उसके तहत केवल तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। इस कानून के मुताबिक 31 दिसंबर, 2014 या उससे पहले भारत आ चुके उक्त तीन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जा सकेगी। नागरिकता संशोधन कानून, 2019 से पहले किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था, लेकिन अब यह समय अवधि 11 से घटाकर पांच साल कर दी गई है।

मुस्लिम समाज को यह भी समझना होगा कि नागरिकता संशोधन कानून नागरिकता देने का कानून है, न कि किसी की नागरिकता छीनने का। इस कानून से किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं जाने वाली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए में पड़ोसी देश के मुसलमानों को शामिल न करने की भी वजह बताई है और यह भी स्पष्ट किया है कि इन देशों के मुस्लिम भी भारत की नागरिकता ले सकते हैं। मुस्लिम समाज इससे अनजान नहीं हो सकता कि जब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश इस्लामिक देश हैं तो फिर वहां के मुसलमान धार्मिक अल्पसंख्यक कैसे हो सकते हैं? यह कैसे संभव है?

वास्तविकता यही है कि इन तीनों पड़ोसी देशों में उत्पीड़न के शिकार लोगों के पास भारत भाग आने के अलावा यदि कोई विकल्प है तो यही कि वे या तो मारे जाएं या फिर अपना धर्म-पंथ त्याग दें। इसी कारण जहां अफगानिस्तान में गैर-मुस्लिम गिनती के बचे हैं, वहीं बांग्लादेश, पाकिस्तान में उनकी आबादी उत्पीड़न के कारण तेजी से कम होती जा रही है। विश्व की अनेक संस्थाओं द्वारा प्रकाशित रपटों में यह बात सामने आ चुकी है कि इन देशों में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है और उनका सम्मान के साथ जीना मुश्किल है। इन देशों के अल्पसंख्यक आसानी से न तो अमेरिका जा सकते हैं, न यूरोप और न ही किसी अन्य देश। उनके पास सबसे आसान विकल्प भारत आना ही है। वे भारत की ओर उम्मीद से न देखें तो किसकी ओर देखें? सीएए अपनी तरह का दुनिया का पहला कानून नहीं है। पश्चिम के देशों और यहां तक कि अमेरिका ने भी मजहब और संस्कृति के आधार पर नागरिकता देने के कानून बना रखे हैं। सीएए का विरोध न सिर्फ अनैतिक है, बल्कि भारतीय सोच के विरुद्ध भी है।

(लेखक इस्लामी मामलों के जानकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

कर्म बंधन

प्रायः लोगों से सुनने में आता है कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस पर यही प्रश्न उठता है कि इस तरह तो सभी प्रकार के शुभ या अशुभ कर्म ईश्वर के अधीन हैं। हम तो कठपुतलियों की भांति मात्र अभिनय कर देते हैं, फिर फल हमारे हिस्से कैसे आता है? वस्तुतः समस्त कर्म प्रकृति के अधीन होकर किए जाते हैं। प्रकृति से तात्पर्य है 'स्वभाव' जिसे जीव ने स्वयं रचा है। ईश्वर न तो किसी से शुभ कर्म करवा कर उसे उन्नति देते हैं, न ही कोई अशुभ कर्म करवा कर उसे अवनति देते हैं। वह पूर्णतः निःस्पृह है।

जब तक स्वभाव शुद्ध नहीं होता, तब तक जीव प्रकृति के अधीन ही रहता है। प्रारब्ध के अनुसार कर्म का फल भुगत कर ही शुद्ध हुआ जा सकता है। इसमें अपनी इच्छा या अनिच्छा का कोई अर्थ नहीं है। यह अपरिहार्य है। ज्ञानी व्यक्ति भी बिना कर्मफलों को भोगे मुक्त नहीं हो सकता। किसी को परसंताप में सुख मिल रहा है, वह उसकी प्रकृति है। इस अशुभ कर्म के फल से वह छूट नहीं पाएगा। किसी को उस यंत्रणा को झेलकर असीमित वेदना मिल रही है, यह उसका प्रारब्ध हो सकता है। ईश्वर अपनी सभी संतानों को शुद्ध करना चाहते हैं। वे शासक भी हैं, नियामक भी हैं। यदि इस जन्म में हमारे हिस्से दुख भोगना लिखा है, तो हमें अच्छे लोग क्यों मिलेंगे? मनुष्य जिस प्रकार से अपने शुभ या अशुभ कर्मों का फल भोग सके, वैसी ही परिस्थिति और बुद्धि बन जाती है।

सूर्य की ऊर्जा से पृथ्वी पर समस्त क्रियाकलाप संपादित होते हैं, परंतु इन कार्यों से सूर्य निर्लिप्त हैं। उसी प्रकार मानव शरीर से होने वाले पाप-पुण्य से ईश्वर का कोई भी संबंध नहीं। अपने जीवन के पूर्वार्ध में किए गए कर्मों के फल जीवन के उत्तरार्ध में दिखने आरंभ हो जाते हैं। बीते जन्मों में स्वयं के किए कर्म को देखने के लिए आज मिल रहे फल को समझना होगा। यदि इसका सूत्र मिल गया तो कर्मों की दिशा सुधारने की राह मिल जाएगी।

ट्विंकल तोमर सिंह

आटिज्म पीड़ित बच्चों का समझें दर्द

सुनीता मिश्रा

आटिज्म बच्चों को होने वाली एक मानसिक बीमारी है, जिसमें बच्चे अपनेआप को सामाजिक रूप से अलग-थलग कर लेते हैं

हर साल दो अप्रैल को पूरी दुनिया में विश्व आटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आटिज्म को मानसिक रोग, स्वलीनता और स्वपरायणता के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2007 में इसकी शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य समूचे विश्व में आटिज्म के प्रति जागरूकता पैदा करना और इससे पीड़ित बच्चों के जीवन में सुधार लाने के लिए कदम उठाना है। प्रत्येक वर्ष इस खास दिन को एक विशिष्ट विषय चुनकर मनाया जाता है। वर्ष 2024 में विश्व आटिज्म जागरूकता दिवस का विषय 'कलर' यानी रंग है। बच्चों को चमकीले रंग आकर्षित करते हैं। इसलिए लाल, पीला, नीला, हरा का उपयोग करके उन्हें अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। रंग के माध्यम से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं। नीला रंग आटिज्म का प्रतीक माना गया है।

आटिज्म बच्चों को होने वाली एक मानसिक बीमारी है, जिसमें बच्चे अपनेआप को सामाजिक रूप से अलग-थलग कर लेते हैं। वे किसी से घुलते मिलते भी नहीं हैं और दूसरों से बात करने से भी कतराते हैं। यह बीमारी बच्चे के मानसिक विकास को रोक देती है, लेकिन कुछ मामलों में ये अद्भुत प्रतिभा वाले भी होते हैं। एक शोध के मुताबिक, लगभग 10 प्रतिशत आटिज्म से पीड़ित बच्चे किसी खास प्रतिभा में काफी अच्छे होते हैं, जैसे गणितीय गणना, संगीत, चित्रकारी आदि। ध्यान दें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम (तंत्रिका प्रणाली) को नुकसान पहुंचने से यह समस्या पैदा होती है। गर्भवती महिला के पेट पर लगी चोट का असर उसके गर्भ में विकसित होते भ्रूण के नर्वस सिस्टम पर पड़ने की आशंका अधिक होती है। इसके अलावा गर्भावस्था में पौष्टिक भोजन नहीं लेने या नशा करने से भी बच्चों का नर्वस सिस्टम दुष्प्रभावित हो सकता है। आनुवंशिक और पर्यावरण संबंधी कई कारण भी इस बीमारी के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दुनिया में 100 में से एक बच्चा आटिज्म से पीड़ित होता है। इसके शुरुआती लक्षण 12 से 13 माह के बच्चों में नजर आने लगते हैं। इसके लक्षणों में शब्दों को बार-बार बोलना, बात करने से घबराना और अकेले रहना पसंद करना इत्यादि शामिल हैं।

अभिभावक इस बीमारी के लक्षणों को पहचान कर खुद से भी बच्चे को इस समस्या से उबरने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए बच्चे को खेलने के लिए प्रोत्साहित करें। लोगों से घुलना मिलना सिखाएं। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिवार के सदस्यों को उनके साथ बहुत ही सकारात्मक व्यवहार अपनाना चाहिए। साथ ही असामान्य स्थिति में डाक्टरों से परामर्श लेना चाहिए।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

स्वच्छ हवा-पानी की चुनौती

पर्यावरणविद् अनिल प्रकाश जोशी ने 'स्वच्छ हवा-पानी सबसे बड़ी चुनौती' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में सारगर्भित टिप्पणी की है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए समवेत प्रयास समय की आवश्यकता हो चले हैं। स्वच्छ हवा-पानी सुनिश्चित करना केवल सरकारों का ही दायित्व नहीं, अपितु यह नागरिकों के कर्तव्य पालन से भी जुड़ा है। कृषि कार्य हों या कल-कारखाने, सभी प्रदूषण को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इस समय कंस्ट्रक्शन कार्य का हवा को प्रदूषित करने में बड़ा योगदान हो चला है। वाहनों का प्रदूषण भी ऐसा ही एक मुद्दा है। यदि इसमें नागरिक अपने स्तर पर थोड़ी सी भी सक्रियता दिखाएं तो अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अच्छी बात है कि लेखक महोदय ने केवल समस्या को रेखांकित ही नहीं किया, अपितु उसके समाधान की दिशा में कुछ उपयोगी सुझाव भी दिए हैं।

योगराज, खरड़ (पंजाब)

भटक गए आंदोलनकारी

उमेश चतुर्वेदी के आलेख 'निराश करती आंदोलन से उपजी राजनीति' से उभरने वाले प्रश्नों के प्रति आंदोलन की तपिश से निकले केजरीवाल सहित उन सभी राजनेताओं की जबावदेही बनती है, जो लक्ष्य हासिल करके उस रास्ते से भटक गए जिसको लोकनायक जयप्रकाश और अन्ना हजारे ने देश की भ्रष्टाचार मुक्त राजनीतिक व्यवस्था के लिए तय किया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में देशव्यापी स्वतंत्रता आंदोलन चलाकर आजादी का बड़ा लक्ष्य तो हासिल कर लिया गया, किंतु इस आंदोलन से निकले कांग्रेसी नेता गांधी के आदर्शों से भटक गए। 1975 में आपातकाल की विभीषिका से उभरे जेपी आंदोलन ने देश की सत्ता को तो बदल दिया, लेकिन इस आंदोलन के सेनानी देश की राजनीतिक व्यवस्था को बदलने में नाकाम रहे। जिससे कांग्रेस को पुनः सत्ता में आने का अवसर मिल गया। 2004 से 2014 तक लगातार सत्ता में रहने वाली कांग्रेस के शासन में चरम पर पहुंच चुके आर्थिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में जो आंदोलन खड़ा हुआ उससे निकलने वाली केजरीवाल टीम ने आम आदमी पार्टी का गठन करके देश को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की हुंकार भरी थी, लेकिन अब उसकी भी कलई खुलकर सामने आने लगी है। देश की शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्था में समाए भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने की बात तो हर कोई करता है, लेकिन वह स्वयं कब भ्रष्टाचारी बन गया, यह उसे खुद नहीं मालूम होता। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए घोषित आय से अधिक आय की जांच के कार्य को चुनिंदा न बनाकर एक अपरिहार्य व्यवस्था के रूप में संचालित करने की जरूरत है। क्योंकि आज अपवाद को छोड़कर हर खासोआम किसी न किसी तरह के भ्रष्टाचार में संलिप्त है। इसलिए भ्रष्ट तरीकों से संपत्ति अर्जित करने वाले हर भ्रष्टाचारी पर ईडी, सीबीआइ और आयकर विभाग का शिकंजा कसा जाना चाहिए। जब तक इस तरह की समान और निष्पक्ष व्यवस्था लागू नहीं होगी तब तक भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ी जाने वाली हर लड़ाई अधूरी ही रहेगी।

डा. बीपी पांडेय, अलीगढ़

यह कैसा गठबंधन?

दिल्ली के रामलीला मैदान में आइएनडीआइए के प्रमुख घटक दलों के नेताओं का एक मंच पर जमावड़ा मजबूत और बाहरी एकता को जरूर दिखाता नजर आया, लेकिन राजनीतिक भाषण प्रतियोगिता से पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मंच पर सजी फोटो को उतरवा देना कहीं न कहीं असमंजस और गंभीर राजनीतिक सवाल खड़े करता हुआ भी जरूर दिखाई दिया। सबके भाषण में लोकसभा चुनाव के लिए कोई राजनीतिक एजेंडा, उद्देश्य या फिर भविष्य की चुनावी रूपरेखा का अभाव नजर आया। आइएनडीआइए के नेताओं का भाषण मात्र जांच एजेंसियों एवं मोदी अंधविरोध की राजनीति तक सीमित रहा।

दीपक गौतम, सोनीपत

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए; नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

संपादकीय जागरण

(8) मंगलवार, 2 अप्रैल, 2024: चैत्र कृष्ण - 8 वि. 2080

सही समय की प्रतीक्षा में बहुत समय व्यर्थ हो जाता है

जेल में केजरीवाल

आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल भेज दिए गए। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उनकी कस्टडी की मांग नहीं की थी, लेकिन यह शिकायत अवश्य की थी कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और अपने फोन का पासवर्ड देने से मना करने के साथ सवालों के गोलमोल जवाब दे रहे हैं। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने की जो जरूरत जताई, उसे न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया। इसका अर्थ है कि केजरीवाल के वकील अदालत को अपनी इन दलीलों से संतुष्ट नहीं कर सके कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को गलत फंसाया गया है और उनका शराब घोटाले से कोई लेना-देना नहीं। शराब घोटाले में केजरीवाल एक ऐसे समय तिहाड़ जेल पहुंचे हैं, जब उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह पहले से ही वहां हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य मामले में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी जेल में हैं। यह आश्चर्यजनक है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बजाय जेल से ही सरकार चलाने पर जोर दे रहे हैं। यह न तो आसान है और न ही व्यावहारिक, क्योंकि मुख्यमंत्री को केवल फाइलों पर हस्ताक्षर ही नहीं करने होते। उसे कैबिनेट बैठक करने के साथ अधिकारियों को लिखित और मौखिक आदेश-निर्देश भी देने पड़ते हैं। क्या यह संभव है कि वह जेल से पत्र जारी कर सरकार चलाते रहें? शायद वह ऐसी ही कोशिश करें, लेकिन इससे दिल्ली सरकार का कामकाज प्रभावित होना तय है। यह सही है कि संविधान इस प्रश्न पर मौन है कि क्या कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकता है, लेकिन इसका कारण यह है कि संविधान निर्माताओं ने कभी यह कल्पना ही नहीं की थी कि यदि किसी मुख्यमंत्री के जेल जाने की नौबत आएगी तो वह इस्तीफा देने के स्थान पर जेल से सरकार चलाने की कोशिश करेगा। शराब घोटाले का सच जो भी हो, अरविंद केजरीवाल का अदालत के समक्ष ईडी की ओर से किए गए इस दावे का प्रतिकार न करना हैरान करता है कि उन्होंने उसे बताया था कि विजय नायर उन्हें नहीं, बल्कि उनके मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। ध्यान रहे कि शराब घोटाले में सबसे पहली गिरफ्तारी विजय नायर की ही हुई थी। उन्हें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का विश्वास पात्र माना जाता है। ईडी की मानें तो शराब घोटाले में पैसे का लेन-देन विजय नायर के जरिये ही हुआ। पता नहीं सच क्या है, लेकिन यदि अब आतिशी और सौरभ भी ईडी की जांच के दायरे में आ जाएं तो हैरानी नहीं। ईडी का आरोप है कि शराब नीति बदलकर शराब कंपनियों से रिश्वत के रूप में जो करोड़ों रुपये लिए गए, उनका इस्तेमाल गोवा और पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए किया गया। चूंकि गोवा की चुनाव प्रभारी आतिशी थीं, इसलिए बहुत संभव है कि ईडी जल्द ही उन्हें पूछताछ के लिए तलब करे।

शर्मनाक घटना

पटना जिले के पितवास थाने की घटना वाकई शर्मसार करने वाली है। हालांकि थानेदार समेत चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर पुलिस प्रशासन ने यह संदेश जरूर दिया है कि पुलिस का चेहरा दागदार करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। अब शायद इस कुकृत्य में शामिल पुलिसकर्मियों को भी समझ में आ रहा होगा कि थाने में बैठे लोग ही सर्वेसर्वा नहीं होते। यहां एक सिस्टम काम करता है। इस सिस्टम में किसी की मनमानी नहीं चल सकती। सबसे गंभीर बात तो यह कि एक 11 वर्षीय बच्ची की अस्मत लूटने वालों को संरक्षण देने के लिए थाने के कारिंदे एक दलाल के इशारे पर काम कर रहे थे। न तो उन्हें अपनी शपथ का ध्यान रहा और न ही कर्तव्य का। दूसरा पक्ष यह कि उस पिता की क्या मनोदशा होगी, जो अपनी पीड़ित बच्ची को न्याय दिलाना चाहता है, लेकिन इस प्रक्रिया की पहली कड़ी में बैठे भ्रष्ट लोगों ने उससे जबरन मनमाफिक एफआइआर लिखवाई। सवाल उठता है कि क्या एक आम आदमी आज भी दबंगों और पैसे के बल पर व्यवस्था को धता बताने वालों के रहमोकरम पर है? सुशासन के लिए ऐसी नौबत बर्दाश्त से बाहर है। इस प्रकरण की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। साथ ही दोषी पाए जाने पर ऐसे पुलिसकर्मियों पर ऐसी कार्रवाई हो, जो मिसाल बने। दानापुर में भी एक मामला ऐसा आया है, जो पुलिस व्यवस्था को चुनौती देता है। छेड़खानी के आरोप में जेल से छूटे आरोपित ने लड़की के पिता को गोली मार दी। पिता उपचाररत हैं। कल्पना की जा सकती है कि उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, जिसने अपनी बच्ची के साथ हो रही गलत हरकत के खिलाफ आवाज उठाई। इस मामले में भी पुलिस को कड़ी कार्रवाई कर मिसाल पेश करनी चाहिए।

लोगों में पुलिस के प्रति भरोसा बढ़ाने के लिए जरूरी है कि दोषी पुलिसकर्मियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या विपक्षी दल साझा रैली के माध्यम से अपनी अपेक्षा के अनुरूप राजनीतिक संदेश देने में सफल हो सके?

आज का सवाल
क्या अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने के बजाय इस्तीफा देना चाहिए?

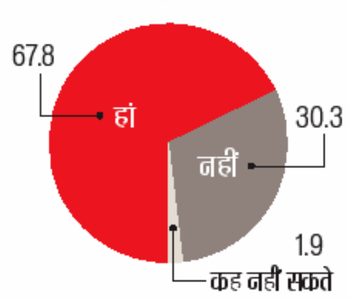

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

विकसित देशों से सीख ले भारत

शिक्कांत शर्मा

विकसित देशों में राजनीतिक दल सरकारी नौकरियां बढ़ाने की जगह उद्योग-धंधों को बढ़ावा देकर रोजगार पैदा करने की बात करते हैं, लेकिन भारत में उलटी कहानी है

अपने उत्कर्ष के दिनों में भारत एक उद्यम प्रधान और कारोबारी देश रहा है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में आए यूनानी सम्राट सेल्यूकस के राजदूत मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक 'इंडिका' में भारतीय समाज के सात वर्गों का उल्लेख किया है। इनमें अधिकांश लोग बुद्धिजीवी, किसान, कारोबारी, शिल्पकार और सैनिक वर्गों के थे। बहुत कम लोग सेवक थे और नौकरी करते थे। नौकरी को निर्भरता और पराधीनता वाला काम होने की वजह से हेय समझा जाता था। आर्थिक इतिहासकार एंगस मैडिसन ने भी विश्व अर्थव्यवस्था के इतिहास में इसकी पुष्टि की है, परंतु सदियों की गुलामी के बाद आजाद हुए भारत में परिस्थितियां पूरी तरह बदल गई हैं। आज लोगों को वेतन की सुरक्षा वाली नौकरी की पराधीनता आर्थिक असुरक्षा वाले कारोबारी उद्यम से बेहतर लगने लगी है। विशेष रूप से सरकारी नौकरी जिसे काम की सुरक्षा और पेंशन की वजह से सर्वोपरि माना जाता है। कारोबारी उद्यम को आर्थिक असुरक्षा के साथ-साथ मुनाफाखोरी के काम के रूप में देखा जाता है। इसकी बड़ी वजह हमारी उपनिवेशकालीन शिक्षा प्रणाली है जो उद्यम, सृजनशीलता और गवेषणा का कौशल एवं अनुभव देने की जगह रटने वाली पढ़ाई पर केंद्रित है। इससे शिक्षित स्नातक उद्यम, श्रम और गवेषणा से विमुख होकर दफ्तरी या मशीनी काम करने योग्य बनते हैं। उनकी उपादेयता खत्म होती जा रही है, क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) के विकास के कारण मशीनें कई कामों को अधिक कुशलता और गति से कर सकती हैं। इसीलिए गांधी जी ने अपनी 'नई तालीम' में शिक्षा को श्रम से जोड़ने की बात की थी।

शिक्षाशास्त्री अनिल सद्गोपाल की अध्यक्षता में बनी समिति की रिपोर्ट में कहा गया था कि शिक्षा को काम के साथ जोड़ना बच्चों को समाज से जोड़ने जैसा है। इससे उनमें श्रम के प्रति श्रद्धा पैदा होती है और अनुभूतिजन्य ज्ञान भी मिलता है। श्रम और बौद्धिकता के इस संतुलन को प्रयोगिक रूप देने के लिए रांची के पास नेतरहाट में एक प्रायोगिक विद्यालय खोला भी गया, लेकिन उसकी सफलता के बावजूद उसे देश भर में नहीं फैलाया गया। नतीजा सबके सामने है। इस पर बहस हो सकती है कि देश में 21-30 के बीच किस आयु वर्ग के शिक्षितों में बेरोजगारी की दर सबसे ऊंची रहती है, किंतु वास्तविकता यह है कि उत्तर प्रदेश में सिपाहियों की लगभग 60 हजार नौकरियों के लिए 50 लाख से भी अधिक स्नातकों ने आवेदन किए और परीक्षा में जाने के लिए रेलगाड़ियों में जगह तक नहीं मिली। यह भी किसी से छिपा नहीं कि मुट्ठी भर नागरिक सेवाओं के लिए कैसे लाखों स्नातक कोटा और पुणे जैसे शहरों के

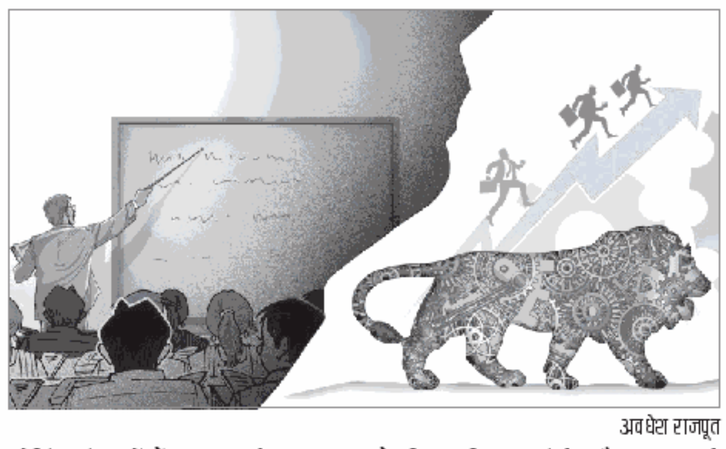

अवधेश राजपूत

कोचिंग संस्थानों में जाकर कई साल तक तैयारी करते हैं। यह सब इसलिए हो रहा है, क्योंकि भारत में हर साल औसतन 15 लाख इंजीनियरों समेत करीब एक करोड़ छात्र स्नातक बनते हैं। योग्यता सर्वेक्षणों के अनुसार इनमें से केवल 25 प्रतिशत एमबीए स्नातक, 20 प्रतिशत इंजीनियर और मात्र 10 प्रतिशत सामान्य स्नातक ही काम के योग्य होते हैं। बाकी को या तो नए सिरे से प्रशिक्षित करना पड़ता है या ऐसा काम देना पड़ता है, जिसके लिए वे मानसिक रूप से तैयार नहीं होते।

काम-धंधों को लेकर सामाजिक सोच इतना नकारात्मक है कि यदि कोई नेता रोजगार के लिए उनकी मिसाल भी दे तो हंसी का पात्र बना दिया जाता है। कारोबारी उद्यम और काम-धंधों के लिए बाजार में प्रतिस्पर्धा भी कड़ी होती जा रही है। छोटी जोत की समस्या के कारण 10 करोड़ से अधिक किसान दूसरे काम-धंधों की तलाश में हैं। दस्तकारी और कारीगरी जैसे काम-धंधों की पुश्तैनी परंपरा या तो टूट चुकी है या मशीनों के माल के सामने टिक नहीं पाती है। इन सभी को रोजगार के लिए प्रशिक्षण, पूंजी और बाजार की जरूरत है। इसीलिए बेरोजगारी का मुद्दा हर चुनाव में चर्चा पाता है। इस बार के आम चुनाव में भी कांग्रेस ने 30 लाख सरकारी नौकरियां, हर स्नातक और डिप्लोमा धारक को एक लाख रुपये प्रति वर्ष का भत्ता एवं प्रशिक्षण और युवाओं को जिला स्तर पर स्टार्टअप फंड देने की घोषणा को युवा न्याय गारंटी का नाम दिया है। भाजपा समेत अन्य दल भी आने वाले दिनों में ऐसी ही घोषणाएं करेंगे, लेकिन शिक्षा प्रणाली को कारोबारी उद्यम और अनुसंधानमुखी बनाकर समस्या के मूल समाधान की बात शायद ही कोई करे।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत में रोजगार का मतलब नौकरी ही माना जाता है। जब भी कोई दल रोजगार की बात करता है तो सरकारी नौकरियां बढ़ाने या भरने की बात ही करता है। उद्योग-धंधे, कारोबार और काम-धंधे बढ़ाकर रोजगार सृजन की बात कम होती है। यूरोप, अमेरिका और जापान में ऐसा नहीं होता। वहां पार्टियां सरकारी नौकरियां बढ़ाने की जगह उन्हें घटाकर खर्च बचाने और बचे पैसों से उद्योग और कारोबार को बढ़ावा देकर रोजगार पैदा करने की बात करती हैं। सरकारी नौकरियों को रोजगार नहीं, बल्कि रोजगार टैक्स के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उनका वेतन टैक्स के पैसे से दिया जाता है। नौकरियों से आज तक कोई देश उन्नत नहीं हुआ। उन्नति उद्योग-धंधों से ही होती है। इसलिए विकसित देशों में पार्टियां सरकारी खर्च घटाने और उद्योगों-कारोबारों को फैलाकर आमदनी बढ़ाने की बात करती हैं।

असली रोजगार सृजन उद्योग और कारोबार ही कर सकते हैं। वे रोजगार भी देते हैं और टैक्स भी। कांग्रेस की 30 लाख सरकारी नौकरियां देने की घोषणा को ही लें। इस समय केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या लगभग 33 लाख है, जिनके वेतन पर 3.25 लाख करोड़ खर्च होता है। यदि इनमें 30 लाख और जोड़ दिए गए तो वेतन पर होने वाला खर्च तीन लाख करोड़ और बढ़ जाएगा। इसी पैसे को यदि उद्योग-धंधों को बढ़ावा देने पर खर्च किया जाए तो रोजगार भी बढ़ सकते हैं और टैक्स की आमद भी। लोगों को बिना काम किए भत्ते और मुफ्त की बिजली देना और सरकारी नौकरियां भरते जाना सामाजिक न्याय नहीं, बल्कि उसके नाम पर किया जाने वाला अनुत्पादक खर्च है। सरकार का दायित्व करदाता की पाई-पाई को उत्पादक कामों में लगाना है, जिससे अर्थव्यवस्था का विकास हो। वोटों के लिए अनुत्पादक फिजूलखर्ची करना नहीं। मतदाताओं को यह बात समझकर और स्वावलंबी बनकर आर्थिक रूप से जिम्मेदार प्रतिनिधियों के चुनाव को प्राथमिकता देनी होगी।

(लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं)

response@jagran.com

सच के साथ खड़ा होता मुस्लिम समाज

केंद्र सरकार की ओर से नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के नियमों को अधिसूचित करने के साथ ही उस पर अमल की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हालांकि कुछ नेता इसका विरोध करने में लगे हुए हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने बीते रविवार को एक रैली में फिर से यही दोहराया कि यह कानून देश के वैध नागरिकों को विदेशी बनाने की एक साजिश है। मुसलमानों को बरगलाने के लिए इसी तरह की आधारहीन बातें तब की गईं थी, जब यह कानून संसद से पारित हुआ था। कुछ राज्य सरकारों ने तो इस कानून के खिलाफ अपनी विधानसभा में प्रस्ताव तक पारित किए थे। वह भी तब जबकि नागरिकता के विषय का राज्यों से कोई लेनादेना तक नहीं। उस समय एक ऐसा माहौल बनाया गया कि तमाम लोगों और संगठनों ने सड़कों पर उतरकर इस कानून का उग्र विरोध किया था। इनमें मुसलमानों की अच्छी खासी भागीदारी थी। इस बार वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा तो इसका यही मतलब है कि पहले मुस्लिम समाज का एक तबका दुष्प्रचार के चलते गुमराह हो गया था।

यह महत्वपूर्ण है कि इस बार मुस्लिम समाज में नागरिकता कानून का कोई खास विरोध देखने को नहीं मिला। इसका कारण यह है कि मुस्लिम समाज को यह सच समझ आ गया कि कैसे कुछ दल और नेता उसे मात्र एक वोट बैंक के रूप में देखते हैं और उसे बरगलाते हैं। सीएए का संबंध केवल केंद्र सरकार से है, लेकिन अनेक राज्य सरकारों ने कहा कि वे इस कानून को अपने राज्यों में लागू नहीं होने देंगे। ऐसे बयानों का मकसद केवल मुस्लिम समाज को यह दिखाना है कि वे तो उनके साथ हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनके खिलाफ है। सीएए पर मुसलमानों को उकसाने की कोशिश कर रहे नेता यह जानते हैं कि वे केवल लफ्फाजी कर रहे हैं। वे यह भी जानते हैं कि इस कानून का संबंध भारत के मुसलमानों तो क्या, देश के किसी भी नागरिक से नहीं है। आजादी के बाद से भारतीय मुस्लिम समाज को कई बार इसी तरह झूठ का सहारा लेकर डराया गया और उसे सड़कों पर उतारा गया, फिर चाहे वह शाहबानो का मामला हो या सीएए का मसला। इससे मुस्लिम समाज को कोई लाभ नहीं मिला। लाभ मिला तो चंद मजहबी और मुस्लिम

रामिश सिद्दीकी

इस बार मुस्लिम समाज उन नेताओं के बहकावे में नहीं आया, जो सीएए को लेकर उसे उकसा रहे हैं

इस बार बेअसर रहा सीएए का विरोध ● फाइल

वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेताओं को। ये वे नेता हैं, जिन्हें मुस्लिम समाज के हितों से कोई लगाव नहीं।

यह शुभ संकेत है कि आज की युवा मुस्लिम पीढ़ी यह समझने लगी है कि मुस्लिम समाज को बरगलाने वाले मजहबी और सियासी नेता उनके समाज को केवल वोट बैंक के रूप में देखते हैं और वे उनके सच्चे हितैषी नहीं। आज जब संपूर्ण विश्व भारत की ओर देख रहा है, तब भारत की मुस्लिम आबादी, जो सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी है और यहां तक कि उनकी संख्या यहां कई इस्लामी देशों से भी अधिक है, को हर मुद्दे पर सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। अज्ञानता किसी भी समाज की सबसे बड़ी शत्रु होती है। इसी अज्ञानता का लाभ उठाकर कुछ नेता मुस्लिम समाज को गुमराह करते हैं। ऐसे लोग सफल न होने पाएं, यह मुस्लिम समाज को सुनिश्चित करना होगा। मुस्लिम समाज को इससे अवगत होना चाहिए कि नागरिकता कानून में 2019 में जो संशोधन किए गए, उसके तहत केवल तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। इस कानून के मुताबिक 31 दिसंबर, 2014 या उससे पहले भारत आ चुके उक्त तीन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जा सकेगी। नागरिकता संशोधन कानून, 2019 से पहले किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था, लेकिन अब यह समय अवधि 11 से घटाकर पांच साल कर दी गई है।

मुस्लिम समाज को यह भी समझना होगा कि नागरिकता संशोधन कानून नागरिकता देने का कानून है, न कि किसी की नागरिकता छीनने का। इस कानून से किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं जाने वाली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए में पड़ोसी देश के मुसलमानों को शामिल न करने की भी वजह बताई है और यह भी स्पष्ट किया है कि इन देशों के मुस्लिम भी भारत की नागरिकता ले सकते हैं। मुस्लिम समाज इससे अनजान नहीं हो सकता कि जब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश इस्लामिक देश हैं तो फिर वहां के मुसलमान धार्मिक अल्पसंख्यक कैसे हो सकते हैं? यह कैसे संभव है?

वास्तविकता यही है कि इन तीनों पड़ोसी देशों में उत्पीड़न के शिकार लोगों के पास भारत भाग आने के अलावा यदि कोई विकल्प है तो यही कि वे या तो मारे जाएं या फिर अपना धर्म-पंथ त्याग दें। इसी कारण जहां अफगानिस्तान में गैर-मुस्लिम गिनती के बचे हैं, वहीं बांग्लादेश, पाकिस्तान में उनकी आबादी उत्पीड़न के कारण तेजी से कम होती जा रही है। विश्व की अनेक संस्थाओं द्वारा प्रकाशित रपटों में यह बात सामने आ चुकी है कि इन देशों में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है और उनका सम्मान के साथ जीना मुश्किल है। इन देशों के अल्पसंख्यक आसानी से न तो अमेरिका जा सकते हैं, न यूरोप और न ही किसी अन्य देश। उनके पास सबसे आसान विकल्प भारत आना ही है। वे भारत की ओर उम्मीद से न देखें तो किसकी ओर देखें? सीएए अपनी तरह का दुनिया का पहला कानून नहीं है। पश्चिम के देशों और यहां तक कि अमेरिका ने भी मजहब और संस्कृति के आधार पर नागरिकता देने के कानून बना रखे हैं। सीएए का विरोध न सिर्फ अनैतिक है, बल्कि भारतीय सोच के विरुद्ध भी है।

(लेखक इस्लामी मामलों के जानकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

कर्म बंधन

प्रायः लोगों से सुनने में आता है कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस पर यही प्रश्न उठता है कि इस तरह तो सभी प्रकार के शुभ या अशुभ कर्म ईश्वर के अधीन हैं। हम तो कठपुतलियों की भांति मात्र अभिनय कर देते हैं, फिर फल हमारे हिस्से कैसे आता है? वस्तुतः समस्त कर्म प्रकृति के अधीन होकर किए जाते हैं। प्रकृति से तात्पर्य है 'स्वभाव' जिसे जीव ने स्वयं रचा है। ईश्वर न तो किसी से शुभ कर्म करवा कर उसे उन्नति देते हैं, न ही कोई अशुभ कर्म करवा कर उसे अवनति देते हैं। वह पूर्णतः निःस्पृह है।

जब तक स्वभाव शुद्ध नहीं होता, तब तक जीव प्रकृति के अधीन ही रहता है। प्रारब्ध के अनुसार कर्म का फल भुगत कर ही शुद्ध हुआ जा सकता है। इसमें अपनी इच्छा या अनिच्छा का कोई अर्थ नहीं है। यह अपरिहार्य है। ज्ञानी व्यक्ति भी बिना कर्मफलों को भोगे मुक्त नहीं हो सकता। किसी को परसंताप में सुख मिल रहा है, वह उसकी प्रकृति है। इस अशुभ कर्म के फल से वह छूट नहीं पाएगा। किसी को उस यंत्रणा को झेलकर असीमित वेदना मिल रही है, यह उसका प्रारब्ध हो सकता है। ईश्वर अपनी सभी संतानों को शुद्ध करना चाहते हैं। वे शासक भी हैं, नियामक भी हैं। यदि इस जन्म में हमारे हिस्से दुख भोगना लिखा है, तो हमें अच्छे लोग क्यों मिलेंगे? मनुष्य जिस प्रकार से अपने शुभ या अशुभ कर्मों का फल भोग सके, वैसी ही परिस्थिति और बुद्धि बन जाती है।

सूर्य की ऊर्जा से पृथ्वी पर समस्त क्रियाकलाप संपादित होते हैं, परंतु इन कार्यों से सूर्य निर्लिप्त हैं। उसी प्रकार मानव शरीर से होने वाले पाप-पुण्य से ईश्वर का कोई भी संबंध नहीं। अपने जीवन के पूर्वार्ध में किए गए कर्मों के फल जीवन के उत्तरार्ध में दिखने आरंभ हो जाते हैं। बीते जन्मों में स्वयं के किए कर्म को देखने के लिए आज मिल रहे फल को समझना होगा। यदि इसका सूत्र मिल गया तो कर्मों की दिशा सुधारने की राह भी मिल जाएगी, जिससे जीवन का दशा बेहतर हो पाएगी।

द्विवंकल तोमर सिंह

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

स्वच्छ हवा-पानी की चुनौती

पर्यावरणविद् अनिल प्रकाश जोशी ने 'स्वच्छ हवा-पानी सबसे बड़ी चुनौती' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में सारगर्भित टिप्पणी की है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए समवेत प्रयास समय की आवश्यकता हो चले हैं। स्वच्छ हवा-पानी सुनिश्चित करना केवल सरकारों का ही दायित्व नहीं, अपितु यह नागरिकों के कर्तव्य पालन से भी जुड़ा है। कृषि कार्य हों या कल-कारखाने, सभी प्रदूषण को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इस समय कंस्ट्रक्शन कार्य का हवा को प्रदूषित करने में बड़ा योगदान हो चला है। वाहनों का प्रदूषण भी ऐसा ही एक मुद्दा है। यदि इसमें नागरिक अपने स्तर पर थोड़ी सी भी सक्रियता दिखाएं तो अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अच्छी बात है कि लेखक महोदय ने केवल समस्या को रेखांकित ही नहीं किया, अपितु उसके समाधान की दिशा में कुछ उपयोगी सुझाव भी दिए हैं।

योगराज, खरड़ (पंजाब)

जन भागीदारी से होगा प्रदूषण पर नियंत्रण

अनिल प्रकाश जोशी द्वारा लिखित आलेख 'स्वच्छ हवा-पानी सबसे बड़ी चुनौती' पढ़ा। स्वच्छ हवा व पानी मानव जीवन का आधार है। दोनों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। आज विकास की अंधी दौड़ में मानव स्वच्छ हवा-पानी से दूर होता जा रहा है, बीमारियां उसके करीब आती जा रही है। आज भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। देश विकासशील से विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आने के लिए तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन दूसरी ओर देश की बड़ी आबादी दूषित पानी पीने के लिए विवश है। वायु प्रदूषण व जल प्रदूषण की वजह से कई तरह की जानलेवा बीमारियों का जन्म हो रहा है। सांस संबंधी रोग में गत कुछ वर्षों में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। वृक्षों का कटाव व सड़कों पर गाडियों की अनियंत्रित भीड़ को रोकना हर नागरिक की जिम्मेदारी होनी चाहिए। सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर हम प्रदूषण नियंत्रण में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक व हाइब्रिड वाहनों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सड़कों पर धूल को नियंत्रित करने की कारगर व्यवस्था होनी चाहिए। जन भागीदारी के बिना प्रदूषण पर नियंत्रण संभव नहीं है। हर नागरिक को अपने जीवन में एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए।

ई हिमांशु शेखर, केसपा, गया

कोर्ट ही कोई व्यवस्था दे

संविधान सभा अपनी मैराथन बैठकों के पश्चात भी इस स्थिति की कल्पना करने में असमर्थ रही कि कोई मुख्यमंत्री भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में निरुद्ध हो सकता है। अनेक मूर्धन्य कानूनविदों से सुसज्जित संविधान सभा इस स्थिति में क्या कार्रवाई हो, इसको बताने में असमर्थ रही। आम सरकारी कर्मी को एक रात के लिए भी जेल में रहने पर नौकरी से निलंबित कर दिया जाता है, परंतु केजरीवाल 10 दिनों से ईडी की हिरासत में सरकार चला रहे हैं। अब उनको 15 दिनों के लिए तिहाड़ जेल भेजा रहा है। जहां सप्ताह में दो बार ही मुलाकात की जा सकेगी। ऐसे में सरकार कैसे चलेगी। ऐसी स्थिति में कोर्ट को ही संज्ञान लेकर कोई विधिसम्मत निर्देश जारी करना चाहिए।

धर्मेन्द्र नाथ रस्तोगी, दुर्गादेवी मंदिर मार्ग चौक, पटना

प्रभावशाली विमर्श करे विपक्ष

संपादकीय पृष्ठ पर 'विपक्षी एकता का प्रदर्शन' शीर्षक आलेख पढ़ा। दिल्ली के रामलीला मैदान में आइएनडीआइए की ओर से लोकतंत्र बचाओ रैली की गई। जिसमें विपक्ष के 27 दलों के नेता उपस्थित थे। सभी ने मोदी हटाओ, लोकतंत्र व संविधान बचाओ के नारों के साथ हमले किए। यह वही रामलीला मैदान है, जहां पांच अप्रैल 2011 को अन्ना हजारे के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए सशक्त लोकपाल की स्थापना की मांग को लेकर अनशन शुरू किया था। अजीब विडंबना है कि 13वें वर्ष उसी मैदान में भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के समर्थन में रैली हुई। रैली में विपक्ष ने सीबीआइ एवं ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया तो दिल्ली से 106 किलोमीटर दूर मेरठ की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है तो विपक्ष भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए दिल्ली में महारैली कर रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहा हूं, इसलिए कुछ लोग अपना आपा खो बैठे हैं। अब इन दोनों आरोप-प्रत्यारोप का प्रभाव तो जनता तय करेगी लेकिन इतना स्पष्ट दिख रहा है कि भ्रष्टाचार के आरोपितों को कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल रही है। ऐसे में विपक्ष को अब सीबीआइ एवं ईडी से इतर प्रभावशाली विमर्श खड़ा कर चुनावी रणनीति तैयार करना चाहिए। जनता भ्रष्टाचारियों को किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं करेगी।

युगल किशोर राही, छपरा, बिहार

पोस्ट

15 अप्रैल तक तिहाड़ में रहेंगे अरविंद केजरीवाल, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर रहेंगे। भारतीय राजनीति में क्या-क्या देखने को मिल रहा है।

हर्ष वर्धन त्रिपाठी@MediaHarshVT

राहुल गांधी और प्रियंका को अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहिए। वहां से इनके चुनाव न लड़ने से कमजोरी का संकेत जाएगा। मुझे उनकी जीत पर कोई संदेह नहीं।

प्रशांत भूषण@pbhushan1

विपक्ष की रैली में कांग्रेस का कहना था कि यह आइएनडीआइए की रैली है। जबकि अखिलेश यादव ने मंच से इस रैली को आम आदमी पार्टी की रैली कहा। सोनिया गांधी को सुनीता केजरीवाल के बगल में बिठाया गया। राहुल गांधी को भगवंत मान के बराबर।

प्रकाश नारायण सिंह@prakashnaraya18

टिकट या कुर्सी न मिलने से नाराज नेताओं का अपने गुस्से का सार्वजनिक प्रदर्शन करना या पार्टी बदल लेना प्रशंसनीय है। कम से कम वे अपनी पार्टी के आदर्शों, विचारों या नीतियों से बंधे होने का ढोंग तो नहीं करते। वे इस मामले में ईमानदार हैं कि उनके लिए पहली प्राथमिकता कुर्सी या पद ही है, बाकी और कुछ नहीं।

अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

जनपथ

लंबे टाइम के लिए गए जेल उस्ताद,
शिखर चूमकर कैरियर कर डाला बर्बाद।
कर डाला बर्बाद याद यदि रहते अन्ना,
तो पढ़ते ना आप कभी यह कड़वा पन्ना।
सीएम बनकर लोग अगर बैचेंगे खम्भे,
तो पक्का इस भांति नपेंगे लंबे-लंबे!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एजीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प.बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि. नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 24 अंक 347

****

अमर उजाला

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक

स्थापना वर्ष : 1948

नई दिल्ली ■ मंगलवार, 2 अप्रैल 2024

जब दिल बोलता है, तो दिमाग को आपत्ति करना अशोभनीय लगता है।
-मिलान कुंदेरा

लोकसभा चुनाव से ऐन पहले कच्चातिवु द्वीप के संवेदनशील मुद्दे के उठने पर विपक्ष की चिंता समझी जा सकती है, लेकिन इससे जुड़े जो तथ्य सामने आए हैं, वे केंद्र की तत्कालीन सरकार के फैसले पर सवाल तो उठाते ही हैं, जिसके कारण तमिल मछुआरों के आर्थिक व सामाजिक ताने-बाने को ठेस पहुंची थी।

अतीत का भूत

विवादास्पद कच्चातिवु द्वीप मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ही अंदाज में कांग्रेस पर निशाना तो साधा ही है, इस रोशनी में इससे जुड़े जो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, उन्होंने तमिलनाडु और देश की राजनीति में एक पुरानी बहस को फिर जिंदा कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दरअसल इस मामले में भाजपा की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के. अन्नामलाई के सूचना के अधिकार आवेदन पर मिली जानकारियों का हवाला देते हुए कच्चातिवु द्वीप को श्रीलंका को सौंपे जाने के लिए कांग्रेस को कसूरवार ठहराया है। उल्लेखनीय है कि कच्चातिवु, रामेश्वरम (भारत) और नेदुनतिवु (श्रीलंका) के मध्य 285 एकड़ में फैला एक छोटा निर्जन द्वीप है, जहां स्थित बीसवीं सदी के एक चर्च की वजह से आगंतुकों की कभी-कभार आमद भले हो, पेयजल के अभाव के चलते स्थायी निवास तकरीबन नामुमकिन है। मध्यकाल की शुरुआत में यह द्वीप श्रीलंका के जाफना साम्राज्य के नियंत्रण में था, लेकिन 17वीं सदी तक यह मदुरई के राजा रामानंद के अधीन आ गया था। ब्रिटिश शासन में यह मद्रास प्रेसीडेंसी के अधीन था, हालांकि पारंपरिक तौर पर दोनों देशों के मछुआरे इसका उपयोग करते रहे। आजादी के बाद भी यह द्वीप भारत का हिस्सा रहा, जिस पर श्रीलंका दावा जताता रहा। 1974 में इस मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व श्रीलंका की तत्कालीन राष्ट्रपति सिरिमावो भंडारनायके के मध्य हुए समझौते के तहत यह द्वीप भारत द्वारा स्वेच्छा से श्रीलंका को सौंप दिया गया। तमिलनाडु की तत्कालीन द्रमुक सरकार समझौते से पहले राज्य सरकार से विमर्श न किए जाने को लेकर शुरुआत से ही इसके खिलाफ थी। 1991 में भी राज्य विधानसभा में इसके विरोध में एक प्रस्ताव पारित हुआ और 2008 में भी राज्य की तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इस फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था। दरअसल, इस मामले से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण पहलू तमिल मछुआरों की आजीविका और उनके सामाजिक ताने-बाने का है।

आलम यह है कि आज कच्चातिवु में मछलियां पकड़ने के लिए भारतीय मछुआरों को अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पार करनी पड़ती है, जिसमें कई बार उन्हें श्रीलंकाई नौसेना का भी सामना करना पड़ता है। खुद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन इसके समाधान के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख चुके हैं। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले इस संवेदनशील मुद्दे के उठने पर विपक्ष की चिंता समझी जा सकती है, पर अरुणाचल और चीन जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने वालों के खिलाफ भाजपा को एक बड़ा मुद्दा जरूर मिल गया है।

कूटनीति से ही हारेगा इस्लामिक स्टेट

तालिबान अकेले 'आईएसआईएस-के' के खतरे को रोकने में असमर्थ है। यह देखते हुए कि अफगानिस्तान में अमेरिकी पदचिह्न अब नहीं हैं, कूटनीति का तकाजा है कि इस्लामिक स्टेट के खिलाफ तालिबान से खुफिया जानकारी लेने के लिए सहयोग बढ़ाया जाए, जिससे आतंकवाद विरोधी हितों को फायदा होगा।

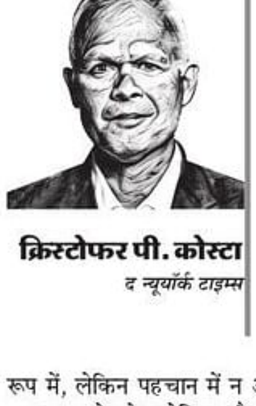

क्रिस्टोफर पी. कोस्टा
द न्यूयॉर्क टाइम्स

इस्लामिक स्टेट के खिलाफ आतंक-विरोधी जंग में अमेरिका ने कई जीतें दर्ज की हैं, इसके बावजूद वह अभी तक यह समझ नहीं पाया है कि उसे कैसे हराया जाए। रूस की राजधानी मास्को में 22 मार्च को एक कन्सर्ट हॉल पर हुए आतंकवादी हमले में 130 से ज्यादा लोग मारे गए और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह ताजा घटना याद दिलाती है कि इस्लामिक स्टेट एक भयावह खतरा बना हुआ है, खासकर इस्लामिक स्टेट-खोरासन (आईएसआईएस-के), जो अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान में सक्रिय है।

नए साल की शुरुआत से ही 'आईएसआईएस-के' ने ईरान और तुर्किये में जानलेवा हमले शुरू कर दिए। मास्को हमले के चार दिन बाद आईएसआईएस से संबद्ध अल-बतर मीडिया ने इटली, स्पेन और ब्रिटेन के लिए धमकी भरा संदेश प्रकाशित किया- 'अगला कौन'? फ्रांस और इटली, दोनों ने तबसे आतंकी खतरे से निपटने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। इस्लामिक स्टेट को उसकी स्वघोषित 'खिलाफत' से अलग करना उसे हराने के समान नहीं है। अपने चरम दिनों में इसमें 80 से अधिक देशों के 40,000 से ज्यादा विदेशी लड़ाके थे। आईएसआईएस ने खुद को अन्य देशों में पुनर्गठित किया है, अब वह ज्यादा खतरनाक रूप में, लेकिन पहचान में न आने योग्य ढंग से भूमिगत हो रहा है।

इस खतरे को अमेरिका और उसके सहयोगियों तक पहुंचने से रोकने के लिए अमेरिका को दो दशकों की आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञता को बचाना होगा। इसके अलावा, कुछ और गंभीर खतरे हैं, जिन पर वाशिंगटन को ध्यान देना चाहिए, जिनमें चीनी दुस्साहस और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की चुनौती शामिल है।

लेकिन अमेरिकियों को सुरक्षित रखने के लिए आतंकवाद का मुकाबला रणनीतिक प्राथमिकता में बने रहना चाहिए-और इसमें दुनिया के उन हिस्सों में इस्लामिक स्टेट पर नजर रखने का तरीका खोजना

शामिल है, जहां अब अमेरिका का कोई पदचिह्न नहीं है।

11 सितंबर, 2001 को अल कायदा के आतंकी हमले के बाद अमेरिकियों को खुद को तैयार रखने के लिए कहा गया था, क्योंकि आतंक से जंग पीढ़ियों तक चलने वाली थी। दशकों तक चली जंग में अमेरिका ने कुछ भयंकर गलतियां कीं और अपना ध्यान राष्ट्रीय सुरक्षा से हटाकर विभिन्न भू-राजनीतिक खतरों पर केंद्रित कर लिया।

सक्रिय संघर्ष क्षेत्रों से अपने सैनिकों और खुफिया तंत्रों को वापस बुलाकर अमेरिका ने 'आईएसआईएस-के' जैसे समूहों को फिर से उभरने का मौका दिया है। यह हार मानने का समय नहीं है, अन्यथा हम खुद को एक उभरते हुए प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए पाएंगे।

पश्चिम के आक्रामक सैन्य अभियानों ने खिलाफत को खत्म करने में मदद की और हाल के वर्षों में फिलीपीन और सीरिया सहित अन्य देशों में आईएसआईएस लड़ाकों की गतिविधियों को कम कर दिया। लेकिन गायब होने के बजाय वे फिर से संगठित हो रहे हैं, इसी बैनर के तले नए लड़ाकों की भर्ती कर रहे हैं और नई साजिशें रच रहे हैं। उनमें से कुछ गुट अन्य देशों में फिर से प्रकट हो गए हैं, वे बेहतर ढंग से प्रशिक्षित हैं और उन्हें तलाशना व उनसे बचना मुश्किल है। जैसा कि हम अभी देख रहे हैं, वे कुछ लक्षित देशों में घुसपैठ करके आतंकी हमलों को अंजाम देने पर आमादा हैं।

अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी से पहले 'आईएसआईएस-के' का प्रभाव सीमित था, खासकर दूसरे देशों में हमला करने की उसकी क्षमता। तालिबान और 'आईएसआईएस-के' एक-दूसरे के दुश्मन हैं और 2015 से ही दोनों एक-दूसरे से लड़ रहे हैं। सत्ता में आने के बाद तालिबान 'आईएसआईएस-के' से मुकाबला करने और उसके लड़ाकों को नियंत्रण में रखने का इरादा रखता था, लेकिन उसे मिली-जुली सफलता ही मिली। बेशक तालिबानी लड़ाके बेहद प्रभावशाली हैं, लेकिन नई आतंकवाद विरोधी भूमिका में वे उतने प्रभावी नहीं हैं। उन्होंने 'आईएसआईएस-के' के कमांडरों को खत्म करने और कुछ क्षेत्र वापस पाने में थोड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी अब भी अफगानिस्तान की सीमाओं पर सक्रिय हैं- और अब भी हमला करने की क्षमता रखते हैं। चूंकि तालिबान को अफगानिस्तान में 'आईएसआईएस-के' के हमलों को सीमित करने में कुछ सफलता मिली है, इसलिए समूह ने जानबूझकर अपनी ऊर्जा 'अंतरराष्ट्रीयकरण' के एजेंडे पर केंद्रित की है। 'आईएसआईएस-के' के पास अब चरमपंथियों का एक विशाल नेटवर्क है, जिसका वह फायदा उठा सकता है, जो काकेशस और मध्य एशिया जैसे अस्थिर क्षेत्रों में फैला हुआ है। हजारों मध्य एशियाई लोग इस्लामिक स्टेट में शामिल हो गए हैं, जिनमें कई उज्बेक और ताजिक 'आईएसआईएस-के' में नेतृत्व की स्थिति में हैं।

तालिबान अकेले 'आईएसआईएस-के' के खतरे को रोकने में असमर्थ है। अल कायदा और तालिबान का विरोध करने वाले समूहों का विवेकपूर्वक समर्थन करके तालिबान को सत्ता से हटाने की कोशिश करने का समय शायद बीत चुका है। ऐसे में, अब कूटनीति का तकाजा है कि वाशिंगटन एवं उसके सहयोगी तालिबान को 'आईएसआईएस-के' पर दबाव बनाने के लिए प्रोत्साहन देकर उनसे खुफिया जानकारी साझा करे। हो सकता है कि तालिबान ने 11 सितंबर के हमलों के बाद ओसामा बिन लादेन को अमेरिका को सौंपने से मुल्ला उमर के दुर्भाग्यपूर्ण इन्कार से सीख ली हो। या शायद नहीं भी।

हालांकि 'आईएसआईएस-के' को हराने के प्रयास में तालिबान से एक विश्वसनीय आतंकवाद विरोधी भागीदार बनने की उम्मीद करना अवास्तविक है। लेकिन सहयोग का कुछ स्तर आवश्यक है, चाहे वह कितना भी अरुचिकर क्यों न हो। आतंकवाद-विरोध में इतनी महत्वपूर्ण मानवीय बुद्धिमत्ता केवल जमीनी स्तर पर ही एकत्रित की जा सकती है। चूंकि अफगानिस्तान में अमेरिकी पदचिह्न अब नहीं है, इसलिए इस्लामिक स्टेट के खिलाफ तालिबान से मिली खुफिया जानकारी से आतंकवाद विरोधी हितों को फायदा होगा। पर यह सहयोग सूचना साझा करने तक ही सीमित रहना चाहिए, प्रशिक्षण या उपकरण देने तक नहीं।

©The New York Times 2024

जीवन धारा

रामचंद्र शुक्ल

साहसी आदमी पहले तो जल्दी डरता नहीं और डरता भी है, तो संभल कर अपने बचाव के उद्योग में लग जाता है। भय जब स्वभावगत हो जाता है, तब कायरता भी भीरुता कहलाती है और भारी दोष माना जाता है।

सुखी और निर्भय होने का सबको अधिकार है

किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण मनोविकार होता है, उसी को भय कहते हैं। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए। क्रोध दुख के कारण के स्वरूपबोध के बिना नहीं होता। यदि दुख का कारण चेतन होगा और यह समझा जाएगा कि उसने जान-बूझकर दुख पहुंचाया है, तभी क्रोध होगा। पर भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं; इतना भर मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुंचेगी। यदि कोई ज्योतिषी किसी से कहे कि 'कल तुम्हारे हाथ-पांव टूट जाएंगे' तो उसे क्रोध न आएगा; भय होगा। पर उसी से यदि कोई दूसरा आकर कहे कि 'कल अमुक-अमुक तुम्हारे हाथ-पैर तोड़ देंगे', तो वह तुरंत त्योरी बदलकर कहेगा कि 'कौन हैं हाथ-पैर तोड़नेवाले? देख लूंगा।'

भय का विषय दो रूपों में सामने आता है-असाध्य रूप में और साध्य रूप में। असाध्य विषय वह है, जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव हो या असंभव समझ पड़े। साध्य विषय वह है, जो प्रयत्न द्वारा दूर किया या रखा जा सकता हो। मान लीजिए, दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे या आनंद से बातचीत करते चले जा रहे हैं। इतने में सामने शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने आदि का प्रयत्न करें, तो बच सकते हैं। विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार तो होती ही है, पर बहुत कुछ मनुष्य की प्रकृति पर भी अवलंबित रहती है। क्लेश के कारण का ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता का निश्चय अपनी विवशता या अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। यदि यह अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने के अनभ्यास या साहस के अभाव के कारण होती है, तो मनुष्य स्तंभित हो जाता है और उसके हाथ-पांव नहीं हिल सकते। पर कड़े दिल का या साहसी आदमी पहले तो जल्दी डरता नहीं और डरता भी है, तो संभल कर अपने बचाव के उद्योग में लग जाता है। भय जब स्वभावगत हो जाता है, तब कायरता भी भीरुता कहलाती है और भारी दोष माना जाता है। जीवन के और अनेक व्यापारों में भी भीरुता दिखाई देती है। एक ही प्रकार की भीरुता ऐसी है, जिसकी प्रशंसा होती है। वह धर्म-भीरुता है।

जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार निर्भय होने का भी। निर्भयता के लिए दो बातें अपेक्षित होती हैं -पहली तो यह कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट न हो; दूसरी यह कि दूसरे हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस न कर सकें। इनमें से एक का संबंध उत्कृष्ट शील से है और दूसरी का शक्ति और पुरुषार्थ से। इस संसार में किसी को न डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती। साधु से साधु प्रकृति वाले को क्रूर लोभियों और दुर्जनों से क्लेश पहुंचता है।

भीरुता का संयोजक...

सूत्र

भीरुता के संयोजक अवयवों में क्लेश सहने की आवश्यकता और अपनी शक्ति का अविश्वास प्रधान है। शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागनेवाला शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता, तभी अपनी शक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी रक्षा का विश्वास नहीं रखता। भीरुता की तह में सहन करने की अक्षमता और अपनी शक्ति का अविश्वास छिपा रहता है।

दूसरा पहलू

ऑस्ट्रेलिया के क्वीन्सलैंड में ही सांपों की सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। वहां 120 किस्म के सांप पाए जाते हैं।

इतने सांप क्यों निकल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में?

ऑस्ट्रेलिया के क्वीन्सलैंड प्रांत स्थित सनशाइन कोस्ट की एक जेल से फोन आया। एक सेल में सांप था। कुछ घंटों के बाद एक स्कूल, एक गैरेज और एक रिटायरमेंट रूम के स्विमिंग पूल से भी सांप निकलने की खबरें आईं। सांप पकड़ने की सर्विस चलाने वाले स्टूअर्ट मैकेंजी के लिए इतना अच्छा समय कभी नहीं था। इन दिनों रोज उनके पास सांप पकड़ने की 35 से ज्यादा कॉल आती है। क्वीन्सलैंड में सांपों की सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। वहां 120 किस्म के सांप पाए जाते हैं। इनमें से दो तिहाई सांप जहरीले होते हैं, जिनमें से कुछ तो अत्यंत खतरनाक होते हैं। इसके बावजूद सांप काटने से होने वाली मौत का आंकड़ा बहुत कम, सालाना दो ही है।

नताशा फ्रॉस्ट

जब से पृथ्वी गर्म हो रही है, और दक्षिणी क्वीन्सलैंड का मौसम उपोष्णकटिबंधीय से उष्णकटिबंधीय हुआ है, तब से सांपों की सुषुप्तावस्था की अवधि भी घटी है।

अप्रैल से सितंबर तक, जो ऑस्ट्रेलिया में ठंड का समय है, सुषुप्तावस्था के दौरान सांपों में अमूमन सुस्ती आ जाती है। इस अवधि में कई बार वे सप्ताह भर तक न खाते-पीते हैं, न ही हिलते-डुलते हैं। लेकिन जब से पृथ्वी गर्म हो रही है, और दक्षिणी क्वीन्सलैंड का मौसम उपोष्णकटिबंधीय से उष्णकटिबंधीय हुआ है, तब से सांपों की सुषुप्तावस्था की अवधि भी घटी है। यानी मानवीय आवासों में उनकी गतिविधियां पहले की तुलना में बढ़ गई हैं।

'सिर्फ यही नहीं कि यहां सांप अब पूरे साल तुलनात्मक रूप से ज्यादा सक्रिय रहते हैं, बल्कि वे रातों को भी लंबे समय तक सक्रिय रहते हैं', क्वीन्सलैंड यूनिवर्सिटी में जीवविज्ञान के प्रोफेसर ब्रायन फ्राई कहते हैं।

मैकेंजी कहते हैं कि सांपों की सक्रियता बढ़ने के कारण अब उनकी जाड़े की छुट्टी छोटी होती जा रही है। सांप पकड़ने वाले अपने साथ सिर्फ धातु का एक हुक रखते हैं, जिसमें सांपों को फंसाकर बैग में बंद कर देते हैं, फिर उन्हें ऐसी जगह छोड़ आते हैं, जहां से उनके मानवीय आवासों में लौटने की आशंका कम रहती है। वे इसका ध्यान रखते हैं कि सांपों को कम से कम नुकसान पहुंचे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का कानून कंगारू और दूसरे वन्यजीवों के साथ सांपों को भी संरक्षण देता है। सांप पकड़ने की फीस करीब 100 डॉलर है।

सांप पकड़ने के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सांपों को कम से कम नुकसान पहुंचे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कंगारू के साथ सांपों को भी संरक्षण देता है।

चूंकि अगले 25 साल में सनशाइन कोस्ट की आबादी 50 फीसदी बढ़कर पांच लाख हो जाने का अनुमान है, ऐसे में वहां बहुत तेजी से जंगल काटकर भवन निर्माण का काम चल रहा है। इससे भी आसपास के जंगल और झाड़ियों में रहने वाले सांप भोजन और ठिकाने की खोज में मानवीय आबादी में घुस रहे हैं।

©The New York Times 2024

आंकड़े

गन्ना उत्पादक देश

गन्ने के उत्पादन में ब्राजील के बाद हमारा देश दूसरे स्थान पर है। ब्राजील में कुल वैश्विक उत्पादन का सबसे ज्यादा 38 फीसदी उत्पादन होता है।

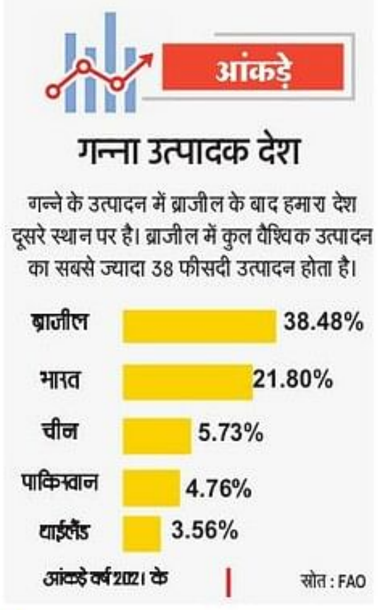

जो व्यक्ति सत्य-शील का त्याग कर देता है, उससे इंसानियत स्वतः दूर हो जाती है। भोग-विलास में फंसकर व्यक्ति अपना और दूसरों का जीवन कष्टमय बना देता है।

सत्य और सुख

अंतर्यात्रा
शिव कुमार गोयल

खलील जिब्रान से एक बार किसी ने पूछा, आज दानवता, हिंसा और अनैतिकता का बोलबाला क्यों है? जिब्रान ने उसे बताया, ईश्वर ने जब आदमी को दुनिया में भेजा, तो उसके दोनों हाथों में एक-एक घड़ा थमा दिया और कहा कि एक घड़े में सत्य भरा है, जिसका पालन कल्याणकारी होगा। दूसरे में सुख है, जो विषय-वासना की चाह पैदा करता है। तुम जगत में जा रहे हो, जहां शैतान (अज्ञान) और माया (अविद्या) का राज है। प्राण देकर भी सत्य की रक्षा करना, और सुख की कामना सीमित रखना। यह मत भूलना कि तुम्हारे दाहिने हाथ में सत्य का घड़ा है और बाएं हाथ में सुख का।

इंसान दोनों घड़े लेकर चला। रास्ते में वह पेड़ की छाया में बैठा, तो नींद आ गई। ईश्वर की बात सुनकर शैतान पीछा कर ही रहा था। उसने घड़े का स्थान बदल दिया। इंसान भ्रम में पड़कर सत्य को लुटाने लगा। सत्य-शील का घड़ा खाली हो गया। उसके पास केवल सुख-सुविधाएं ही रह गईं। इसी कारण आज संसार में दानवता, हिंसा और क्रूरता का बोलबाला दिखाई देता है। जो व्यक्ति सत्य-शील का त्याग कर देता है, उससे इंसानियत स्वतः दूर हो जाती है। भोग-विलास और दुर्व्यसनों में फंसकर व्यक्ति अपना और दूसरों का जीवन कष्टमय बना देता है।

(अमर उजाला आर्काइव से)

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 25 जनवरी, 1957

उत्तर प्रदेश के स्वशासन मंत्री से सवाल-जवाब

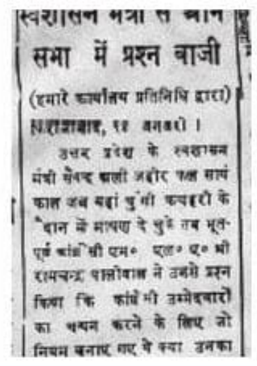

सभा में प्रश्न बाजी

(हमारे कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा)

इलाहाबाद, 24 जनवरी।

उत्तर प्रदेश के स्वशासन मंत्री सैयद अली जहीर कल सायं काल जब यहां चुंगी कचहरी के मैदान में भाषण दे चुके तब भूत-पूर्व कांग्रेसी एम० एल० ए० श्री रामचन्द्र पालीवाल ने उनसे प्रश्न किया कि कांग्रेसी उम्मीदवारों का चयन करने के लिए जो नियम बनाए गए थे क्या उनका

उत्तर प्रदेश के स्वशासन मंत्री से पूर्व कांग्रेसी विधायक ने प्रश्न किया कि कांग्रेसी उम्मीदवारों के चयन के लिए जो कानून बनाए गए थे, उनका कितना पालन किया गया। लेकिन मंत्री ने कहा कि उम्मीदवारों के चयन में उनका कोई दखल नहीं है।

साइबर सुरक्षा के लिए मजबूत पहल

'आई4सी' के कारण प्रवर्तन एजेंसियों और हितधारकों के बीच समन्वय में न सिर्फ सुधार हुआ है, बल्कि यह साइबर अपराध से निपटने में भी सक्षम है।

रूपाली मेहरा — रणनीति

प्रधानमंत्री की पहल पर देश के नागरिकों को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करने के लिए आई4सी कार्यक्रम चलाया गया है, जिसके सुखद परिणाम देखे जा रहे हैं। आई4सी को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र भी कहा जाता है, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की निगरानी में बना है। वर्ष 2020 में अपनी स्थापना के बाद से इस केंद्र ने देश भर में 4.7 लाख से अधिक शिकायतों का निपटारा कर के 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की बचत की है। इन आंकड़ों से यह तो पता चलता ही है कि भारत साइबर अपराधों को रोकने में कितना सफल हुआ है, यह भी स्पष्ट होता है कि 2020 के बाद से दर्ज मामलों की संख्या में 500 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और बचाई गई धनराशि में 800 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यानी राष्ट्रव्यापी साइबर अपराध रोकथाम तंत्र अब गति पकड़ चुका है।

ऐसे समय में, जब भारत दुनिया की शीर्ष तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की ओर अग्रसर है, मजबूत साइबर सुरक्षा प्रणाली का काफी

महत्व है। जब तक देश खुद को साइबर-अनुकूल राष्ट्र के रूप में स्थापित नहीं कर लेता, तब तक विकसित भारत की परिकल्पना अधूरी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक भाषण में कहा भी था- 'साइबर सुरक्षा अब केवल डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है। यह राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा का विषय है।'

भारत के सामने साइबर सुरक्षा की बड़ी चुनौती है। जब भारत ने जी-20 की वेबसाइट लॉन्च किया था, तो हैकरों द्वारा प्रति मिनट 16 लाख हमले हुए थे और भारत इनसे बचाव करने में सफल रहा था।

जी-20 शिखर सम्मेलन में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा भी था- 'हालांकि, प्रौद्योगिकी मनुष्यों, समुदायों और देशों को करीब लाने की दिशा में एक सकारात्मक विकास है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व और वैश्विक ताकतें प्रौद्योगिकी का उपयोग नागरिकों और सरकारों को आर्थिक व सामाजिक नुकसान पहुंचाने के लिए कर रही हैं। इसलिए यह सम्मेलन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह डिजिटल दुनिया को सभी के लिए सुरक्षित बनाने की समन्वित कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण वैश्विक पहल हो सकता है।' गृहमंत्री अक्सर कहते रहे हैं कि, आतंकवाद, आतंक के वित्तपोषण, कट्टरपंथ, सहित नई और उभरती, पारंपरिक और गैर-पारंपरिक चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्रों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों की क्षमताओं को बढ़ाना आवश्यक है।

केंद्र सरकार ने एक समान साइबर रणनीति की रूपरेखा तैयार करने, साइबर अपराधों की वास्तविक समय पर रिपोर्टिंग करने, एलईए क्षमता का निर्माण करने, विश्लेषणात्मक उपकरण बनाने, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं का राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित करने, साइबर स्वच्छता सुनिश्चित करने और हर नागरिक तक साइबर जागरूकता फैलाने की दिशा में काम किया है। देश में शुरू की गई सेफ सिटी परियोजना ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों अपराधों से निपटने के लिए अत्याधुनिक कमांड सेंटर प्रदान करती है।

देश में जो तीन नए आपराधिक कानून बने हैं, उनमें भी साइबर अपराधियों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले कानूनों की खामियों को लगभग समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। अपराधी तत्वों द्वारा इस्तेमाल किए गए डिजिटल उपकरणों को अब सबूत के रूप में मान्यता दे दी गई है।

जांच एजेंसियों को सशक्त बनाते हुए देश के सभी पुलिस स्टेशनों में क्राइम ऐंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क ऐंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) लागू किया गया है। भारतीय साइबर-अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) के जरिये साइबर अपराध के खिलाफ एक समन्वित और व्यापक कार्रवाई सुनिश्चित हो सकती है। आई4सी साइबर अपराध से संबंधित सभी मुद्दों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके कारण प्रवर्तन एजेंसियों और हितधारकों के बीच समन्वय में न सिर्फ सुधार हुआ है, बल्कि साइबर अपराध से निपटने के लिए जरूरी क्षमता भी हासिल हो गई है। इससे नागरिक संतुष्टि के स्तर में सुधार करना संभव हो गया है। सरकार ने 'साइट्रेन' पोर्टल नाम से एक विशाल ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम मंच भी तैयार किया है। यह साइबर सुरक्षा में दुनिया का सबसे व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम माना जा सकता है। गृह मंत्रालय ने बारीकी से और सुव्यवस्थित रणनीतियों के जरिये देश को एक ऐसे युग में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया है, जहां वर्चुअल रियलिटी ने दुनिया का एक अलग ही स्वरूप तैयार कर दिया है।

-लेखिका ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी एसोसिएशन की गवर्निंग काउंसिल की सदस्य हैं।

edit@amarujala.com

कल्पमेधा

दुर्जन एक गुट बना लें, तो सज्जनों को भी संगठित हो जाना चाहिए, वरना एक-एक करके उन सबकी बलि चढ़ जाएगी।

– एडमंड बर्कले

अवैध दावेदारी

अरुणाचल प्रदेश पर चीन ने एक बार फिर अपनी दावेदारी दिखाने की कोशिश की है। वहां के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अरुणाचल की तीस जगहों के नाम जारी किए हैं। पिछले सात वर्षों में यह चौथी बार है, जब चीन ने अरुणाचल की जगहों के भारतीय नामों को बदल कर चीनी नाम जारी किए हैं। अरुणाचल को वह जंगनान कहता और उसे दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बता कर उसे अपने नक्शे में दिखाता रहा है। हालांकि भारत ने हर बार उसकी ऐसी हरकतों का पुरजोर विरोध किया और दोहराया है कि अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। मगर चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ करने की कोशिशों से बाज नहीं आता। उसके ताजा कदम के पीछे की वजहें समझी जा सकती हैं। पिछले महीने प्रधानमंत्री ने अरुणाचल में सैन्य सुरंग का उद्घाटन किया था, तब भी चीन ने आपत्ति दर्ज की थी। दरअसल, उसी के बाद से चीन को लगता है कि भारत के अरुणाचल वाले हिस्से पर उसके कब्जे की रणनीति अब कामयाब नहीं होने पाएगी, क्योंकि इस सुरंग के खुल जाने से चीन के बहुत करीब तक भारतीय सेना की आसान पहुंच हो सकेगी।

प्रधानमंत्री की अरुणाचल यात्रा के बाद अमेरिका ने भी कह दिया कि अरुणाचल को वह भारतीय क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है और वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार सैन्य या असैन्य घुसपैठ या अतिक्रमण के जरिए क्षेत्रीय दावे करने के किसी भी एकतरफा प्रयास का दृढ़ता से विरोध करता है। इससे चीन की तिलमिलाहट और बढ़ गई। दरअसल, चीन इसी तरह धौंस-पट्टी से या चोरी-छिपे वास्तविक नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण करने का प्रयास करता रहा है। गलवान घाटी में उसके सैनिक इसी कोशिश के तहत घुसे थे, जिसे भारत ने पूरी ताकत से नाकाम कर दिया था। हालांकि बताया जाता है कि अब भी भारत के कुछ हिस्सों पर उसने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। मगर इस तरह अंतरराष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन कर और अपने नक्शे में पड़ोसी देश के हिस्से को दिखा कर कोई देश उस भूभाग का अधिकारी नहीं बन सकता। चीन इस तथ्य को नहीं झुठला सकता कि अरुणाचल को वह जिस तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा बताता है, उस तिब्बत पर उसने खुद अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। अंतरराष्ट्रीय संधि के मुताबिक तिब्बत उसका हिस्सा नहीं, बल्कि स्वतंत्र राष्ट्र है। इस तरह चीन दो-दो भूभागों पर अवैध दावेदारी जताता रहा है।

चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के तहत किस तरह पड़ोसी देशों, खासकर भारत की सीमा से सटे देशों में अपनी उपस्थिति बनाए रखने के तरह-तरह के हथकंडे अपनाता रहा है, वह अंतरराष्ट्रीय समुदाय से छिपा नहीं है। पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव आदि को वित्तीय मदद पहुंचा कर वह उनके बंदरगाहों आदि पर लंबी अवधि का करार करके कब्जा जमा चुका है। दरअसल, भारत का आर्थिक विकास और दुनिया में एक ताकतवर शक्ति के रूप में उदय चीन को लगातार खटकता रहा है। फिर, अमेरिका के साथ बढ़ती उसकी नजदीकी भी उसे रास नहीं आती। इसलिए मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की मंशा से वह भारत के आसपास अपनी सामरिक और जासूसी गतिविधियां चलाने की कोशिश करता देखा जाता है। अन्यथा चीन इस बात से अनजान नहीं होगा कि किसी देश के किसी भूभाग का नाम बदल कर और उसे अपने नक्शे में दिखा कर उस पर कब्जा नहीं किया जा सकता।

जागरूक बच्चे

आमतौर पर किसी सामाजिक कुरीति का विरोध, उसे खत्म करने के लिए पहल की उम्मीद उम्र और समझ के स्तर पर परिपक्व माने जाने वाले लोगों से की जाती है। मगर नोएडा में आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली कुछ बच्चियों ने बाल विवाह जैसी कुप्रथा की शिकार हो रही एक बच्ची को बचाने के लिए जैसी हिम्मत दिखाई, वह उनकी जागरूकता का एक बेहतरीन उदाहरण है। हाल ही में नोएडा के एक सरकारी स्कूल में आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा जब उदास दिखी, तो उसकी कुछ सहपाठियों ने इसका कारण पूछा। पता चला कि उसकी शादी जबरन कराई जा रही है, जबकि वह अभी पढ़ना चाहती है। इसके बाद उसकी सहपाठियों ने स्कूल के शिक्षकों और प्रबंधन को इस बारे में जानकारी दी। फिर स्कूल प्रबंधन ने इस बात की सूचना बच्चों के लिए जारी हेल्पलाइन और पुलिस को दी। पता चलते ही पुलिस ने ऐन मौके पर पहुंच कर शादी रुकवाई और आरोपियों को पकड़ा। अब वह छात्रा फिर पहले की तरह अपनी पढ़ाई कर रही है।

इस घटना की अहमियत इस रूप में है कि जिन कुरीतियों को खत्म करने की जिम्मेदारी समाज और परिवार के वयस्कों और बुजुर्गों की होनी चाहिए, उसे रोकने के लिए बच्चों ने पहल की। यह छिपा नहीं है कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा की वजह से कितनी बच्चियों का जीवन एक तरह से बर्बाद हो जाता है। उनकी पढ़ाई-लिखाई छूट जाती है, उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित होता है। इसका असर समूचे समाज के ढांचे पर पड़ता है, जिसमें स्त्री-पुरुष के बीच कई स्तर पर खाई पैदा होती है। कानूनी रूप से प्रतिबंधित होने के बावजूद अक्सर बाल विवाह के मामले सामने आते रहते हैं। दरअसल, ज्यादातर कुप्रथाएं इसीलिए चलन में रहती हैं कि समाज और परिवार के जिम्मेदार लोग ही उसे संरक्षण देते या उसकी अनदेखी करते हैं। मगर नोएडा में स्कूली बच्चियों ने अपनी एक सहपाठी के लिए जो किया, उससे उम्मीद बंधती है कि लोग अपने आसपास अनुचित और गलत रिवाजों के विरोध को लेकर मुखर होंगे और इस तरह बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को जड़ से खत्म करने में मदद मिलेगी।

कचरे का भंडार बनते समंदर

विश्व आर्थिक मंच द्वारा किए गए एक अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण 2050 तक चौगुना हो सकता है, जबकि माइक्रोप्लास्टिक सन 2100 तक पचास गुना बढ़ सकता है।

मनीष कुमार चौधरी

समंदर ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम उसे कचरे के सिवाय कुछ नहीं दे रहे। 'इंटरनेशनल यूनियन फार कंजर्वेशन आफ नेचर' की एक रपट के मुताबिक, हर साल लगभग तीस करोड़ टन प्लास्टिक का निर्माण होता है। इसमें से लगभग 1.4 करोड़ टन प्लास्टिक कचरे के रूप में हर साल समंदर में डाल दिया जाता है। समुद्र की गहराई का उपयोग बड़ी मात्रा में परमाणु सामग्री दफ्न करने के लिए भी किया गया। पहले और दूसरे विश्वयुद्ध के बाद के वर्षों में, ब्रिटिश, अमेरिकी, सोवियत, आस्ट्रेलियाई और कनाडाई सरकारों ने सैकड़ों-हजारों टन अप्रचलित रासायनिक हथियारों को ड्रमों में भर कर या टुकड़ों में बांट कर पानी की गहराई में दफ्न कर दिया। हालांकि सार्वजनिक आक्रोश के कारण इस प्रथा को 1972 में समाप्त कर दिया गया था। मगर वर्ष 2019 के एक अध्ययन में आर्कटिक महासागर के तल पर कम से कम अठारह हजार रेडियोधर्मी वस्तुएं बिखरी हुई पाई गईं, उनमें से कई सोवियत संघ द्वारा फेंकी गई थीं। जब ये वस्तुएं अपना जहर पानी में छोड़ना शुरू कर देंगी, तब क्या होगा! कई पर्यावरणविदों ने इस स्थिति को 'समुद्र तल पर धीमी गति से चल रहा चेर्नोबिल' कहा है।

हालांकि सोवियत संघ ने किसी भी अन्य देश की तुलना में समुद्र तल पर अधिक परमाणु कचरा फेंका था, लेकिन इस मामले में वह अकेला नहीं था। 1948 और 1982 के बीच, ब्रिटिश सरकार ने लगभग सत्तर हजार टन परमाणु कचरा समुद्र की गहराई में भेज दिया। कम मात्रा में ही सही, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जापान और नीदरलैंड ने रेडियोधर्मी सामग्री के निपटान के लिए समुद्र का उपयोग किया है। अब जबकि अंतरराष्ट्रीय संधियां समुद्र में रेडियोधर्मी सामग्री के निपटान पर रोक लगाती हैं, ब्रिटिश सरकार कुंब्रिया के समुद्र तल के नीचे सौ टन से अधिक प्लूटोनियम सहित साढ़े सात लाख घन मीटर परमाणु कचरे के निपटान की योजना तलाश रही है। ब्रिटिश अधिकारियों का कुतर्क है कि इस प्रकार का भूवैज्ञानिक निपटान सैकड़ों-हजारों वर्षों तक कचरे को स्थिर और सुरक्षित रखने का एक तरीका प्रदान करता है। समुद्र में परमाणु कचरे का निपटान लापरवाही और लालच की एक बहुत बड़ी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। प्लास्टिक और अन्य वस्तुओं के रूप में भी मानव अपशिष्ट गहरे समुद्र में हर जगह दफ्न है।

कचरे का यह ज्वार समुद्र के सबसे गहरे और दूरस्थ हिस्सों तक पहुंच गया है। सबसे अधिक परेशान करने वाली बात समुद्र की गहराई में माइक्रोप्लास्टिक का बढ़ता संचय है। कुछ माइक्रोप्लास्टिक बड़ी प्लास्टिक वस्तुओं के पानी में टूटने का परिणाम होते हैं। समुद्र की ऊपरी परतों में माइक्रोप्लास्टिक ने खाद्य शृंखला पर आक्रमण किया है। जैसे-जैसे माइक्रोप्लास्टिक परतों को पार करता हुआ ऊपर की ओर बढ़ता है, उच्च और उच्चतर सांद्रता में एकत्रित होता जाता है। व्हेल और पक्षी बड़ी मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक का उपभोग कर रहे हैं, जिससे उन्हें कुपोषण हो रहा है और उन जीवों के कई अंगों को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक उनके ऊतकों में एकत्र

हो जाते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा किए गए एक अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण 2050 तक चौगुना हो सकता है, जबकि माइक्रोप्लास्टिक सन 2100 तक पचास गुना बढ़ सकता है। यह समुद्री जैव विविधता के लिए खतरा तो है ही, कुछ

> **भारत में लगभग 6.5 करोड़ टन ठोस अपशिष्ट पैदा होता है, जिसमें से लगभग 6.2 करोड़ टन नगरीय ठोस अपशिष्ट होता है। इसका लगभग 75 से 80 फीसद ही नगर निकायों द्वारा संग्रहित किया जाता है। शेष अपशिष्ट नदियों के माध्यम से अंततः समुद्र में पहुंच कर समुद्री मलबे का हिस्सा बन जाता है। भारत की प्रमुख नदियों और सहायक नदियों द्वारा लगभग पंद्रह से बीस फीसद प्लास्टिक अपशिष्ट को बहाकर समुद्र तक लाया जाता है। अगर इसी प्रकार से वैश्विक स्तर पर यह क्रम चलता रहा तो 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक कचरे की मात्रा होगी।**

प्रजातियों को विलुप्ति के कगार पर पहुंचा सकता है।

भारत में लगभग 6.5 करोड़ टन ठोस अपशिष्ट पैदा होता है, जिसमें से लगभग 6.2 करोड़ टन नगरीय ठोस अपशिष्ट होता है। इसका लगभग 75 से 80 फीसद ही नगर निकायों द्वारा संग्रहित किया जाता है। शेष अपशिष्ट नदियों के माध्यम से अंततः समुद्र में पहुंच कर समुद्री मलबे का हिस्सा बन जाता है। भारत की प्रमुख नदियों और सहायक नदियों द्वारा लगभग पंद्रह से बीस फीसद प्लास्टिक अपशिष्ट को बहाकर समुद्र तक लाया जाता है। अगर इसी प्रकार से वैश्विक स्तर पर यह क्रम चलता रहा तो 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक कचरे की मात्रा होगी।

'वर्ल्डवाच इंस्टीट्यूट' की एक रपट के मुताबिक, अमेरिका और यूरोप में प्रति व्यक्ति वर्ष में करीब सौ किलो प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। इसमें ज्यादातर प्लास्टिक का इस्तेमाल पैकेजिंग के लिए किया जाता है, जो एक बार इस्तेमाल होने के बाद फेंक दिया जाता है। एशिया में प्रति व्यक्ति सालाना प्लास्टिक का इस्तेमाल बीस किलोग्राम है। यह सारा प्लास्टिक कचरा धीरे-धीरे समुद्रों में दफ्न कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आज समुद्र कचरे का ढेर बन गया है। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का सिर्फ एक तिहाई हिस्सा पुनर्चक्रित हो पाता है। प्लास्टिक के साथ समस्या यह है कि वह जल्दी से नहीं गलता, कई सौ वर्ष तक जमीन या समंदर में वैसे का वैसा पड़ा रहता और धीरे-धीरे माइक्रोप्लास्टिक के जरिए अपने आसपास के हिस्से को प्रदूषित करता रहता है।

अध्ययनों से पता चलता है कि हर साल समुद्र में दफ्न होने वाले 1.1 करोड़ टन से अधिक प्लास्टिक का 99.8 फीसद हिस्सा गहरे पानी में रहता है। बड़ी प्लास्टिक वस्तुएं आसानी से डूब जाती हैं, लेकिन माइक्रोप्लास्टिक कहीं अधिक घुमावदार रास्ते अपनाते हैं। कुछ समुद्री बर्फ के साथ नीचे की ओर बहते हैं, कुछ मछलियों और अन्य जानवरों के मल में निकल जाते हैं। कुछ तो शैवाल के टुकड़ों में जमा हो जाते हैं। यह प्रक्रिया हर साल चार लाख टन से अधिक प्लास्टिक को गहरे समुद्र में ले जा सकती है। 2019 में चीनी वैज्ञानिकों ने मारियाना ट्रेंच के तल पर रहने वाले उभयचरों के शरीर में 1940 और 1950 के दशक में परमाणु बमों के विस्फोट से रेडियोधर्मी कार्बन-14 की खोज की।

1946 से 1993 तक, तेरह देशों ने मुख्य रूप से चिकित्सा, अनुसंधान और परमाणु उद्योगों से निकले लगभग दो लाख टन परमाणु/रेडियोधर्मी कचरे के निपटान के लिए समुद्रों का उपयोग किया। अपशिष्ट पदार्थों में विभिन्न कंटेनरों में रखे गए तरल और ठोस पदार्थ, रिएक्टर जहाज, खर्च किए गए या क्षतिग्रस्त परमाणु ईंधन शामिल थे। वर्ष 1993 से अंतरराष्ट्रीय संधियों द्वारा महासागर निपटान पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भले समुद्र में निपटान के मामले में अब तक केवल निम्न स्तर का रेडियोधर्मी कचरा ही डाला गया है, लेकिन समुद्र तल पर फैले सैकड़ों-हजारों टन परमाणु कचरे के धीमे क्षय की तरह, समुद्री जीवों के शरीर में प्रवेश कर गई मानव उद्योगों की जहरीली विरासतें याद दिलाती हैं कि गहराई भूलने की जगह नहीं है कि जहां कुछ भी डाल दो और भूल जाओ। गहरा महासागर पृथ्वी पर सबसे बड़ा वातावरण है, जो समुद्री जीवमंडल का 95 फीसद हिस्सा बनाता है। गहरे समुद्र को मानव गतिविधि से किसी भी तरह अलग मानना अब संभव नहीं है। इसे कचरा निपटान स्थल मान लेना सबसे बड़ी भूल होगी।

दुनिया मेरे आगे

कराहती कुदरत

सुरेशचंद्र रोहरा

वृक्ष और जंगल कट रहे हैं। यह ग्रामीण जीवन के करीब वक्त गुजार चुके किसी भी व्यक्ति का दुख हो सकता है कि गांव में एक समय में जो दर्जन भर अमराइयां थीं, वे देखते-देखते कट गईं। वहां आज बस्तियां बस गई हैं। यह हमारी आज की आधुनिक जीवन पद्धति का नमूना है। जब हम गांव, कस्बे में रहते थे तो वृक्षों से प्रेम करते थे। उनके महत्त्व को समझते थे, अमरैया सजाते थे। आम, जामुन और अन्य फलदार वृक्ष किसी मायावी चमत्कार से नहीं उगते थे। निस्संदेह हमारे पुरखों ने इन्हें बड़े जतन से लगाया होगा। उन्हें मालूम था कि आने वाली पीढ़ी के लिए यह अपरिहार्य है। क्या ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने अपनी दृष्टि से आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा प्राकृतिक संबल दिया था, विरासत दी थी कि जिसकी छाया में हम सुखी, समृद्ध या खुशहाल जीवन जीएं। मगर हमारी लालच की, अकर्मण्यता की शायद कोई इंतिहा नहीं है। सवाल है कि क्या हमने इस मसले पर कभी सोचा है कि हमारी इस उदासीनता और नींद में खोए रहने का हासिल क्या होने वाला है!

हम सब समझते हैं और यह सच है। एक अपढ़ से भी पूछ लिया जाए तो वह संवेदना का भरपूर प्रदर्शन करते हुए कहेगा कि वृक्ष हमारा जीवन है। आज की स्थिति पर वह दुख भी जाहिर करेगा। जिसके हाथों में दारोमदार है, वह खामोश है। यह सब कुछ जान कर भी अनजान बनने का नाटक क्यों करते हैं हम? इस मसले पर हमारे बीच कोई गंभीर विमर्श और कुछ जमीनी स्तर पर सक्रिय गतिविधियां क्यों नहीं दिखाई देतीं?

दरअसल, शहरों को जोड़ने वाले लंबे राजमार्ग बन रहे हैं। सरकारों की ओर आश्वासन दिया जाता है कि जितने वृक्ष कटेंगे, उससे चार गुना ज्यादा पेड़ सरकार और ठेकेदार के कारिंदे लगाएंगे। सौभाग्य या दुर्भाग्य, हमारे शहर में भी छह या चार लेन की सड़कें बड़ी तेजी से बन रही हैं। यह सड़कें विकराल दिखाई देती हैं, मानो कहां जा रही हों, कुछ पता नहीं। यह भी ध्यान में आता है कि अचानक प्रकट होकर ये कितनी जिंदगियों को लील जाएंगी!

जहां राजमार्ग जैसी सड़कें बन रही हैं, वहां प्रतिदिन कितने ही पेड़ कट रहे हैं। सोचने वाली बात है और इसका कारण क्या होगा कि स्थानीय लोग ऐसी जगहों पर काम नहीं कर रहे, बल्कि किसी और शहर से या दूर से आकर लोग वृक्षों को काट रहे हैं। यह समझना मुश्किल है कि यह स्थानीय लोगों की राय भिन्न होने या उनके दुखी होने की वजह से है या फिर यह कोई नीतिगत फैसला होता है।

जिन वृक्षों को तैयार होने में पच्चीस-तीस वर्ष लगे हों, वे अब विशाल होकर फलदार और छायादार हो चुके हैं, सड़क की शोभा और सुविधा बन गए हैं, उन्हें सिर्फ सुविधाओं के विस्तार के लिए काट दिया जाए तो इसे कैसे देखा जाएगा? आगे वृक्ष फिर नहीं कटेंगे, इसकी क्या गारंटी है? अगर काटना ही था तो लगाया क्यों गया? क्या यह नीतियों की दूरदर्शिता पर प्रश्न-चिह्न नहीं है? शायद ऐसा हर जगह हो रहा है। कस्बे, गांव का नाम बदल दिया जाए, देश-दुनिया में यही हो रहा है। यह दिखावे की जिंदगी और दुनिया बन चुकी है, जहां संवेदनाएं मर रही हैं। अन्यथा सैकड़ों-हजारों पेड़ काटने पर भी स्थानीय लोगों के सिवा कहीं और से ठोस विरोध नहीं दिखता।

> **जिन वृक्षों को तैयार होने में पच्चीस-तीस वर्ष लगे हों, वे अब विशाल होकर फलदार और छायादार हो चुके हैं, सड़क की शोभा और सुविधा बन गए हैं, उन्हें सिर्फ सुविधाओं के विस्तार के लिए काट दिया जाए तो इसे कैसे देखा जाएगा? आगे वृक्ष फिर नहीं कटेंगे, इसकी क्या गारंटी है?**

कहते हैं, मनुष्य की तरह ज्ञान और संवेदना सृष्टि में किसी अन्य प्राणी में नहीं है। मनुष्य अपनी संवेदनाओं के कारण ही मनुष्य है। वह सृष्टि के कण-कण से प्रेम करता है। उसे यह ज्ञान है कि आज इस सुंदरता के बीच तादात्म्य के साथ जीना है। जीवन में शिवम् का भी स्थान है और सत्यम् तो अंतरस्थ है। इस सबके बावजूद छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करता मनुष्य क्या किसी बड़े बदलाव की आहट ले रहा है, जो मौन है। जहां मुखर होना चाहिए वहां खामोश है।

यह सच है कि सरकार और सत्ता के सामने लोगों का विरोध तूती की आवाज है। ठीक है कि लोग दैनंदिन के काम में इतना डूब चुके हैं कि उनके पास देखने-सुनने के लिए समय नहीं है। मगर क्या हम सभी ऐसे हो चले हैं? ऐसा संभव है। मगर जंगल और वृक्षों के मामले में संघर्ष की राह पर एक भी चेहरा सामने नहीं है जो प्रेम से या चीख कर प्रतिकार दर्ज कराता दिखता हो। सच तो यह है कि बड़े-छोटे लोक लुभावन नारों और आज के महापुरुषों के भरोसे जंगल नहीं बचा सकते। इसके लिए सामान्य साधारण आदमी को सामने आना होगा। अगर गांव की बात करें, जंगल के आसपास बसे सामान्य गरीब को भी यह समझ और जुगत लगानी होगी कि वृक्ष की रक्षा कैसे की जाए। जिम्मेदारी जंगल के वन अमले के ऊपर डालना बेकार सिद्ध हो चुका है। जंगल में जमीन पर काबिज होना, फिर कानूनी दांवपेच से पट्टे ले लेना सामान्य बात हो चुकी है। ये हालात बन रहे हैं तो विशाल जंगल जो आज सिमट रहे हैं, सिमटते जा रहे हैं, अपना अस्तित्व खो देंगे। अगर उस दिन हमारी नींद खुलेगी तंद्रा टूटेगी तो फिर यह दुर्भाग्य है और हमारे संवेदनशील होने पर भी प्रश्न चिह्न।

यह कैसा समय है, जब हम तेज गति से चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ठिठक कर देखने का हमारे पास समय नहीं है। हमारे आसपास प्रकृति के विनष्ट होने कि जो खाई स्वयं हम खोद रहे हैं, वह एक दिन हमारे अस्तित्व को समाप्त कर देगी। इतनी भी समझ हमें नहीं है तो फिर मनुष्य पृथ्वी का सबसे तीव्र बुद्धि वाला प्राणी कैसे है?

त्योहार की सूरत

हर त्योहार का अपना एक मूल उद्देश्य होता है, जो हमें एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इसके केंद्र में बंधुत्व, मानवतावाद, आपसी समझ, सहयोग और सम्मान आदि शामिल रहे हैं। मगर हम देख रहे हैं कि वर्तमान में हमारे त्योहार अपनी मूल भावना से पूरी तरह भटक चुके हैं। इन्हें भटकाने वाला कोई और नहीं, हम-आप ही हैं। हमने अपने त्योहारों को बाजारवाद के हिसाब से परिभाषित कर दिया या फिर अपनी अपनी सुविधा अनुसार मनाने का प्रचलन बढ़ चुका है। अब इन त्योहारों की मूल भावना लगभग गर्त में जा चुकी है। हम अपने उत्सवों के नाम पर हुड़दंग, नशाखोरी, छेड़खानी और नफरत की गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। हाल में बीती होली में एक अर्थहीन वाक्य के नाम पर जबरन लोगों को या किसी अन्य समुदाय को प्रताड़ित किया जाना हो या नशे में धुत युवा पीढ़ी द्वारा किए जाने जीवन के जोखिम वाले कतरब या फिर महिलाओं से की जाने वाली अभद्रता हो, ऐसे दृश्य निश्चित रूप से चिंताजनक और डरावने हैं। एक आदर्श समाज ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा ही रहा तो कहीं ऐसा न हो कि अब हमारे त्योहार मुबारक के बजाय दुर्व्यवहार मुबारक हो जाए!

– सौरभ बुंदेला, भोपाल

महंगा चुनाव

एक समय था जब हर पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता जी-जान लगाकर अपने दल को जीतने के लिए कई दिनों तक मुफ्त सेवाएं देते थे और ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार के लिए सेव मुरमुरा से पेट भरकर प्रचार करते थे। अब कार्यकर्ताओं को अच्छे खाने-पीने के साथ पर्याप्त राशि का भुगतान करना होता है। जब चुनाव में इस तरह के खर्च में बढ़ोतरी होगी तो लोकतंत्र का मकसद कैसे पूरा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इस बार फिर चुनावों में खर्च को लेकर सभी दल उत्साहित दिख रहे हैं। हालांकि माना जा सकता है कि सर्वाधिक खर्च सत्ता पक्ष द्वारा होगा जो शायद निर्धारित खर्च सीमा से कई गुना अधिक भी हो सकता है। दरअसल, प्रत्येक प्रत्याशियों के लिए राशि निर्धारित है, लेकिन अगर पार्टी द्वारा प्रत्याशियों पर किए जाने वाले खर्च को प्रत्याशी के खर्चे में नहीं जोड़ा जाएगा तो जाहिर है इस रास्ते से असीमित धन खर्च होगा, जिस पर आयोग की कोई पाबंदी नहीं रहेगी। ऐसा लगता है कि हमारा लोकतंत्र अब बहुत महंगा पड़ने लगा है। कम खर्चे में चुनाव करवाने के रास्ते खोजने होंगे।

– विभूति बुपक्या, खाचरोद, मप्र

बढ़ता खतरा

'पृथ्वी की घूर्णन गति में कमी' (30 मार्च) पढ़ा। इससे पता चलता है कि हम किस हालत में पहुंच चुके हैं और कितनी चिंताजनक स्थिति है। मगर लगभग सभी लोगों को इन विषयों के प्रति कोई गंभीर रुचि नहीं है। अगर इन खबरों के आधार पर विचार किया जाए तो पूरी पृथ्वी खतरे में है। 2015 के पेरिस समझौते की 1.5 डिग्री ताप की सीमा को हम लांघ चुके हैं। भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में पानी की कमी हो रही है। समुद्र तटीय शहर खतरे में है। मगर जागरूकता फैलाने के लिए जिम्मेदार लोगों सहित सरकार, आम लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं। लोग केवल सुर्खियों में आई घटनाओं पर विचार करते हैं, नेताओं के बयानों पर उभरी बहस में उलझते हैं। जबकि शायद किसी भी मुद्दे की सच्चाई जानने में कोई रुचि नहीं है।

– वेद सिंह, लखनऊ

दिल्ली का मैदान

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की राजधानी राजनीतिक अखाड़ा बनी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी का धरना-प्रदर्शन जारी है। दूसरी तरफ, भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के विरोध में खड़ी है और सड़कों पर आंदोलनरत है। इन सब स्थितियों को देखते हुए दिल्ली में कभी संवैधानिक संकट भी खड़ा हो सकता है। दिल्ली की जनता चाहती है कि मुद्दों का हल किया जाए, आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। मगर वर्तमान स्थिति संकेत दे रही है कि दिल्ली में स्थिति और बिगड़ सकती है। फिलहाल शायद दिल्ली वालों के लिए यह बहुत बुरा वक्त है। उम्मीद की जानी चाहिए कि दिल्लीवासी जल्दी ही राजनीतिक दांवपेंच और खींचतान के दौर से बाहर आएंगे।

– वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid

www.readwhere.com

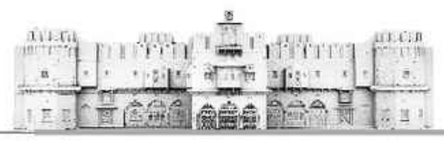

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

कोरी नसीहत काफी नहीं, सख्ती भी दिखाए आयोग

देश की सबसे बड़ी अदालत से लेकर राज्यों के हाईकोर्ट तक कई बार चुनावों के दौरान व्यक्तिगत छींटाकशी और अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल को लेकर राजनीतिक दलों व उनके कार्यकर्ताओं को नसीहतें देते रहे हैं। यह अपेक्षा भी की जाती रही है कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति दूसरों के प्रति आदर का भाव रखें। लेकिन चुनाव आते ही राजनीतिक दलों के नेताओं में अपने प्रतिद्वंद्वियों को लेकर तिरस्कारपूर्ण भाषा के इस्तेमाल की जैसे होड़ सी लग जाती है। इन सबके बीच जब चुनाव आयोग भी ऐसे अमर्यादित आचरण को लेकर संबंधित लोगों को चेतावनी जारी करने की खानापूर्ति ही करता नजर आए तो चिंता होना स्वाभाविक है।

महिलाओं को लेकर अमर्यादित टिप्पणियों के पिछले दिनों हुए ऐसे ही दो प्रकरणों में चुनाव आयोग ने भाजपा नेता व कांग्रेस की नेत्री को चेतावनी भरी नसीहत देकर अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर ली है। इन दोनों मामलों में से एक में कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने मंडी (हिमाचल प्रदेश) से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत व दूसरे में भाजपा नेता दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। चुनाव आयोग ने इन दोनों नेताओं को आचार संहिता के दौरान सार्वजनिक बयानबाजी में सावधानी बरतने की सलाह दी है। साथ ही यह भी कहा है कि वह अब इनके बयानों पर और निगाह रखेगा। हालांकि दोनों ही मामलों में संबंधित नेताओं ने इसके लिए सफाई भी दी थी। लेकिन आयोग की यह फौरी कार्रवाई दूसरे नेताओं को अमर्यादित आचरण करने से रोक पाएगी, ऐसा लगता नहीं। जो नसीहत दी गई है वह तो आयोग पहले ही चुनाव आचार संहिता में उल्लेखित कर चुका है। सवाल इस आचार संहिता के उल्लंघन का है। आयोग के दिशा-निर्देशों को धता बताते हुए जब राजनेता मनमानी पर उतर आएं तो ठोस कार्रवाई ही ऐसी मनमानी को रोक सकती है। चिंता की बात यही है कि चुनाव कार्यक्रम का ऐलान करते वक्त जिस अंदाज में आयोग की ओर से आचार संहिता की कठोरता से पालना कराने की बात कही जाती है, वह कठोरता इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के दौरान नजर नहीं आती।

चुनाव आयोग की शक्तियां व्यापक हैं, इसमें संदेह नहीं। लेकिन इन शक्तियों का इस्तेमाल भी तभी संभव होगा जब नियमों की अनदेखी करने पर ठोस सजा का प्रावधान भी किया जाए। आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी आम लोगों से मांगने के लिए चुनाव आयोग ने जो सी-विजिल ऐप बनाया है, उसका भी बेहतर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके लिए मतदाताओं को जागरूक भी करना होगा।

पत्रिका लोकतंत्र का उत्सव

लोकसभा चुनाव 2024

4 दलों को 1 प्रतिशत मत भी नहीं मिले

2019 के लोकसभा चुनाव में लक्षद्वीप की एक सीट पर 6 राजनीतिक दलों ने चुनाव लड़ा था। इनमें से 4 दल एक प्रतिशत मत भी प्राप्त नहीं कर पाए। यहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 48.71 प्रतिशत मत मिले।

राष्ट्रीय दलों को 60.70 प्रतिशत मत मिले

लोकसभा चुनाव 2014 में देशभर में 6 राष्ट्रीय दलों के 1591 प्रत्याशियों में से 807 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी। इनमें से सबसे ज्यादा 447 प्रत्याशी बसपा के थे। सभी राष्ट्रीय दलों को कुल 60.70 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे।

अवध भाजपा और विपक्ष जीत का आंकड़ा बढ़ाने की कोशिश में

श्रीराम के भव्य मंदिर की छटा में गुम हो रहे हैं दूसरे मुद्दे

पत्रिका LIVE चुनाव मैदान से

अयोध्या
डॉ.संजीव मिश्र

राजा रामु अवध रजधानी।
गावत गुन सुर मुनि बर बानी।।

गोस्वामी तुलसीदास की लिखी यह चौपाई इस समय उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र पर पूरी तरह खरी उतर रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी भले ही लखनऊ हो, किंतु अवध के लिए तो अयोध्या ही राजधानी है और राम उसके राजा। यही कारण है कि इस बार लोकसभा चुनाव में समूचे अवध में राम मंदिर की छटा ने स्थानीय मुद्दों को छिपा सा दिया है।

अवध क्षेत्र की सोलह संसदीय सीटों में अयोध्या को सहेजे फैजाबाद के साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और गांधी परिवार का गढ़ मानी जाने वाली रायबरेली भी शामिल हैं। मोहनलालगंज, सुल्तानपुर, उन्नाव, सीतापुर, धौरहरा, लखीमपुर खीरी, हरदोई, मिश्रिख, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, कैसरगंज, श्रावस्ती से बहराइच संसदीय सीटों तक सभी जगह चर्चा के केंद्र में भव्य राम मंदिर का निर्माण है। राम मंदिर ने सभी स्थानीय समस्याओं को पीछे छोड़ दिया है। हर ओर से राम को अपना मानने की आवाज उठ रही है और इस अपने-अपने राम के बीच असली राम-राज्य की चर्चा जरूर चौराहों पर होती नजर आती है। भाजपा के लोग राम मंदिर निर्माण के साथ राम राज्य लाने की बात करते हैं, तो विपक्ष कानून व्यवस्था से लेकर किसानों को हो रही परेशानियों के मसले उठाकर असली राम-राज्य की बात कर रहा है।

डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय देश भर में प्रसिद्ध है।

सीटें बढ़ाने की मशक्कत

पिछले लोकसभा चुनाव में अवध क्षेत्र की 16 सीटों में से भाजपा ने 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। विपक्ष के पास जो तीन सीटें थीं, उनमें से रायबरेली सीट कांग्रेस ने जीती थी और अंबेडकर नगर व श्रावस्ती बसपा के पास रही थी। भाजपा इन तीनों सीटों पर नजर गड़ाकर अवध में अपनी जीत का आंकड़ा मजबूत करना चाहती है। विपक्ष भी पूरा जोर लगा रहा है।

विरासत भी चर्चा में

अवध क्षेत्र पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी परिवार की विरासत के लिए भी चर्चा में रहता है। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत को आगे बढ़ा रहे राजनाथ सिंह एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं, वहीं रायबरेली में गांधी परिवार के वारिस पर सस्पेंस कायम है। रायबरेली के कांग्रेसी चाहते हैं कि सोनिया की जगह प्रियंका चुनाव लड़ें और वे प्रतीक्षारत भी हैं। सुल्तानपुर से गांधी परिवार की भाजपाई प्रतिनिधि मेनका गांधी नौवीं बार सांसद बनने के लिए मैदान में हैं।

विवादों से भी रहा नाता

लखीमपुर खीरी के सांसद अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र पर किसानों को कार से कुचलने का आरोप लगा था और आशीष को जेल भी जाना पड़ा था। टेनी को भाजपा ने फिर टिकट दे दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह टिकट की प्रतीक्षा में हैं।

चुनावी चटकारा

वोटों के खातिर लड़वाया मुर्गा...

छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव लड़ रहे एक प्रत्याशी का पुराना शौक चर्चा में बना हुआ है। वह इसलिए कि राजनीति में आने से पहले वे मुर्गा लड़वाते थे। किसी कार्यकर्ता ने उन्हें सलाह दे दी कि जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए बाजार में भीड़ एकत्र करके मुर्गा लड़वाया जाए। यह सुझाव उन्हें पसंद आया और बस्तर के पुसपाल बाजार में मुर्गा लड़वाया। इसके बाद से ही वे चर्चा में आ गए और काफी भीड़ यह मुकाबला देखने के लिए आई। भीड़ को देखकर उन्होंने वोट भी मांग लिए। यहां तक तो ठीक था, लेकिन अब ये नेताजी जहां भी जा रहे हैं, वहीं लोग मुर्गा लड़वाने की मांग कर रहे हैं। कार्यकर्ता भी लोगों की बातों का समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि जब मुर्गा लड़वाने से ही बात बनती दिख रही हो तो वही करना चाहिए। चुनाव में तो जनता को जो अच्छा लगे वही करने में भलाई है।

राग सियासी

गरमी विकट चुनाव की,
टिकट बचे हैं चंद।
समरभूमि नेता खड़े,
छिड़ा सियासी द्वंद्व।।
छिड़ा सियासी द्वंद्व,
ताल हर दल ने ठोकी।
करत जीत का दंभ,
सांस वोटर ने रोकी।।
अपनों के संग बैर,
गैर से बरतें नरमी।
रहे आसमां तैर,
उतारे जनता गरमी।।

-राम नरेश गौतम

ओडिशा होगी राजनीतिक दलों की दोहरी परीक्षा

नवीन पटनायक की प्राथमिकता सिंगल इंजन, भाजपा को चुनौती

पत्रिका LIVE चुनाव मैदान से

भुवनेश्वर
कानाराम मुण्डियार

ओडिशा का चुनाव देश के कुछ दूसरे राज्यों से कई मायने में बिल्कुल अलग है। देश की सबसे बड़ी पंचायत के साथ राज्य की सत्ता के लिए भी मतदाता सभी दलों को कसौटी पर कस रहे हैं। चुनावी समर में यहां यूं तो तीन किरदार हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला उन दो पुराने 'दोस्तों' के बीच है, जो इस बार भी 'दोस्त' बनते-बनते रह गए। सीटों के गुणा-भाग की पहेली अनसुलझी रही। लिहाजा राज्य में सत्तारूढ बीजू जनता दल और केन्द्र में सत्तारूढ़ भाजपा आमने-सामने हैं।

एक साथ दो परीक्षाएं पास करने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने दोगुनी ताकत झोंक रखी है। भाजपा के सामने पुराना प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है तो कांग्रेस के सामने सीटों की संख्या में बढ़ाने की चुनौती है।

ओडिशा में लंबे समय से से बीजू जनता दल (बीजेडी) की सरकार है। नवीन पटनायक को राजनीति विरासत में मिली है। राज्य में सत्तारूढ़ बीजेडी अपना वर्चस्व पहले की तरह कायम रखने में जुटी हुई है। इसलिए बीजेडी ने बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं किया। कई वर्षों बाद खासकर बीजेडी व बीजेपी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कोशिशें हुईं। बीजेडी व बीजेपी के बीच गठबंधन होना लगभग तय था, लेकिन शर्तों पर सहमति नहीं बन पाने के कारण यह हो नहीं पाया। दोनों तरफ से सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर टिकट जारी कर दिए गए।

ओडिशा की चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है।

सत्ता के दो केंद्र नहीं

1998 में नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने भाजपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। पटनायक को वाजपेयी सरकार में मंत्री भी बनाया गया। लेकिन पटनायक ने ओडिशा में कभी सत्ता के दो केन्द्र नहीं बनने दिए। वे अपनी सरकार को सिंगल इंजन से चलाना ज्यादा बेहतर मानते रहे हैं। विरासत में राजनीति के गुर सीखने वाले पटनायक राजनीतिक समीकरण और सही समय पर सही फैसले लेने के लिए चर्चित हैं, इसलिए 24 साल से उनकी सरकार है।

31 दलों ने लड़ा चुनाव

ओडिशा में पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में कुल 34 दलों ने चुनाव लड़ा था, लेकिन इनमें से 31 राजनीतिक दलों को एक भी सीट पर जीत नहीं मिल पाई। ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। यहां बीजू जनता दल को 12, भाजपा को 8 व कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली थी। इसके अलावा यहां किसी भी दल की दाल नहीं गल पाई।

नए चेहरों पर लगाया दांव

अब तक जारी सूची के अनुसार अधिकतर सीटों पर नए चेहरों पर दांव खेला गया है। बीजेडी कुछ विधायकों को टिकट काट कर उनके परिवार के युवा सदस्यों को आगे लाने का फार्मूला अपनाया है। साथ ही बीजद ने कुछ पुराने चेहरों को नए क्षेत्रों से भी उतारा है।

भाजपा डायरी

पीएम मोदी हैं चेहरा, पर्दे के पीछे हैं कई रणनीतिकार

चुनाव लड़ा कैसे जाता है और जीता कैसे जाता है, यह आज की भाजपा से बेहतर शायद ही कोई जानता हो? दबी जुबां में विपक्षी नेता भी इस तथ्य को स्वीकार करने से परहेज नहीं करते। आम धारणा यह है कि भाजपा नरेन्द्र मोदी के चेहरे पर चुनाव जीत रही है। यह सच भी है लेकिन आधा। पूरा सच यह है कि मोदी तो चेहरा हैं लेकिन पर्दे के पीछे रणनीतिकार तमाम दूसरे लोग भी हैं। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर राज्यों की राजधानियों में भाजपा की तमाम टीमें पिछले कई महीनों से सक्रिय हैं। ये टीमें पेशेवर लोगों से अलग हैं। कमजोर संसदीय क्षेत्रों में भाजपा कैसे जीत सकती है, किस प्रत्याशी को किस जाति के नेता की दरकार है या फिर कौनसा प्रत्याशी साधनों में कमजोर पड़ रहा है? इन सबके लिए अलग-अलग टीमें काम कर रही हैं। प्रदेश में नेताओं के बीच समन्वय

अथवा रूठे नेताओं को मनाने के लिए टीमों को अलग जिम्मेदारी भी दे रखी है और अधिकार भी। खास बात यह कि इन टीमों को सहयोग देने के लिए पर्दे के पीछे से विचार परिवार की टीम अलग काम कर रही हैं। विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के संगठन भाजपा के लिए माहौल बनाने के लिए पृथक रणनीति पर काम में जुटे हुए हैं। इतना ही नहीं चुनाव के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रहे हैं। मंगलवार को मोदी का बिहार के कार्यकर्ताओं से संवाद इस बात का उदाहरण है कि पार्टी चुनाव जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती।

कांग्रेस डायरी

तपती रेत पर बारिश की बूंदों जैसे अहसास का दिन

पहले चरण के चुनाव की तस्वीर साफ होने के साथ ही दूसरे चरण के शेष रह गए लोकसभा प्रत्याशियों के चयन को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। कई राज्यों के नामों पर विचार हुआ है। बैंक खाते फ्रीज होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी जयपुर में 6 अप्रेल को बड़ी रैली से चुनाव प्रचार अभियान के आगाज की तैयारियों में जुट गई है। इलेक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यमों में 'मेरे विकास का हिसाब दो' जैसे छोटे-छोटे विज्ञापन भी नजर आए हैं। आयकर विभाग से संबंधित एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की तरफ से अंडरटेकिंग दी है कि कांग्रेस पार्टी को दिए गए 3500 करोड़ रुपए से अधिक के टैक्स नोटिस पर जुलाई 2024 से पहले आयकर विभाग कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इससे कांग्रेस खेमे में मामूली राहत जरूर महसूस की जा रही है।

कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के घटक दल के नेताओं के चेहरे दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकतंत्र बचाओ रैली में उमड़ी भीड़ देख खिल गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते चुनाव से ऐन पहले फ्रीज करने की आयकर विभाग की कार्रवाई पर चुनाव आयोग की चुप्पी का मुद्दा प्रभावी तरीके से उठाया। अरविंद केजरीवाल की पत्नी और सुनीता केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का इमोशनल कार्ड विपक्षी नेताओं का असर करता हुआ दिखाई दे रहा है। दिन कुल मिला कर अच्छा बीता 'इंडिया' के लिए।

तमिलनाडु: भाजपा ने उठाया कच्चातीवु का मसला

भाषाई विवाद का लाभ उठाने की कोशिश में द्रमुक नीत गठबंधन

पी. एस. विजयराघवन

चुनाव प्रचार की बुलंदियों के बीच तमिलनाडु का आम आदमी गायब सा हो गया है। गठबंधनों के बीच केवल जुबानी तीर चल रहे हैं और वे ही सुर्खियां बन रहे हैं। महंगाई, कराधान व्यवस्था, बिजली-पानी आपूर्ति, स्वास्थ्य संरचना और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं की हालत क्लास के 'बैक बेंचर' की हो गई है। इन आधारभूत मसलों पर भाषाई आवरण ने अपनी गहरी छाया डाल दी है, जो सीधे-सीधे इस चुनाव को उत्तर और दक्षिण के बीच संघर्ष के रूप में बदल रही है।

हाल के पीएम नरेंद्र मोदी के बयान, जिसमें उन्होंने निराशा जताई थी कि वे तमिल नहीं बोल पाते, को द्रमुक ने हवा दी है। इस हवा को आंधी बनाने की जुगत में पूरा गठबंधन लगा है। वहीं, भाजपा बैकफुट पर है। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के. अन्नामलै ने इस मसले की तुलना 'फटी चप्पल' से कर दी। उनकी इस टिप्पणी ने द्रमुक नीत गठबंधन को एक नया कैम्पेन दे दिया है। द्रमुक, तमिलनाडु में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विरोध में इसीलिए ही है कि वह तीन भाषाई फार्मूला नहीं चाहती है। सत्तारूढ़ द्रमुक के राज्यसभा सांसद पी. विल्सन ने कहा कि विद्यार्थियों पर तीसरी भाषा सीखने का जोर नहीं डाल सकते, इसलिए टू लैंग्वेज फॉर्मूला पर ही अमल करेंगे। हम हिन्दी समेत किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं हैं।

'तमिल' को सियासी प्रचार के केंद्र में देख अब कच्चातीवु का मसला उठाया गया है ताकि कैम्पेन की दिशा को बदला जा सके। यह वह क्षेत्र है जहां तमिल मछुआरे अक्सर श्रीलंकाई नौसेना की ज्यादती का शिकार बनते हैं और यह भूभाग एक समझौते के तहत 1974 में श्रीलंका को दे दिया गया था। भाजपा, इस मसले के जरिए द्रमुक और कांग्रेस के मछुआरा वोट बैंक में सेंधमारी के प्रयास में है।

राजनीतिक वर्ग पहेली

हल 1

नेताओं के नाम

1. अखिलेश यादव
2. जे पी नड्डा
3. प्रियंका गांधी
4. सचिन पायलट
5. योगी आदित्यनाथ
6. मायावती
7. अमित शाह
8. भजन लाल
9. भूपेश बघेल
10. ममता बनर्जी

कमल खिलावन — POLI नोक-झोंक — पंजा सिंह

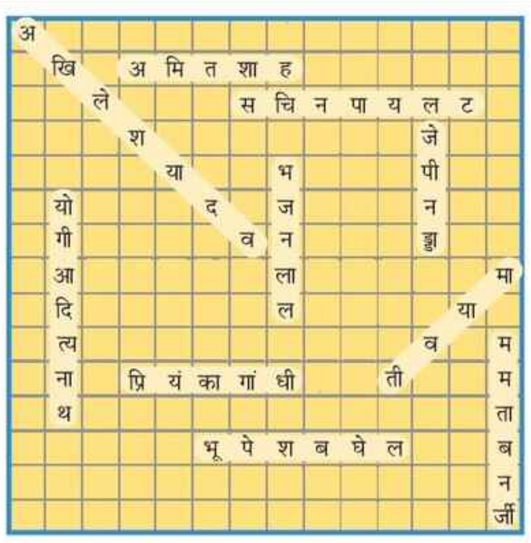

हवा का रुख या ईडी...

श्रीनगर की डल झील। शिकारे चल रहे हैं। एक शिकारे पर दिल्ली से आए पर्यटक पहाड़ो की बर्फ पर धरती के स्वर्ग सरीखे कसीदे कस रहे हैं। एक छोटा शिकारा चाय सर्व करता है। यूपीआइ स्कैन करा कर ऑनलाइन पेमेंट लेता है। शिकारे में बैठे ताया जी खुशी से- देखा कमाल हमारे पीएम का। कश्मीर मे यूपीआइ। ताई जी नाराज। अब यहां तो राजनीति की बात मत करो। ताया जी उनसे नाराज। कहने लगे- 370 न हटी होती तो आज तुम यूं बिना डर के शिकारे में न बैठे होती। बात ही मत किया करो मुझसे।

इस वायरल वीडियो को अपने मोबाइल में कमल खिलावन भोपाल के न्यू मार्केट मे बनारसी पान वाले के बाहर देख रहे हैं। पंजा सिंह को दिखाते हुए, मुंह में पान एडजस्ट करते हुए कहते हैं-

कमल खिलावन: *लो राजा, ये है हमारी गारंटी। अबकी बार 400 पार।*
पंजा सिंह : *तुम्हारी आइटी सेल के वायरल वीडियो हमें तो मत दिखाओ। दिखाना है तो इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब दिखाओ।*
कमल खिलावन : *(कुछ सोचने लगते हैं)*
पंजा सिंह : *क्यों जवाब नहीं सूझ रहा।*
कमल खिलावन : *वक्त तो दो..*
पंजा सिंह : *कितना, जितना एसबीआइ ने मांगा था..*
कमल खिलावन : *अमा मियां धरातल पर आओ। चुनाव सर पर हैं। अप्रेल आ गया है। चुनाव की बात करो। हम 400 पार की बात कर रहे हैं, तुम्हारी पार्टी, गठबंधन से भी तो कोई आंकड़ा दो.. कोई नंबर तो बताओ।*
पंजा सिंह : *तुम और तुम्हारे नंबर। 15 लाख का तो आज तक इंतजार है।*
कमल खिलावन : *हां आलू में से तो सोना निकल रहा है न, रोज। दो दिन पहले दिल्ली में रामलीला मैदान में निकला है। सारे कुनबे के साथ। दीदी नहीं दिखी। सीट भी नहीं मिली पश्चिम बंगाल में बंटवारे में। कहिए। कुछ तो कहिए।*
पंजा सिंह : *मैच फिक्स करते हो तुम लोग। हमारे दो-दो खिलाड़ी जेल भेज दिए। एजेंसियों का मिस यूज करते हो।*
कमल खिलावन : *सिखाया किसने। तुमने 70 साल किया। हमें तो दस साल ही हुए। ट्रेलर में ही आंसू आ गए। पिक्च र अभी बाकी है मेरे दोस्त।*
पंजा सिंह : *क्या ट्रेलर क्या पिक्चर। सिनेमा हॉल भी तुम्हारा। पॉपकॉर्न भी तुम्हारा, दर्शक भी तुमही ला रहे हो, रिव्यू भी तुम ही करा रहे हो। (पंजा सिंह का मोबाइल बजता है। वो देखता है। कहता है-*
पंजा सिंह : *ये लो राजस्थान में एक दर्जन हमारे नेता तुम्हारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं।*
कमल खिलावन : *देखा हवा का रुख..*
पंजा सिंह : *काहे का रुख, इन सबके खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स के केस थे। गुंडागर्दी है ये।*
कमल खिलावन : *(पंजा सिंह की कॉलर पकड़ते हुए) गुंडागर्दी। बहुत बोल रहे हो।*
पंजा सिंह : *(कमल खिलावन की गर्दन पकड़ते हुए।) आज आलू से सोना निकाल ही देता हूं। (चंद सेकंड में दोनों पुलिस की जीप में। अखबार पढ़ते हुए।)*

सुप्रिया शर्मा

आज का सवाल

विपक्ष के वरिष्ठ नेता भी चुनाव लड़ने से क्यों बच रहे हैं?

ईमेल करें :edit@epatrika.com

सोशल मीडिया भी जिम्मेदार

सोशल मीडिया के ज्यादा उपयोग से भी युवाओं में अवसाद बढ़ रहा है। दोस्तों और रिश्तेदारों से दूरी होती जा रही है जिसके कारण तनाव बढ़ता जा रहा है।

-कृत भट्ट, बांसवाड़ा

दिखावा और महंगे शौक

दिखावे, महंगे शौक, विलासितापूर्ण जीवन की तरफ झुकाव के कारण युवा अवसाद ग्रस्त हो रहे हैं। सादा जीवन उच्च विचार को अपनाने से अवसाद से दूर रहा जा सकता है।

-कमल कोठारी, मंदसौर

नशे से बढ़ता अवसाद

शिक्षा तथा रोजगार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा युवाओं को अवसादग्रस्त बना रहा है। इसके साथ ही नशे की लत के चलते भी युवा वर्ग अवसाद की जद में आ रहा है।

—हुकुम सिंह पंवार, इन्दौर

कम आमदनी भी कारण

कम आमदनी से युवा कुंठाग्रस्त हो जाते हैं। अवसरों की कमी के चलते कई युवा संविदाकर्मी के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन वेतन कम है। इससे युवा अवसाद में रहते हैं।

-आनंद सिंह राजावत, पाली

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की प्रतिक्रियाएं

पत्रिकायन का सवाल था, 'युवा वर्ग में अवसाद की समस्या क्यों बढ़ रही है?' पाठकों की प्रतिक्रियाएं ऑनलाइन भी देखें।

इसे स्कैन करें

rb.gy/37dih8